DEVELOPMENT OF AGRO-BASED INDUSTRIES IN EASTERN U.P. - A GEOGRAPHICAL ANALYSIS

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विकास - एक भौगोलिक विश्लेषण
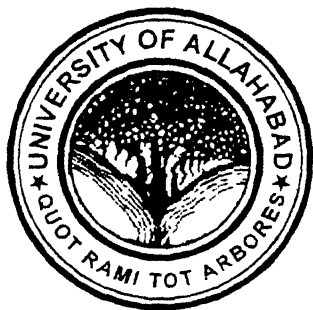
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी.फिल. (भूगोल)
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निदेशक
डॉ. आर. सी. तिवारी
प्रोफ़ेसर, भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ.प्र.)
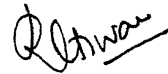
प्रस्तुतकर्ता
गिरीश त्रिपाठी
शोधछात्र - भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ.प्र.)

सितम्बर, २००२

CERTIFICATE

This is to certify that the matter embodied in this thesis entitled "Agro-based industries in Eastern U.P.- A Geographical analysis "- is a record of bonafide research work carried out by Mr. Girish Tripathi under my supervision and guidance . He has completed all the requirements for submitting the thesis for the award of the Degree of Doctor of Philosphy of the University of Allahabad .

Dated : 28.09.2002

Prof.(Dr.) R.C. Tiwari
Supervisor
Department of Geography
University of Allahabad
ALLAHABAD-211002

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 'पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विकास-एक भौगोलिक विश्लेषण ' को मूर्त रूप प्रदान करने में मेरे द्वारा जिन शोध विशेषज्ञों का आश्रय लिया गया है, उनके प्रति श्रद्धावनत होना मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूँ ।

मैं (स्व०) डॉ० आर० एन० तिवारी पूर्व विभागाध्यक्ष , भूगोल विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय , इलाहाबाद का चिरऋणी हूँ जिन्होनें अपने निर्देशन में मुझे कार्य करने की अनुमति प्रदान की एवं निरन्तर प्रेरणा के स्रोत बने रहे । डॉ० तिवारी जी की इच्छा के अनुरूप ही मैनें इतने बृहद क्षेत्र का चयन शोध कार्य हेतु किया । अन्तिम क्षणों में इनका अभाव थोड़े समय के लिए मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न कर गया । उनके द्वारा किये गये सहज प्रयत्नों के प्रति मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा ।

प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुवर डॉ० आर० सी० तिवारी , वरिष्ठ प्रोफेसर, भूगोल विभाग ,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का भी मैं आजीवन कृत्तज्ञ रहूँगा , जिन्होंनें मेरी समस्या को बड़ी गम्भीरता से सुना और अत्यंत सहज भाव से अवशेष कार्य को अपने पर्यवेक्षण में पूरा कर शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी । आपके सद प्रयासों का ही प्रतिफल है कि यह शोध कार्य आज मेरे द्वारा पूरा किया जा सका है ।

मैं डॉ० सबीन्द्र सिंह , प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , भूगोल विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे

पूर्व पर्यवेक्षक के अभाव को महसूस नहीं होनें दिया और नये पर्यवेक्षक की व्यवस्था करके प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

डॉ० सुधाकर प्रसाद तिवारी के अथक प्रयासों को मैं स्वप्न में भी नहीं भूल सकता , जिन्होंनें मेरे शोध कार्य के पंजीकरण तथा उसकी समाप्ति तक अपना पूरा सहयोग प्रदान किया । मैं इनका भी सदैव आभारी रहूँगा । भूगोल विभाग के ही प्रो० वी० एन० मिश्र एवं प्रो० एच० एन० मिश्र का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ , जो मेरे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे ।

मैं , भूगोल विभाग , का० सु० साकेत महाविद्यालय ,फैजाबाद के वरिष्ठ प्राध्यापकों डॉ० के० जी० दूबे, विभागाध्यक्ष , डॉ० राम अवध, डॉ० दीना नाथ वर्मा , डॉ० बब्वन सिंह ,डॉ शिव नारायण मिश्र , डॉ० बृज विलास पाण्डेय , डॉ०जैशराज शुक्ल एवं डॉ० राम करन पाठक तथा डॉ० दुर्गादत्त शुक्ल , प्राचार्य , आचार्य नरेन्द्रदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,वभनान , गोण्डा , डॉ० विनोद कुमार पाण्डेय , विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग , डॉ०(श्रीमती) अनिता सिंह, डॉ० श्रवण कुमार शुक्ल का भी मैं ह्रदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अन्दर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध कार्य करने की उत्सुक्ता उत्पन्न की और उत्कृष्ट शोध कार्य करने के लिए निरन्तर प्रेरित करते रहे ।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिला उद्योग केन्द्रों तथा अनेक अध्ययन संस्थानों के अधिकारियों का भी मैं कृत्तज्ञ हूँ ,जिन्होंनें मेरे शोध कार्य हेतु अपने कार्यालयों से आवश्यक सूचनायें उपलब्ध करा कर मेरा निरन्तर

सहयोग किया ।

इस शोध कार्य को पूरा करने में मुझे अपने समस्त पारिवारिक सदस्यों एवं शुभ चिन्तकों का पूर्ण सहयोग मिला है । मैं उन सभी लोगों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

अन्त में , मैं श्री भाल चन्द्र मिश्र का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अत्यधिक रूचि प्रदर्शित कर अत्यल्प समय में ही टंकन का कार्य सम्पादित किया ।

गिरीश त्रिपाठी

दिनांक : 28/9/02

गिरीश त्रिपाठी

शोध छात्र , भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद ।

विषय सूची

सारणी सूची

LIST OF DIAGRAMS

LIST OF MAPS

छायाचित्रों की सूची

प्रस्तावना

प्रस्तावना

विज्ञान के बढ़ते हुये प्रभाव से आर्थिक विकास का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है। हमारी वर्तमान सभ्यता को भी विज्ञान ने नया मोड़ दे दिया है। अब हम रूढ़िवाद से ऊपर उठकर तर्कपूर्ण विवेचनों को अधिक महत्त्व देने लगे हैं। हमारे रहन-सहन विचार-विवेक और जीवनयापन की पद्धति में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि हमारा सांस्कृतिक व आर्थिक पक्ष पहले से अधिक परिवर्तित हो गया है और आगे भी होता रहेगा।

मानव की आर्थिक क्रियाओं के विकास में प्रथमतः कृषि का विशेष महत्त्व रहा है। तत्पश्चात उद्योगों का महत्व प्रारम्भ हुआ और क्रमशः बढ़ने लगा। आज कृषि और उद्योग में कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसे सुनिश्चित करना कठिन कार्य है। देश, स्थान और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मानव के प्राविधिक विकास के साथ-साथ भी इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। अब उद्योग कृषि का सहचर ही नहीं रह गया है बल्कि विकसित देशों में तो इससे बहुत आगे बढ़कर वह एक बड़े मानव समुदाय का प्रमुख पेशा बन गया है।

भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों का विशेष महत्व है। जनसंख्या की तीव्रवृद्धि के कारण तथा कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुये भार के कारण लोगों का उद्योगों की ओर झुकाव बढ़ने लगा है। इससे बेरोजगारी की भी आंशिक समस्या का समाधान हो सका है। उद्योगों के बढ़ते हुये प्रभाव से कृषि कार्य भी पृथक नहीं रह सका है। विकसित देशों में कृषि कार्य भी आंशिक रूप से उद्योग बन गया है। बागाती कृषि या अन्य मुद्रादायनी कृषि के सम्बन्ध में तो उक्त कथन विशेष प्रकार से चरितार्थ है। भारत में भी कृषि का औद्योगीकरण प्रारम्भ हो गया है। निकट भविष्य में इसका स्वरूपनिखरकर सामने आ

जायेगा। कृषि में यन्त्रीकरण एवं विद्युतीकरण से तथा व्यापारिक दृष्टिकोण के बढ़ते जाने से औद्योगिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भारत जैसे देश के लिये यह एक ओर तो अधिक कृषिगत उत्पाद का साधन बन गया है किन्तु दूसरी ओर श्रम विस्थापन के कारण बेरोजगारी की समस्या का उन्नायक भी बन गया है। वास्तव में कृषि औद्योगीकरण और सामान्य औद्योगीकरण में समुचित सन्तुलन की आवश्यकता है। तभी भारत की अर्थव्यवस्था लाभप्रद सिद्ध हो सकेगी।

उद्योगों का स्वरूप भी पहले से बहुत कुछ बदल गया है। अब तो सेवाकार्य भी उद्योगों का रूप लेने लगा है। यही कारण है कि सेवा केन्द्र एंव विकास ध्रुव जैसी परिकल्पनायें भी उद्योगों से जुड़ गयी हैं। ग्राम्य विकास भी लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों से जुड़ गया है।

सामान्य पदार्थों को विशेष प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित रूप देकर अधिक उपयोगी बनाना ही औद्योगिक कार्य है। कभी-कभी कृषि कार्य और सेवाकार्य को भी अधिक उपयोगी बनाकर उद्योगों से जोड़ा जाता है। उपरोक्त सभी विवरणों को ध्यान में रखकर उद्योगों को निम्न प्रकार से विभाजित कियाजासकता है-

(१) संरचनात्मक या विनिर्माणं उद्योग-

इसमें औद्योगिक क्रिया द्वारा मानव के विशेष प्रकार के उपयोग हेतु वस्तुयें तैयार की जाती हैं। जैसे- रबर या प्लास्टिक निर्मित पदार्थ जो मनुष्य के विभिन्न उपयोगों में आते हैं।

(२) निष्कर्षणीय उद्योग-

इसमें पदार्थों के दोहन, उत्खनन तथा गलन (पिघलन) कार्य

द्वारा विशेष उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है- जैसे लकड़ी चीरकर विशेष उपयोगी टुकड़े बनाना, खदानों से खनिज प्राप्त करना तथा उसे परिशुद्ध करना, चट्टानों को प्राप्त कर या गलाकर धातुपिण्ड बनाना। ये उद्योग प्रमुख भारक्षयी पदार्थों पर आधारित होते हैं।

(३) पुनरोत्पादक उद्योग-

इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर या अन्य संसाधनों पर आधारित ऐसे उद्योग आते हैं जो अन्य उद्योगों को जन्म देते हैं। एक उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे उद्योग के लिये कच्चा पदार्थ बन जाती है। कभी-कभी ऐसे उद्योग भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। जिनका कच्चा पदार्थ पुनः पुनः उद्भूत होता रहता हैं।

साधनात्मक उद्योग-

ऐसे उद्योग मानवीय अधिवासों के निकट आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिये विकसित हो जाते हैं। ये छोटे-छोटे उद्योग होते हैं। जैसे-बिस्कुट एवं डबलरोटी उद्योग जो उपभोक्ता केन्द्रों पर आधारित होते हैं। (रेनर, १९४७)

कभी-कभी उद्योगों का विभाजन प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में किया जाता है। प्राथमिक उद्योगों में प्रकृति से या प्रकृति प्रदत्त साधनों से सहज रूप से वस्तुयें प्राप्त की जाती है। जैसे पशुपालन से दूध, वनों से गोंद आदि। द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण द्वारा वस्तुयें प्राप्त की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा, प्लास्टिक के सामान, कांच के बर्तन आदि। तृतीयक उद्योग मुख्यतः लघु उद्योग होते हैं जो विशेषकर सेवा कार्यों से सम्बन्धित होते हैं जैसे कपड़ा सीना, होटल चलाना, बाल काटना आदि।

उद्योगों को कभी-कभी आकार के अनुसार भी विभाजित किया जाता है। जैसे-वृहत् उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग । लघु उद्योग में ग्रामीण उद्योग एवं कुटीर उद्योग भी

सम्मिलित किये जाते हैं। इस प्रकार का विभाजन प्रायः उद्योगों में लगायी गयी धनराशि के आधार पर किया जाता है और यह धनराशि कालान्तर में बदलती रहती है। इसलिये यह विभाजन निश्चित आधारों पर निर्भर नहीं है। वर्तमान समय में बड़े उद्योगों की श्रेणी में वे उद्योग रखे जाते हैं जिनमें ५ करोड़ रुपये से अधिक पूँजी का विनियोग होता है। जिन उद्योगों में मशीन एवं सयन्त्र पर ६० लाख से ५ करोड़ तक की पूंजी लगी होती है उन्हें मध्यम उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें मशीन एवं संयन्त्र की कीमत ६० लाख रुपये या उससे कम होती है, लघु उद्योग की श्रेणी में रखे जाते हैं । ऐसे उद्योग जो परम्परागत ग्रामीण कारीगरों द्वारा घर पर ही चलाये जाते हैं तथा जिसमें ऐसी वस्तुयें उत्पादित की जाती है जिनकी गांव में ही खपत हो जाती है, कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। ऐसे उद्योग जो किसी बड़े मध्यम या लघु उद्योगों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और जो अधिकतम ७५ लाख रुपये की मशीन एवं संयन्त्र की लागत से स्थापित होते हैं, पूरक उद्योग कहे जाते हैं।

कभी-कभी उद्योगों के छोटे बड़े होने का आभास श्रमिकों की संख्या से भी लगाया जाता है। किन्तु उद्योगों में यन्त्रीकरण के बढ़ते जाने से यह आधार भी विश्वसनीय नहीं रह गया है। इसी प्रकार निर्मित पदार्थ की मात्रा व मूल्य पर भी ऐसा विभाजन आधारित किया जा सकता है, किन्तु इनके बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर इसे भी विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये लघु उद्योग (विशेषकर ग्रामीण उद्योग एवं कुटीर उद्योग) अधिक उपयोगी हैं। भारत का विकास बहुत हद तक गांवों के विकास पर ही आधारित है और गांवों का विकास लघु उद्योगों से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसी सन्दर्भ को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य हेतु उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग का चयन

किया है, जहाँ उद्योगों के उपयोग के लिये भूमि एवं जल जैसे मूल संसाधन प्रचुरता से उपलब्ध हैं साथ ही अनेक कृषि उत्पाद एवं कच्चे माल के उत्पादन में भी यह अग्रणी भाग है तथा जनसंख्या की अधिकता के नाते प्रचुर श्रम एवं विविध कृषि उत्पाद सम्बन्धी संसाधन आधार उपलब्ध हैं, वही दूसरी ओर अधिक जनसंख्या के कारण खपत के लिये बाजार सम्बन्धी प्रबल सम्भावनायें कृषि आधारित उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग के कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास से सम्बन्धित है। इस पूर्वी भाग को पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत २६ जिले सम्मिलित हैं। खगोलीय दृष्टि से इसकी स्थिति २३°४५' उत्तरी से २८°३०' उत्तरी अक्षांश तथा 80° 45' पूर्वी से 84°30' पूर्वी देशान्तर के मध्य है तथा इसका क्षेत्रफल ८५८४४ वर्ग किमी है। (सिंह, एम० बी०, १९९७, पृष्ठ ३७७) इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस प्रदेश की लम्बाई उत्तर से दक्षिण ४०० किलोमीटर तथा चौड़ाई पूरब से पश्चिम २४० किलोमीटर है अध्ययन क्षेत्र की पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण बिहार एवं मध्यप्रदेश राज्यों द्वारा होता है तथा उत्तरी सीमा का निर्धारण नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा किया जाता है तथा पश्चिमी सीमा का निर्धारण इलाहाबाद, फैजाबाद, सुलतानपुर जिलों द्वारा होता है। मानचित्र संख्या ०.०१ में सीमा का प्रदर्शन किया गया है। सारणी संख्या ०.०१ से स्पष्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल २६ जनपद हैं। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, देवीपाटन, आजममढ़ एवं मिर्जापुर कमिश्नरियाँ है। सम्पूर्ण पूर्वी उत्तरप्रदेश मुख्यतः एक मैदानी क्षेत्र है सामान्यतः पूरा मैदान सागर तल से १०० मीटर के नीचे स्थित है। कुछ पहाड़ियाँ दक्षिण में सोनभद्र एवं मिर्जापुर जनपदों में स्थित है। इस प्रदेश का उत्तरी

सारणी संख्या -०.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश - प्रशासनिक विभाजन

मण्डल	जनपद	जनसंख्या २००१	क्षेत्रफल (वर्ग कि०)	विकास खण्ड
वाराणसी	१-वाराणसी	३१४७९२७	१५७८	चिरईगाव,हरहुआ,पिण्डरा,बड़ागांव,सेवापुरी,काशी विद्यापीठ,अराजीलाइन,चोलापुर
	२-जौनपुर	३९११३०५	४०३८	शांहगंज,सूईथाकला,बदलापुर,खुटहन,महराजगंज,सुजानगंज,मुगरा बादशाहपुर,मछ्ली शहर,केराकत,गंज-डोभी,मुफ्तीगंज,जलालपुर,करंजाकला, बकशा,सिकरारा,धर्मापुर,मड़ियाहूँ,बरसंठी,रामनगर,रामपुर,सिरकोनी ।
	३-गाजीपुर	३०४९३३७	३३७७	गाजीपुर,करण्डा,मरदह,बिरनों,मुहम्मदाबाद,भरावल कोल,बाराचबर,काशीमाबाद,जमानिया,रेवतीपुर,भदोरा,सैदपुर,देयहुली,सादात,मनिहारी,जखनिया
	४-चन्दौली	१६३९७७७	२५५०	चकिया,शाहगंज,नौगढ़,चन्दौली,बरहनी,सकलडीहा,थानापुर,चहनियाँ,नियमताबाद
इलाहाबाद	१-इलाहाबाद	४९४१५१०	५४२२	धनुपुर,हण्डिया,प्रतापपुर,सैदाबाद,बहादुरपुर,बहरिया,फूलपुर,होलागढ़,कौडिहार,मऊआइमा,सोराँव,चाका,करछना,कोंधियारा,जसरा,शंकनगढ़,कोराँव,मण्डा,मेजा,उरवा
	२-प्रतापगढ़	२७२७१५६	३७१७	सदर,मान्धाता,सण्डवाचन्द्रिका,रामपुर खास,लक्ष्मणपुर,सांगीपुर,पही,आसपुर देवसरा,मंगरोरा,शिवगढ़,कण्डा,कालाकोकर,विहार,बाबागंज,रामपुर संग्रामगंढ
मिर्जापुर	१-मिर्जापुर	२११४८५२	४५२२	नगर,कोन,छानये,मझवां ,पहाड़ी,लालगंज,हलिया,मडियान,नरायण्नपुर,जमालपुर,राजगंढ,सीखड़ ।
	२-सोनभद्र	१४६३४६८	६७८८	राबर्टसृगंज,धोरावल,चतरा,नगवां,चौपन,दुध्धी,म्योरपुर,वमनी ।
	३-संतरविदास	१३५२०५६	६५८८	ज्ञानपुर,डीह,औराई,भदोही,सुरियावाँ।
आजमगढ़	१-आजमगढ़	३९५०८०८	४२३४	रानी की सरायँ,तहबरपुर,मिर्जापुर,मोहम्दपुर,पल्हनी,जहानागंज,साठेयाँव,लालगंज, ठेकमा,तरैवा,मेहनगर,बिलरियागंज,अजमगंढ़,महाराजगंज,हरैया,फूलपुर,पवई,मार्टीनगंज,कोयलसा,अतरोलिया,अीरौला,पल्हनी ।
	२-मऊ	१८४९२६४	१७१३	घोसी,बड़गांव,दोहरीघाट,फतेहपुर मण्डरॉव,मुहम्मदाबादगोहना,रानीपुर,परदहा,कोपागंज,रतनपुरा ।
	३-बलिया	२७५२४१२	२९८१	रसडा,नगरा,सीयर,चिलकहर,गड़वार,सोहावं,हनुमानगंज,दुबहड़,बेलहरी,बैरिया,मेरलीछपरा,बासडीह,बेरूवारबारी,रेवती,मनियर,पन्द्रह,नवानगर।
गोरखपुर	१-गोरखपुर	३७८४७२०	३३२५	पिपराइच,बांसगांव,गोला,पाली,पिपरौली,सहजनवा,खैराबाद,कौडीराम,गगहा,खजनी,भटहट,वेलघाट,सरदारनगर,बड़हजगंज,उरूवाँ,ब्रहापुर,ज.कोड़िया,चरगांव,कैम्पीयरगंज।
	२-महराजगंज	२१६७०४१	२९५१	महाराजगंज,सिसवां,परिवारा,बगमनगज,धानी,लक्ष्मीपुर,घुघली,नौतनवा,फरेन्दा,परतावल,निचलोल,भिठोरा ।
	३-देवरिया	२७३०३७६	२५३५	गौरीबाजार,देवरिया सदर,देसई देवरिया,पथरदेवा,बैतालपुर,रामपुर कारखाना,रूद्रपुर,बरंहज,भागपुर,भटनी,बनकटा,भाटपारानी,भुलुबनी,लार,सलेमपुर ।
	४-कुशीनगर	२८९१९३३	२९१०	कप्तानगंज,खड्डा,नेबुआ नौरंगिया,मोतीचक,रामकोला,सुकरोली,हाटा,कसया,तमकुही,दुधई,पडरौना,फाजिलनगर,विशुनपुरा,सेवरही।
बस्ती	१-बस्ती	२०६८९२२	३०३५	बहादुरपुर,बनकटी,बस्ती,गोर,हरैया,कप्तानगंज,कुदरहा,परसरामपुर,रुधौली,साउघाट,सल्टौवा गोपालपुर,विक्रमजोत ।
	२-सिद्धार्थनगर	२०३८५९८	२७५०	बांसी,बढनी,मनवापुर,बडैपुर,डुमरियागंज,इटवा,जोगिया,खेसरह,खुनियाव,मिठवल,नौगढ़,उस्काबाजार,सोहरतगंढ़ ।
	३-संतकबीरनगर	१४२४५००	१४४१	बघोली,हैसरबाजार,खलीलाबाद,मेंहदावल,नाथ नगर,सेमिरियरवां,सोथा ।

सारणी संख्या -०.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश - प्रशासनिक विभाजन

मण्डल	जनपद	जनसंख्या २००१	क्षेत्रफल (वर्ग कि०)	विकास खण्ड
वाराणसी	१-वाराणसी	३१४७९२७	१५७८	चिरईगाव,हरहुआ,पिण्डरा,बड़ागांव,सेवापुरी,काशी विद्यापीठ,अराजीलाइन,चोलापुर
	२-जौनपुर	३९११३०५	४०३८	शांहगंज,सूईथाकला,बदलापुर,खुटहन,महराजगंज,सुजानगंज,मुगरा बादशाहपुर,मछली शहर,केराकत,गंज-डोभी,मुफ्तीगंज,जलालपुर,करंजाकला, बकशा,सिकरारा,धर्मापुर,मड़ियाहूँ,बरसंठी,रामनगर,रामपुर,सिरकोनी ।
	३-गाजीपुर	३०४६३३७	३३७७	गाजीपुर,करण्डा,मरदह,बिरनों,मुहम्मदाबाद,भरावल कोल,बाराचबर,काशीमाबाद,जमानिया,रेवतीपुर,भदोरा,सैदपुर,देयहुली,सादात,मनिहारी,जखनिया
	४-चन्दौली	१६३९७७७	२५५०	चकिया,शाहगंज,नौगढ़,चन्दौली,बरहनी,सकलडीहा,थानापुर,चहनियाँ,नियमताबाद
इलाहाबाद	१-इलाहाबाद	४९४१५१०	५४२२	धनुपुर,हण्डिया,प्रतापपुर,सैदाबाद,बहादुरपुर,बहरिया,फूलपुर,होलागढ़,कौडिहार,मऊआइमा,सोराँव,चाका,करछना,कोंधियारा,जसरा,शंकनगढ़,कोराँव,मण्डा,मेजा,उरवा
	२-प्रतापगढ़	२७२७१५६	३७१७	सदर,मान्धाता,सण्डवाचन्द्रिका,रामपुर खास,लक्ष्मणपुर,सांगीपुर,पट्टी,आसपुर देवसरा,मंगरोरा,शिवगढ़,कण्डा,कालाकोकर,विहार,बाबागंज,रामपुर संग्रामगढ
मिर्जापुर	१-मिर्जापुर	२११४८५२	४५२२	नगर,कोन,छानये,मझवां ,पहाड़ी,लालगंज,हलिया,मडियान,नरायण्नपुर,जमालपुर,राजगंढ,सीखड़ ।
	२-सोनभद्र	१४६३४६८	६७८८	राबर्टसृगंज,धोरावल,चतरा,नगवां,चौपन,दुद्धी,म्योरपुर,वमनी ।
	३-संतरविदास	१३५२०५६	६५८८	ज्ञानपुर,डीह,औराई,भदोही,सुरियावाँ।
आजमगढ़	१-आजमगढ़	३९५०८०८	४२३४	रानी की सरायँ,तहबरपुर,मिर्जापुर,मोहम्दपुर,पल्हनी,जहानागंज,साठेयाँव,लालगंज, ठेकमा,तरैवा,मेहनगर,बिलरियागंज,अजमगढ़,महाराजगंज,हरैया,फूलपुर,पवई,मार्टीनगंज,कोयलसा,अतरोलिया,अीरौला,पल्हनी ।
	२-मऊ	१८४६२६४	१७१३	घोसी,बड़गांव,दोहरीघाट,फतेहपुर मण्डरॉव,मुहम्मदाबादगोहना,रानीपुर,परदहा,कोपागंज,रतनपुरा ।
	३-बलिया	२७५२४१२	२९८१	रसडा,नगरा,सीयर,चिलकहर,गड़वार,सोहावं,हनुमानगंज,दुबहड़,बेलहरी,बैरिया,मेरलीछपरा,बासडीह,बेरूवारबारी,रेवती,मनियर,पन्द्रह,नवानगर।
गोरखपुर	१-गोरखपुर	३७८४७२०	३३२५	पिपराइच,बांसगांव,गोला,पाली,पिपरौली,सहजनवा,खैराबाद,कौडीराम,गगहा,खजनी,भटहट,वेलघाट,सरदारनगर,बड़हजगंज,उरूवाँ,ब्रहापुर,ज.कोड़िया,चरगांव,कैम्पीयरगंज।
	२-महराजगंज	२१६७०४१	२९५१	महाराजगंज,सिसवां,परिवारा,बगमनगज,धानी,लक्ष्मीपुर,घुघली,नौतनवा,फरेन्दा,परतावल,निचलोल,भिठोरा ।
	३-देवरिया	२७३०३७६	२५३५	गौरीबाजार,देवरिया सदर,देसई देवरिया,पथरदेवा,बैतालपुर,रामपुर कारखाना,रूद्रपुर,बरंहज,भागपुर,भटनी,बनकटा,भाटपारानी,भुलुबनी,लार,सलेमपुर ।
	४-कुशीनगर	२८९१९३३	२९१०	कप्तानगंज,खड्ड़ा,नेबुआ नौरंगिया,मोतीचक,रामकोला,सुकरोली,हाटा,कसया,तमकुही,दुधई,पडरौना,फाजिलनगर,विशुनपुरा,सेवरही।
बस्ती	१-बस्ती	२०६८९२२	३०३५	बहादुरपुर,बनकटी,बस्ती,गोर,हरैया,कप्तानगंज,कुदरहा,परसरामपुर,रुधौली,साउघाट,सल्टौवा गोपालपुर,विक्रमजोत ।
	२-सिद्धार्थनगर	२०३८५९८	२७५०	बांसी,बढनी,मनवापुर,बडैपुर,डुमरियागंज,इटवा,जोगिया,खेसरह,खुनियाव,मिठवल,नौगढ़,उस्काबाजार,सोहरतगंढ़ ।
	३-संतकबीरनगर	१४२४५००	१४४१	बघोली,हैसरबाजार,खलीलाबाद,मेंहदावल,नाथ नगर,सेमिरियरवां,सोथा ।

सारणी संख्या -०.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश - प्रशासनिक विभाजन

मण्डल	जनपद	जनसंख्या २००१	क्षेत्रफल (वर्ग कि०)	विकास खण्ड
फैजाबाद	१-फैजाबाद	२०८७६१४	२७६२	मसौधा,पूराबाजार,सोहवल,मयाबाजार,बीकापुर,तारून,हैरिंगटनगंज,रानीगंज,मिल्कीपुर,रुदौली ।
	२-सुल्तानपुर	३१९०९२६	४४३६	अमेठी,मांहर,भेटुवा,संग्रामपुर,मुसाफिरखाना,जगदीपुर,बाजारशुक्ल,बल्दीराय,गौरीगंज,जामो,शाहगढ़,कूडेभार,जयसिंहपुर,कूडवार,दूबेपुर,भदैया, कादीपुर,दोस्तपुर,अखण्डनगर,जम्भुआ,पंतापपुरकमेचा,धनपतगंज।
	३-अम्बेडकरन	२०२५३७३	२३७०	अकबरपुर,कटेहरी,भीटी,जलालपुर,भियाँव,टाण्डा,बसखारी,रामनगर,जहाँगीरगंज ।
देवीपाटन	१-गोण्डा	२७६५७५४	४४२०	रूपईडीह,कटराबाजार,हलधरमऊ,झंझरी,पण्डरी कृपाल,इटियाथोक,मुजहना,बभनजोत,मनकापुर,छपिया,करनैलगंज,परसपुर,बेलसर,तरबगंज,वजीरगेज,नवाबगंज ।
	२-बहराइच	२३८४२३९	५७६९	चित्तौरा,कैसरगंज,जरवल,पुरवापुर,तजवापुर,महसी,हुजूरपुर,बलहा,शिवपुर,मिहीपुरवा,नवाबगंज,रिसिया ।
	३-बलरामपुर	१६८४५६७	२९२०	श्री दत्तगंज,उतरौला,गैण्डासबुर्जर्ग,रेहराबाजार,बलरामपुर,तुलसीपुर,गैसड़ी,पचपेड़वा,हरैयासत धरवा ।
	४-श्रावस्ती	११७५४२८	११२६	पयागपुर,विशेश्वरगंज,गिलौला,इकौना,सिरसिया,हरिहरपुरानी ,जमुनहा ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश ९९ पृष्ठ ७८०-७८३

२- जनगणना सेन्सस २००१

LOCATION OF EASTERN UTTAR PRADESH
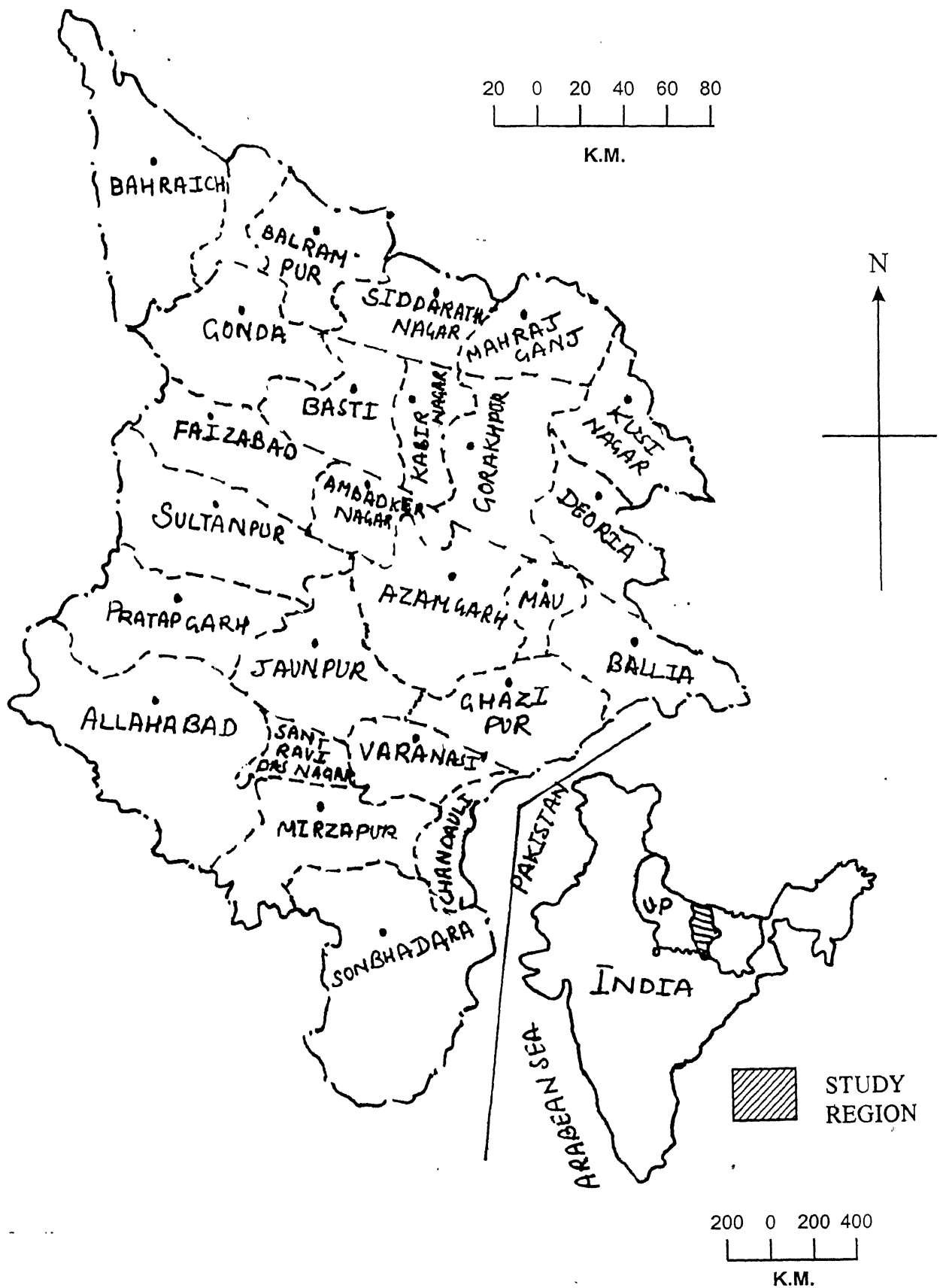
MAP No.- 0.01

EASTERN UTTAR PRADESH
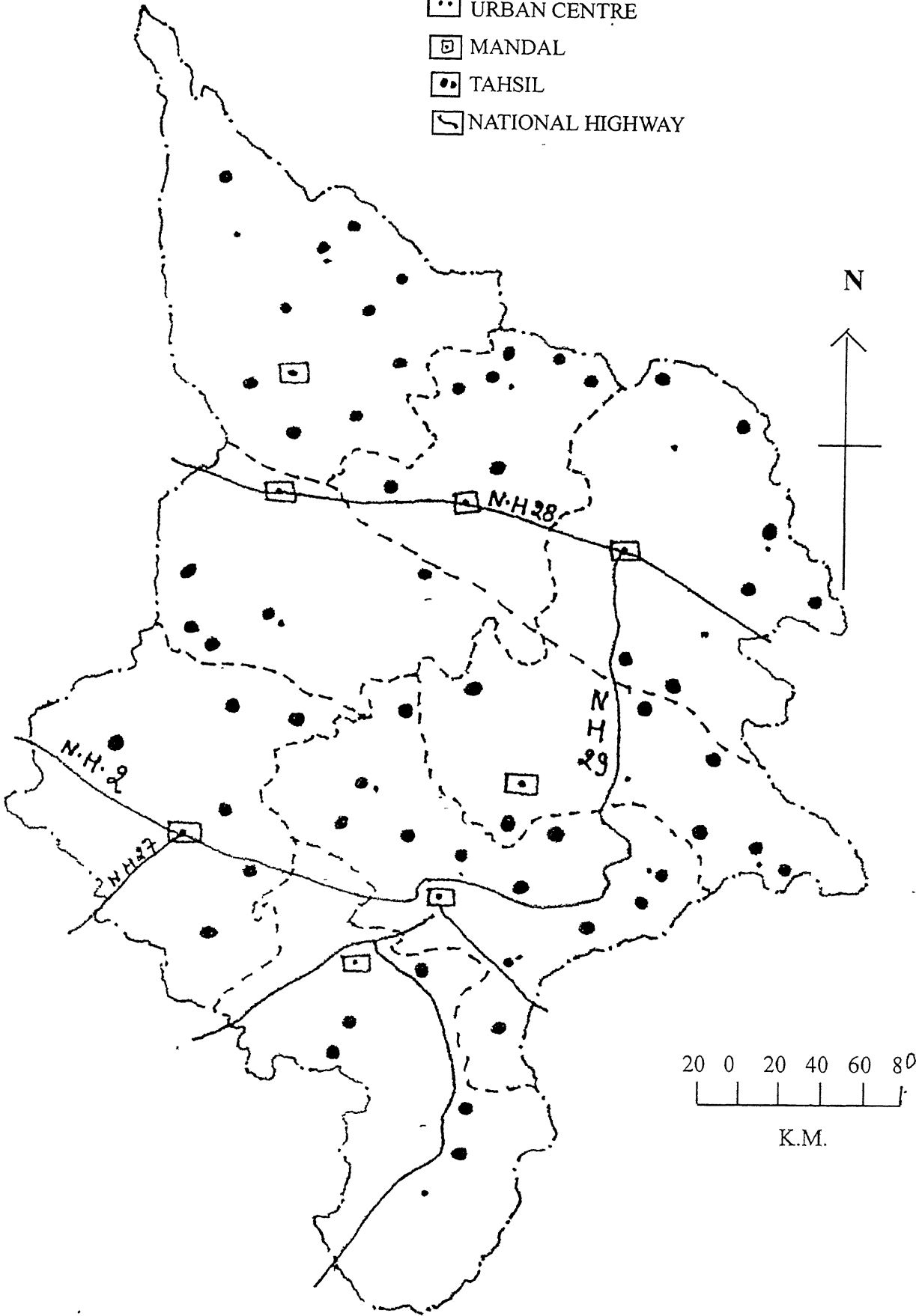
FigNo-0.02

भाग तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है जिसमें पर्याप्त नमी एवं दलदली क्षेत्र स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, फैजाबाद, अम्बेदकरनगर, सुलतानपुर, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में उचचावच १०० से १५० मीटर के बीच पाया जाता है। प्रदेश का उत्तरी, मध्य एवं पूर्वी हिस्सा पूर्ण रूपेण मैदानी हैं। राप्ती, घाघरा, गोमती, सई गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचाई हेतु जल प्रदान करती हैं।

अध्ययन क्षेत्र में तीन प्रमुख ऋतुयें-जाड़ा, गर्मी, बरसात पायी जाती हैं, (सिंह आर० ए०, १६७१, पृष्ठ १६८) मार्च महीने में तापमान २०°C से अधिक हो जाता हैं मई एवं जून का तापमान ४०°C के आसपास पहुँच जाता है। जब तापमान 40°C के ऊपर होता है तो गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। लू के कारण मौसम कष्टप्रद होने लगता है। जाड़े में तापमान 15°C के आसपास पाया जाता है। जनवरी मे तापमान कभी-कभी 10°C के नीचे भी चला जाता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा जून से सितम्बर के मध्य होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा १५० सेमी है (वर्मा, आर० बी०, १६७२ पृष्ठ ८२-१०४) तराई एवं भांवर मिट्टी सुदूर उत्तर तथा लालमिट्टी दक्षिणी भाग में मिलती है। सम्पूर्ण मध्यवर्ती भाग जलोढ़ मिट्टी से युक्त है। जिसमें कहीं क्षारीय मिट्टी भी पायी जाती है।

अध्ययन क्षेत्र का महत्त्व

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र का धार्मिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रहा है। इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद तथा श्रावस्ती आदि धार्मिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण जनपद हैं। इलाहाबाद जनपद में गंगा एवं यमुना नदियों का संगम है।

पौराणिक एवं प्रचलित विश्वास के अनुसार सरस्वती नदी की एक गुप्त धारा भी यहीं पर इन नदियों से मिलती है। जिससे हजारों वर्षों से ही इसे एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता रहा है। रामायण के अनुसार बनवास यात्रा के समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण और सीता जी ने सिगरौर (श्रृंगवेरपुर) के पास गंगा नदी को पार किया था यहाँ भिल्ल राजा गुह ने उनका स्वागत किया था। गंगा नदी के तट पर बसे निषाद राज्य की राजधानी श्रृंगवेरपुर में रुके थे और गंगा पार करके उन्होंने प्रयाग में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया था। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था। कहा जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणीसंगम के पास यज्ञ विशेष रूप से होते थे इसी से इसका नाम प्रयाग पड़ गया। यहीं पर ब्रह्मा जी ने जो कि देवों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं अश्वमेघ यज्ञ किया था तथा यहीं पर उन्होंने संखासुर से वेद प्राप्त किये थे तथा वेदों की पुनः प्राप्ति के उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया था। इन कई कारणों से प्रयाग को तीर्थों का राजा या तीर्थराज कहा जाता है। प्रत्येक माघ के महीने में यहाँ माघ का मेला लगता है तथा प्रत्येक बारहवें वर्ष कुम्भ का महोत्सव आयोजित होता है। जिसमें देश-विदेश से लाखों लोग एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग त्रिवेणी संगम में स्नान भी करते हैं। इसी प्रकार वाराणसी नगर का भी धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रहा है। इसे काशी भी कहते हैं। वरुणा और असी का इस नगरी के पास गंगा में संगम होने से इस नगर को वाराणसी कहते हैं। यहीं पर विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मन्दिर है जिसमें भगवान शंकर का प्रसिद्ध शिवलिंग है। फैजाबाद जनपद के अयोध्या नामक स्थान में मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि है। यही टीकमगढ़ या ओरछा की महारानी का बनवाया हुआ सुन्दर कनक भवन है। यहीं सीता रसोई बड़ा स्थान है। रत्न सिंहासन वह स्थान है जहाँ बनवास से लौटने पर रामचन्द्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल होने के नाते एवं सारनाथ

(वाराणसी के समीप) भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। सामरिक दृष्टिकोण से भी पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, महालेखाकार कार्यालय, शिक्षा निदेशालय तथा कई उच्च शिक्षण संस्थायें यहाँ स्थित हैं।

औद्योगिक भूगोल का अर्थ एवं महत्त्व-

भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य के निवास स्थल के रूप में किया जाता है। भूगोल को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, यथा (१) भौतिक भूगोल (२) मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक परिस्थितियों एवंमानव के कार्यकलापों केपारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। इसमें हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनिमय इत्यादि का क्षेत्रीय सन्दर्भ में अध्ययन करते हैं। विगत तीस वर्षों में आर्थिक भूगोल में विशेष विकास हुआ है। इसी कारण इसकी अनेक शाखायें विकसित हो गयी हैं, जो अपने आपमें विशिष्ट रूप धारण कर चुकी हैं। आर्थिक भूगोल की वह शाखा जो विनिर्माण कार्यों के क्षेत्रीय वितरण एवं विकास से सम्बन्धित है, औद्योगिक भूगोल कहलाती है।

औद्योगिक भूगोल के विकास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में यह आर्थिक भूगोल का ही अभिन्न अंग था।(लोढ़ा,आर०एम०, २०००. पृष्ठ २) परन्तु कालान्तर में यह पृथक रूप से विकसित हो गया। वैज्ञानिकों के शोधों के परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाओं में समग्र रूप से विश्वव्यापी विकास हुआ। जिससे आर्थिक भूगोल की अनेक शाखायें विकसित हो गयी। इनमें कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल विशेषरूप से

उल्लेखनीय है। औद्योगिक भूगोल में अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं तथा अध्ययन की नयी-नयी विधियाँ भी विकसित हुईं। इससे कालान्तर में औद्योगिक भूगोल अध्ययन की एक स्वतन्त्र शाखा बन गयी।(लोढ़ा,आर०एम०, २०००.पृष्ठ ५)

यूरोप में १७५० से १८५० के मध्य अभूतपूर्व तकनीकी विकास हुआ। इस अवधि को सामान्यतः औद्योगिक युग कहा जाता है। इसमें औद्योगिक प्रक्रिया, परिवहन क्षेत्र तथा विद्युत उपयोग में तीव्र गति से विकास हुआ। (कुमार प्रमीला, १९९७.पृष्ठ १७ - १८) फलस्वरूप औद्योगिक विकास द्रुत गति से होने लगा। यह क्रान्ति पहले इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुई परन्तु धीरे-धीरे संसार के अन्य भागों में फैलने लगी। उद्योगों को अब बड़े पैमाने पर चलाया जाने लगा। इसके साथ ही औद्योगिक भूगोल का क्षेत्र भी अधिक सुनिश्चित और विस्तृत होने लगा। इसे मात्रात्मक विधियों कातथा स्थानिक विश्लेषणों काभी प्रयोग किया जाने लगा। औद्योगिक भूगोल के प्रारम्भिक विकास में अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा परन्तु बाद में भूगोलवेत्ताओं ने भी इसके अध्ययन में सक्रिय योगदान दिया । इन दोनों प्रकार के अध्ययनों में सहसम्बन्ध भी स्थापित होनें लगा। फिर भी भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन की विधियाँ बहुत हद तक भिन्न हैं।

आधुनिक युग में औद्योगिक भूगोल में अवस्थिति वितरण एवं क्षेत्रीय सन्तुलन का विवेचन विशेष रूप से किया जा रहा है। क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित होने के कारण औद्योगिक भूगोल में शोध का विशेष स्थान है। जनकल्याण योजनायें भी क्षेत्रीय विकास से किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित होती हैं। अतः किसी भी योजनाबद्ध प्रक्रिया में भूगोल का विशेष महत्त्व है और प्रगतिशील देशों या क्षेत्रों के लिये औद्योगिक भूगोल का योगदान और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि औद्योगिक विकास के स्वरूप पर ध्यान दिया जाय तो ज्ञात होगा कि प्रारम्भ में उद्योगों के विकास में कोयले एवं लोहे का विशेष स्थान था। यही

कारण है कि प्रारम्भिक औद्योगिक क्षेत्र कोयला एवं लोहा प्राप्ति के क्षेत्रों के निकट ही विकसित हुये। कालान्तर में जल विद्युत एवं पेट्रोल के उपयोग के कारण अन्य स्थानों पर भी उद्योगों का विकास हुआ। आगे चलकर परमाणु उर्जा के विकास का उद्योगों के स्थानीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार उद्योगों की अवस्थिति एवं वितरण पर ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता रहा जो सामाजिक आर्थिक कारकों को भी प्रभावित करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों से प्रभावित होकर औद्योगिक स्थानीकरण के नये-नये सिद्धान्तों का विकास सम्भव हो सका है।

भारत में औद्योगिक भूगोल का विकास

भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की प्रचुर सुलभता है। देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उनके उपयोग द्वारा विकास की योजनायें बनायी गयी हैं। स्वतन्त्रता के पहले भारत का औद्योगिक विकास मन्द गति से हुआ था। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के युग में इसमें तीव्रता आने लगी है।(कुमार प्रमीला, १९९७. पृष्ठ ३३३ - ३४०)

अर्थशास्त्रियों ने औद्योगिक विकास की ओर तो पहले ही विशेष ध्यान दिया और इसके स्वरूप को समझने के लिये कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी किया। प्रारम्भ में भूगोल वेत्ताओं का ध्यान इस ओर कम था। उन्होंने इसके व्यावहारिक पक्षों का भी विशेष अध्ययन नहीं किया था। किन्तु गत चार दशाब्दों से भूगोलवेत्ताओं ने भी औद्योगिक भूगोल के माध्यम से उद्योगों की स्थानिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार वे औद्योगिक अवस्थिति, क्षेत्रीय वितरण तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के कारकों का भी अध्ययन करने लगे। हाल के वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के अध्ययन पर भी

बल दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे उद्योग कृषि पर आधारित हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। अनेक भूगोल वेत्ताओं ने इस सन्दर्भ में शोधकार्य भी प्रारम्भ कर दियाहै। इनमें से कुछ शोध कार्यों तथा विवरणात्मक अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

(क) स्थानिक पक्ष-

भारत में सर्वप्रथम उद्योगों के स्थानीकरण के सम्बन्ध में सी० वी० वी० आइंगर १९३० ने कोयम्बटूर में औद्योगिक विकास का अध्ययन किया। उन्होंने उद्योगों की स्थिति एवं प्रगति से सम्बन्धित अनेक तथ्यों का परीक्षण किया। इसी वर्ष आर० एच० राव ने कोयम्बटूर में औद्योगिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया। पी० एस० लोकनायक १९३२ ने अपने शोध में भारत के उद्योगों को स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन किया। उन्होंने सूती वस्त्र, जूट, चीनी, लौह इस्पात, कागज, सीमेण्ट एवं रसायन उद्योगों के स्थानीकरण के कारकों का विश्लेषण किया एवं देश में उद्योगों के असमान वितरण की आलोचना भी की। बी० एल० एस० प्रकाशराव १९४२ ने उद्योगों के स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के महत्त्व पर अपना शोध प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड बेबर ने उद्योगों की स्थापना में आर्थिक कारकों की अपेक्षा भौगोलिक कारकों को कम महत्त्व दिया था। ये उनके विचारों से सहमत नहीं थे। एच० थामस १९३४ ने भारत में औद्योगिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया तथा अनेक भूगोलवेत्ताओं का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया। एच० घोष १९४६ ने देश के संसाधनों के सन्तुलित विकास के लिये उद्योगों को कुछ ही चुने हुये केन्द्रों जैसे कलकत्ता, अहमदाबाद, बम्बई आदि में ही स्थापित करने के बजाय उनके विकेन्द्रीकरण एवं क्षेत्रीय विकास पर बल दिया। वी० एस० गांगूली १९४६ ने बंगाल बिहार औद्योगिक पेटी में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में

उत्खनन एवं खनिज सम्बन्धी उद्योगों के विकास के सन्दर्भ में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था।

एम० एस० कृष्णन १९५२ ने लोहा एवं इस्पात तथा खनिज आधारित अन्य उद्योगों के स्थानीकरण में भौगोलिक कारकों यथा- कच्चे माल शक्ति के स्रोतों के महत्त्व पर बल दिया। १९५६ में इनायत अहमद ने भारत में औद्योगिक मण्डलों के सीमांकन के मुख्य आधारों का अध्ययन किया तथा उनके वितरण प्रारूप तथा भविष्य की योजनाओं का भी विश्लेषण किया उन्होंने भारत को वृहत उद्योगों के वितरण के आधार पर १८ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में भारत में उद्योगों का विकास देश के प्रमुख क्षेत्रीय संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। बी०एन० सिन्हा १९५९ ने उड़ीसा में भारी उद्योगों की समस्याओं एवं उनके भविष्य की सम्भावनाओं पर अपना विचार व्यक्त किया था। उन्होंने उस प्रदेश में लौह इस्पात, फेरोमैग्नीज, एलुमिनियम, सीमेण्ट एवं रेफ्रीजरेटर उद्योगों के स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की भूमिका पर भी अपना अध्ययन प्रस्तुत किया।

इसी अवधि में जार्ज कूरियन ने भूगोलवेत्ताओं का ध्यान देश में उद्योगों के असमान वितरण की ओर आकर्षित किया। क्योंकि इससे प्रदेशों के मध्य आर्थिक असन्तुलन बढ़ रहा था। एम० आर० चौधरी १९६२ ने भारत में औद्योगिकीकरण के इतिहास एवं प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तराल में देश के उद्योगों के विकास के स्वरूप का अध्ययन किया था। उन्होंने उद्योगों के स्थानीकरण से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों का मूल्यांकन भी किया। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन सिद्धान्तों में भौगोलिक कारकों को, जो उद्योगों के स्थानीकरण को मूलरूप से प्रभावित करते हैं, उचित महत्त्व नहीं दिया गया है।

एम० एफ० करेन्नावार १९६० ने मैसूर के औद्योगिक केन्द्र भद्रावती में लौह, इस्पात, सीमेण्ट, कागज एवं कई अन्य उद्योगों के स्थानीकरण के कारकों का अध्ययन किया। सी० आर० पाठक १९६० ने दामोदर घाटी प्रदेश के औद्योगिक विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया था।

आर० के० दुर्रानी १९६५ ने राजस्थान में उद्योगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण किया था। उसके अनुसार उस राज्य में रसायन खाद, सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योगों की स्थापना के लिये अनेक सुविधायें उपलब्ध हैं, किन्तु वहाँ शक्ति के संसाधनों की कमी होने के कारण इन उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सका है। इसी वर्ष आर० एन० तिवारी ने अपने लेख में इस बात पर बल दिया कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास का मूल्यांकन करते समय राज्य की सघन जनसंख्या एवं पर्याप्त संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए।

सी० बी० तिवारी १९६९ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों की अनेक समस्याओं का अध्ययन किया एवं इस उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिये चीनी मिलों की पुर्नस्थापना का सुझाव भी दिया था। इसी अवधि में एम० आर० चौधरी ने पश्चिमी बंगाल में उद्योगों के वितरण प्रारूप की जटिलताओं का अध्ययन किया और भविष्य में उद्योगें के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

गत तीन दशाब्दों में कई अन्य भूगोलवेत्ताओं एवं अर्थशास्त्रियों ने भी भारत में उद्योगों के स्थानिक पक्ष का विश्लेषण किया है। उन्होंने वेबर, लाश, पैलेण्डर, हूवर एवं ग्रीनहर आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सैद्धान्तिक मॉडलों के भौगोलिक अनुप्रयोगों का भी विश्लेषण किया तथा भारत के सन्दर्भ में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिये उनमें उचित संशोध

नों का सुझाव भी दिया।

औद्योगिक विकास-

अनेक भूगोलवेत्ताओं ने भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में उद्योगों के विकास का अध्ययन किया है। फूलरानी सेनगुप्ता एवं ओ० पी० भार¯द्वाज ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सेनगुप्ता १९५० ने पश्चिमी बंगाल के हुगली प्रदेश में औद्योगिक प्रगति पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उनके अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि हुगली प्रदेश मे जूट उद्योग की प्रमुखता होने से अन्य उद्योगों को अपनाने की प्रवृत्ति मन्द हो रही थी।

ओ० पी० भारद्वाज ने स्वतन्त्रता के बाद से पंजाब में उद्योगों के विकास का अवलोकन किया और उन्होंने वहाँ के औद्योगिक विकास का श्रेय उत्साही एवं साहसी पंजाबवासियों को दिया।

महामाया मुकर्जी ने बिहार में औद्योगिक विकास का विवेचन किया और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि राज्य में उद्योगों का विकास मुख्यतः संसाधनों पर आधारित है।

संसाधनों के अनुसार कृषि, खनिज, वन तथा अन्य श्रोत्रों पर विकसित उद्योगों का अध्ययन पृथक-पृथक रूप से भी किय गया है। इन क्षेत्रों में किये गये अध्ययनों का विवरण निम्नवत है-

१. खनिज आधारित उद्योग

(अ) लौह इस्पात उद्योग -

भारत में स्थापित भारी उद्योगों में लौह-इस्पात उद्योगों का

सर्वप्रमुख स्थान रहा है। कल्याण सुन्दरम १६३५ ने सर्वप्रथम देश में लौह इस्पात उद्योग के विकास में सहायक भौगोलिक कारणों का मूल्यांकन किया था। उन्होंने इस उद्योग के लिये भारत में आवश्यक कच्चे माल के रूप में लौह भण्डारों का आंकलन भी किया था और निष्कर्ष निकाला था कि निकट भविष्य में इस देश में लौह इस्पात उद्योग की तीव्र प्रगति होगी। बी०एन० गांगुली १६४६ ने भारत में जमशेदपुर, हीरापुर एव कुल्टी में स्थापित वृहत इस्पात केन्द्रों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के प्रस्तावों का भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया और इस्पात संयन्त्र के स्थानीकरण के लिये उड़ीसा के राउरकेला की स्थिति को भी उपयुक्त बताया। एम० आर० चौधरी १६६४ ने भारत में लौह-इस्पात उद्योगों के विकास का विशेष अध्ययन किया तथा उसके स्थानीकरण के कारकों का विवेचन किया। इन्द्रपाल ने उत्तरी भारत में लौह इस्पात का उत्पादन न करने वाले राज्यों में जैसे- उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में, लघु इस्पात संयन्त्र स्थापित करने की सम्भावना का विवेचन किया। उनके अनुसार इनके लघु इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिये आयरन स्क्रैप (जो अधिक मात्रा में समीपवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध भी हो जाता है)का प्रयोग किया जा सकता है।

(ब) अलौह धात्विक उद्योग-

अलौह धात्विक उद्योगों में मुख्यतः ताबां एवं अल्युमिनियम उद्योगों की ओर भूगोलवेत्ताओं का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ था। एम० ए० माजिद १६६५ ने बिहार में ताबां उद्योग का सर्वेक्षण किया था। पी० दयाल १६६८ ने अल्युमिनियम उद्योग के स्थानीकरण में मुख्य कारकों के महत्त्व का आंकलन किया था। उनके अनुसार इस देश में अल्युमिनियम संयन्त्रों की वर्तमान उत्पाद क्षमता के उपयोग एवं

प्रगति में मुख्य बाधा सस्ती विद्युत शक्ति की अनुपलब्धता है।

(स) अन्य उद्योग-

वी० एल० एस० राव १६४१ ने जलयान निर्माण उद्योग के स्थानीकरण में भौगोलिक कारकों की भूमिका का मूल्यांकन किया। उन्होंने सामान्य औद्योगिक प्रगति का भी विवेचन किया और पाया कि इस प्रगति में मुख्य बाधक तत्त्व शक्ति की कमी है। आई० एन० चावला १६५५ ने रासायनिक खादों की मुख्य इकाइयों जैसे- सिन्द्री, नांगल आदि के स्थानिक वितरण तथा उनके उत्पादन एवं भविष्य की योजनाओं का अध्य¯यन किया तथा उनकी अवस्थिति के कारकों का विश्लेषण किया। आर० एन० तिवारी १६६२ ने उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग के स्थानीकरण में सहायक भौगोलिक कारकों के महत्त्व का विश्लेषण किया। इसी अवधि में बी० बनर्जी एवं एस० चक्रवर्ती ने पश्चिमी बंगाल में चीनी मिट्टी की उत्पत्ति, उसके स्थानिक वितरण तथा आर्थिक पक्ष पर अपना विचार व्यक्त किया था। उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता था कि पश्चिमी बंगाल में यह उद्योग अर्द्ध विकसित अवस्था में है। मांग की अपेक्षा उत्पादन कम होने के कारण भारत के अन्य भागों में चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात करने में कई कठिनाइयाँ थी। इस कारण प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के विकास की अनेक सम्भावनायें थीं।

एस० एम० आजम १६३७ ने बिहार में सीमेण्ट उद्योग का भौगोलिक विवेचन प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ नई इकाइयों की स्थापना एवं वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

२. कृषि आधारित उद्योग-

भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान है। यहाँ कृषि

पर आधारित उद्योगों का विशेष महत्व रहा है। भारत में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जूट, चीनी एवं चाय से सम्बन्धित उद्योग, जो कृषि पर ही आधारित हैं, विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग तो इस देश में अधिक प्राचीन है और यह यहाँ अधिक विकसित भी हुआ है।

भारत के सूतीवस्त्र उद्योग के स्थानिक वितरण एवं प्रगति के सन्दर्भ में पी० एस० लोकनाथन १६३६ ने विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग के कुछ बड़े केन्द्रों में (जैसे बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि में) इसके अत्यधिक स्थानीकरण के कारणों की समीक्षा की। इसी सन्दर्भ में नारायण स्वामी ने कोयम्बटूर में सूतीवस्त्र उद्योग का विवेचन किया। कानन चक्रवर्ती ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थिति का विश्लेषण किया। उनके अनुसार भारत में इस उद्योग की अनेक समस्यायें थीं। उनके विचार से सूतीवस्त्र उद्योग के सन्तुलित विकास के लिये लघु औद्योगिक इकाइयों का विकास अधिक संगत होगा। अरुण गुप्ता ने वाराणसी में रेशम उद्योग की स्थापना एवं प्रगति का विश्लेषण किया। आर० पी० सिंह एवं अनिल कुमार ने भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास का अध्ययन किया।

आर० एन० तिवारी १६६२ ने चीनी मिल की स्थिति के चुनाव में अनेक आर्थिक कारकों, जैसे वाहन, व्यय, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से दूरी एवं परिवहन के साधनों के प्रभावों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि चीनी मिल की स्थिति के चुनाव को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की समीपता ही सबसे अधिक प्रभावित करती है। पी० दयाल १६६८ ने भारत में चीनी उद्योग के विकास की प्रवृत्तियों का विवेचन किया। इसी वर्ष एस० ए० रशीद ने बिहार में चीनी उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया। इसी वर्ष सी० बी० तिवारी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की समस्याओं का विवेचन किया। उनके अनुसार इस

प्रदेश में इस उद्योग के सन्तुलन के लिये चीनी मिलों का विस्थापन आवश्यक है। एम० एन० खाँ ने भारत में चाय उद्योग के विकास के अनेक पक्षों का तथा भारत के विदेशी व्यापार में इसके योगदान का विश्लेषण किया।

३. वनों पर आधारित उद्योग-

एस० ए० मजीद १६६० ने बिहार के लौह उद्योगों के विकास का अध्ययन किया। के० आर० दीक्षित १६६३ ने भारत में कागज उद्योग की प्रगति का विवेचन किया एवं इस उद्योग के स्थानीकरण में कच्चे माल एवं जल आपूर्ति के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन उद्योगों के विकास की प्रवृत्तियों एवं उसके स्थानिक वितरण के प्रारूपों का भी विवेचन किया। उन्होंने वनों के संरक्षण पर बल दिया ताकि विभिन्न उद्योगों के लिये वनों से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सके। अपने अध्ययन में इन्होंने कागज उद्योग की अनेक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला।

४. लघु एवं कुटीर उद्योग-

भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्त्व है। देश के अधिकांश भागों में कुटीर उद्योग चल रहे हैं। इनमें स्थानीय कच्चा माल की खपत की जाती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का कई ग्रामीण एवं कई उपनगरीय क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में कृषक अपने खाली समय में इन उद्योगों मे कार्य करके धन का उपार्जन करते हैं।

आर० एच० राव १६३० ने कोयम्बटूर जनपद में खादी हैण्डलूम, रेशम के कीड़े पालनें, रेशमी वस्त्र बुननें, कालीन बनानें एवं कुछ धातु उद्योगों से सम्बन्धित अनेक गृह उद्योगों का विशेष सर्वेक्षण किया। इसी प्रकार आर० एस० राव ने मालाबार प्रदेश में कुटीर

उद्योगों के विकास की समस्याओं का अध्ययन किया। उनके मतानुसार मालाबार प्रदेश में कुटीर उद्योगों की प्रगति में पूंजी की कमी तथा असंगठित बाजार मुख्य समस्यायें हैं। रंगप्पा ने मैसूर राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का परीक्षण किया और उस राज्य में इन उद्योगों के अधिक विकास की सम्भावनायें भी व्यक्त कीं। एस० ए० मजीद ने बिहार के पालामऊ, धनबाद , हजारीबाग, रांची से संयाल परगना जनपदों में विकसितटसर उद्योग के विकास का सर्वेक्षण किया और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला।

बी० एन० सिन्हा १९६० ने उड़ीसा में लघु उद्योगों के विकास का अध्ययन किया। इसमें कांच, चीनी, चावल मिल, दाल मिल, चीनी मिट्टी, जूट एवं चमड़ा उद्योग सम्मिलित थे। उन्होंने इसमें लगे कुल श्रमिकों की संख्या का, उद्योगों के वर्तमान स्थिति का एवं उनकी विकास की सम्भावनाओं का भी विश्लेषण किया।

एम० जी० भसीन ने भारत में आटोमोबाइल्स उद्योग के विकास के कई पक्षों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार इस उद्योग के लिये कुशल श्रमिको की आवश्यकता होती है। अतः उद्योग कुशल श्रमिकों के प्राप्ति स्थलों के समीप ही स्थापित किये जाते हैं। इसलिये इस उद्योग का देश के नगरीय क्षेत्रों में ही अधिक विकास हुआ है।

आर० एन० सिंह १९७७ ने भारत में औद्योगिक स्थानों की संकल्पना एवं उनके सामाजिक-आर्थिक महत्त्व का विश्लेषण किया। उन्होंने औद्योगिक अस्थानों से सम्बन्धित विचारधारा के उद्भव एवं इनके लक्ष्यों की भी व्याख्या की। आर० एन० सिंह १९७८ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक आस्थानों के सम्बन्ध में अपना शोध प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने इस क्षेत्र के अनेक औद्योगिक स्थानों का परीक्षण किया एवं निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कारकों की विफलता के कारण अधिकांश औद्योगिक

स्थान निष्क्रिय हो गये हैं। उन्होंने इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये अनेक सुझाव भी दिये। महेन्द्र बहादुर सिंह १६८२ ने पूर्वोत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्रतिरूप एवं उत्पादन पर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया और उद्योगों के विकास की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया।(रजा , एम०१६७२-१६६८ बासाक १६६४)

ऊपर दिये गये विवरणों से स्पष्ट हैकि कई भूगोलवेत्ताओं ने भारत में औद्योगिक भूगोल के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने देश में औद्योगिक विकास के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया है। वर्तमान समय में भूगोलवेत्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय विषमता दूर करने हेतु औद्योगिकीकरण करने सम्पूर्ण क्षेत्र की विकास योजना तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास जैसे कार्यक्रम एवं उनकी समस्याओं पर शोधकार्य किये जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भी इसी दिशा में एक लघु प्रयास है।

शोध प्रबन्ध की परिकल्पनायें-

हर एक अनुसन्धान कार्य किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। समस्यायें का अनुमानित हल परिकल्पनाओं के माध्यमसे प्रस्तुत किया जाता है। जिन्हें परीक्षण के उपरान्त सत्य या असत्य सिद्ध किया जाता है। सत्य पाये जाने पर उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। इस शोध प्रबन्ध में भी समस्याओं का अनुमानित उत्तर एवं उनका प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि प्रमाण कितना सार्थक है।प्रस्तुत शोध की मुख्य परिकल्पनायें निम्नवत हैं।

१. पूर्वी उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है, यद्यपि इसमें कई सुदृढ़ एवं

विकसित नगर भी स्थित हैं। अनेक वृहद कस्बे जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं इस क्षेत्र की परिधि में आते हैं। इन विकसित एवं सम्पन्न नगरों का प्रभाव निकटवर्ती ग्रामीण अंचलों पर पड़ा है। दूरस्थ गाँवो पर इसका प्रभाव सीमित है लेकिन औद्योगिक इकाइयाँ इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करती हैं।

२. अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के अन्तर्गत आटा उद्योग, चावल उद्योग, दाल मिल, चीनी मिल उद्योग प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे कृषि आधारित उद्योग भी विकसित हुये हैं। इनउद्योगों के विकास की सम्भावनायें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं। किन्तु गन्ना प्रधान क्षेत्रों में इसके विपरीत स्थिति पायी जाती है। यहाँ ग्रामीण आंचलों में वृहद पैमाने के चीनी मिल उद्योग विकसित हो जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत इन उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ही हुआ है। जबकि अन्य उद्योग नगरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों नगरों में अधिक विकसित हुये हैं।

३. अध्ययन क्षेत्र में उद्योगों के विकास में परिवहन एवं विद्युतीकरण का विशेष महत्त्व है। जहाँ कहीं भी ये दोनों सुविधायें पायी जाती हैं। वहाँ उद्योगों का विकास आसान हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र में रेल एवं पक्की सड़कों की सीमित सुविधायें प्राप्त हैं। विद्युत सुविधा भी उपलब्ध है किन्तु पर्याप्त नहीं है। इस सन्दर्भ में उद्योगों का विकास बहुत कम हो पाया है जो बहुत हद तक (चीनी एवं दाल मिलों को छोड़कर) क्षेत्र की माँग के ऊपर निर्भर हैं।

४. अध्ययन क्षेत्र में उद्योगों के विकास में प्राविधिक शिक्षा या प्रशिक्षण का भी योगदान रहा है। अध्ययन क्षेत्र में ये सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। इसका यहाँ के कृषि उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है।

५. कृषि में फसलों के उत्पादन पर ही कृषि आधारित उद्योग निर्भर हैं। ये फसलें इन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती हैं। यदि ऐसा न हो तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास सम्भव न हो सकेगा। क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख फसलों का विकास कम हुआ है।

६. अध्ययन क्षेत्र में उद्योगों के विकास में आर्थिक साधनों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। सभी प्रकार के और सभी स्तर के उद्योग इससे प्रभावित होते हैं। जहाँ ऐसे साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहाँ उद्योगों के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जहाँ इनकी उपलब्धता कम है या नहीं है वहाँ उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक साधनों की उपलब्धता कम पायी जाती है अतः कृषि आधारित उद्योगों के विकास को ग्रामीण क्षेत्रों मे कम प्रोत्साहन मिल पाया है। नगरों के समीपवर्ती भागों में ये साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है अतः यहाँ उद्योगों के विकास पर प्रेरणात्मक प्रभाव पड़ा है।

७. परिवहन के साधनों तथा मशीनों की मरम्मत के लिये अभियान्त्रिक सेवा कार्यों की भी आवश्यकता उद्योगों के विकास में होती है। बड़े से लेकर छोटे नगरों तक तथा कुछ बड़े गाँवों में भी इन्जीनियरिंग सेवा के छोटे-छोटे उद्योग विकसित हो जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी इसका प्रभाव देखा जाता है।

८. अध्ययन क्षेत्र के कुछ भागों में तम्बाकू उद्योग, सिल्क उद्योग, इत्र बनाने का उद्योग, मुरब्बा उद्योग तथा दरी एवं टाट बोरे बनाने के छोटे-छोटे उद्योग विकसित हुये हैं जो कि कृषि पर ही आधारित है। इनके लिये समुचित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षणों की नितान्त कमी है अतः इस प्रकार के उद्योगों का विकास बहुत ही सीमित क्षेत्रों में हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र में इन परिकल्पनाओं पर विचार किया जायेगा तथा विश्लेषणों से पता लगाया जायेगा कि इसमें कौन सी परिकल्पनायें सही है और कौन सी सही नहीं है। उनके ऐसा होने के कारणों का भी विवेचन किया जायेगा।

अध्ययन की कार्यविधि- प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। उनके आधार पर मानचित्र एवं आरेख बनाये गये हैं जिनसे अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न तथ्यों का उचित बोध हो सके। उद्योगों की प्रवृत्तियों को जानने के लिये कहीं कहीं कई वर्षों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। आवश्यकतानुसार सारणी बनाकर भी उन आंकड़ों को दर्शाया गया है जिससे तथ्यों का सरलता से बोध हो सके। सांख्यिकीय दुरूहता को भरसक दूर रखने का प्रयास किया गया है क्योंकि इससे सामान्य रूप से समझने में कठिनाई हो सकती है।

विश्लेषण का स्वरूप-

विश्लेषण हेतु वर्णानात्मक, तथ्यात्मक तथा गवेषणात्मक विधियों को अपनाया गया है। विश्लेषण की सार्थकता के लिये सर्वेक्षण द्वारा तथ्यों का निरूपण करने का प्रयास किया गया है। मानचित्र एवं आरेखों की सहायता से विश्लेषणों को अधिक सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं उसकी सार्थकता-

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास से ही कृषिगत अर्थव्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। केवल कृषि के माध्यम से कृषकों की अर्थदशा को सुधारना बहुत कठिन है। इसी प्रकरण को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का विश्लेषण किया गया है जो कि एक सघन कृषि क्षेत्र होने के साथ-साथ सघन

जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है, एवं अनेक कृषि उत्पाद एवं कच्चे माल के उत्पादन से मुक्त है। इस अध्ययन का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों का विकास से सम्बन्धित है। भारत जैसे देश के लिये ऐसे अध्ययनों की विशेष सार्थकता है और आगे भी बनी रहेगी।

शोध प्रबन्ध का अनुक्रम-

विवेचना की सरलता के लिये शोध प्रबन्ध को कई सोपानों में (अध्यायों में) विभक्त किया गया है। इन सोपानों से पहले सामान्य सन्दर्भ हेतु प्रस्तावना के माध्यम से कई तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है जो शोध क्षेत्र का परिचय देते हैं। इसमें औद्योगिक भूगोल की रूपरेखा को, उसके महत्त्व का तथा भारत में उसके अध्ययन का विवरण दिया गया है।

प्रथम सोपान में अध्ययन क्षेत्र की भौतिक पृष्ठभूमि को समझाया गया है। द्वितीय सोपान में इस क्षेत्र की आर्थिक पृष्ठभूमि का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय सोपान में उक्त क्षेत्र के मानव संसाधनों का विवरण दिया गया है। चतुर्थ सोपान में औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धान्तों का विवेचन दिया गया है तथा पंचम सोपान में जनपदवार तथा प्रदेशवार औद्योगिक विकास (कृषि आधारित) की समीक्षा दी गयी है। सप्तम सोपान में प्रतिदर्श औद्योगिक इकाईयों का विश्लेषण दिया गया है। अष्टम सोपान में इस क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों का विश्लेषण दिया गया है। अष्टम सोपान में इस क्षेत्र के औद्योगिक नियोजनं का विश्लेषण दिया गया है। अष्टम सोपान में इस क्षेत्र के औद्योगिक नियोजन पर प्रकाश डाला गया है। तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है। किन उद्योगों के लिये किन स्थानों पर विकास की सुविधायें हैं इस तथ्य का भी परीक्षण

किया गया है। अन्त में अध्ययन का मूल तत्त्व दर्शाया गया है। उद्योगों की समस्याओं का विवेचन किया गया है तथा उन्हें सुलझाने के लिये कुछ समाधानों को प्रस्तुत किया गया है। यह शोध प्रबन्ध का अपना योगदान हो सकता है।

आंकड़ों के स्रोत एवं उनकी उपलब्धता-

प्रस्तुत आंकड़े उद्योगों से सम्बन्धित कार्यालयों से तथा उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं विवरणों से प्राप्त किये गये हैं। उद्योग सम्बन्धी आंकड़े जिला उद्योग केन्द्रों तथा उद्योग निदेशालय से प्राप्त किये गये हैं। जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े पृथक-पृथक रूप से प्राप्त किये गये हैं। कुछ अप्रकाशित आंकड़े भी सम्बद्ध कार्यालयों से समय-समय पर प्राप्त किये जाते रहे हैं। जिला उद्योग केन्द्रों से निम्नलिखित प्रकाशित सन्दर्भों का भी अध्ययन किया गया है।

१. औद्योगिक प्रेरणा वर्ष, १९९८-१९९९

२. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रगति समीक्षा १९९८-१९९९

परिकल्पनायें एवं उनका परीक्षण-

इस प्रस्तावना में ८ परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में उनका परीक्षण द्वारा युक्ति संगत पाये जाने पर ही उन्हें संकल्पनाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है।

शोध-प्रबन्ध के अन्तिम सोपान में इन परिकल्पनाओं की सार्थकता पर विचार किया गया है। कुछ को सही पाया गया है तथा कुछ को आंशिक रूप से सही पाया गया है। तथा कुछ को सार्थक से परे पाया गया है। इस सम्बन्ध का विशेष विवरण अन्तिम सोपान में देखा जा सकता है।

इस प्रकार इस शोध प्रबन्ध में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

■

References

1. Alexander, J. W.,(1950) Geography of Manufactur ing What is it ? Journal of Geography- 49.
2. Abler, R. J. S. and P. Gould,(1971) Spatial organisation The Geographer's view of the world.Englewood clifts, N.)
3. Basak. J. K.(1964) Industrial Estate in India- The journal of Industries and Trade, P. ed.
4. Chauha n,V. S. and Gautam(1995) : An Advanced Geography of India (15ed) Rastogi Publications, Meerut.
5. Hunker, H. L. (1964), Zimmerman's Introduction to world Resources.Harper and Row U. N. Publication.
6. Kumar, P.(1977); Udyogic Bhogol : M. P.Hindigranth Acadimy,Bhopal.
7. Lodha, R. M.(2000) : Udyogic Bhogol (IInd Edition) Jaipur.
8. Mamoria, C. India (15 ed)(1995),Sahitya Bhawan Publication, Agra.

9. Raza. M., : A trend Report in Geography 1972 to 1998. ICSSR popular Prakshan, Bombay.

10. Singh, M. B.(1997) : Regional development planning (IInd Edition), Varanasi.

11. Singh, M. B. (1983) : Industrial development pat -terns and potentials in eastern U.P. lotus publications, Varanasi.

12. Singh, R.L.(1971) ; India :A Regional Geography N.G.S.T., Varanasi.

13. Singh K. N., Singh J.(1996) Economic Geography. Gyanodaya Publications, Gorakhapur.

14. Tiwari, R. N. (1965) Location and development of Large Scale Industries in Uttar Pradesh. Unpublished D. Lit., Agra University, Agra, Vol.-I.

15. UTTAR PRADESH 99' सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16. Zimmermann. W. E. (1951) World Resources and Industries. Harper and Row. U. N. Publication.

प्रथम सोपान

भौतिक पृष्ठभूमि

भौतिक पृष्ठभूमि

सामान्य परिचय-

पूर्वी उत्तर प्रदेश २३° ४५ उत्तरी अक्षांश से २८° ३० मिनट उत्तरी अक्षांश तथा ८०° ४५ मिनट पूर्वी देशान्तर से ८४° ३० मिनट पूर्वी देशान्तर के मध्य ८४३२० वर्ग किमी० क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस प्रदेश की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लम्बाई ४०० किमी० तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई २४० किमी० है। इसके पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड राज्य, दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य तथा उत्तरी भाग में नेपाल देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। पश्चिम में इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोण्डा तथा बहराईच जनपद इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। २००१ की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या ६०८७२ मिलियन है। इसमें इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन तथा फैजाबाद कमिश्नरियों के २६ जनपद सम्मिलित हैं। (उत्तर प्रदेश ९६ पृष्ठ ७७८)

इस प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल भारत के उत्तरी विशाल मैदान का ही एक भाग है, जो सामान्यतः समतल है और जिसका ढ़ाल नदियों की ओर उन्मुख है तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को है। अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश इसी विशाल मैदान का ही एक अंग है। दक्षिण का कुछ क्षेत्र पठारी है। सामान्यता पूरा मैदान सागर तल से १०० मी० नीचे स्थित है। कुछ लुप्त पहाड़ियां दक्षिण में सोनभद्र एवं मिर्जापुर में स्थित हैं। प्रदेश का उत्तरी मध्य एवं पूर्वी हिस्सा पूर्णरूपेण मैदानी है। राप्ती, घाघरा, गोमती, सई, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश को जल प्रदान करती हैं। (सिंह, एम० वी०

१९९७.पृष्ठ ३७७)

यह प्रदेश जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ओल्ड़हम ने इस प्रदेश के जलोढ़ की गहराई का आँकलन ४०००-६००० मी० के बीच किया था। ग्लेनी ने इसकी अधिकतम मोटाई १३०० मी० बताई है। नवीनतम अध्ययनों के आधार पर हरिनारायण (१९९५) ने जलोढ़ की मोटाई १३०० से १४०० मी० के बीच अंकित किया है।

इस प्रदेश में नदियों की घाटियों से सटे हुये खादर मैदान पाये जाते हैं जो सामान्यतः भूमि से नीचे हैं और जो वर्षा काल में नदियों की बाढ़ से भर जाते हैं। इन मैदानों में प्रतिवर्ष नई मिट्टी की तह फैल जाती है। जिनमें नमी की मात्रा अधिक पायी जाती है। खादर मैदानों में रबी की कुछ फसलें बिना सिंचाई के भी उगाई जाती हैं। खादर मैदान से ऊपर प्रदेश का भाग बांगर मैदान के रूप में पाया जाता है जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव मिलता है। इस मैदान से वर्षा ऋतु में भूक्षरण होता रहता है। जिसमें कभी-कभी नीचे का लवण अंश उभरकर ऊपर आ जाता है। जो कालान्तर में रेह बनकर कुछ क्षेत्रों को अनुपजाऊ बना देता है। बांगर मैदानों से वर्षाकाल से पूर्व या उसके बाद नमी की कमी रहती है। अतः फसलों के उत्पादन हेतु उस अवधि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बांगर मैदानों का ढाल नदियों की ओर पाया जाता है।(सिह.आर० एल० १९७१)

धरातलीय संरचना-

शोध का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्वी भाग है जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उत्तरी बड़े मैदान का

अभिन्न अंग है। इसलिए इस बड़े मैदान का उद्भव ही उक्त प्रदेश के उद्भव का परिचायक है। दोनों की भूगर्भिक संरचना एक ही प्रकार से निर्मित हुयी है। अतः उनमें समरूपता प्रतीत होती है। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय क्षेत्र एवं दक्षिण पठार के बीच महागर्त के भर जाने से बना है। विद्वानों के अनुसार यह महागर्त अति प्राचीन काल में टेथीज महासमुद्र का भाग था जिसके उत्तर में लारेशिया के अन्तर्गत यूरेशिया (अरब और भारत के प्रायद्वीपों को छोड़कर) तथा उत्तरी अमेरिका के भूखण्ड सम्मिलित थे। जबकि गोण्डवाना लैण्ड के अन्तर्गत अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी भारत प्रायद्वीप, अफ्रीका, द० अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं अन्टार्कटिका के भूखण्ड सम्मिलित थे। प्रारम्भ में लारेशिया उत्तरी ध्रुव के निकट तथा गोड़वाना लैण्ड मेडागास्कर के निकट प्रतिस्थापित था। यह स्थितियां लगभग ढाई अरब वर्ष पूर्व थीं। जब पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि थी। किन्तु इसी महाकल्प के मध्य इन महाखण्डों का विघटन होने लगा था। जो आगे चलकर कार्बोनीफरस काल में बडे पैमाने पर सम्पन्न हो गया और क्रिटैशियस काल में इन महाभूखण्डों के भिन्न-भिन्न भाग एक दूसरे से पृथक हो गये। इस विघटन ने विस्थापना की गतियां भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रभावित थी।

टेथीज महासमुद्र वर्तमान में मेडीटेरिरियन समुद्र का ही विस्तृत स्वरूप रहा था। जो पश्चिम में जिब्राल्टर से लेकर पूर्व में जावा द्वीप तक फैला हुआ था। इसके अन्तर्गत फारस की खाड़ी के क्षेत्र तथा भारत के उत्तरी वृहत मैदान के क्षेत्र सम्मिलित थे। जिस समुद्र से भारत का उत्तरी वृहत मैदान उद्भूत हुआ था वह भूसन्नति के रूप में बद गया था। जिसमें जलोढ़ जमाव होने लगा था और जो प्रबल वलनशक्तियों के दबाव के कारण अपने उत्तरी परिक्षेत्र में हिमालय जैसी महान पर्वत श्रृंखला को जन्म देने में सफल हुआ था।

कालान्तर में टेथीज तल उत्थान और जमाव की निरन्तर क्रियाओं से वृहत मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया था। टेथीज समुद्र का जब संकीर्ण भाग रह गया था तो वह बड़ी नदी के रूप में अवशेष टेथीज रह गया जिसे भूगर्भशास्त्री "इण्डोब्रह्मा" नदी की संज्ञा देते हैं। कुछ विद्वान इसे शिवालिक नदी भी कहते हैं और उनके अनुसार शिवालिक पर्वत श्रेण्यिां इसी नदी के किनारे प्राकृतिक तटबंध के रूप में उद्भूत हुयी थीं। इन श्रेणियों में कच्चे अवसादों की मात्रा अधिक पायी जाती है। इनमें कठोर चट्टानों का अभाव सा है।

इस वृहत मैदान के भूगर्भिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जलोढ़ जमाव की मोटाई हिमालय तलहटी क्षेत्र में अधिक है तथा उससे हटकर दक्षिण पठार की ओर कम होती जाती हैं। मिट्टी की तहें परतों के रूप में विकसित हुयी थीं। जो कालान्तर में सन्नीभूत होकर मोटी हो गयीं और एक ठोस परत का आभास देने लगीं। इन परतों के बीच-बीच में कहीं कंकड़ों के ढेर मिलते हैं जो जमाव प्रक्रिया में भॉवर जैसी स्थित का बोध कराते हैं।

अध्ययन क्षेत्र मे ऊँची भूमि जहाँ बाढ़ का पानी नही पहुँच पाता बांगर भूमि कहलाती हैं तथा निचला भाग जहाँ नदी की बाढ़ पहुँच जाती है, खादर भूमि कहलाती हैं। दोनों मैदानों का मिलन क्रमशः हुआ है इसकी सीमा निर्धारण कठिन कार्य हैं। वास्तव ये मिले जुले रूप मे विकसित हुये हैं। बांगर मैदानों का बडा भाग भी पहले खादर मैंदानों के रूप में ही उद्भूत हुआ होगा और कालान्तर में अधिक जमाव एवं उत्थापन से प्लीस्टोसीन काल में बांगर मैदान में परिणत हो गया। बांगर मैदान में कहीं-कहीं बालू के ढेर पाये जाते हैं जिन्हे 'भूड़' कहते हैं। ये प्राचीन काल में जल के बहाव के साथ बालू

के जमाव के रूप में विकसित हो गये थे और कालान्तर में मिट्टी के जमाव से ढक गये थे जो बाद में अपरदन के कारण उभर कर ऊपर आ गये।

जलोढ़ मिट्टी की परतें दबते जाने से और अधिक मोटाई के नीचे पड़ जाने से ऊपर की परतों से कुछ कठोर हो गयी हैं। फिर भी अधिक ठोस बनकर कठोर चट्टानों का रूप धारण नहीं कर सकी हैं। इन नींचे की तहों में हल्का कालान्तरण तो हुआ है किन्तु इनमें कायान्तरित चट्टानें नहीं बन सकी हैं। यही कारण है कि इन चट्टानों में खनिजों का अभाव है।

अध्ययन क्षेत्र के मैदान का ढाल भी भूगर्भिक प्रक्रिया पर निर्भर है। सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है फिर भी बांगर मैदानों की ओर से खादर मैदानों की ओर ढालों का पाया जाना स्वाभाविक है।

भौतिक स्वरूप-

अध्ययन क्षेत्र भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला है। इसका ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। पश्चिम भाग में समुद्र तल से इसकी ऊचांई १५० मी० के आस-पास है जबकि पूर्व की ओर इसकी ऊँचाई क्रमशः कम होती गयी है। अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भू-भाग सामान्यतः समतल है केवल दक्षिण में मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद के कुछ स्थानों पर कैमूर एवं सोनपार की पहाडियां लगभग ६०० मी० तक ऊँची है तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील में भी कुछ पहाडियां स्थित है। जिसकी ऊँचाई सामान्यतः ४५० मी० के आसपास है। अध्ययन क्षेत्र के

बहराइच, गोण्ड़ा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया जनपदों का कुछ भाग तराई क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। गंगा, राप्ती, गोमती, सई, घाघरा आदि अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं।

अध्ययन क्षेत्र की उत्पत्ति-

भूगर्भिक उद्भव के सन्दर्भ में स्पष्ट किया गया है कि यह भारत के उत्तरी विशाल मैदान का ही अभिन्न अंग है। इस मैदानी भाग का निर्माण नदियों द्वारा लाये गये अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। वृहत् मैदान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक भूगर्भ वेत्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। एडवर्ड स्वेस के अनुसार इस मैदान की उत्पत्ति एक विशाल गर्त के भर जाने से हुयी है जो दक्षिण पठार एवं हिमालय क्षेत्र के मध्य था। आज भी हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण से यह मैदान भरता जा रहा है। पहले भी यह प्रक्रिया जारी थी। सिड़नी बुर्राड के मतानुसार इस मैदान की उत्पत्ति एक भ्रंशघाटी के भर जाने से हुयी है।(सिंह,सविन्द्र १९८६·पृष्ठ १६३-१६४) टलेनफोर्ड के अनुसार अति प्राचीन काल में एक सागर असम क्षेत्र से इरावती नदी तथा उसके पूर्व तक और दूसरा सागर ईरान और बलूचिस्तान से पूर्व लद्दाख क्षेत्र तक विस्तृत था। पहले ये दोनों सागर मिले हुये रहे होगें। कालान्तर में हिमालय श्रेणी के ऊपर उठने से दक्षिण में स्थित सागर धीरे-धीरे संकीर्ण होकर समाप्त प्राय होने लगे और इस प्रकार उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुयी। कुछ आधुनिक भूगर्भशास्त्रियों के मतानुसार इस वृहत मैदान के स्थान पर पहले साधारण गहराई का एक छिछला समुद्र था जो बाद में नदियों द्वारा लायी गयी काँप मिट्टी के जमाव से भर गया यही कालान्तर में वर्तमान उत्तरी मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। भारत के इस वृहत मैदान की उत्पत्ति में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र

एवं इनकी सहायक नदियों का विशेष योगदान रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलोढ़ के जमाव में गंगा, घाघरा, राप्ती, गोमती आदि नदियों का प्रमुख योगदान रहा है।

उच्चावच-

अध्ययन क्षेत्र सामान्य रूप से समतल मैदानी भाग है जिनका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके दक्षिणी भाग में मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली जनपद में कुछ पहाड़ियाँ पायी जाती हैं। जो विन्ध्यन श्रेणी का ही प्रसरण मानी जाती हैं जिनकी ऊँचाई १३५ से २७० मी० के आसपास है। (सिंह,एम० वी० १९८३ पृष्ट १२-१३)अतः इस उच्चावचीय विशेषता के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। १- उत्तरी मैदानी भाग २- दक्षिण उच्चभूमि (देखें रेखाचित्र १.०१)। यहाँ इस प्रदेश का भूगर्भ प्रत्यक्ष रूप से इसके विभाजन में मद्द करता और जलोढ़ मैदानीं भाग तथा विन्ध्यन उच्चभूमि बनाता है। पहला विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा जीवन यापन वाला क्षेत्र है एवं अधिक जनघनत्व वाला है। जबकि दूसरा विन्ध्यन उच्च भूमि पहले की तुलना में बहुत कम कृषि क्षेत्र एवं जनसंख्या वाला है। परन्तु इसमें उर्जा एवं खनिज संसाधनों की अधिकता है। मिर्जापुर सोनभद्र के कुछ स्थानों पर जो कि विन्ध्ययन उच्च भूमि के अन्तर्गत आता है कैमूर और सोनपाल की पहाड़ियाँ फैली हैं जो १८० से २७६ मी० तक ऊँची हैं। इसी प्रकार चन्दौली जिले के अन्तर्गत भी कुछ छोटी पहाडियां देखी जाती हैं। इस क्षेत्र का ढाल सामान्यतः उत्तरपूर्व की ओर है।

अपवाह प्रणाली-

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ी नदियों का प्रवाह देखा जाता है।

सारणी संख्या -१.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग प्रारुप

क्र०स०	जनपद	कुल क्षेत्रफल (हक्टयर मे)	वन क्षेत्र	कृषि अयोग्य क्षेत्र	परती भूमि	अन्य भूमि	कृषि भूमि
१	फैजाबाद	२७६२००	७१७	२६६४	६८२०	५६३४२	१५२०५
२	गोण्डा	४४२०००	४०२५०	४५५०	३०६२०	३६०६०	२०४०६
३	सुल्तानपुर	४४०१८०	१६४६	१५३५७	४११८१	५०००१	२२०२३
४	प्रतापगढ़	३६४४२३	५६८	६५३८	४६८४१	४२१०६	२०२१३
५	इलाहाबाद	७२७८६७	१६५२५	२६८७६	४८३१५	८२०६५	५०४०२
६	वाराणसी	१५७८००	४२१६५	५२७०	८५७०	३२७५०	१६७२४
७	महराजगंज	३०००८६	५४८४१	२८३६	४२०६	२७६७६	२६२८६
८	सोनभद्र	७०११४१	३७४२१६	२२६७५	२५२०६	४२६४४	५०१०३
९	बलिया	२६६२६५	-	१३३३१	१६५४६	३७८१२	२०२१४
१०	गाजीपुर	३३३२०६	-	५८७४	११०८०	३७६७३	२६२४३
११	मऊ	१७१५७८	५६०	२४२२	१०१६६	२२०७२	३८३०२
१२	आजमगढ़	४२३६८५	१०१	७३७१	२८३७६	५१०८३	४०२०१
१३	बहराइच	५७६६००	५२७११	३५६०	६६२०	३७४३२	३५३०६
१४	मिर्जापुर	४६६०३७	११३७६८	१५७७२	२५२६५	४१८८३	२५२६३
१५	जौनपुर	३६६७१३	५१	७३५७	२४५७०	४३६७१	२४२००
१६	बस्ती	३०३८००	२०३०	४०१५	५०३२	३०७५२	२६३०३
१७	गोरखपुर	३३८४३६	५६७६	४४११	५५०३	४०७६१	२०२१३
१८	देवरिया	२५२३६०	२६०	५०३७	४२५०	२६६१३	४५३००
१९	संतरविदास नगर	६५८८००	३६३६५	४४६०	८१५०	२६८१०	२०१०१
२०	बलरामपुर	२६२०००	३०६५५०	३७७२	२०७२०	३५०८०	१८४००
२१	श्रावस्ती	१२१३१४	४८७३१	२६७८	८६१०	३१६६०	१३१००
२२	संतकबीरनगर	१४४१००	१४३८	३२१६	४२७६	२४७३२	२०३०५
२३	चन्दौली	२३३६३४	-	११२१	१३१३	२०१४४	२२१६६
२४	कुशीनगर	२८६५०५	१०४२	६००२	३०४६	४६८२६	२८२०३
२५	सिद्धार्थनगर	३२३६६६	५०११	२५५२	६४१६	३१५७७	२२१०६
२६	अम्बेडकरनगर	२३७०००	५१७	३३८०	१५६०२	५२४२	२०४०१

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकड़े १९९८-९९

MAP No.- 1.01
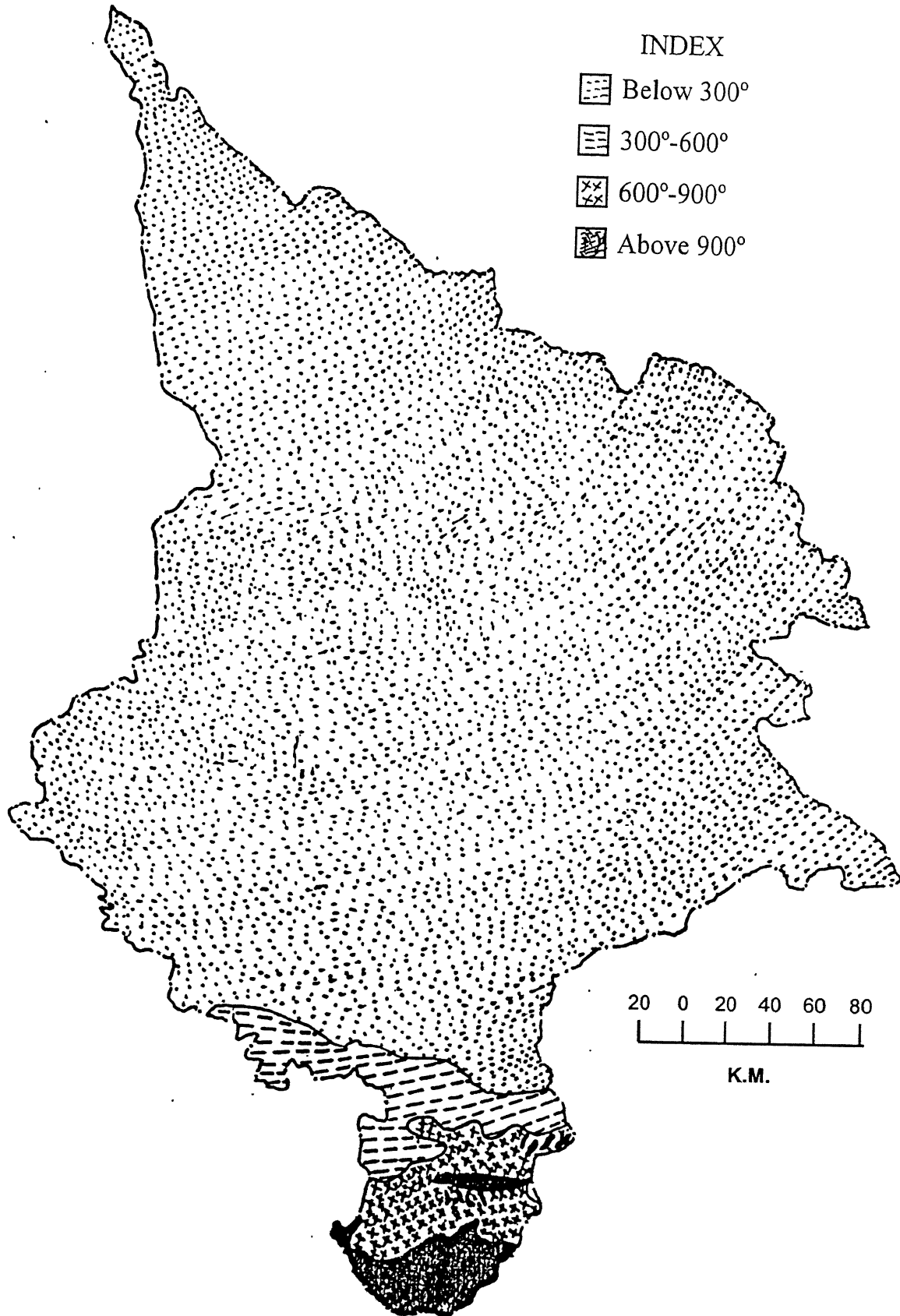
इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को तीन प्रमुख अपवाह तंत्रों में रखा जा सकता है (देखें चित्र १.०२)-

१. घाघरा अपवाह तंत्र

२. गंगा अपवाह तंत्र

३. सोन अपवाह तंत्र

इसके अलावा गण्डक, राप्ती, कुआनों, सई, गोमती आदि अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ क्षेत्र के कृषि एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

१. घाघरा अपवाह तंत्र-

यह नदी तिब्बत के पठार से निकल कर नेपाल में बहती हुयी बहराइच जनपद से अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करती हैं (सिंह,आर० एल० १९७१ पृष्ट १९४)तथा गोण्डा, आजमगढ़, फैजाबाद, गाजीपुर एवं बलिया जिलों में प्रवाहित होती हुयी छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती हैं। यह नदी गोण्डा एवं फैजाबाद तथा उत्तर में बस्ती और गोरखपुर तथा दक्षिण में आजमगढ़ एवं बलिया जनपदों की सीमा भी बनाती है।(वर्मा आर० बी० १९७२ पृष्ट १२६-१२७) टाण्डा (अम्बेडकरनगर) और बरहज (गोरखपुर) घाघरा के प्रधान व्यापारिक केन्द्र हैं। घाघरा नदी को फैजाबाद जनपद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। राप्ती एवं कुआनो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।

(i) राप्ती नदी- नेपाल में लघु हिमालय की श्रेणीयों से निकलकर अध्यन क्षेत्र के बहराइच जनपद में प्रवेश करती हैं तथा बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर जनपदों

KUWANA R.
RAPTI R.
GANDAK R.
GHAGHARA R.
TONS R.
GOMTI R.
VARUNA R.
GANGA R.
SON R.
REHAND R.
N
20 0 20 40 60 80
K.M.
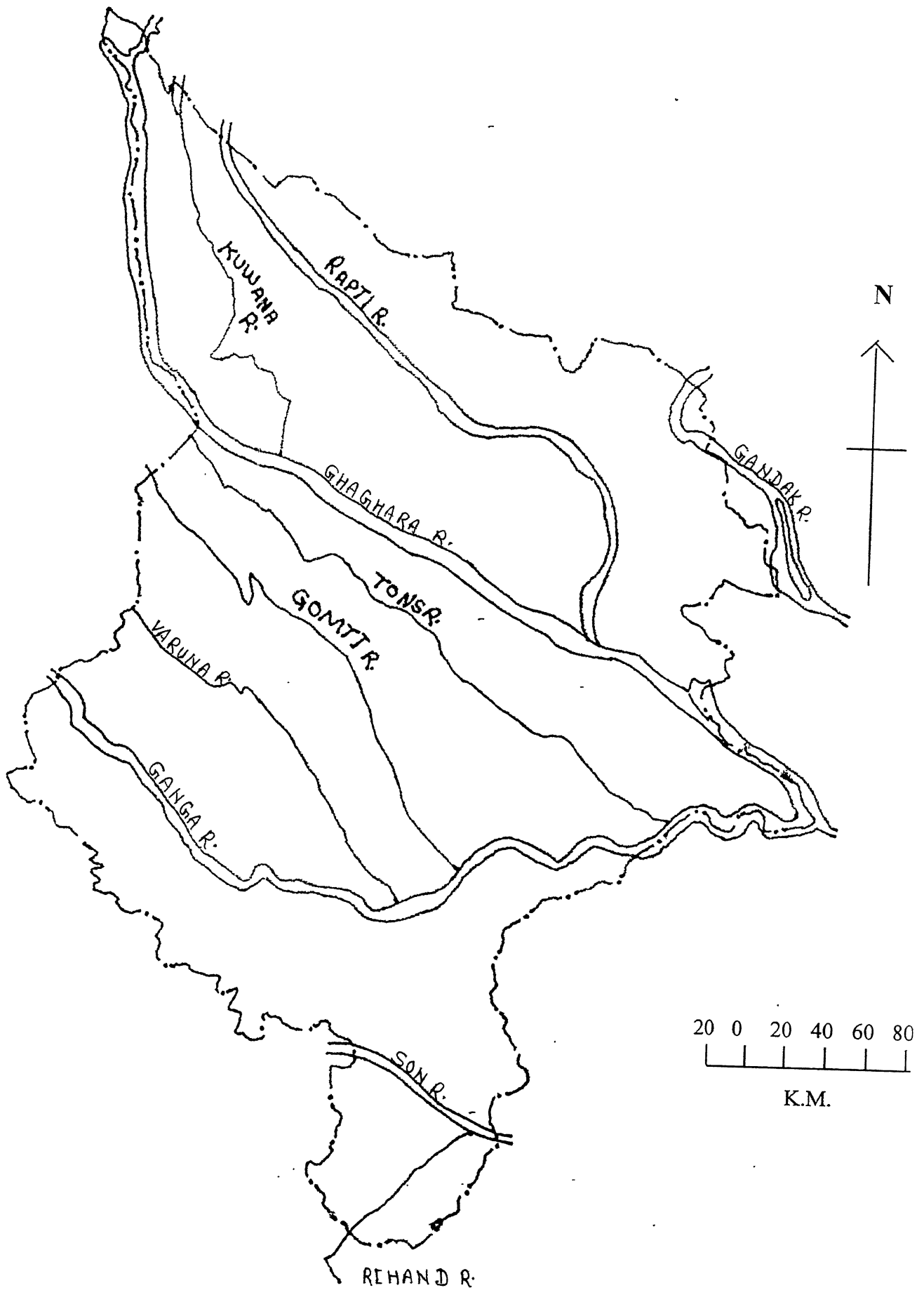
में प्रवाहित होती हुयी बरहज के पास घाघरा नदी से मिल जाती है।

(ii) गंण्डक नदी- इसको नारायणी भी कहते हैं। यह नेपाल राज्य में मुख्य हिमालय क्षेत्र के ७६०० मी० की ऊँचाई से निकलती है। अध्ययन क्षेत्र के गोरखपुर जनपद में प्रवेश करती है। जहाँ ३२ किमी० तक गोरखपुर जनपद के बीच में सीमा बनाने के बाद यह बिहार प्रान्त में प्रवेश कर जाती है।

२. गंगा अपवाह तंत्र-

गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ये दोनों नदियाँ देव प्रयाग के पास मिलती हैं।(वर्मा, आर० बी० १६७२ पृष्ठ १२३-१२४) भागीरथी गंगोत्री (टेहरी राज्य) से निकलती है और अलकनंदा विष्णुप्रयाग के पास विष्णु गंगा और धौला गंगा के मिलने से बनती है। यह नदी अध्ययन क्षेत्र के इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर एवं बलिया जनपदों में प्रवाहित होती है। जब यह बलिया जनपद के बाहर शाहाबाद या आरा जनपदमें प्रवेश करती है तो बिहार राज्य में बहती हैं। अध्ययन क्षेत्र में इस नदी के किनारे पवित्र तीर्थ स्थल एवं बड़े नगर स्थित हैं। इलाहाबाद जनपद में प्रयाग जहाँ गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है प्रमुख तीर्थ राज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। टोंस, गोमती एवं वरूणा उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।

(i) गोमती नदी-

यह नदी उत्तर प्रदेश की तराई में पीलीभीत जनपद के दलदली क्षेत्र से निकलती है। जो समुद्र तल से २०० मी० ऊँचाई पर स्थित है। अध

ययन क्षेत्र के सुल्तानपुर, जौनपुर तथा गाजीपुर जनपद में प्रवाहित होती हुयी गाजीपुर जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है।

(ii) टोंस नदी-

इसको तमसा नदी के नाम से जाना जाता है इसका उद्‌गम फैजाबाद जनपद मे होता है। जहाँ से यह आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जनपदों से गुजरती हुयी बलिया जनपद में गंगा से मिल जाती है।

(iii) सई नदी- यह नदी उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद के दक्षिण पश्चिम भाग में एक छोटी जल धारा के रूप में जन्म लेती है जो अध्ययन क्षेत्र के प्रतापगढ़ जनपद में प्रवाहित होती है तथा आगे निकलकर जौनपुर जनपद में गोमती नदी में मिल जाती है।

३. सोन अपवाह तंत्र-

महानदी अमर कंटक पहाड़ियों से निकलती है एवं अध्ययन क्षेत्र सोनभद्र जनपद से होकर गुजरती है। यहाँ रिहन्द तथा कनहर नदियाँ आकर इससे मिलती हैं।

प्राकृतिक वनस्पति

अध्ययन क्षेत्र का धरातल नदियों द्वारा निक्षेपण युक्त उपजाऊ मिट्टी से बना होने के कारण अतीत काल में सघन वनों से आवृत था। इन वनों में मानसूनी पर्णपाती वृक्षों की प्रधानता थी। कृषि क्षेत्रों के विस्तार के कारण वन क्षेत्र निरन्तर सिकुड़ते गये

एवं आज तो मूल वनस्पति लगभग समाप्त हो चुकी है। वृक्षों के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध है। वह मानव द्वारा रोपित बाग एवं बगीचा के रूप में है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम २०% भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। इस अध्ययन क्षेत्र में वनों, चारागाहों, वृक्षों एवं उद्यानों के अन्तर्गत प्रयुक्त कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यहाँ की स्थिति पर्याप्त दयनीय है। मुख्य कारण यह है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाने के पश्चात ग्राम समाज की भूमि उन लोगों में बांट दी गयी है। जिनके पास भूमि नहीं थी। उन लोगों ने वनों को काट कर खेती योग्य भूमि बना लिया तथा विभिन्न क्षेत्रों में भूमि को दूसरे विभागों द्वारा विभिन्न विकास कार्यो में भी उपयोग कर लिया गया जिससे यहाँ वनों की भूमि कम हो गयी। इस क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से पूर्व ही बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो चुकी थी। निजी वनों एवं बागों के वृक्षों की बड़ी संख्या में कटाई हो जानेके फलस्वरूप न केवल जनसाधारण की अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए लकड़ी व ईंधन का तथा पशुओं के लिए चारा, घास, फल-फूल का आभाव हो गया है। बल्कि वनों पर आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकतानुसार आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। वनों की अनियंत्रित कटाई से यहाँ का पर्यावरण भी असंतुलित हो गया हैं इस लिए यहां भून्क्षरण की गति तीव्र हो गयी है।

प्राकृतिक वनस्पति के रूप में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत-पीपल, बरगद, इमली, महुवा, नीम, बबूल, खजूर, ढ़ाख आदि वृक्ष तथा तराई में बेर, मूंज, घास एवं खेती वाली दूब एवं मोथा पायी जाती हैं। (सिंह,आर० एल० १९७१ पृष्ट २०४) आम, अमरूद,

आंवला आदि प्रमुख फलदार वृक्ष हैं।

उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र के बंजर, अनुपजाऊ व कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत नहरों, सड़कों व रेल मार्गो के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण पर बल दिया जा रहा है। पहले किये गये वृक्षारोपण में पाकड़, शीशम, आम, नीम, जामुन, अर्जुन, पीपल, आदि हैं किन्तु नये पथ वृक्षारोपण में यूकेलिप्टिस, शीशम आदि के पेड़ मुख्य रूप से लगाये जा रहे हैं। अध्ययन के क्षेत्र में बहुउद्देशीय वनरोपण के लिए भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा पोषित सामाजिक वानिकी परियोजना तथा उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चलायी जा रही है। (उत्तर प्रदेश ९९ पृष्ठ ६८० -६८२)

जीव जन्तु-

विगत दशकों में वन क्षेत्रों के निरन्तर सिकुड़ते जाने और बिना सोचे समक्षे जंगली पशुओं के शिकार किये जाने के कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवरों की संख्या अत्यंत घट गयी है। अध्ययन क्षेत्र में इन जानवरों में अब मुख्यतः नीलगाय, जंगली सुअर, सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि प्रकार के जानवर और मोर, तीतर, बटेर आदि पक्षियों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं। रेंगने वाले जन्तुओं में साँप प्रमुख है।

अध्ययन क्षेत्र में किसानों द्वारा पालतु पशुओं की रखने की परम्परा दीर्घ काल से चली आ रही है। इन पशुओं में भैंस, गाय, भेंड, बकरी आदि प्रमुख हैं। जो किसानों के लिए विशेष उपयोगी है। कृषि कार्य के साथ सहकार्य के रूप में किसानों ने इन

पशुओं का सदा से पालन किया है। अब कृषि में यन्त्रीकरण बढ़ने से इनका महत्व कम हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र में जीव जन्तुओं की घटती हुयी संख्या के नाते वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं तथा राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहारों की स्थापना प्रारम्भ की गयी है। वन्य जीव परिरक्षण की प्रमुख योजनाएं प्रोजेक्ट टाइगर, घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना, कछुआ पुनर्वास योजना, गैंड़ा पुनर्वास योजना, लुप्तप्राय वन्य जीव परियोजना, बायोस्फियर रिजर्व आदि हैं। (उत्तर प्रदेश ६६' पृष्ठ ६८६- ६८५)

मिट्टी

मिट्टी प्राकृतिक वातावरण का एक प्रमुख अंग है। मानव उपयोग की दृष्टि से सभी देशों की मिट्टियाँ वहाँ धरातलीय प्रस्तर के मूल्यवान अंश है। प्राकृतिक संसाधनों में इनका विशेष महत्व है। (वाडिया १६६६ पृष्ठ ५१७)

मिट्टी पृथ्वी के मृतप्राय धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। जल में रहने वाले जीवों को छोड़कर पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के लिए मिट्टी का आधार महत्वपूर्ण है। जो उनके जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मिट्टी से ही मानव की तीन आधारभूत आवश्यकताओं (वस्त्र, भोजन एवं गृह) की पूर्ति होती है।

कृषि का समस्त उत्पादन कार्य मिट्टी पर आधारित है। पशुपालन एवं वन व्यवसाय भी अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही आधारित है। उद्योगों में उपर्युक्त होने वाले

कच्चे मालों का ८०% भाग किसी न किसी रूप में मिट्टी की ही देन है। विश्व के लगभग ७०% मानव कृषि व्यवसाय में ही लगे हुये हैं। अतः वे भी मिट्टी पर ही आश्रित है।

अध्ययन क्षेत्र में पायी जाने वाली मिट्टियों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

१. कांप मिट्टी

२. मिश्रित लाल व काली मिट्टी

१. कांप मिट्टी-

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश भाग में कांप या जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पायी जाती है। (सिह आर० एल० १६७१ पृष्ठ २०३-२०४) यह दो प्रकार की होती है -

१. पुरानी कांप (बांगर)

२. नवीन कांप (खादर)

१. पुरानी कांप या बांगर मिट्टी-

नदियों के बाढ़ प्रभाव से दूर स्थित बेसिनों की मिट्टी को पुरातन कांप मिट्टी कहा जाता है। इसे बांगर नाम से भी जाना जाता है। इन भागों में नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। जिससे वर्षाकाल के पूर्व एवं बाद में फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।(सिंह आर० एल० १६७१ पृष्ठ २०४)

२. नवीन कांप या खादर मिट्टी-

यह मिट्टी नदियों के तलहटी के भागों में पायी जाती है। यहां बाढ़ के समय नदियों द्वारा मिट्टी की एक नवीन पतली पर्त बिछा दी जाती है जिससे इस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इस क्षेत्र में सिंचाई के बिना भी फसलों को उगाया जाता है।

स्थानीय भाषा में पुरानी कांप को 'भाट' और बंजर तथा नवीन कांप को 'ढूह' कहते हैं। भाट मिट्टी चिकनी बलुई होती है तथा चूना अपेक्षाकृत कम होता है। बंजर मिटट्री चिकनी और बलुई दोनो प्रकार की है इस चूना अपेक्षाकृत कम होता है । अध्ययन क्षेत्र के लगभग ६०% भाग में यह मिट्टी पायी जाती है। नवीन कांप या खादर मिट्टी में जैविक तत्व न्यून मात्रा में मिलते हैं तथा इसमें कैलशियम की मात्रा भी बहुत कम होती है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होती है साथ ही साथ मृदा ऊर्वराशक्ति भी प्रायः कम होती है। (ममोरिया २००१)

इस मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा एवं जलधारण क्षमता बढ़ाने के लिए हरी खाद, गोबर की खाद एवं कम्पोस्ट खाद का उपयोग करना लाभप्रद होता है। जहाँ कहीं इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अंश होता है वहाँ यह मिट्टी उपजाऊ होती है और उसमें जलधारण की शक्ति भी बढ़ जाती है। इस मिट्टी में खरीफ फसलों में बाजरा तथा इसी कोटि की अन्य फसलें उगायी जाती हैं। रबी की फसलों में समुचित सिंचाई करके गेहूँ, जौ, अरहर आदि की फसले और जायद फसलों में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, लौकी, टमाटर

कद्दू आदि आसानी से उगायी जा सकती है।

२. मिश्रित लाल व काली मिट्टी-

इस प्रकार की मिट्टी अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित पठारों पर पायी जाती है। इसके अन्तर्गत मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद आते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद जनपद की करछना तथा मेजा तहसील तथा वाराणसी जनपद की चकिया तहसील के क्षेत्र में भी यह मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी को सामान्यतः 'मार' और काबर कहते हैं। (वर्मा आर० वी० १९७२ पृष्ठ १०७-१०८) यह चिपचिपी तथा कैलकेरिया युक्त और उर्वर होती है। भीग जाने पर चिपचिपी और फैलने वाली होती है तथा सूखने पर सिकुड़ती है और गर्मियों में इसमें दरारे पड़ जाती हैं। लाल मिट्टी पठार के ऊपरी भाग में तथा ऊपरी ढलानों पर पायी जाती है। यह दो प्रकार की होती है 'परवा और राकर'। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है। जबकि राकर अपक्षारित मिट्टी होती है। अध्ययन क्षेत्र में पायी जाने वाली मिट्टियों को चित्र १.०३ में दर्शाया गया है।

3774-10
6921.
UNIVERSITY LIBRARY ALLAHABAD
1 MAR 2004
T-696
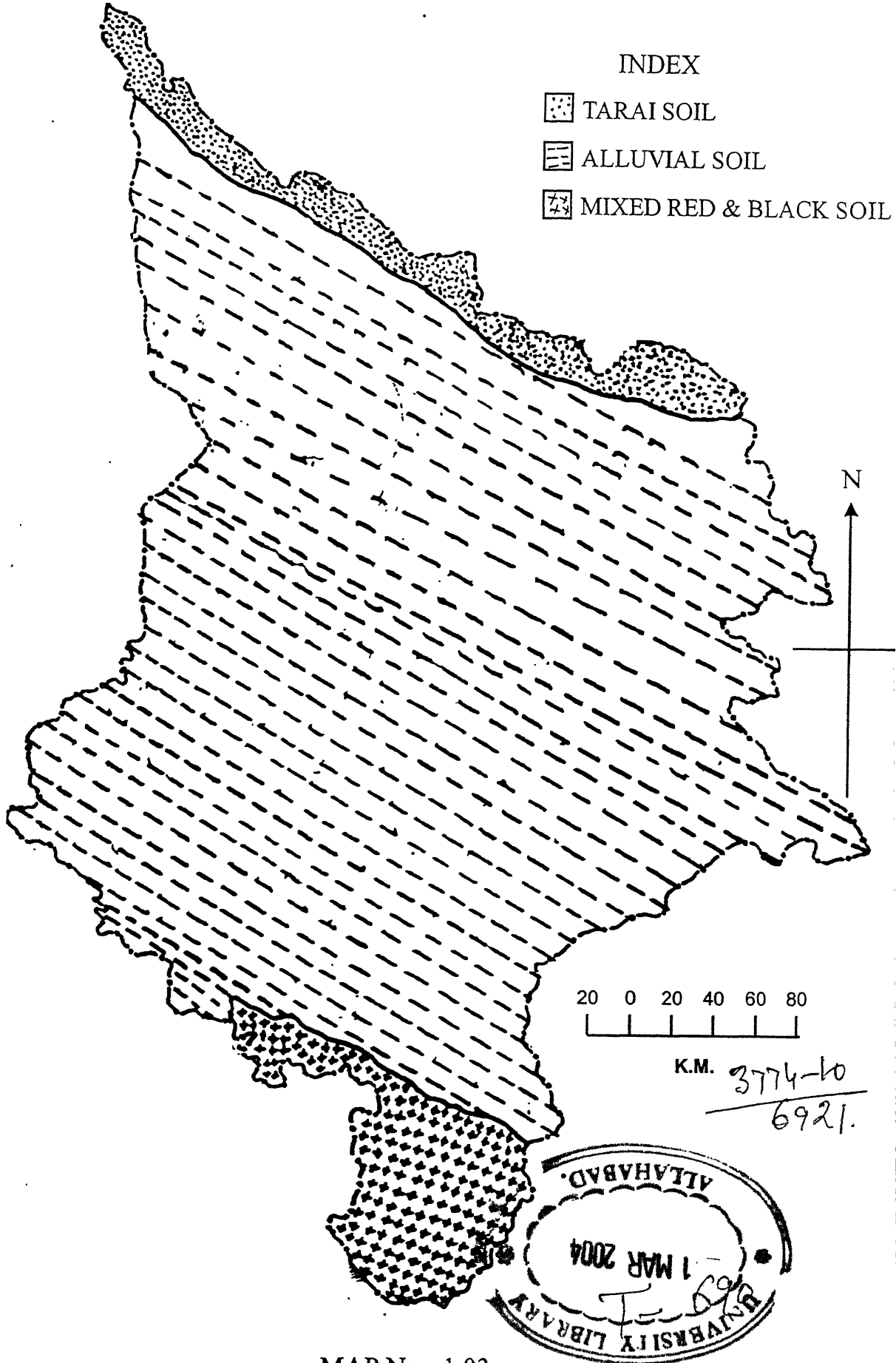
MAP No.- 1.03

जलवायु

किसी भी क्षेत्र के स्थल रूप एवं आर्थिक क्रिया कलापों पर जलवायु का विशेष प्रभाव पडता हैं। अध्ययन क्षेत्र में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यहां प्रायः समशीतोष्ण जलवायु पायी जाती है तथा यह भाग सागरीय प्रभाव से बहुत ही कम प्रभावित रहता है। यहां शीत ऋतु शीतल एवं शुष्क, ग्रीष्म ऋतु लम्बी तथा उष्ण एवं वर्षा ऋतु छोटी तथा आर्द होती है। मध्य अक्टूबर से मध्य जून तक यहां का मौसम प्रायः सूखा रहता है। कभी-कभी जनवरी फरवरी के महीने में हल्की वर्षा हो जाती हैं। मध्य मार्च के बाद अध्ययन क्षेत्र में तापमान बढने लगता है और मई के अन्त तक यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता हैं। कभी-कभी यह दशा मध्य जून तक बनी रहती हैं। जून माह की तीसरे सप्ताह में क्षेत्र में ग्रीष्म कालीन दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें सक्रिय हो जाती है (सिंह, आर० एल० १६७१ पृष्ठ १६८) मानसूनी वर्षा प्रारम्भ हो जाती है और तापमान में कमी आने लगती है। जुलाई से सितम्बर महीने तक वायु में विशेष आर्द्रता बनी रहती है जिससे समय-समय पर साधारण या भारी वर्षा होती रहती है। वर्षा रूकने पर तापमान एवं आर्द्रता के मिले जुले प्रभाव के कारण उमस का अनुभव होता है।

तापमान की दिशायें-

अध्ययन क्षेत्र में जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। इस समय यहां औसत दैनिक तापमान १६.६ अंश सेंन्टीग्रेट रहता है। इन दिनों न्यूनतम तापमान कभी-कभी शून्य के आस पास भी पहुंच जाता है। जनवरी के बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है और मार्च के अन्त

में ग्रीष्म ऋतु आरम्भ हो जाती है।(सिंह, आर० एल० १६७१ पृष्ठ २०१) अप्रैल माह में औसत दैनिक तापमान ३२ डिग्री सेन्टीग्रेट के आस पास हो जाता है। मई के महीने में ३५ डिग्री सेन्टीग्रेट के आस-पास हो जाता है । मध्य.जून के बाद तापमान में कमी आने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में विशेष कर मई के महीने में कभी-कभी उष्णता बहुत बढ़ जाती है और तब ताप लहर का प्रकोप हो जाता है जिसे 'लू' भी कहते है। सामान्यता मई वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है परन्तु जिस वर्ष मानसून का आगमन देर से होता है उस वर्ष मध्य जून तक भी गर्मी अधिक रहती है। जून के बाद तापमान में गिरावट आने लगती है और नवम्बर तक औसत दैनिक तापमान घटकर १७.२ अंश सेन्टीग्रेट के निकट पहुंच जाता है। (रेखा चित्र १.०४) इस अवधि में कभी-कभी तापमान में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा जाता है। मई या जून महीनें में प्राय शुष्क एवं उष्ण धूल भरी हवायें चलती हैं। इन हवाओं को 'लू' कहते हैं। मई और मध्य जून के बाद लू चलना बंद हो जाती है क्योंकि तब इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का आगमन प्रारम्भ हो जाता है और तापमान में भी कमी आने लगती है। वर्षा ऋतु में आर्द्रता बढ़ने के कारण तापमान में क्रमशः गिरावट आने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता है। मई एवं जून के महीने काफी गर्म होते हैं। जिसमें तापमान कभी-कभी ४४ डिग्री सेन्टीग्रेट या इससे अधिक भी पहुंच जाता है। इन दिनों गर्म एवं शुष्क पछुआ हवा चलती है जिसे 'लू' कहते है। मानसून के आगमन के उपरान्त तापमान में गिरावट देखी जाती है एवं सितम्बर के उपरान्त तापमान में उत्तरोत्तर ह्रास दिखाई पड़ता है। सर्वाधिक मासिक तापान्तर मार्च महीने में देखा जाता है । (सारणी १.०२)

EASTERN U.P. MONTHLY DISTRIBUTION OF TEMPERATURE AND RAINFALL (1999)
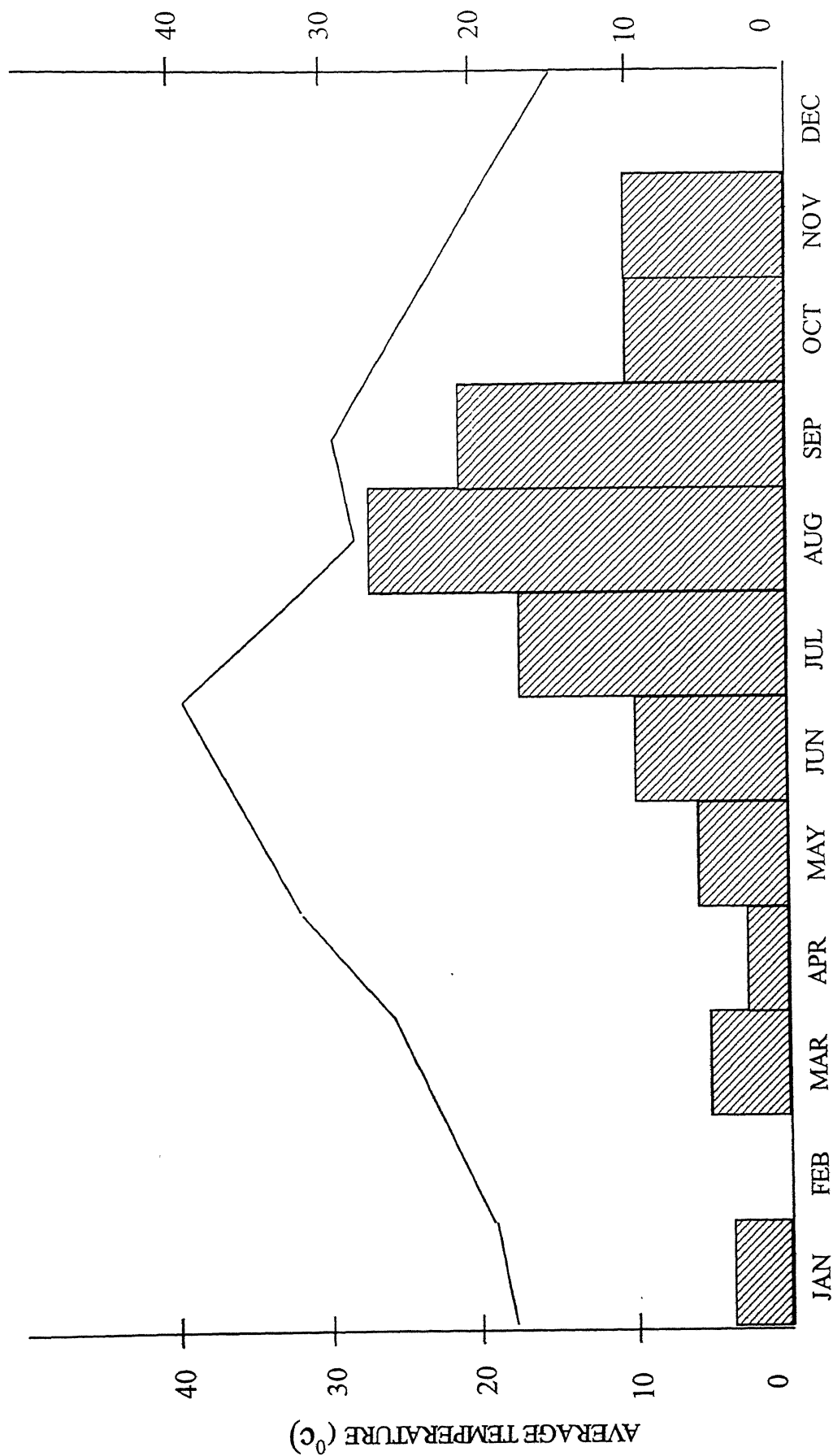
EASTERN U.P. MONTHLY VARIATION IN MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES
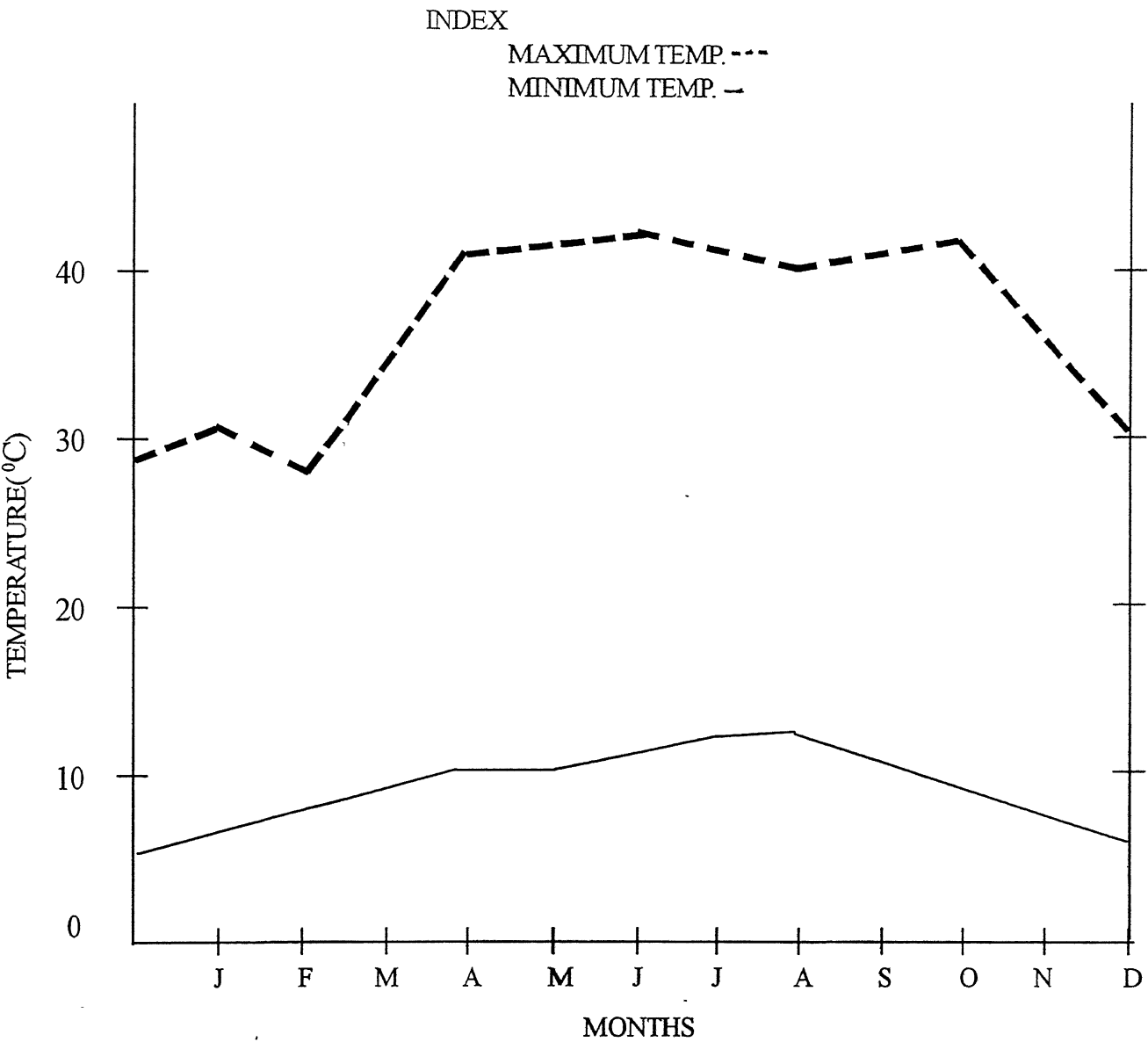
FIG. NO-1.05

सारणी १.०२

अध्ययन क्षेत्र में औसत तापमान का मासिक वितरण (१९९९ से २००० तक)

माह	औसत अधिकतम तापमान डिग्री से०ग्रे० में	औसत न्यूनतम तापमान डिग्री से०ग्रे० में	औसत मासिक तापान्तर डिग्री से० में
जनवरी	२५.२	४.७८	२०.४२
फरवरी	२८.७	६.०६	२२.६४
मार्च	३८.६	११.१४	२७.७६
अप्रैल	४१.६	१७.७०	२३.९०
मई	४३.२	१६.२६	२४.६४
जून	४३.४	२३.१४	२०.२६
जुलाई	३८.६	२३.६	१४.७०
अगस्त	३४.६	१३.१७	२१.४३
सितम्बर	३४.१	२४.१०	१०.००
अक्टूबर	३३.२	१३.४६	१९.७४
नवम्बर	३०.६	८.९२	२१.६८
दिसम्बर	२६.६	६.६८	२२.९२

स्रोत :- उत्तर प्रदेश सीजन , क्राप्स एण्ड वेदर रिपोट १९९९-२०००

वर्षा

अध्ययन क्षेत्र में सामान्यतः १५० सेन्टीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्रायः होती है जिसका लगभग ८०% भाग जुलाई,अगस्त एवं सितम्बर महीनों में प्राप्त होता है। शेष वर्षा जून के अन्तिम सप्ताह में अक्टूबर के प्रारम्भ में तथा

जाड़े के जनवरी एवं फरवरी महीने मे प्राप्त होती है। शीत ऋतु की वर्षा मुख्यतः शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों के माध्यम से होती है।

सामान्यतः अध्ययन क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून के तीसरे सप्ताह तक पहुँचता है और सितम्बर के अन्त तक सक्रिय रहता है जिस कारण जुलाई अगस्त एवं सितम्बर के महीने वर्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर में वर्षा बहुत कम या न के बराबर होती है।

कई वर्षों के वर्षा सम्बन्धी आंकड़ों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि किसी भी माह में होने वाली वर्षा की मात्रा प्रति वर्ष एक समान नही रहती बल्कि इसमे कुछ न कुछ अन्तर होता रहता है। वर्ष १९९६ में १५० सेंटीमीटर वर्षा हुई थी जब कि १९९८ में १६५ सेंटीमीटर तथा २००० में यह १७६ सेंन्टीमीटर रही। इन विवरणों से वर्षा में पर्याप्त विचलन का बोध होता है (चित्र संख्या १.०६)

हवायें

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष भर हवायें मन्द गति से बहती हैं। परन्तु ग्रीष्म काल में विशेषकर मई माह में दोपहर गर्म शुष्क 'लू' और वर्षा काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में हवायें कभी-कभी तीव्र गति से भी चलती हैं ग्रीष्म काल में कभी-कभी आंधियाँ भी आती हैं। जिससे पेड़ों आदि को काफी क्षति होती है। इस क्षेत्र में नवम्बर से मई तक हवायें मुख्यतः

EASTERN U.P. DISTRIBUTION OF ANNUAL RAINFALL
(1996-2000)
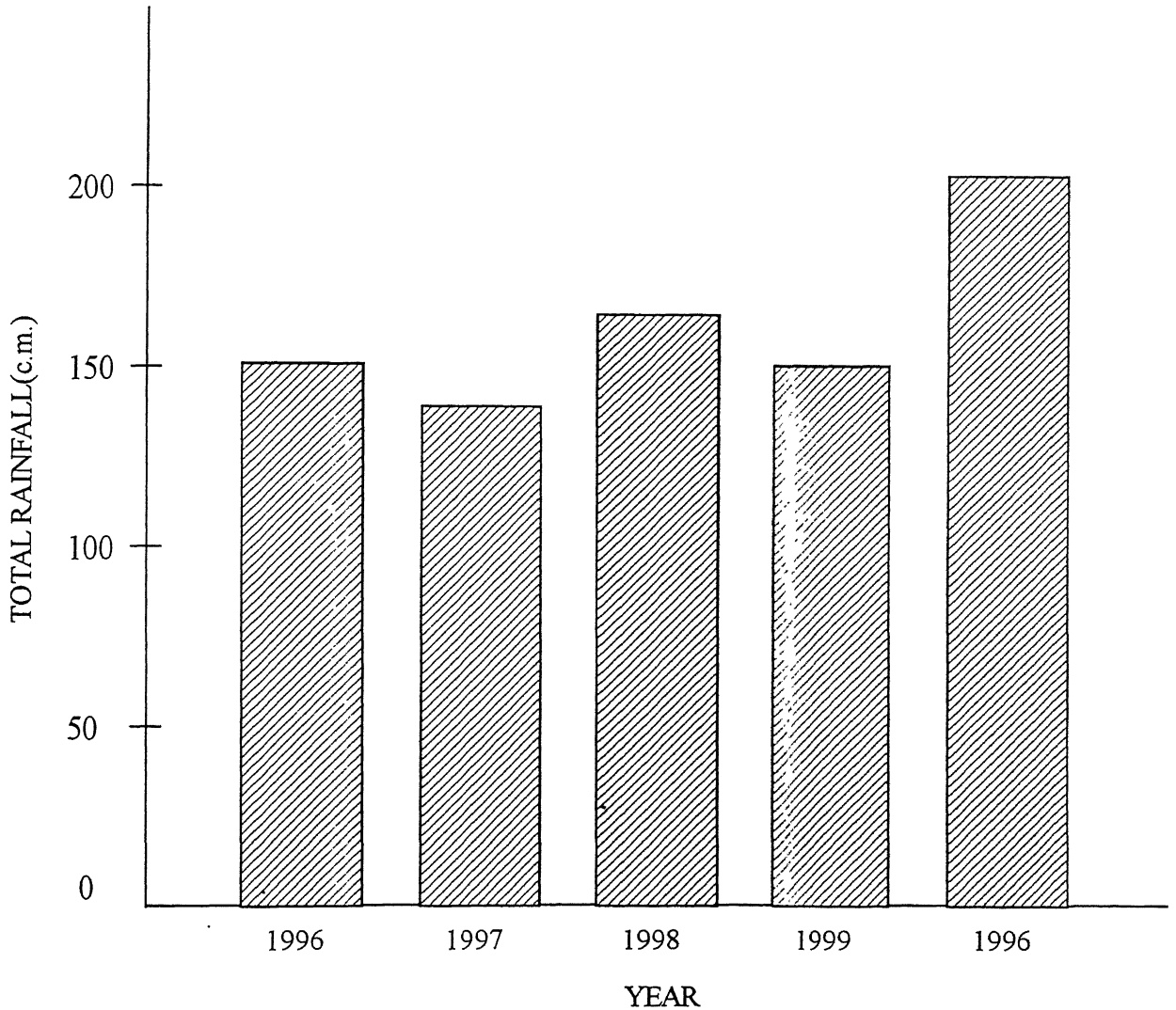
पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से चलती हैं जबकि जुलाई से सितम्बर तक इसकी प्रवाह दिशा पूर्व अथवा उत्तर पूर्व से होता है।

शीतकालीन वर्षा-

अध्ययन क्षेत्र में नवम्बर से फरवरी तक अर्थात जाड़े के चार महीनों में सामान्यतः वर्ष भर होने वाली वर्षा का मात्र ६% ही प्राप्त होता है। इस शीतकालीन वर्षा की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता मिलती हैं।

वायु दाब -

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष में सबसे अधिक वायु दाब दिसम्बर माह में प्राप्त होता है। इस समय यह १००६.८ मिली० बार तक पहुँच जाता है। इसके उपरान्त वायु दाब कम होने लगता है और मई में घट कर ६६२.६ मिलीबार के आस पास आ जाता है। मध्य जून के बाद क्षेत्र में वायु दाब पुनः बढ़ने लगता है।

(ब्लैन फोर्ड, एच.एफ.- क्लाइमेट एण्ड वेदर आफिस इण्डिया, लंदन)

आर्द्रता-

वर्षा ऋतु में इस क्षेत्र में हवायें बहुत नम रहती हैं। वर्षा काल समाप्त हो जाने के बाद सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः घटती जाती है और ग्रीष्म काल

सारणी संख्या -१.०३

अध्ययन क्षेत्र में तापमान एवं वर्षा का माहवार वितरण वर्ष १९९९

माह	मासिक अधिकतम तापमान (डिग्री से०ग्रे)	मासिक न्यूनतम तापमान (डिग्री से०ग्रे)	मासिक औसत तापमान (डिग्री से०ग्रे)	मासिक वर्षा से० मी०
जनवरी	२६.७०	५.१०	१६.६०	२०.००
फरवरी	३२.६०	७.३०	१८.००	नगण्य
मार्च	२८.७०	११.२०	२५.६०	नगण्य
अप्रैल	४३.३२	१८.०२	३१.५०	नगण्य
मई	४६.३०	२०.८०	३२.८०	२.००
जून	४७.५०	२३.५०	३४.००	७.००
जुलाई	४३.८०	२२.७०	३१.००	१२०.००
अगस्त	३५.५०	२२.७०	२८.००	१७०.२०
सितम्बर	३७.२०	२१.१०	२७.८०	१२०.००
अक्टूबर	३७.१०	१६.००	२६.६०	७७.००
नवम्बर	३३.४०	८.३०	२२.१०	७.००
दिसम्बर	२७.८०	५.५०	१७.२०	००.००

के दिनों में हवा के बहुत शुष्क हो जाने के कारण यह बहुत ही कम हो जाती है।

मेघाच्छा दन-

अध्ययन क्षेत्र में वर्षा काल में घने बादल छाये रहते हैं। वर्ष के शेष भाग में आकाश स्वच्छ रहता है अथवा कभी-कभी उस पर हल्के बादल देखे जाते हैं। शीतकाल में जब कभी भी इस क्षेत्र में पश्चिम चक्रवातों का आगमन होता है तो आकाश घने बादलों से छा जाता है अन्यथा शीतकाल में भी आकाश स्वच्छ एवं मेघ रहित रहता है।

मौसम सम्बन्धी विशेष दशायें-

अध्ययन क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से व्यापक वर्षा होती है। यहां कभी - कभी प्रचण्डवायु के साथ गड़गडाहट युक्त तूफान भी आ जाते हैं। इस प्रकार के तूफान वर्षा काल में भी आते रहते हैं। शीतऋतु में कभी-कभी प्रातःकाल कोहरामय हो जाता है और दृश्यता काफी कम हो जाती है। दिसम्बर एवं जनवरी महीनें में कुहरेका प्रभाव अधिक रहता है। कभी-कभी ओला भी गिरता है लेकिन ओला गिरने वाले दिनों की संख्या बहुत कम होती है।

जलवायु और मानव जीवन

जलवायु एवं मानव जीवन में गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य का खान-पान, रहन-सहन, वेष-भूषा तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्रियायें जलवायु से प्रभावित

होती हैं। कृषि कार्य एवं उद्योग पर भी जलवायु का प्रभाव दिखायी देता है। जलवायु द्वारा ही कृषि के मुख्य कार्य निर्धारित होते हैं। कहीं मुख्यतःगेंहू की खेती तो कहीं चावल की खेती की जाती है, कहीं चाय के बाग तो कहीं सेब के बाग लगाये जाते है कहीं घने जंगल का विस्तार पाया जाता है तो कहीं घास के मैदान। इन सब पर ध्यान देने से विदित होता है कि जलवायु का मानवीय आर्थिक क्रियाओं पर तथा प्राकृतिक वनस्पति के विस्तार पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

हरियाणा में रहने वाले लोगों का खान-पान तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के साथ खान-पान से भिन्न हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के वासियों की वेश-भूषा दार्जीलिंग में रहने वाले वासियों से भिन्न है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में सांस्कृतिक कार्यो में भी अन्तर पाया जाता है। यदि हम विवेकपूर्ण विशलेषण करें तो ज्ञात होता है कि इन विभिन्नताओं का एक मुख्य कारण जलवायु एवं मौसम सम्बन्धी विषमता है।

परिवहन के विकास पर भी जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है। जो समुद्र अति ठण्डे प्रदेशों में स्थित है उनके तट वर्ष के अधिकांश महीने बर्फ से जमे रहते हैं। जिससे वहाँ समुद्री परिवहन बाधित रहता है। मौसम खराब होने पर वायुयान की उड़ाने भी रोक दी जाती हैं।

शीत काल में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि ग्रीष्म काल में हम हल्के सूती कपड़े पहनते है। जलवायु के प्रकोप से बाढ़ एवं सूखे की समस्या

उत्पन्न हो जाती है। जिससे मानव समुदाय प्रभावित होता है। जलवायु के प्रतिकूल होने से कई प्रकार के रोग एवं बीमारियों का जन्म होता है। जिससे भी मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

अतः स्पष्ट है कि जलवायु का मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि विज्ञान ने इसके कुप्रभावों को कुछ हद् तक कम कर दिया।

Reference

1. Blanford, H.E., (1889) The climates and weather of India, Ceylon and Burma.
2. Mamoriya, C.V. and Gautam (2001) Geography of India, Sahitya Bhawan Prakasion,Agra.(U.P.)
3. Spate, O.H.K.,(1957) India and Pakistan, A General and Regional geography, (2nd edition) London.
4. Singh, U. (1968) "Middle Ganga" mountains and Rivers of India, 21st international Geographical Congress, India.
5. Singh, Savindra, (1986) Physical Geography, Vasundara Prakasion, Gorakhpur.
6. Singh, R.L. (1971) India : A Regional Geography, N.G.S.T, Varanasi.
7. Singh, M.B.,(1997) Regional Development Planning, Varanasi.
8. Singh, S.C.,(1965) "Delimitation of the middle Ganga Plain", The National Geographical Journal of India Vo. XI Part II(June).
9. Ray Chaudhary, S.P. (1963) Soils of India, New Delhi.
10. Trewartha, G.T.,(1961) The Earths Problem Climates, Wisconsin.
11. Verma, R.V. (1972) Bharat Ki Bhaugolik Vivachna, Kitab Ghar, Kanpur.

12. Wadia, D.N. (1957) Geology of India, Londan.
13. Wadia, D.N. (1937) An out Line of the Geological History of India, Calcutta.
14. Mithal, R.S. (1968) " The Physiographical and structural Evolution of the Himalaya", Mountains and Rivers of India, edited by B.C. Law Calcutta.
15. Thornbury,W .D. (1954) Principles of Geomorphology, New York.
16. Singh, M.B., (1983) Industrial Development Patterns and Potentials in Eastern U.P.,Varanasi.
17. उ.प्र. 99' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, लखनऊ

द्वितीय सोपान
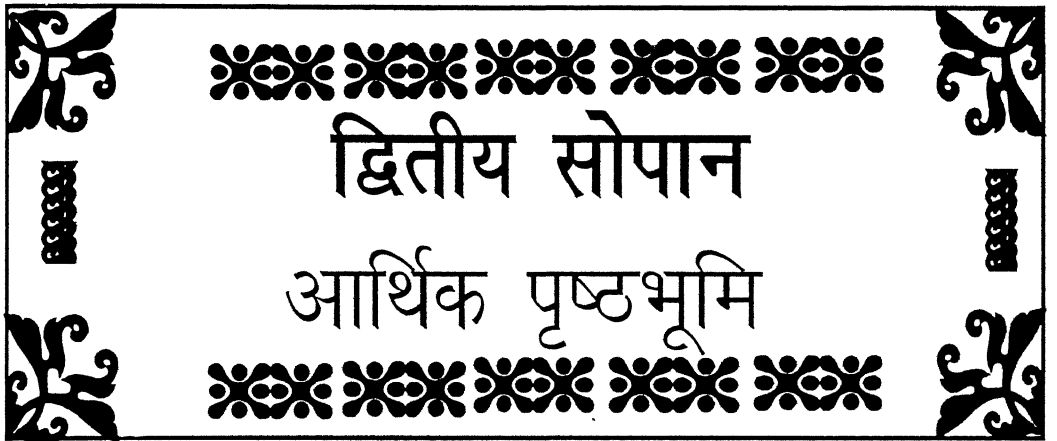
आर्थिक पृष्ठभूमि

आर्थिक पृष्ठभूमि

सामान्य परिचयः-

मनुष्य का व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बहुत हद तक आर्थिक संसाधनों पर निर्भर है। देश एवं प्रदेश का विकास भी आर्थिक संसाधनों की देन है। (कौशिक, १९९५ पृष्ठ १५) आर्थिक संसाधनों से तात्पर्य उन सम्पूर्ण साधनों या कार्यो से है, जिनसें अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, विकसित होती है और चलती रहती है। इसमें कृषि, खनिज, उद्योग,परिवहन, दूरसंचार तथा इनको विकसित करने वाले स्रोत प्रमुख हैं। इनको विकसित करने के लिए मनुष्य स्वंय भी संसाधनों के रूप में कार्य कर सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्राद्यौगिकी के योगदान ने भी इस दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है क्योकि इन दोनों के माध्यम से आर्थिक पृष्ठभूमि को विकसित करने मे काफी सीमा तक सफलता मिली है।

किसी भी देश की आर्थिक पृष्ठभूमि को विकसित करने मे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संसाधनों की जरूरत होती है। प्राथमिक संसाधनों से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का बोध होता है ऐसे संसाधनो में वनों से प्राप्त पदार्थ, खदानों से उपलब्ध खनिज, धरातल से प्राप्त मृदा एवं जलाशयों से प्राप्त मछली इत्यादि हैं। द्वितीयक ससाधनों से उन संसाधनों का बोध होता है, जो निर्मित किये जाते है या जिनका परिशोधन किया जाता है। जैसे- कपास से कपड़ा, लौह चट्टान से लोहा, वन की लकड़ियों से खिलौना तथा मछली से तत्सम्बन्धी खाद्य संसाधन आदि।

तृतीयक संसाधनों से अभिप्राय विकास में सेवा कार्य से है जैसे अभियांत्रिकी का कार्य, श्रम कौशल, प्रौधोगिकी क्रिया आदि। (कौशिक १९९५ पृष्ठ ३५) इन संसाधनों के अतिरिक्त सहायक संसाधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक पृष्ठभूमि के विकास में होती है। इसमें परिवहन, दूरसंचार, विधुत प्रमुख यंत्र एवं उपकरण उल्लेखनीय हैं।(कौशिक, एस० डी० १९९५ पृष्ठ ४८३-४८४) पर्याप्त परिवहन के बिना आर्थिक पृष्ठभूमि अविकसित रहती है। आधुनिक समय में विधुत का प्रयोग सभी विकास कार्यों में अनिवार्य सा हो गया है। दूर संचार का महत्व आर्थिक विकास में स्वतः स्पष्ट है। उघोगों में तो बिना विघुत, दूरसंचार एवं परिवहन के कार्य सम्भव ही नहीं हैं। ये सभी आर्थिक विकास के सक्रिय स्रोत हैं और आगे भी रहेंगें।

आर्थिक संसाधनों का महत्वः-

आधुनिक युग में आर्थिक संसाधनों का महत्व सर्वोपरि है। सम्पूर्ण विकास हेतु आर्थिक संसाधनो की आवश्यकता मनुष्य को, देश को एवं सम्पूर्ण विश्व को है। यही कारण है कि जिस देश में आर्थिक संसाधनों की बहुलता होती है वे आर्थिक रूप सें अधिक समृद्ध होते हैं। इसी कारण विश्व मे विकसित, विकासशील, अर्द्धविकसित एवं अविकसित देशों की श्रेणियां मिलती हैं। विकसित देशों ने अपने संसाधनों के अतिरिक्त दूसरे देश के संसाधनों को भी उपयोग में लाकर अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ा ली है। ऐसे देशों ने अफ्रीका से कच्चा माल प्राप्त कर तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया से खनिज तेल प्राप्त कर अपना आर्थिक विकास समायोजित किया है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप

के देश इसी प्रकार के हैं। अर्थशास्त्री संसार के देशों का एक बड़ा वर्ग विकासशील वर्ग में रखते हैं।(यूनाइटेड नेशन, स्टेटिकल इयर बुक, १९७९-१९८० पृष्ठ ६२८) जिन्होंनें प्राचीन समय में अपनी सम्पदा का पूर्ण उपयोग नही किया था। लेकिन अब वे इस ओर प्रयत्नशील हो गये हैं। भारत ऐसा ही देश है।

अविकसित देशों की श्रेणी में अफ्रीका महाद्वीप के कई देश हैं।(मामोरिया १९९७ पृष्ठ ४२९) क्योंकि उन्होंनें न तो स्वयं और न तो किसी दूसरे देश की सहायता से अपना आर्थिक विकास किया है। हांलाकि उनके पास आर्थिक विकास के साधन विधमान हैं। इस महाद्वीप के कुछ देशों में विदेशियों ने उनके संसाधनो का उपयोग कर अपना आर्थिक विकास किया है। यधपि इन देशों का भी कुछ न कुछ लघु स्तरीय विकास हुआ है।

आर्थिक संसाधनों का तुलनात्मक महत्व अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग है। भारत जैसे देश में कृषि का महत्व उधोंगों से कहीं अधिक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में तो यह बात स्वतः स्पष्ट है। इस क्षेत्र में उधोगों का पर्याप्त विकास नही हो पाया है। कुछ लघु एवं ग्रामीण स्तर के उधोग अवश्य विकसित हो गये हैं।

विकसित देशों में उधोगों का महत्व कृषि की तुलना में अधिक है। ग्रेटब्रिटेन और जापान मे यही स्थिति है। यहां कृषि कार्य करने वालों की संख्या बहुत कम है।(मामोरिया एवं चतुर्वेदी १९८९ पृष्ठ ६४)

अर्द्धविकसित देशों में भी कृषि की प्रधानता है लेकिन उधोगों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। अविकसित देशों में आर्थिक विकास की दिशा निश्चित नही हो सकी है। इसी कारण न तो कृषि का विकास हुआ है और न ही उधोग विकसित हो सके हैं। तुलनात्मक दृष्टि से वहां भी कृषि की प्रधानता है।

किसी भी देश में परिवहन के महत्व को नकारा नही जा सकता है। परिवहन आर्थिक विकास की प्रमुख कड़ी है। कृषि से उत्पादित सामानों को बाजारों तक ले जाने मे परिवहन का महत्व सर्वविदित है। उद्योगों के लिए कच्चे मालों को लाने तथा उत्पादित पदार्थ को उपभोक्ता केन्द्रों तक ले जाने में परिवहन अह्म भूमिका निभाता है। सड़क यातायात के अलावा जलमार्ग एवं वायुमार्ग द्वारा भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाये जाने लगे हैं। आर्थिक विकास हेतु दूरसंचार भी अनिवार्य कड़ी है। भविष्य में इसका और महत्व बढ़ने की संभावना है।

आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रमुख घटक-

किसी भी देश की आर्थिक पृष्ठभूमि कई अवयवों के संयुक्त प्रयासों या क्रिया कलापों की देन है। धरातल का प्राकृतिक स्वरूप, उसकी जलवायु प्रक्रिया उसका वनस्पति आवरण तथा उसका मृदा वितरण आर्थिक विकास की भौतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। इस आधार पृष्ठभूमि पर मनुष्य अपनी क्षमता एवं कौशल के अनुरूप प्रयास कर आर्थिक विकास करता है। भौतिक आधार की भिन्नता से तथा मानव प्रयासों की विभिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न देशों का आर्थिक विकास एक समान नही हो सका है और न हो सकेगा। समृद्ध भौतिक आधार पर मनुष्य का थोड़ा प्रयत्न भी सरलता से सफलता प्राप्त कर लेता है लेकिन कमजोर भौतिक आधार पर मनुष्य के कठिन प्रयास से ही आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है और ऐसा ही हुआ है जापान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैदानी भागों के अलावा पर्वतीय भागों में आर्थिक विकास कठिन

होता है। पर्वतीय भागों में जहाँ कहीं खनिजों का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं वहाँ सुगमता से आर्थिक विकास हुआ है।

भौतिक आधार के उपरान्त किसी देश में आर्थिक विकास की श्रंखला मानव प्रयासों से जुड़ी होती है। इसमें उसका अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान उसे सक्षम बनाता है। मनुष्य आशावाद के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। उसने भौतिक आधारों में परिवर्तन का प्रयत्न किया है तथा सफलता भी प्राप्त की है। स्पष्ट है कि मनुष्य का ऐसा प्रयास निरन्तर चलता रहेगा।

आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रमुख स्रोत

आर्थिक पृष्ठभूमि कई अवयवों या श्रंखलाओं के संयोजन से निर्मित होती है। इन सभी का अलग-अलग वर्णन करना कठिन है। आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रमुख स्रोत निम्न है-

१- कृषि विकास

२- औद्योगिक विकास

३- परिवहन विकास

४- दूरसंचार विकास

५- विद्युतीकरण

६- यंत्रीकरण

सारणी संख्या -२.०१ एवं २.०२

पूर्वी उत्तर प्रदेश

जनपद स्तर पर कृषि योग्य क्षेत्रफल, खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल तथा खरीफ रबी फसलों का प्रतिहेक्टेयर उत्पादन

-१९९८-९९

क्र०स०	जनपद	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कृषि योग्यक्षेत्र (हेक्टेयर में)	खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल प्रतिशत में	खरीफ उत्पादन	रबी उत्पादन
१	फैजाबाद	४३७५८६	४८१८५६	८६.६३	१४.०	१६.१
२	गोण्डा	७३४९६२	७०७९९१	८९.६९	१४.५	१८.०
३	सुल्तानपुर	४४०१८०	४४३१५६	८६.९१	१५.१	१६.०
४	प्रतापगढ़	३६४४२३	३४२२१३	९४.६९	१४.२	१५.०
५	इलाहाबाद	७२७८९७	६५७२२०	९२.३६	१४.६	१७.०
६	वाराणसी	५०९१९८	५३३१३१	९१.०७	१५.०	१८.०
७	महराजगंज	३०००८६	३५९८९९	८८.६६	१६.४	१८.३
८	सोनभद्र	७०११४१	२६५३५४	८७.८१	१७.०	१९.०
९	बलिया	२९९२६५	३३९०२८	८९.९७	१४.३	१७.४
१०	गाजीपुर	३३३२०९	४००७४०	८७.७३	१५.०	१६.०
११	मऊ	१७११५७८	२११५३६	९५.५१	१८.४	१९.६
१२	आजमगढ़	४२३९८५	४९६७०१	८८.९८	१६.२	१५.०
१३	बहराइच	८८८६१३	७०७९९१	८८.१४	१८.०	१९.२
१४	मिर्जापुर	४६६०३७	३०३९२३	८६.८३	२०.४	१९.०
१५	जौनपुर	३९९७१३	४०८६९३	९१.५२	१५.४	१८.३
१६	बस्ती	४२६९६४	४९२३७५	९२.२१	१४.३	१९.२
१७	गोरखपुर	३३८४३६	४००६६५	९५.८४	१८.२	१६.०
१८	देवरिया	२५२३९०	३१५२९४	९०.४०	१६.३	१८.३
१९	संतरविदास नगर	१२२३०७	९२४०८	९७.६१	१६.१	१८.२
२०	बलरामपुर	२२२४०१	१९२३०७	९४.६५	१४.१	१६.२
२१	श्रावस्ती	२५४०१३	२०३०१२	८९.६५	१४.०	१८.६
२२	संतकबीरनगर	२१०७३१	१९०२३२	९५.६७	१५.०	१९.२
२३	चन्दौली	२५३८०३	२०३००१	८९.६१	१४.०	१८.७
२४	कुशीनगर	२४२२०१	२०२२६६	८९.९९	१६.७	१८.१
२५	सिद्धार्थनगर	४७०११४१	२६५३५४	८३.६६	१८.०	१९.१
२६	अम्बेडकरनगर	३८९११७	३०८३१२	८८.८७	१८.७	१८.०

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकड़ेउ०प्र०सरकार द्वारा प्रकासित

DISTRICT WISE KHARIF CROPS PRODUCTIVITY IN EASTERN U.P. (1998-99)
PRODUCTIVITY (Kg PER HECTARS)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
MIRZAPUR
AMBEDKAR
MAU
GORAKHPUR
SIDHARTH
BAHRAICH
SONBHADRA
KUSINAGAR
MAHARAJ
DEORIA
AZAMGARH
RAVIDAS
JAUNPUR
SULTANPUR
GHAZIPUR
SANT KABIR
VARANASI
ALLAHABAD
GONDA
BALIA
BASTI
PRATAPGARH
BALARAMPUR
SRAVASTI
CHANDULI
FAIZABAD
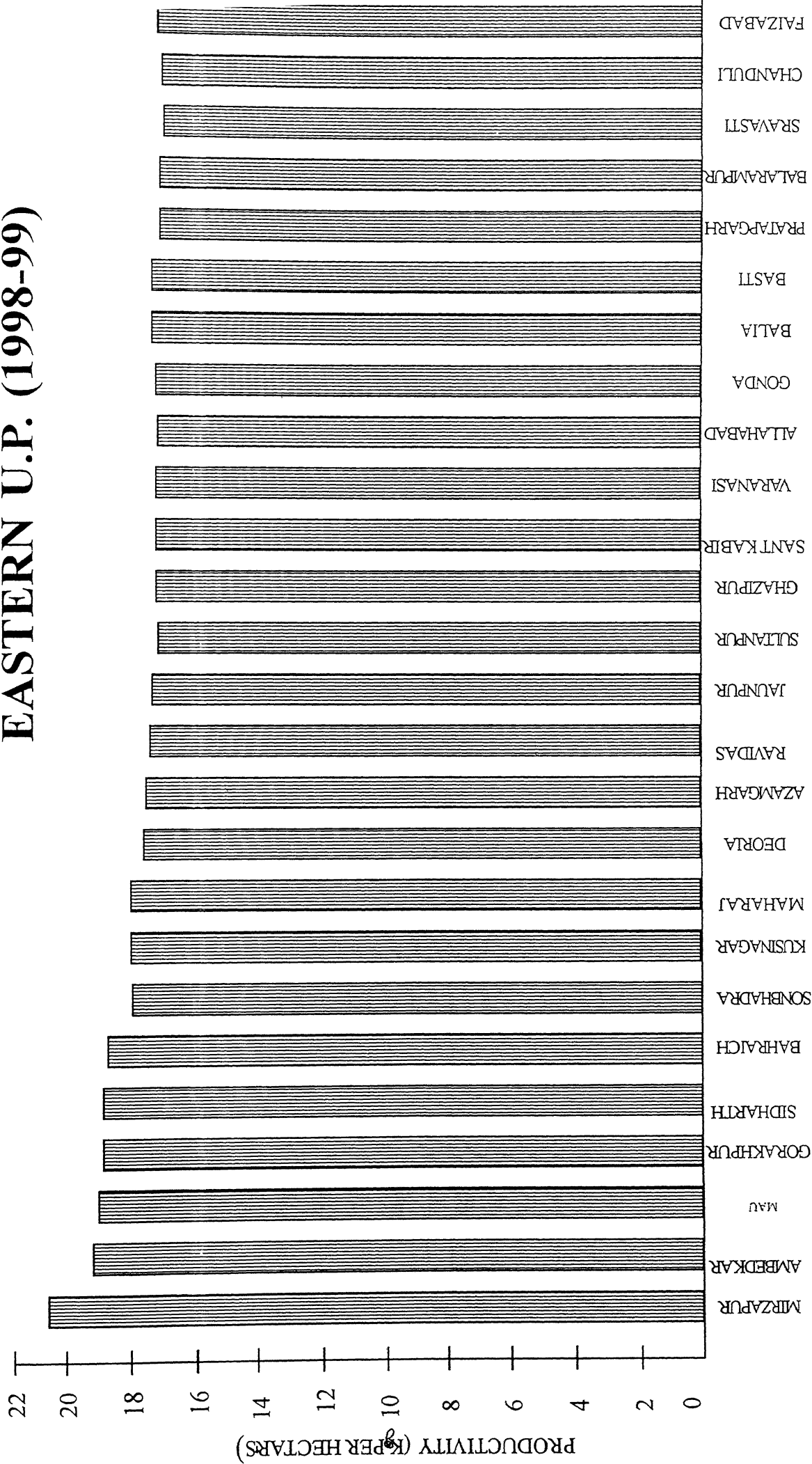
Fig No-2.03

DISTRICT WISE RAVI CROPS PRODUCTIVITY IN EASTERN U.P. (1998-99)
PRODUCTIVITY (Kg PER HECTARS)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
MAU
BAHRAICH
SANT KABIR
SONBHADRA
MIRZAPUR
CHANDULI
SRAVASTI
DEORIA
JAUNPUR
MAHARAJ
SANT RAVIDAS NAGAR
KUSINAGAR
GONDA
VARANASI
AMBEDKAR
ALLAHABAD
SIDHARTH
BALIA
BASTI
BALARAMPUR
FAIZABAD
SULTANPUR
GHAZIPUR
GORAKHPUR
PRATAPGARH
AZAMGARH
Fig.No-2.04
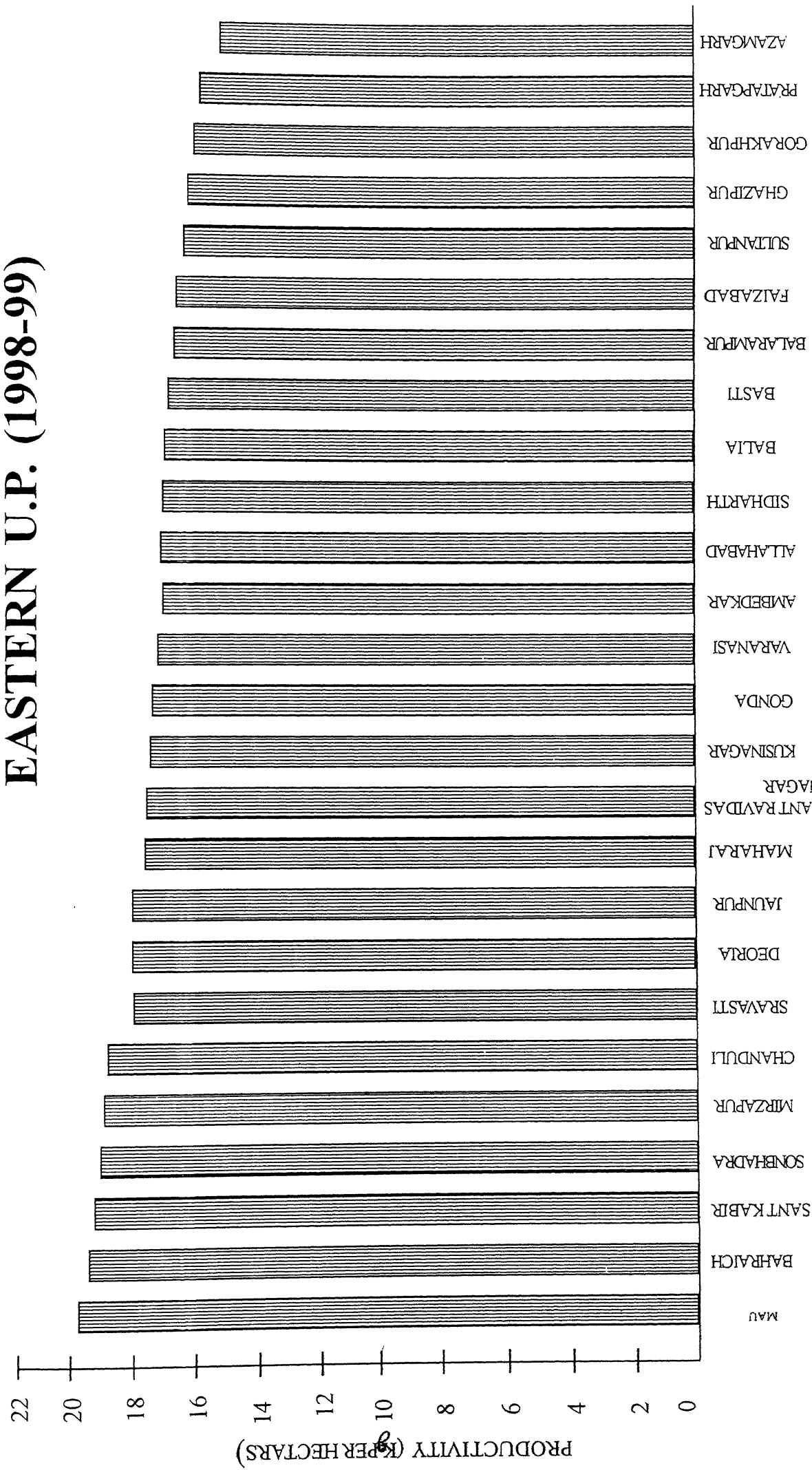
इन्हें सांस्कृतिक स्रोत भी कहा जाता है। भौतिक आधारों का उल्लेख पूर्व में ही किया जा चुका है। इस अनुभाग में सांस्कृतिक स्रोतों का ही विवरण किया जा रहा हैं।

कृषि कार्यः-

पूर्वी उत्तर प्रदेश नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित है। अतः सामान्य रूप से यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। यहां कृषि योग्य क्षेत्रफल लगभग ६५२४६६१ हेक्टेयर हैं जो लगभग कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का ६६.०६प्रतिशत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग ८०प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुयी है। जिससें यह स्पष्ट होता है कि यहां की जनसंख्या का मुख्य उद्यम कृषि कार्य है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश एक सघन जनसंख्या वाला भाग है। जिसकी जनसंख्या तीव्र गति सें बढ़ती जा रही हैं। अतः इसके भरण-पोषण के लिए अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। इसी कारण यहां अधिकांश क्षेत्रफल पर खाद्यान्न फसलें ही उगायी जाती है। १६६८-६६ के आकड़ों के अनुसार यहां कुल कृषि योग्य भूमि के ६२.८प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलों की कृषि की गयी थी। यहां सिचांई की सुविधाओं की कमी है तथा कृषि कार्य में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग भी कम होता है। इसी कारण यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मुख्यतः तीन फसलें उत्पन्न की जाती हैं- रबी, खरीफ, जायद की फसलें । इन फसलों का संक्षिप्त विवरण सारणी संख्या २.०१ में दिया गया है।

रबी की फसलें-

ये शीत ऋतु की फसलें है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग ६८.८ हजार हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसलें उत्पादित की जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलों में मुख्यतः गेंहूं, चना, मटर, अरहर, तोरिया, राई, सरसों एवं अलसी की फसलें प्रमुख है। रबी की फसलों की औसत उत्पादकता के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। रबी की फसलों की जनपदवार प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सारणी संख्या २.०२ में दी गयी है।

क- न्यून उत्पादकता वाले क्षेत्रः-

इसके अन्तर्गत देवरिया १८.३, बलरामपुर १६.२, बस्ती १६.२, फैजाबाद १६.१, सुल्तानपुर १६.०, गाजीपुर १६.०, गोरखपुर १६.०, प्रतापगढ़ १६.०, आजमगढ़ १५.० जनपद सम्मिलित हैं।

ख- अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत मऊ १६.६, सिद्धार्थ नगर १६.४, बहराइच १६.२, संतकबीर नगर १६.२, तथा मिर्जापुर १६.० जनपद आते है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा इन जनपदों में रबी की फसलों की औसत उत्पादकता अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि हम रबी की फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पर पृथक -पृथक विचार करें तो स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अन्य फसलों की तुलना में अधिक है। उत्पादकता की दृष्टि से जौ का द्वितीय, मटर का तृतीय एवं चने का चतुर्थ स्थान है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढनें के लिए

PRODUCTIVITY OF RAVI CROPS IN EASTERN U.P.-1998-99
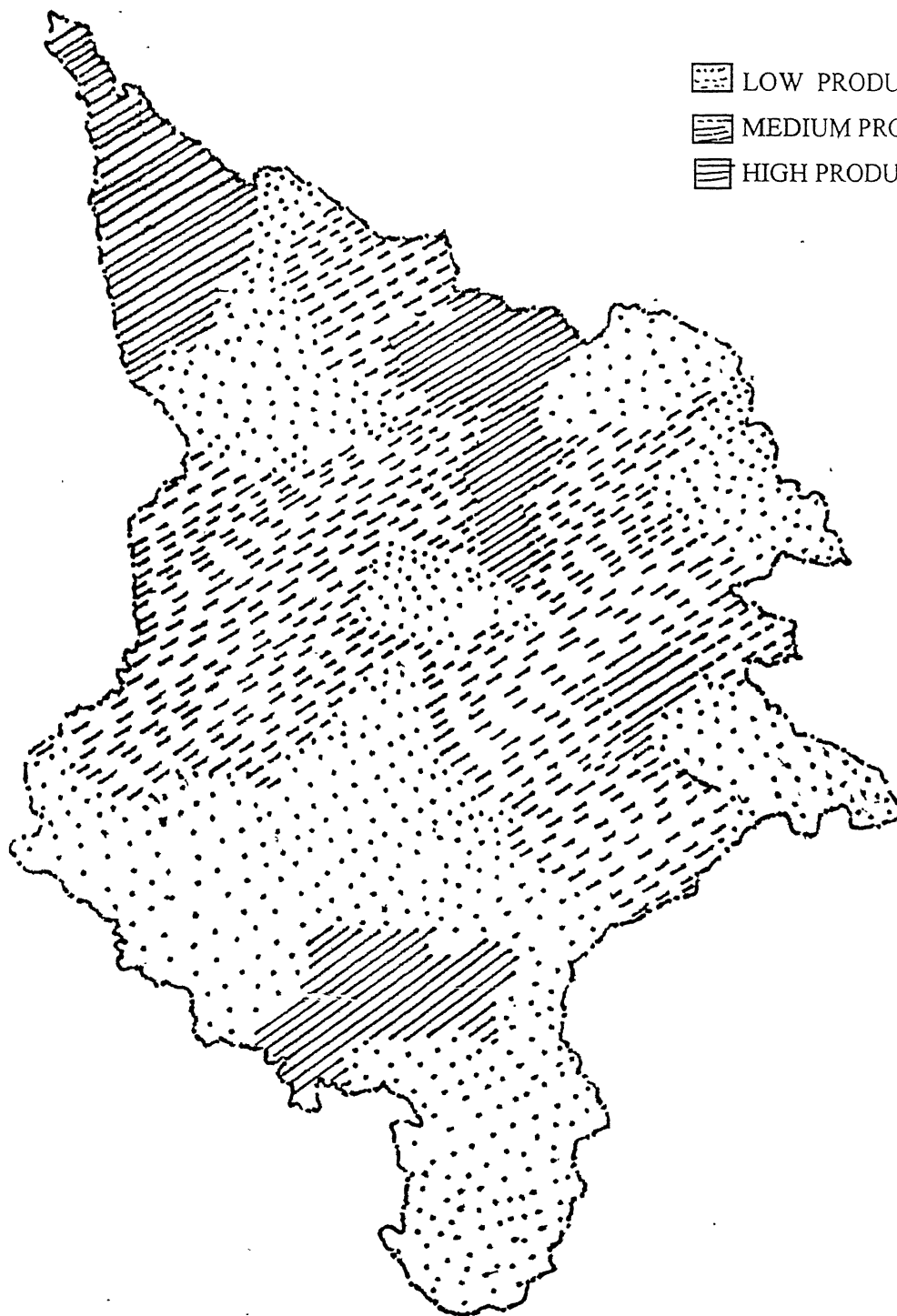
PRODUCTIVITY OF KHARIF CROPS IN EASTERN U.P.-1998-99
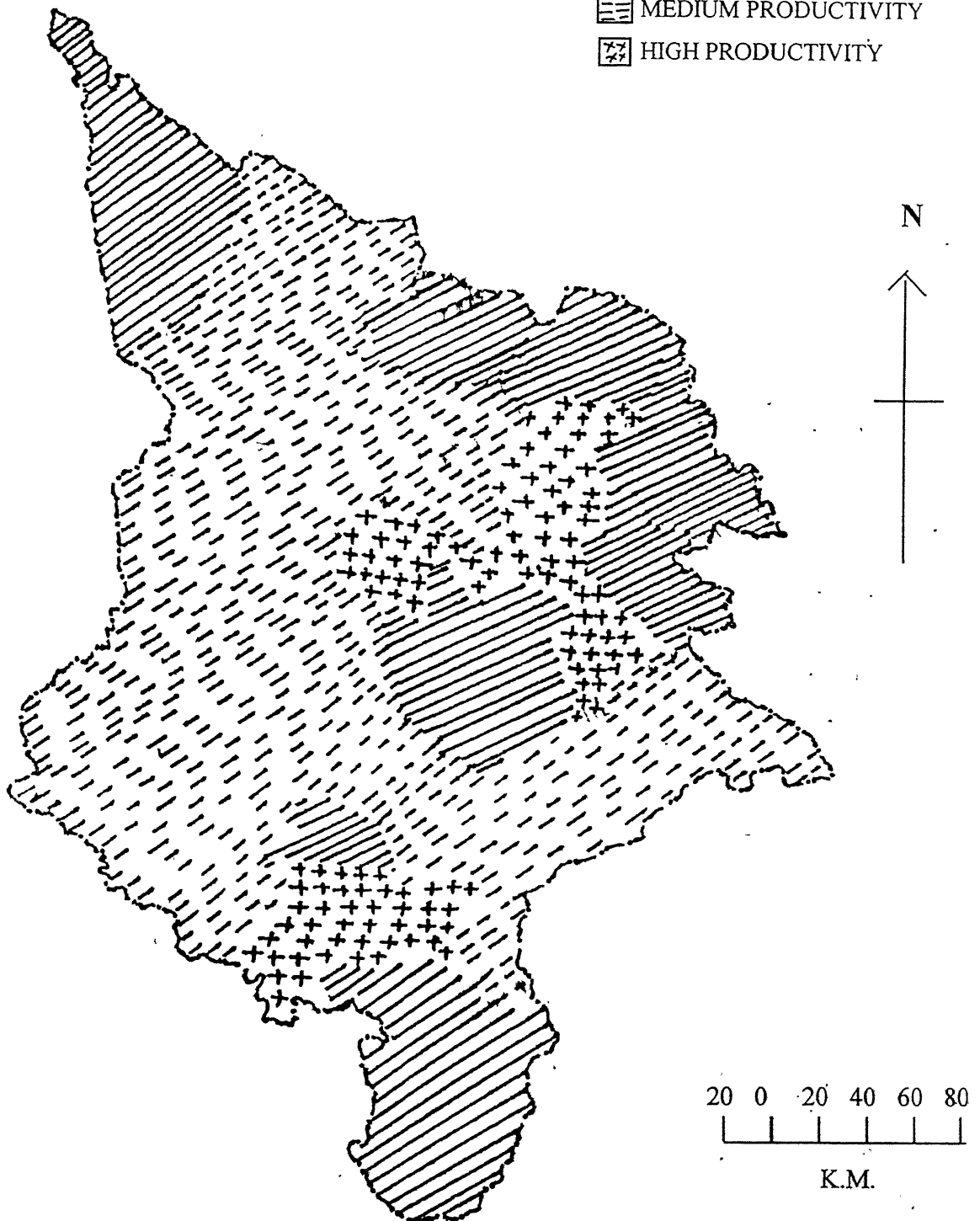
सरकार अनेक प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से उत्पादकता में वृद्धि हेतु फसल उत्पादन तकनीक प्रदर्शन, एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सामान्य कार्यक्रमों के साथ चलाया जा रहा है। दलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

ग- औसत उत्पादकता वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत इलाहाबाद, बलिया, गोण्ड़ा, बनारस, महाराजगंज, जौनपुर, संतरविदास नगर, श्रावस्ती, चन्दौली, कुशीनगर जनपद शामिल हैं। इन जनपदों की औसत उत्पादक्ता १७.० से १८.५ के मध्य है। मानचित्र संख्या २.०१ तथा २.०२ में रबी एवं खरीफ फसलों की उत्पादकता दिखायी गयी है।

खरीफ की फसलें

खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु की फसलें हैं। ये फसलें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग ६८.८ हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर बोयी जाती हैं। यहां खरीफ की फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल व अरहर प्रमुख हैं। महराजगंज, सोनभद्र, मऊ, बहराइच, मिर्जापुर, देवरिया जनपद उत्पादन में अग्रणी हैं। जहां खरीफ फसलों की औसत उत्पादकता १६ से २० कुन्तल प्रति हेक्टेयर पायी जाती हैं। शेष जनपदों की औसत उत्पादकता १४ से १५ कुन्तल प्रति हेक्टेयर हैं।

खरीफ की अन्य फसलों की तुलना में यहां धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। उत्पादकता की दृष्टि से बाजरे का द्वितीय एवं ज्वार का तृतीय स्थान हैं।

जायद या अतिरिक्त फसलें-

ये ग्रीष्म ऋतु में उगायी जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जायद फसलों की कृषि लगभग २६हजार हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। जायद फसलों में मुख्यतः कुछ फलों, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और कुछ सब्जियों की कृषि की जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः अमरूद, केला, आम, नींबू, ककड़ी, तरबूज, खरबूज फलों के रूप में तथा टमाटर, भिण्ड़ी, तरोई, मिर्च, लौकी आदि सब्जियों के रूप में जायद फसलों के अन्तर्गत उगायी जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीफ, रबी, एवं जायद फसलों का विशेष विवरण निम्नवत है-

खरीफ की फसलें-

धान-

यह खरीफ की प्रमुख फसल है। इसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वर्षा एवं उचित सिंचाई व्यवस्था का होना आवश्यक है। साथ ही साथ कठिन परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। धान पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाधान्न फसल है। वर्ष १९९८-९९ में यहां ३१. ०२ लाख हेक्टेयर क्षेत्रपर धान की कृषि की गयी थी जिससें ५८६१६२१ मिट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हुआ था। सरकार द्वारा धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने की सम्भावनायें हैं। सारणी संख्या २. ०३ में जनपदवार धान की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता दिखायी गयी है।

बाजरा-

पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद बाजरे की फसल का द्वितीय स्थान है। यहां वर्ष १९९८-९९ में १२०४८३ हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की कृषि की गयी थी। बाजरे की कृषि में प्रयुक्त क्षेत्र फल की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में इलाहाबाद जनपद का प्रथम स्थान है। यहां वर्ष १९९८-९९ में ५१७८१ हेक्टेयर भूमि पर बाजरा बोया गया था। उध्ययन क्षेत्रमें बाजरे की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। सारणी संख्या २.०३ में जनपदवार बाजरे की प्रतिहेक्टेयर उत्पादकता दिखयी गयी है।

ज्वार-

मोटे अनाजों के अन्तर्गत ज्वार एक प्रमुख फसल है। यह कम उपजाऊ एवं बलुई भूमि में बिना सिंचाई के द्वारा भी सफलता पूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। यह पशुओं के चारें का भी एक प्रमुख स्रोत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरे का तीसरा स्थान है। वर्ष १९९८-९९ में यहां ८५५९८ हेक्टेयर भूमि पर ज्वार की फसल बोई गयी थीं।

अरहर-

अध्ययन क्षेत्र में अरहर की कृषि सह-फसल के रूप में की जाती है। जिसके कारण इसमें वांछित उत्पादन नही मिल पाया हैं। वर्ष १९९८-९९ में अध्ययन क्षेत्र के ३०१४ हेक्टेयर क्षेत्र पर अरहर की कृषि की गयी थी।

सारणी संख्या -२.०३

पूर्वी उत्तर प्रदेश

जनपद स्तर पर मुख्य खरीफ फसलों की उत्पादकता का विवरण (कुन्टल / हेक्टेयर)

क्र०स०	जनपद	धान उत्पादकता		ज्वार उत्पादकता		बाजरा उत्पादकता	
		वर्ष १९९७-९८	वर्ष १९९८-९९	वर्ष १९९७ - ९८	वर्ष १९९८-९९	वर्ष १९९७-९८	वर्ष १९९८-९९
१	फैजाबाद	२२.४१	२७.६८	९.५५	८.३५	८.३५	१२ ००
२	गोण्डा	१८ ८३	१७.६६	७.३१	८.३४	८.३४	१३.५२
३	सुल्तानपुर	२१.७६	२८.५७	८ ०३	८.९४	८.९४	११ ४३
४	प्रतापगढ़	२०.७९	२८.४७	१२.९५	१२.४३	१२.४३	९.३२
५	इलाहाबाद	१९.७६	२९.१०	८.७५	९.३०	९.३०	८.८३
६	वाराणसी	२७.६६	२९.८६	७.७८	९.७०	९.७०	९ ९३
७	महराजगंज	२४.७८	२४.२३	१२.५०	१५.२७	१५.२७	१५ ३८
८	सोनभद्र	२१.४२	२३.११	६.१२	९.३४	९.३४	१५ ००
९	बलिया	१७.९६	२८.२१	९ ०४	९.४३	९.४३	१० ०५
१०	गाजीपुर	२०.७६	२८.२२	७.५५	९.३४	९.३४	१०.०३
११	मऊ	१७.६३	२९.२९	८.०३	९.३४	९.३४	१०.४०
१२	आजमगढ़	१८.१८	२८.८०	९त्र२५	९.२७	९.२७	१३.८९
१३	बहराइच	१६.७८	१८.३०	९.५९	८.८२	८.८२	१०.८५
१४	मिर्जापुर	२२.००	२७.१२	६.२३	९.३४	९.३४	११.७०
१५	जौनपुर	२२.८१	२९.४१	८.६४	९.६७	९.६७	१०.१९
१६	बस्ती	१७.२८	२५.००	-	१५.६७	१५.६७	१८.२०
१७	गोरखपुर	१९.६८	२८.६०	१४.८८	१५.६७	१५.३४	१३.६६
१८	देवरिया	२१.८९	२८.११	१२.६६	१५.२४	१५.२४	१४.१३
१९	संतरविदास नगर	२६.२३	२९.४६	६.७२	९.६७	९.६७	१०.०१
२०	बलरामपुर	२५.४३	२७.४३	१३.३१	१४.१२	१४.१२	१६.४१
२१	श्रावस्ती	२४.७४	२५.४३	१५.७८	१५.०४	१५.०४	१६.७१
२२	सतकबीरनगर	२३.७२	२५.४२	१४.९३	७.४३	७.४३	९.४८
२३	चन्दौली	२२.४७	२५.२३	१५.२५	१२.६४	१२.६४	१०.२५
२४	कुशीनगर	२५.०१	२६.०७	१०.३४	१५.६७	१३.६७	१७.००
२५	सिद्धार्थनगर	१९.९१	२५.८४	९.४२	१५.३४	१५.३४	१६.६६
२६	अम्बेडकरनगर	२४.६०	२१.६३	१०.८०	८.४३	८.४३	१७.९१

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकडे १९९८-१९९९ उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित

.

रबी की फसल

गेहूं-

खाद्यन्न फसलों में गेहूं अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल लोगों के भोजन का प्रमुख श्रोत है बल्कि एक मुद्रादायनी फसल भी है। इसके भूसे का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिये किया जाता है। गेहूं के पौधे में जलवायु के अनुसार समायोजन करने की पर्याप्त क्षमता होती है।

गेहूं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। वर्ष १९९८-९९ में इस अध्ययन क्षेत्र में लगभग ३३२८६१७ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया गया था जिसकी औसत उत्पादकता २५.०४ कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी। गेहू की उत्पादकता में वृध्दि के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। सारणी संख्या २.०४ में जनपदवार गेहूं के फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दिखायी गयी है।

जौ-

यह भी रबी की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम उपजाऊ भूमि तथा सिचांई की आवश्यकता नही होती । अध्ययन क्षेत्र में वर्ष १९९८-९९ में ८४९७४ हेक्टेयर भूमि पर जौ की कृषि की गयी तथा १०५२८४ मिट्री टन उत्पादन प्राप्त हुआ। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सारणी संख्या २·०४ से स्पष्ट है।

सारणी संख्या -२.०४

पूर्वी उत्तर प्रदेश

जनपद स्तर पर मुख्य रबी फसलों की उत्पादकता का विवरण (कुन्टल / हेक्टेयर)

क्र०स०	जनपद	धान उत्पादकता		ज्वार उत्पादकता		बाजरा उत्पादकता	
		वर्ष १९९७-९८	वर्ष १९९८-९९	वर्ष १९९७ - ९८	वर्ष १९९८-९९	वर्ष १९९७-९८	वर्ष १९९८-९९
१	फैजाबाद	२६.७६	२४.९३	२२ ३३	२३.०९	८.८७	१५.९१
२	गोण्डा	२५.४५	२६.९७	२२.४३	२२.७४	७.९३	११.६६
३	सुल्तानपुर	२६.३४	२९.७९	२२.२४	२५.६०	८.९४	१५.०१
४	प्रतापगढ़	२२.५७	२३.०९	९.६४	९.६७	१२.९५	१३.३५
५	इलाहाबाद	२१.६७	२९.७८	१४.४४	१६.७८	८.६०	१०.३०
६	वाराणसी	२७.४८	३०.००	१६.३४	१९.६४	१३.४०	१४.११
७	महराजगंज	२८.८१	२५.००	२४.९२	२०.८५	८.३६	९.९८
८	सोनभद्र	१०.०४	१९.८३	१६ ५०	९.१३	५.७६	११.८६
९	बलिया	२५.९६	२९.३२	१४.६२	२३.१८	९.२४	१२.६३
१०	गाजीपुर	२४.४८	३०.१८	१६.०१	१९.०८	१२.९२	१३.२८
११	मऊ	२५.८१	२९.८७	१४.१०	१५.४२	१०.३४	१३.७३
१२	आजमगढ़	२५.२०	२८.७१	१४.६२	१५.०४	१०.५३	११.८२
१३	बहराइच	२२.३१	३१.६२	२२.३३	२१.५६	८.१४	१०.२१
१४	मिर्जापुर	१९.८१	२९.९१	१६.२२	१७.२२	८.९२	११.३३
१५	जौनपुर	२४.४९	२०.६६	१४.१४	१८.११	१०.१२	११.६३
१६	बस्ती	२५.३७	२९.२७	२४.०१	२५.९२	८.५६	१०.२१
१७	गोरखपुर	२५.२३	२९.४६	२४.०४	२३.७६	८.०१	११.२१
१८	देवरिया	२६.३४	२०.७०	२४.३४	२५.५०	८.४१	१०.७७
१९	संतरविदास नगर	३१.८७	२९.९९	१६.१४	१७.२२	१३.०१	१४.६४
२०	बलरामपुर	२३.२३	२६.७०	१०.५४	१२.२२	११.९४	१४.९८
२१	श्रावस्ती	२२.६७	२५.०९	१५.३४	१७.८८	१२.६७	१६.१७
२२	संतकबीरनगर	२४.३२	२८.४३	१४.४३	१७.४९	१०.१२	१२.८१
२३	चन्दौली	२५.३५	२६.२७	१२.३४	१४.४१	१२.३४	१५.३०
२४	कुशीनगर	२५.४५	२९.७२	२४.३४	२९.२३	८.३७	१०.४१
२५	सिद्धार्थनगर	२६.६६	२८.५३	२४.१४	२५.९२	८.३४	९.७१
२६	अम्बेडकरनगर	२८.७८	१९.२८	२२.१४	२२.७४	८.९७	१५.०२

स्रोत :- १- जनसंख्या सेन्सस, जनगणना विभाग (उ०प्र०) लखनऊ द्वारा प्रकाशित

चना-

चना एक फलीदार फसल है। ये भूमि की ऊर्वरता को बढ़ाती है। अतः चने की कृषि हेतु बहुत अच्छी भूमि अथवा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। चने की फसल भी अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख फसल है। मिर्जापुर जनपद में चने की सर्वाधिक कृषि की जाती है।

मटर-

यह भी रबी की एक महत्त्वपूर्ण फसल है। सामान्यतयः यह जौ और चने के साथ मिलाकर बोयी जाती है। फसलों की हेर-फेर द्वारा भूमि की ऊर्वरता बढ़ानें के लिए इसका विशेष उपयोग किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष १६६८-६६ में १२५३८५ हेक्टेयर क्षेत्र पर मटर की कृषि की गयी और १३०००४ मीट्रिक टन मटर का उत्पादन प्राप्त हुआ। जिसकी उत्पादकता १०. ३६ रही। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सारणी संख्या २. ०५ से स्पष्ट हैं।

राई/सरसों-

अध्ययन क्षेत्र से सभी जनपदों के कुछ भागों पर राई/सरसों की कृषि की जाती है। वर्ष १६६८-६६ में १०००७ मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन प्राप्त हुआ।

जायद की फसलें

फलों की कृषि-

इस अध्ययन क्षेत्र में वर्ष १६६८-६६ में १०६५२५ हेक्टअर भूमि पर फलों की कृषि की गयी थी। जिससें लगभग एक हजार टन फलों का उत्पादन हुआ।

जनपद स्तर पर मुख्य रवी फसलों की उत्पादकता का विवरण (कुन्टल / हेक्टेयर)

क्र०स०	जनपद	मटर उत्पादकता	
		वर्ष १९९७-९८	वर्ष १९९८-९९
१	फैजाबाद	११.५६	१२.०६
२	गोण्डा	११.६६	१०.८२
३	सुल्तानपुर	१०.५६	१८.५०
४	प्रतापगढ़	१०.१४	१२.६८
५	इलाहाबाद	१०.१६	१०.१६
६	वाराणसी	१२.५५	१३.३५
७	महराजगंज	१३.२०	१४.४७
८	सोनभद्र	१२.३४	१४.८७
९	बलिया	१२.३४	१३.०८
१०	गाजीपुर	१२.२४	१४.०२
११	मऊ	१२.१४	११.८०
१२	आजमगढ़	१२.०३	१३.६८
१३	बहराइच	११.३४	१६.०१
१४	मिर्जापुर	१२.६४	१३.८८
१५	जौनपुर	१२.२४	१३.१४
१६	बस्ती	१२.५५	१४.२६
१७	गोरखपुर	१३.१४	१४.४८
१८	देवरिया	१३.१४	१३.६२
१९	संतरविदास नगर	१२.१४	१३.७६
२०	बलरामपुर	१२.०४	१५.०३
२१	श्रावस्ती	१३.६७	१६.५०
२२	संतकबीरनगर	१०.३४	१२.१७
२३	चन्दौली	१०.७८	१२.६८
२४	कुशीनगर	१३.२०	१७.६५
२५	सिद्धार्थनगर	१३.३४	१३.६७
२६	अम्बेडकरनगर	११.१४	१३.५६

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकडे १९९८-१९९९ उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित

इस अध्ययन क्षेत्र में वर्ष १६६८-६६ में १०६५२५ हेक्टअर भूमि पर फलों की कृषि की गयी थी। जिससें लगभग एक हजार टन फलों का उत्पादन प्राप्त हुआ था। फलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में अमरूद , केला , नीबूं , आम जैसे फलों की कृषि विशेष रूप सें की जाती है।

सब्जियों की कृषि-

पूर्वी उत्तर प्रदेश में १६६८-६६ में लगभग २३६६४ हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों की खेती की गयी थी। जौनपुर एवं गोण्डा जनपद में सबसे अधिक सब्जियां बोयी गई थीं।

इस अध्ययन क्षेत्र में आलू का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। १६६८-६६ में इस क्षेत्र में ८६६३२ हेक्टेयर भूमि पर आलू की कृषि की गयी थी। जिससें लगभग २२३२३६२ लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। देखें सारणी संख्या २.०६।

कृषि में सुधार-

अध्ययन क्षेत्र के लगभग प्रत्येक जनपद में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। इसके मुख्य कारण सिंचाई के सुविधाओं की कमी है अधिकांश भागों में कृषि का वर्षा पर निर्भर होना तथा उन्नतशील बीजों एवं ऊर्वरकों का कम उपयोग है। उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा निम्न उपाय किये जा रहे हैं-

सारणी संख्या -२.०६

पूर्वी उत्तर प्रदेश

जनपद स्तर पर आलू के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन १६६८ -६६

क्र०स०	जनपद	आलू के अन्तर्गत क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन मीट्रिक टन	शीत गृहों की संख्या
१	फैजाबाद	५१४०	१००८२१	१०
२	गोण्डा	६४२६	१११५६२	१२
३	सुल्तानपुर	६५३१	१०७८२७	१०
४	प्रतापगढ़	७११६	१२३५०८	१३
५	इलाहाबाद	१७४०५	३६००११	१४
६	वाराणसी	२६८१	८६६५८	१६
७	महराजगंज	२१६६	४००११	१०
८	सोनभद्र	६७३	१२११४	१२
६	वलिया	७७१५	१७७६०८	११
१०	गाजीपुर	१०७६८	२३०६८७	१०
११	मऊ	२६०५	५३८०४	१२
१२	आजमगढ़	६३६५	११७८८८	१४
१३	बहराइच	३८२२	७७६८८	१०
१४	मिर्जापुर	२६८५	४८३३८	८
१५	जौनपुर	१०५३६	१६५१४१	१४
१६	वस्ती	५६१६	७०३०७	१६
१७	गोरखपुर	५२७६	६६०३८	१६
१८	देवरिया	२८६०	३५८०४	१४
१६	संतरविदास नगर	२६८४	४८३१२	१०
२०	बलरामपुर	३२१२	४६६१२	६
२१	श्रावस्ती	२८२४	४८२१०	८
२२	संतकबीरनगर	२६३०	४६२१२	६
२३	चन्दौली	३०२३	४५२१०	१०
२४	कुशीनगर	३२२४	४६२०१	१२
२५	सिद्धार्थनगर	३०१८	३७६८२	१०
२६	अम्बेडकरनगर	५१६७	१२७८७२	८

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकड़े १६६८-६६ उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित

क- प्रमाणित बीजों का वितरण-

प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ाने का विशेष महत्व है। सरकार द्वारा उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न फसलों के लिए अधिक से अधिक उन्नतशील बीजों का वितरण कराया जाता है। वर्ष १६६८-६६ में विभिन्न संस्थाओं द्वारा २२२४४६ कुन्तल धान, १८२२४ कुन्टल बाजरा , १०२२१ कुन्तल अरहर, ७८७२ कुन्तल ज्वार , ३०३२३४ कुन्तल गेहूं , ६८२०१ कुन्तल सरसों के सुधारे हुयें बीजों का वितरण किया गया।

ख- कृषि में खादों का प्रयोग-

किसी भी भूमि पर लगातार कई वर्षो तक लगातार कृषि करने से उस भूमि में कुछ पोषक तत्वों जैसे नत्र¯जन , पोटाश, फासफोरस आदि की कमी हो जाती है। इससे भूमि की ऊर्वराशक्ति क्षीण होती जाती है। इस कारण उस खेत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होती है। अध्ययन क्षेत्र के अनेक भागों में भू-उत्पादकता बहुत कम है। इसका एक उल्लेखनीय कारण यह है कि कृषकों द्वारा ऊर्वरकों का संतुलित उपयोग नहीं किया जाता है। यहां के कृषक या तो रसायनिक खादों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जो करते भी हैं उचित ज्ञान के अभाव में उनका ठीक उपयोग नही कर पाते।

सरकार द्वारा कृषि में रसायनिक खादों के साथ-साथ ही हरी खादों के उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। आज दूर संचार माध्यमों द्वारा खादों के उपयोग क़े महत्व का एवं उनके उचित उपयोग का प्रचार किया जाता है। सरकार उचित दर पर कृषकों को खादों का वितरण भी करवा रही है। जनपदवार ऊर्वरक का वितरण सारणी संख्या २. ०७ में दिखाया गया है।

सारणी संख्या -२.०७

पूर्वी उत्तर प्रदेश

उर्वरक वितरण (मीट्रिक टन)

क्र०स०	जनपद	नत्रजन	फास्फेस्टिक	पोटैशिक
१	फैजाबाद	६६४३८	१२७१६	१२७६
२	गोण्डा	३६५४७	५८७४	११६५
३	सुल्तानपुर	३०७७५	६२६७	६६३
४	प्रतापगढ़	२६००१	५५०६	४५८
५	इलाहाबाद	७६८६७	१४१०४	१७६४
६	वाराणसी	६४४५३	१५६०६	४६६०
७	महराजगंज	२६४०६	८२४६	१३६६
८	सोनभद्र	५३१२	२६६०	१६३
९	बलिया	३०४१७	४७६०	८८४
१०	गाजीपुर	४२६२२	६२२८	१५०४
११	मऊ	१८६६५	४१५८	४३०
१२	आजमगढ़	३२४६३	६८७१	६६२
१३	बहराइच	२८१४६	६२८२	६३१
१४	मिर्जापुर	१२४४२	६८०३	३०४
१५	जौनपुर	३५७८३	७५३६	७००
१६	बस्ती	४३६५४	४३४७	६५१
१७	गोरखपुर	४३१६६	१२३०३	३२७३
१८	देवरिया	७३३६८	१६३५३	४३३७
१९	संतरविदास नगर	४२१६३	१२३५१	८१०
२०	बलरामपुर	४०१६०	१८२२०	६४३
२१	श्रावस्ती	४१२३०	१६२२०	८४३
२२	संतकबीरनगर	४३२१३	१८२१०	६७०
२३	चन्दौली	३२१४६	१२२०१	८०७
२४	कुशीनगर	३१६०२	११०३२	६१०
२५	सिद्धार्थनगर	२८२२६	४०६२	३८४
२६	अम्बेडकरनगर	३०२१६	१६०१६	८०३

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकड़े १९९८-९९ उ०प्र० सरकार लखनऊ द्वारा प्रकाशित

फसली ऋण-

कृषि उत्पादन को बढ़ानें के लिए कृषकों को आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक एवं सहकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ताकि आर्थिक रूप में कृषकों को समय से कृषि हेतु धन प्राप्त हो सके।

बिक्री केंन्द्र-

किसानों की सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से अनेक क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र खोले गये हैं। जहां कृषकों द्वारा उत्पादित अनाजों को उचित मूल्य पर बेंचा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में लगभग हर एक ब्लाक या ग्राम स्तर पर एक-एक केन्द्र खोले गये हैं जो रबी एवं खरीफ की फसलों का क्रय करते हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कृषि के सुधार हेतु अनेक अन्य कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं और उनमें पर्याप्त सफलता भी मिली है यदि सरकार कृषि के प्रति इसी प्रकार ध्यान देती रहेगी तो अन्न का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायेगा।

ऊसर सुधार कार्यक्रम-

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से भूमि सुधार द्वारा वर्ष १९९२-९३ से प्रारम्भ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुल्तानपुर,

प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद जनपदों में ऊसर क्षेत्रों का सुधार करके उसमें खेती प्रारम्भ की जा रही है। इस परियोजना को और विस्तृत आश्रय देने का कार्यक्रम राज्य सरकार का है। इसमें प्रत्येक चार हेक्टेयर भूमि में पूर्णता निःशुल्क बोरिंग के साथ ही अनिवार्य रूप से नगद या ऋण से एक पम्पसेट की स्थापना की व्यवस्था भी है। इसके फलस्वरूप परियोजना ऊसर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सिचाई के अतिरिक्त स्रोत सृजित हो रहे हैं। यहां धान एवं गेहूं की अच्छी पैदावार हो रही है। इन क्षेत्रों में लगभग २२०० हेक्टेयर में बागवानी भी की जानी प्रारम्भ की गयी है। जिनमें आवंला, बेर, अमरूद, करौंदा तथा सुगंध एवं औषधियों युक्त फसलें भी सम्मिलित हैं। ऊसर सुधार की योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार को अधिक स्थायी तथा कृषकों के लिए आार्थिक रूप में अधिक लाभप्रद बनानें के साथ ही पर्यावरण संस्थान पर जोर देतें हुए अबकुल सुधारे जानें वाले ऊसर क्षेत्रों के ३० प्रतिशत हिस्से में अनिवार्य रूप से आधुनीकीकरण के साथ ही मिश्रित खेती को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

आधुनीकीकरण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में पौधों की आपूर्ति हेतु निजी पौधशाला की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ऊसर सुधार कार्यक्रमों में कृषकों की सार्थक सहभागीदारी का एक अभिनव प्रयोग और भी किया जा रहा है। इसके लिए चार-चार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों के समूह का गठन कर उन्हीं के माध्यम से सभी कार्य कराये जा रहे हैं। अनुदान की राशि इन समूहों के खातों मे ही जमा करायी जाती है जिसका बंटवारा समूह के सदस्य स्वयं ही करते हैं। इन समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे सम्बन्धित क्षेत्रों की उत्पादकता में २०० प्रतिशत सें भी अधिक की वृद्धि

हो जाने की सम्भावना है और प्रदेश में हरित क्रान्ति की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

पायलट ऊसर सुधार कार्यक्रम-

नीदरलैंण्ड़ सरकार की वित्तीय सहायता से आजमगढ़ जनपद में यह कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ प्रारम्भ किया गया है कि गांवोंमेंन केवल ऊसर भूमि सुधार बल्कि गांवों में अच्छी जमीन पर भी तकनीकी मार्ग दर्शन देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाय। इसके साथ-साथ मत्स्य पालन, तालाबों का पुनर्निर्माण, ग्राम समाज की जमीनों पर चारा एवं ईंधन हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि तथा कृषि योग्य बेकर भूमि का पर्याप्त प्रतिशत है। गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, फैजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर में भी भूमि का प्रतिशत अधिक है। इस भूमि को सुधारने का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। (तालिका संख्या २.०८)

सिंचाई-

वर्षा के अभाव में खेतों को कृत्रिम ढ़ंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत एक उष्ण कटिबंन्धीय देश है। जहां कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहती है। इस वर्षा की प्रकृति एवं वितरण में अनेक

सारणी संख्या -२.०८

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि अयोग्य एवं बेकार भूमि का प्रतिशत

क्र०स०	जनपद	ऊसर एवं कृषि अयोगय भूमि का प्रतिशत	कृषि योग्य बेकार भूमि का प्रतिशत
१	फैजाबाद	२.१४	२.८१
२	गोण्डा	१.१३	१.५०
३	सुल्तानपुर	३.८३	३.२०
४	प्रतापगढ़	३.००	२.४६
५	इलाहाबाद	४.३३	३.६५
६	वाराणसी	२.२५	१.१०
७	महराजगंज	-	-
८	सोनभद्र	-	-
९	बलिया	६.५६	१.०५
१०	गाजीपुर	२.०८	१.६५
११	मऊ	१.६६	१.७०
१२	आजमगढ़	२.३२	२.०२
१३	बहराइच	१.१६	१.३६
१४	मिर्जापुर	४०.३६	४.३६
१५	जौनपुर	२.१०	२.२५
१६	बस्ती	०.६७	२.०१
१७	गोरखपुर	०.८०	०.८२
१८	देवरिया	२.३०	१.१३
	पर्वी उत्तर प्रदेश	७.३५	२.७०

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकड़े १९९८-९९ उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित

कमियां पायी जाती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का अधिकांश भाग तीन महीनों अर्थात जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में ही प्राप्त होता है। वर्ष के अन्य महीनों में अत्यन्त अल्प वर्षा होती है अथवा नही होती है। ऐसी दशा में सिंचाई करना आवश्यक होता है। कई क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में भी अनिश्चितता पायी जाती है। किसी वर्ष तो अधिक मात्रा में वर्षा होती हैं तो किसी वर्ष बहुत कम वर्षा होती है। कभी तो समय से पहले ही वर्षा हो जाती है, परन्तु कभी देर से वर्षा होती है। वस्तुतः नियमित रूप से कृषि करने के लिए सिंचाई अनिवार्य हो जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अतः प्रतिवर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के भर-पोषण के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिक वृद्धि गहरी कृषि, कृषि क्षेत्र में विस्तार एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि से ही सम्भव है, और इसके लिए सिंचाई अनिवार्य साधन है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधन प्रयोग में लाये जाते हैं। जैंसे- नहरें, नलकूप, कूप, तालाब, और पोखरा इत्यादि।

नहरें-

नहरें बनाने के लिए उपयुक्त दो तथ्यों का होना आवश्यक होता है- समतल भूमि एवं नदियों में पर्याप्त जल का निरन्तर प्रवाह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग अधिकांश स्थानों पर ये दोनों ही सुविधायें उपलब्ध

सारणी संख्या -२.०६
पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें

क्र०स०	नहर	उदगम स्थल एवं सम्बधित नदी	लाभान्वित जनपद
१	निचली गंगा नहर	नरौरा (बुलन्दशहर) गंगा नदी	इलाहाबाद
२	शारदा नहर	वनवसा गोमती नदी	सुल्तानपुर ,आजमगढ़, प्रतापगढ, जौनपुर ।
३	घघरा नहर	सोन की सहायक नदी घघरा	मिर्जापुर एवं सोनभद्र
४	वेलनटोन्स नहर	रीवां वेलन नदी	इलाहाबाद
५	नगवा नहर	कर्मनासा नदी	मिर्जापुर एवं सोनभद्र
६	नैगढ़ बाँध नहर	नैगढ़ (गाजीपुर)	चन्दौली एवं गाजीपुर ।
७	चन्द्रप्रभा बाँध नहर	चकिया (वराणसी)	चकिया ,चन्दौली ।
८	वान गंगा वैयराज नहरें	शोहरतगढ़(बस्ती) वान गंगा	बस्ती ।
९	अहरौरा बाँध नहर	अहरौरा (वराणसी)	वाराणसी , मिर्जापुर ।
१०	गडंक नहर	बूढ़ी गड़क नदी (भारत नेपाल सीमा)	गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया ।
११	सरयू या घाघरा नहर	नानपारा (बहराइच) घाघरा नदी	बहराइच ,गोण्डा , बस्ती ।

स्रोत :- 'उत्तर प्रदेश'-२/११ए०स्वदेशी बीमा नगर ,उपकार प्रकाशन आगरा ।

सारणी संख्या -२.१०

पूर्वी उत्तर प्रदेश

वास्तविक सिंचित क्षेत्र(हेक्टेयर में) १९९८-९९

क्र०स०	जनपद	नहर	राजकीय नलकूप	निजी नलकूप	अन्य कूप	तालाब पोखर	अन्य साधन
१	फैजाबाद	३१७९३	१९३८४	१९४९८८	२६	२६	२७
२	गोण्डा	-	३४४९२	१४६८३४	४५०३	३३४९८	१८८४३
३	सुल्तानपुर	६८४२२	१५०७९	१२२२२२	३१७	१९४	८
४	प्रतापगढ़	७८८३७	१२७४	९१०४८	६६५	२९	४९
५	इलाहाबाद	१३६४५७	२६५७१	११५६६७	३८९५	२५२४	२२३७
६	वाराणसी	१२८८५१	४८६३८	९१७५४	११२३	१५७	१६६२
७	महराजगंज	५१४१६	६८९०	९०७३३	२८६	३५५१	५०७१
८	सोनभद्र	४१९४३	७५८	३५	३७२	८४७	२९१७
९	बलिया	३०६९६	१८०३७	१८२६४९	४८१	-	-
१०	गाजीपुर	४५११९	१८७३५	१४५५९४	४७३	१३८	६
११	मऊ	१४९९७	३९४८	९२८७७	२०२	३७	-
१२	आजमगढ़	४४३२४	५२९८	२१२०३४	१८१	१०४	१८
१३	बहराइच	११३७७	३३७७०	९१९९६	७६७७	५२१७	२६४५
१४	मिर्जापुर	९५३३४	११५९३	१२१६२	४१७२	१८७८	२७७७
१५	जौनपुर	६५३५९	८८८५	१३२३७१	४	१९४	२५
१६	बस्ती	५२७३	४४८६७	१३८३५८	६६५५	२०९७६	३०७८
१७	गोरखपुर	१३०६२	३२०४४	१४३३८३	६६५५	२०९७६	५३५७
१८	देवरिया	३१११२	२९२१०	९३८९५	५	८१	२६२
१९	संतरविदास नगर	१३३६२	२९२३०	१२२४४	१०	९२	१९७
२०	बलरामपुर	१८२२४	२५५२४०	११२३४	६३२	९२	२६७
२१	श्रावस्ती	२०४०२	२०३६०	१४२३३	७७८	११०	४०
२२	संतकबीरनगर	३२१३२	१९२३०	११२६४	११२१	७१०	१२३४
२३	चन्दौली	३६२३४	२१२३४	२१३२४	१२३४	७३२१	१२६४
२४	कुशीनगर	७९९६१	१४६२	५७५८३	५००१	२८१	२६२
२५	सिद्धार्थनगर	५०२७	९६९०	११७२७२	७०	१८८०	८२५३
२६	अम्बेडकरनगर	३२७१	९३२१	१२३४२१	८०	१२७२	२२४३

स्रोत :- १- उत्तर प्रदेश के कृषिगत आंकड़े १९९८-९९ उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकासित

DISTRIBUTION OF CANALS IN EASTERN UTTAR PRADESH
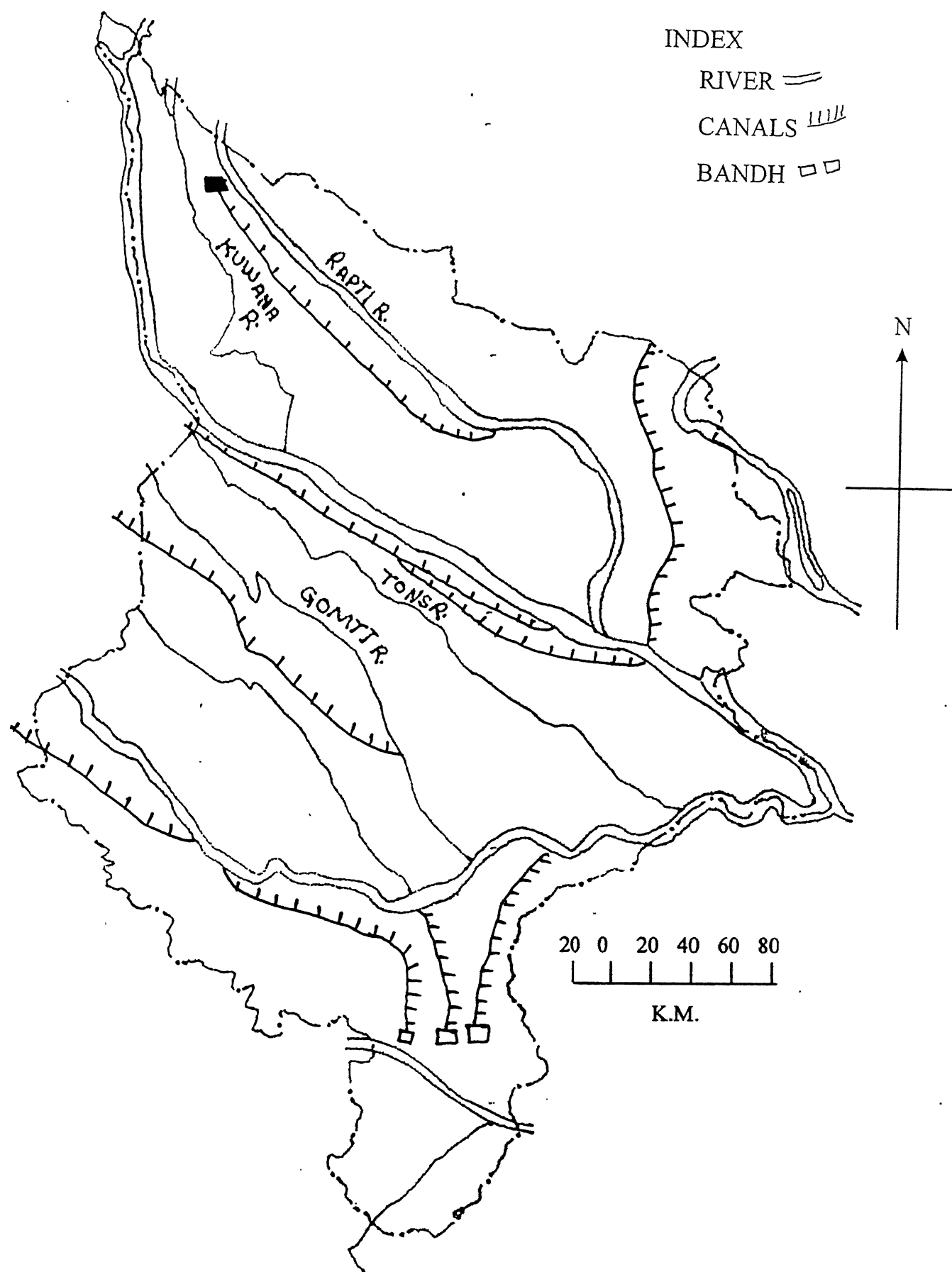
MAP No.- 1.02

हैं फिर भी इस क्षेत्र में नहरों का कम विकास हुआ है। नहरों एवं उनके उद्‌गम स्थलों का विवरण निम्न है। (सारणी संख्या २.०६)

नलकूप-

अध्ययन क्षेत्र में नलकूप सिंचाई का लोकप्रिय साधन है। कुछ नलकूप सरकार की ओर से लगाये गये हैं जबकि अधिकतर नलकूप किसानों ने निजी रूप से लगायें हैं।

जनपद की दृष्टि से वाराणसी जनपद में सबसे अधिक क्षेत्र पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती हैं। नलकूपों के माध्यम से सबसे कम क्षेत्र पर सोनभद्र जनपद में सिंचाई कार्य किया जाता हैं।

कुंओं द्वारा सिंचाई-

अध्ययन क्षेत्र में कुओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है। यहां लगभग ३७४१६ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर कुओं द्वारा सिंचांई होती हैं। कुओं द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बहराइच जनपद में की जाती है।

अन्य साधन-

अध्ययन क्षेत्र में अन्य साधनों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। जिसमें तालाब तथा पोखर प्रमुख हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ६५२५६६१ हजार हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि योग्य है। जबकि ६२४४००६ हजार हेक्टेयर भूमि ही सिंचित है। इस प्रकार इस क्षेत्र में केवल ६५.५५ प्रतिशत कृषि भू-भाग पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न जनपदों की दृष्टि से वाराणसी जनपद का सबसे अधिक कृषि क्षेत्र सिंचित हैं। अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग में सिंचाई के साधनों का समुचित विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र अभी भी सिंचाई की सुविधाओं से वंचित हैं और वहां कृषक वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों मे कृषि उत्पादन भी कम प्राप्त होता हैं।

वर्तमान समय में तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या के भरण-पोषण के लिये कृषि द्वारा अधिक से अधिक खाघान्न उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनो के मामले में भी पिछड़ा हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में जो भी उघोग विकसित हुयें हैं वे कृषि पर आधारित हैं। अतः कृषि से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हैं। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं में वृध्दि होना आवश्यक है। यघपि विगत वर्षो में सिंचाई के साधनों मे विकास पर बल दिया गया हैं। फिर भी वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र की कुल कृषि भूमि के केवल ६० प्रतिशत भू-भाग में ही सिंचाई सुविधायें प्राप्त हो सकी हैं। अतः इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों में वृध्दि आवश्यक है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास मे गतिशीलता लाने के उद्देश्य से कृषकों को निजी लघु सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

परिवहन एवं संचार

आधुनिक युग में परिवहन का विशेष महत्व है क्योकि प्राचीन युग की तुलना में आज मनुष्यों एवं पदार्थों की गतिशीलता का अधिक महत्व है। आर्थिक संगठन का प्रारम्भिक युग आत्मनिर्भरता का युग था। उस समय मनुष्यों एवं पदार्थों कें स्थानान्तरण की आवश्यकता कम थी या होती ही नहीं थी। आज की आर्थिक व्यवस्था व्यापार प्रधान है, जिसमें मनुष्यों एवं पदार्थों के तीव्र गति से स्थानान्तरण की अधिक आवश्यकता होती है। साथ ही साथ विचारों के आदान-प्रदान में तीव्रता अपेक्षित है। आधुनिक युग में परिवहन के विस्तार और उसकी शीघ्रता ने ही विश्व के सुदूर स्थित देशोंके निवासियों से सम्पर्क स्थापित करके व्यापार की प्रगति को सम्भव बनाया हैं। इस प्रकार हम आज की अर्थव्यवस्था को परिवहन पर आधारित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। औद्योगिक अवस्थिति के तत्वों में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है।(स्मिथ, डी० एम० १९७१ पृष्ठ ६६) क्योंकि यह कच्चे माल को एकत्रित करने एवं उसे परिष्कृत कर अधिक मूल्य वाले तैयार माल के वितरण में महत्वपूर्ण है।(कोस, बी० सी०१९४५ पृष्ठ ३) विश्व में जापान की आर्थिक शक्ति की मजबूती के पीछे सस्ता, आधुनिक एवं कार्यकुशल परिवहन ही प्रमुख हैं। जबकि उसके पास न तो अधिक कच्चा माल है और न ही बाजार।(कोल्ब, ए० १९७१ पृष्ठ ४८४-५२२)

अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ उत्पन्न होने वाली फसलों से प्राप्त उत्पादनों को बिक्री केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है। फलों एवं सब्जियों को तो शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाया जाता है। यह सब कार्य परिवहन के बिना सम्भव नही है। अध्ययन क्षेत्र खनिज पदार्थों

TRANSPORT MAP OF EASTERN UTTAR PRADESH

Fig: 2.06
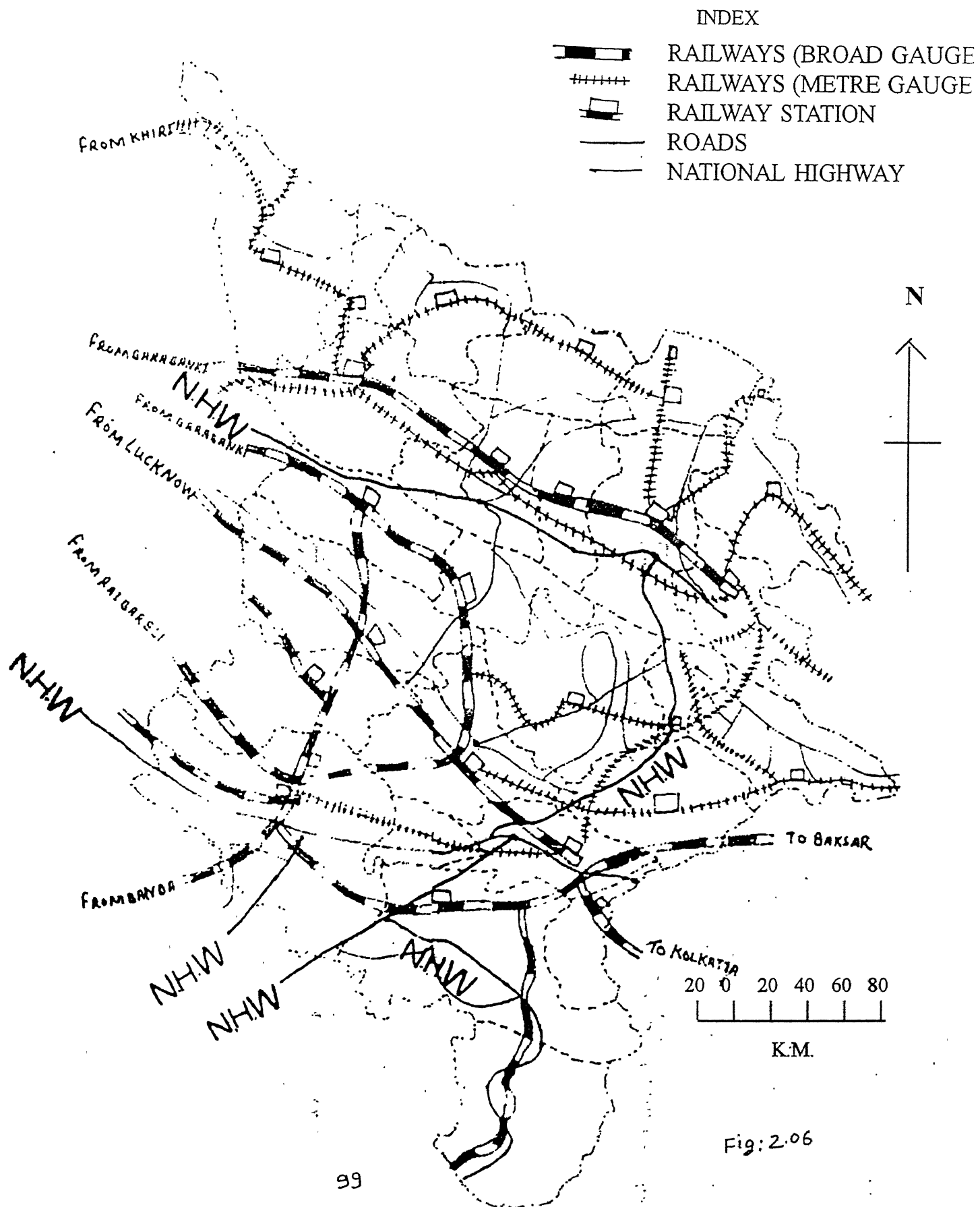
की दृष्टि से सम्पन्न नही हैं। अतः तत्सम्बन्धी उधोग धन्धों के लिए अधिकांश कच्चा माल देश के अन्य भागों मे आयात करना पड़ता है और उसको कारखानों तक लाने एवं तैयार माल को अन्य भागों को भेजनें के लिए परिवहन की विशेष आवश्यकता होती है।

परिवहन के प्रकार-

अध्ययन क्षेत्र में थल, जल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन साधनों का न्यूनाधिक विकास हुआ हैं। इन परिवहन के मार्गों का पृथक-पृथक विवरण निम्नवत् है-

थल परिवहनः-

इस प्रकार के परिवहन में सड़कें तथा रेलमार्ग प्रमुख हैं।

सड़क मार्गः-

थल मार्गों में सड़कें सबसे प्राचीन हैं। अध्ययन क्षेत्र के सभी भागों में इसका विकास हुआ है। यहाँ अन्य परिवहन मार्गों की अपेक्षा सड़क मार्ग का अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में कच्ची व पक्की सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। पक्की सड़कों की सुविधा अधययन क्षेत्र के थोड़े ही भागों पर है। जबकि अधिकांश सड़के कच्ची हैं। अधिकांश गांव एवं बाजार कच्ची सड़कों एवं पगडन्ड़ियों सें जुड़े हैं। इन कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरें आदि चलने में बहुत असुविधा होती है। वर्षा ऋतु में कीचड़ एवं शुष्क ऋतु में धूल के कारण इन पर यातायात में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन

क्षेत्र से ६ राष्ट्रीय राजमार्ग- राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर २, नम्बर ७, नम्बर २७, नम्बर २८, नम्बर २६, नम्बर ५६ होकर गुजरते हैं। जिनकी कुल लम्बाई उत्तर प्रदेश मे १५८७ कि० मी० है।

रेल मार्गः-

रेल परिवहन ने मानव संसाधनों एवं माल को शीध्रता से ढोनें की सुविधा प्रदान कर औघोगिकरण को विशेष बल प्रदान किया है। लम्बी दूरी तय करने के लिए रेल परिवहन बहुत ही उपयोगी एवं सस्ता साधन है। अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में रेल मार्गों का विकास हुआ है। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी इसका विकास नही हो पाया है।

जल परिवहनः-

जल परिवहन प्राचीन समय से लोकप्रिय रहा है। बड़ी मात्रा में माल ढोनें एवं यात्रियों को ले जाने में जल परिवहन का विशेष महत्व रहा है। जल परिवहन की मुख्य विशेषता यह है कि यह अन्य परिवहन मार्गो की तुलना मे सस्ता होता है क्योकि इसके रखरखाव एवं निर्माण में व्यय नही करना होता है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में गंगा, राप्ती, घाघरा आदि बड़ी नदियां स्थित हैं तथापि इस समय यहां जल परिवहन का बहुत कम विकास दृष्टिगत है। हाल के वर्षों में हाल्दिया से इलाहाबाद तक के गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया गया है। जिसमें कलकत्ता से इलाहाबाद के बीच माल का परिवहन नदी मार्गों से होने लगा है। घाघरा नदी को नब्य बनाने का प्रयास किया जा रहा

है। इस क्षेत्र में कही-कहीं थोड़ी-थोड़ी दूर जाने के लिये ही जल परिवहन का सहारा लिया जा रहा है।

वायु परिवहनः-

यह अत्यन्त तीव्रगामी परिवहन साधन है। इस प्रकार के परिवहन द्वारा समय की काफी बचत होती है। लेकिन यह बहुत मंहगा परिवहन साधन है। अध्ययन क्षेत्र के इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, फैज़ाबाद जनपदों में एक-एक हवाई अड्डे हैं। जहां से प्रदेश एवं देश के विभिन्न मार्गों तक जानें की सुविधा उपलब्ध है।

अध्ययन क्षेत्र के परिवहन मानचित्र संख्या २.०४ पर दृष्टिपात ड़ालने से स्पष्ट होता है कि यहां परिवहन साधनों का कम विकास हुआ है। गांवों को मिलाने वाली अधिकांश सड़के कच्ची हैं। जो वर्षा ऋतु में आवागमन के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। आधुनिक युग में परिवहन का समुचित विकास किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ग्रामीण परिवहन में सुधार हेतु सर्वप्रथम सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता है इसी प्रकार वायु एवं जल परिवहन के विकास के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए।

संचार व्यवस्थाः-

आधुनिक युग में संचार के साधनों का भी विशेष महत्व है। अध्ययन क्षेत्र में संचार साधनों का पर्याप्त विकास नही हो सका है। इस क्षेत्र में कुल ८४३४ डाकखाने २३६६ तारघर एवं ५२४ टेलीफोन केन्द्र हैं।

अतःइस क्षेत्र में संचार व्यवस्था में सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है। तारघरों एवं टेलीफोन केन्द्रों का अधिक विकास होना चाहिए। जनपदवार संचार व्यवस्था का विवरण सारणी संख्या २.११ में दिया गया है।

विद्यु तीकरणः-

आधुनिक युग में अनेक विद्युत चलित मशीनें एवं उपकरण उपलब्ध हैं जिनका कृषि कार्यों एवं विभिन्न उद्योगों में प्रयोग करके कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक विधियों का बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र का आज भी समुचित विकास नही हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां विभिन्न जनपदों के कुछ भाग आज भी विघुत सुविधा से वंचित हैं।

विघुत की आपूर्ति भी नियमित एवं संतोषप्रद नहीं है। नये विघुत शक्ति गृहों का निर्माण कर विघुत व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी को दूर करनें के लिए गोबर गैंस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है।

सारणी संख्या -२.११

पूर्वी उत्तर प्रदेश

जनपदवार संचार व्यवस्था का विवरण - १९९८

क्र०स०	जनपद	डाकखानो की संख्या	तारघरों की संख्या	टेलीफोन केन्द्रां की संख्या
१	फैजाबाद	६४६	१५५	४०
२	गोण्डा	५०३	१५५	२८
३	सुल्तानपुर	४८२	८३	२८
४	प्रतापगढ़	३५०	७३	२१
५	इलाहाबाद	५४८	१३५	४१
६	वाराणसी	५३०	१३७	४३
७	महराजगंज	२१५	५६	१४
८	सोनभद्र	१४४	१३	१७
९	बलिया	३४६	१३३	२६
१०	गाजीपुर	३७६	१२६	२२
११	मऊ	२०४	५६	१७
१२	आजमगढ़	३९५	६६	३१
१३	बहराइच	३७५	८४	२४
१४	मिर्जापुर	१९४	४७	१७
१५	जौनपुर	४२४	६६	२६
१६	बस्ती	४६३	१०६	२१
१७	गोरखपुर	३८७	१४०	२३
१८	देवरिया	४६४	२१०	१३
१९	संतरविदास नगर	२००	५०	१०
२०	बलरामपुर	२१०	१००	१५
२१	श्रावस्ती	१००	८०	२०
२२	संतकबीरनगर	११०	९०	१०
२३	चन्दौली	२००	६०	४४
२४	कुशीनगर	२००	११०	४०
२५	सिद्धार्थनगर	२१५	१४०	१६
२६	अम्बेडकरनगर	१२०	१३०	१५
	योग	८४३४	२६४०	६२२

स्रोत :- सांख्यिकीय हैण्डबुक -१९९८

EASTERN U.P. STAGE OF COMMUNICATIONFACILITIES 1998-99
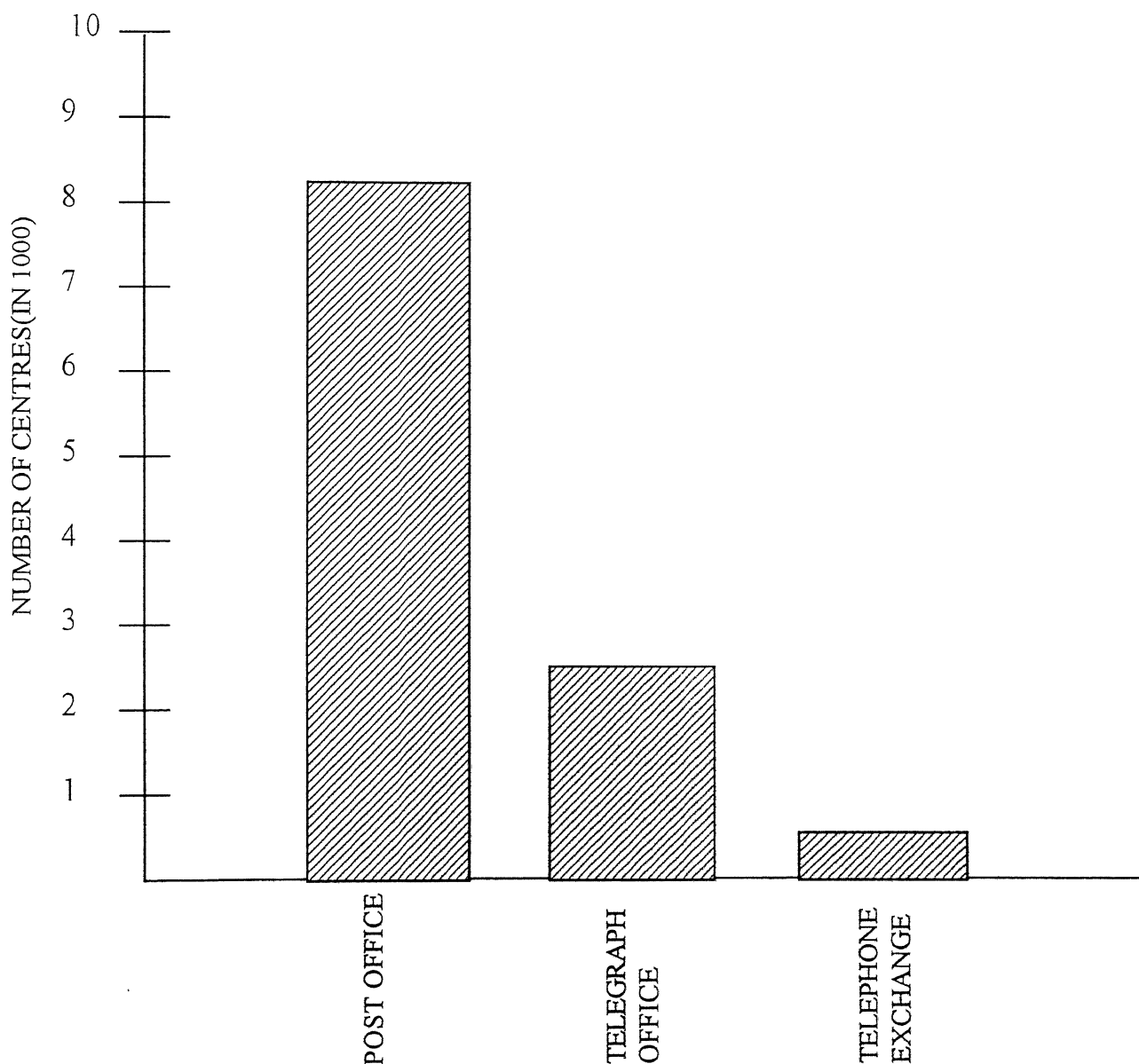
FIG. NO-2.07

References

1- Alexander .J I and Gibson : L I (1979), Economic Geography .N.I. U.S.A

2- Ghose B.C. (1945) , Industrial Location ,Oxford Panchcel on India Affairs No. 32 London

3- Kumar P; and Gautam(1997)- Industrial Geography Jaipur.

4- Kaushik .S.D. (1995) Principles of Economic Geography (9th ed.) Rastogi and Co. Meerut.

5- Kaushik .S.D. (1995) , Geography of Resources (IInd ed.) Rastogi and Co. Meerut.

6- Kolb, A(1971), East Asia – Geography of Cultural Region,Methuen and Co. London .

7- Mamoria . C. and Gautam (1998) : Geographyof India . Sahitya Bhavan Prakation,Agra.

8- Royan , Von. W. and Bengston N.A. (1971) Fundamental of Economic Geography . Prentice Hall.

9- Spengler , J.I. (1961) , Natural Resources and Economic Growth . U.S.A.

10- Stringer .F. and Davis J.S. (1966) Geography of Resources World Survey and British Isles London .

11- Symons ,L. (1967) Agricultural Geography . London .

12- Singh, R.B.(1963); Road Traffic Flow in U.P. . N.G.N I,Vasanasi .

13- Singh, K.N.(1990); Transport Network in Rural Development , Daudpur Gorakhpur .

14- Singh, K.N.and Singh .J. (1999); Economic Geography , Gyanodaya Prakason,Gorakhpur .

15- Smith , D.M.(1971); Industrial Location,John Wiley and Sons,New York .

16- Thoman, R.S. , Conkling E.C. and Yeates ,M.H. (1968) ; Geography of Economic Activity,Mc. Graw Hill.

17- Wills , K.G.(1969) ;Transport in Rural Areas Methuen and Co. London .

18- Wilson , A.G. (1967) ; A Statistical Theory of Spatial Distribution Models Transportation Research .

19- Zimmermann, W.E. (1951) ; World Resources and Industries ,Harper and Row, U.N. Publication .
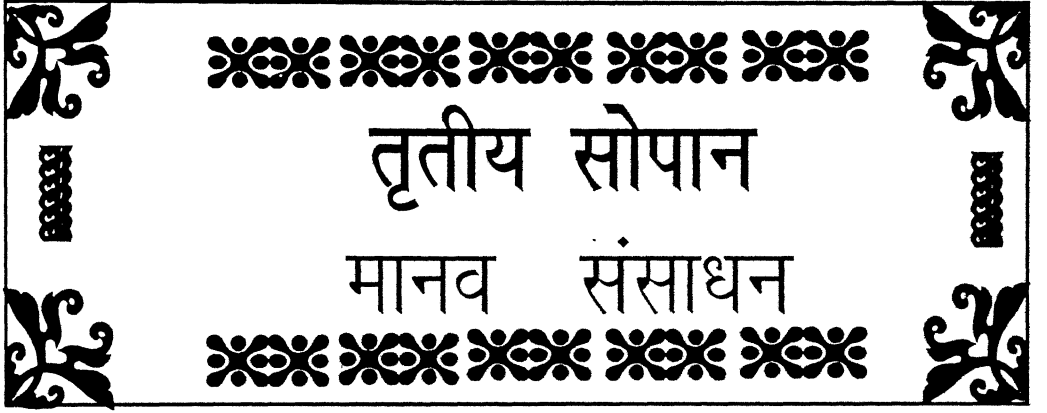
तृतीय सोपान
मानव संसाधन

मानव संसाधन

सामान्य परिचय-

किसी भी प्रदेश के संसाधनों के बहुमुखी उपयोग एवं विकास में मानव संसाधन या जनसंख्या का विशेष महत्त्व है।(मामोरिया एवं जैन २००१ पृष्ठ ३५०) किसी भी देश में शिक्षा या सैन्य सेवा, सामाजिक कार्य, कृषि एवं औद्योगिक विकास, यातायात विकास, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार, आवास निर्माण, मनोरंजन आदि कार्यक्रमों या उपक्रमों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिये इस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनंसख्या के आकार एवं सरंचना प्रकार का पूर्ण ज्ञान होना तथा सामान्य विकास क्रियाओं को नियोजित करते समय उसके यथोचित उपयोग पर ध्यान देना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा उस देश की प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक उन्नति भी वहाँ पायी जाने वाली जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व एवं वहाँ के लोगों की कार्यकुशलता पर निर्भर है।(मामोरिया एवं जैन २००१ पृष्ठ ३५०) जनसंख्या एक प्रमुख संसाधन है जिसके समुचित एवं वैज्ञानिक उपयोग से किसी क्षेत्र की काया पलट की जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की विशेषताओं के विश्लेषण का प्रयास किया गया है।

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति-

समकालीन विश्व की सबसे बड़ी समस्या सीमित संसाधनों के अनुपात में वृहदाकार जनसंख्या एवं उसकी अप्रत्याशित वृद्धि है। जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या परिवर्तन दर एवं नागरिकों एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। (Zelinsky, 1966). जनसंख्या वृद्धि आज विश्व की प्रमुख समस्या बन गयी है एवं विकासशील देशों की तो यह सबसे बड़ी त्रासदी बन गयी है जिससे सम्पूर्ण विकास की गति अवरुद्ध हो गयी है। अध्ययन क्षेत्र भी जनसंख्या वृद्धि की इसी समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है जिससे उसका आर्थिक एवं सामाजिक विकास प्रभावित होता है। यदि इस वृद्धि को चिकित्सा तकनीक द्वारा रोका न गया तो यह एक समस्या बन जायेगी।(Kosinski , L.A.)

सारणी संख्या -३.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनपदवार जनसंख्या का वितरण -२००१

क्र०स०	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या २००१	जनघनत्व (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या वृद्धि(प्र०में) (१९९१-२००१)
१	फैजाबाद	२७६२	२०८७६१४	७५५	२३.८७
२	गोण्डा	४४२०	२७६५७५४	६२५	२५.४६
३	सुल्तानपुर	४४३६	३१९०९२६	७१९	२४.२०
४	प्रतापगढ़	३७१७	२७२७१५६	७३४	२३.३६
५	इलाहाबाद	५४२२	४९४१९०	९११	२६.७२
६	वाराणसी	१५७८	३१४७९२७	१९९५	२५.५१
७	महराजगंज	२९५१	२१६७०४१	७३४	२६.२७
८	सोनभद्र	६७८८	१४६३४६८	२१६	३६.१३
९	बलिया	२९८१	२७५२४१२	९२३	२१.६७
१०	गाजीपुर	३३७७	३०४९३३७	९०३	२६.१८
११	मऊ	१७१३	१८४९२९४	१०८०	२७.९१
१२	आजमगढ़	४२३४	३९५०८०८	९३८	२६.२८
१३	बहराइच	५७९९	२३८४२३९	४१५	२९.५५
१४	मिर्जापुर	४५२२	२११४८५२	४९८	३७.६२
१५	जौनपुर	४०३८	३९११३०५	९६९	२१.६७
१६	बस्ती	३०३५	२०६८९२२	६८२	२२.६९
१७	गोरखपुर	३३२५	३७८४७२०	१०४०	२३.४४
१८	देवरिया	२५३५	२७३०३७६	१०७७	२५.०३
१९	संतरविदास नगर	१०५६	१३५२०५६	१४०९	३५.४७
२०	बलरामपुर	२९२०	१६८४५६७	५७६	२३.०८
२१	श्रावस्ती	११२६	११७५४२८	१०४४	२७.३०
२२	संतकबीरनगर	१४४१	१४२४५००	९८८	२३.६४
२३	चन्दौली	२५५०	१६३९७७७	६६२	२८.६३
२४	कुशीनगर	२९१०	२८९१९३३	९९४	२८.१७
२५	सिद्धार्थनगर	२७५०	२०३८५९८	७४१	२६.७८
२६	अम्बेडकरनगर	२३७०	२०२५३७३	८५४	२४.३१

स्रोत :- १- जनसंख्या सेन्सस, जनगणना विभाग (उ०प्र०) लखनऊ द्वारा प्रकाशित

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति मुख्यतः धनात्मक रही है। इस क्षेत्र में १९९१ से २००१ तक के मध्य जनसंख्या में ४३.५६ प्रतिशत की वृद्धि थी जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश एवं भारत की जनसंख्या वृद्धि २५.८० एवं २४.० प्रतिशत से काफी अधिक है। किसी भी पिछड़े या विकासशील प्रदेश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है तथा उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता के निम्नस्तर, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, रूढ़िवादी विचारधारा आदि के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है तथा कृषकों में शिक्षा की कमी के कारण यहाँ प्राचीन विधि से कृषि की जाती है जिसमें मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है ऐसी स्थिति में जन्मदर ऊँची होने के कारण भी जनसंख्या दर में तीव्र वृद्धि हुई है। गरीबी भी अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति में सहायक रही है 'वर्ल्ड डेवलेपमेण्ट रिपोर्ट' १९८४ में कहा भी गया है कि 'गरीब माता-पिताओं के लिये बच्चों की परवरिश की लागत नीची होने के ठोस कारण हैं। जबकि बच्चों से लाभ ज्यादा है, इस लिये ज्यादा बच्चे होना आर्थिक दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण है। अध्ययन क्षेत्र में यह प्रवृत्ति नीचे वर्ग के परिवारों में देखने में आती है। अध्ययन क्षेत्र के सभी जनपदों में जनसंख्या वृद्धि दर समान नही है। (सारणी संख्या ३.०१) सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर सोनभद्र जनपद में ३६.१३ प्रतिशत रही तथा बलिया जनपद में २१.६७ सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार अध्ययन क्षेत्र को निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं-

१. न्यून जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत २५ प्रतिशत से कम जनसंख्या वृद्धि वाले जनपद आते हैं। इसमें १० जनपद सम्मिलित हैं। बलिया २१.६७, जौनपुर २१.६७, प्रतापगढ़ २३.३६, बस्ती २२.६६, फैजाबाद २३.८७, गोरखपुर २३.४४, सुलतानपुर २१.२०,बलरामपुर २३.०८, सन्तकबीरनगर २५.६४, अम्बेदकरनगर २४.३१ जनपद इस वर्ग में आते हैं। सारणी संख्या ३.०१ मे जनसंख्या वृद्धि जनपदवार स्पष्ट है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन

POPULATION GROWTH IN EASTERN U.P.
(1971-2001)
POPULATION (IN KAROR)
6
5
4
3
2
1
1971
1981
1991
2001
YEARS
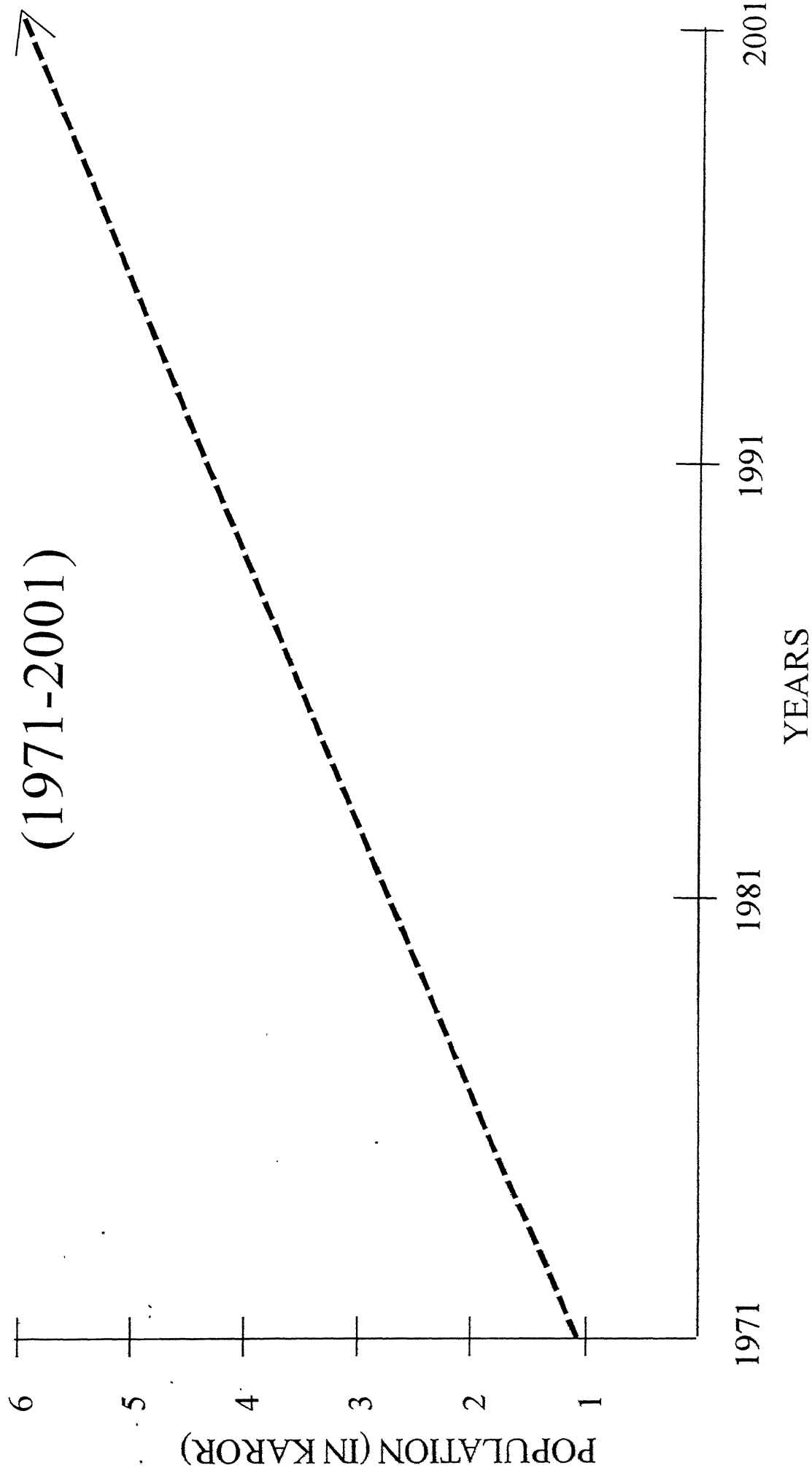
Fig. No-3.01

भागों से दूसरे क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानान्तरण भी होता रहा है। सिंचाई के साधनों की कमी, अशिक्षा, वैज्ञानिक विधि से कृषि न किये जाने के कारण सामान्य कृषि द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इन जनपदों में उद्योगों का भी यथोचित विकास नहीं हो पाया है अतः यहाँ रोजगार के अवसर कम होने के कारण बहुत से निवासी रोजगार खोज में अन्य क्षेत्रों में मुम्बई, दिल्ली, पंजाब आदि राज्य चले जाते हैं।

२. मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत २५ प्रतिशत से २८ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र आते हैं। इलाहाबाद २६.७२, वाराणसी २५.५१, गाजीपुर २६.१८, गोण्डा २५.४६, मऊ २७.६१, आजमगढ़ २६.२८, देवरिया २५.०३, श्रावस्ती २७.३०, सिद्धार्थनगर २६.७८ प्रतिशत जनपद इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। वृद्धि की दरें कोष्ठक में दी हुई हैं। इस क्षेत्र में निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों की तुलना में कृषि एवं लघु उद्योगों का विकास अधिक हुआ है।

३. अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत २८ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र आते हैं। इस वर्ग में महाराजगंज २९.२७, बहराइच २९.५५, चन्दौली २८.६३, कुशीनगर २९.०१, सन्तरविदासनगर ३५.४७ तथा सोनभद्र ३६.१३ प्रतिशत जनपद आते हैं। इन जनपदों में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विकास अधिक हुआ है तथा जनसंख्या स्थानान्तरण कम हुआ है। रेखाचित्र ३.०१ से अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर स्पष्ट है।

जनसंख्या का वितरण एव घनत्व-

मानव एवं भूमि मानव समाज के प्रमुख अंग है। कितनी भूमि पर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, के मौलिक अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व की संकल्पना में मानव और भूमि के बीच सम्बन्ध को दर्शाते हैं जो कि सम्पूर्ण क्षेत्र की कुल जनसंख्या में सम्पूर्ण

क्षेत्रफल का गणितीय अनुपात है। (डिमकोजी १६७० पृष्ठ २२) ट्रिवार्था ने भी इसी सम्बन्ध में लिखा है- सभी भौगोलिक तथ्यों में जनसंख्या वितरण भौगोलिक अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। प्राकृतिक भूदृश्य के सहयोग से मानव सांस्कृतिक भृदृश्य का निर्माण करता है जो कि त्रिभुज के सबसे ऊपरी भाग पर है जबकि आधार पर भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है। (ट्रिवार्थ १६५३ पृष्ठ ७१-७६) क्लार्क (१६७६) ने भी यह स्पष्ट किया है कि जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के लिये जनसंख्या का आकार एवं घनत्व तथा उसकी विषमता का अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। भौतिक, सामाजिक, प्रजातान्त्रिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के सम्बन्ध में इसकी व्याख्या करना भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख कार्य है।

अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी घना बसा हुआ है (मानचित्र ३.०१) जहाँ २००१ में भारत में जनघनत्व ३२४ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है तथा उत्तरप्रदेश राज्य में ६८६ व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व ७३४ व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। यदि अध्ययन क्षेत्र की केवल ग्रामीण जनसंख्या पर दृष्टिपात किया जाय तो स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व ५६६ व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। यह घनत्व सभी जनपदों में भिन्न-भिन्न है। इसका प्रमुख कारण है कि इन जनपदों में उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ मैदान समतल है जो कृषि कार्य के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है। अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग पर कृषि के आधार पर अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता है। इसके अलावा प्रशस्त समतल भूमि, यातायात के अन्य साधनों का विकास उपयुक्त जलवायु, स्वच्छ जल की प्राप्ति आदि इसके कारण हैं। जो इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के लिये सहायक है। मानचित्र संख्या ३.०२ में अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है तथा रेखाचित्र संख्या ३.०२ में जनपदवार जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित है। इसको सारणी संख्या ३.०१ में भी दिखाया गया है।

जनसंख्या घनत्व के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है।

DISTRIBUTION OF POPULATION IN
EASTERN U.P. -2001
N
20 0 20 40 60 80
K.M.
1 POINT =25 THOUSAND
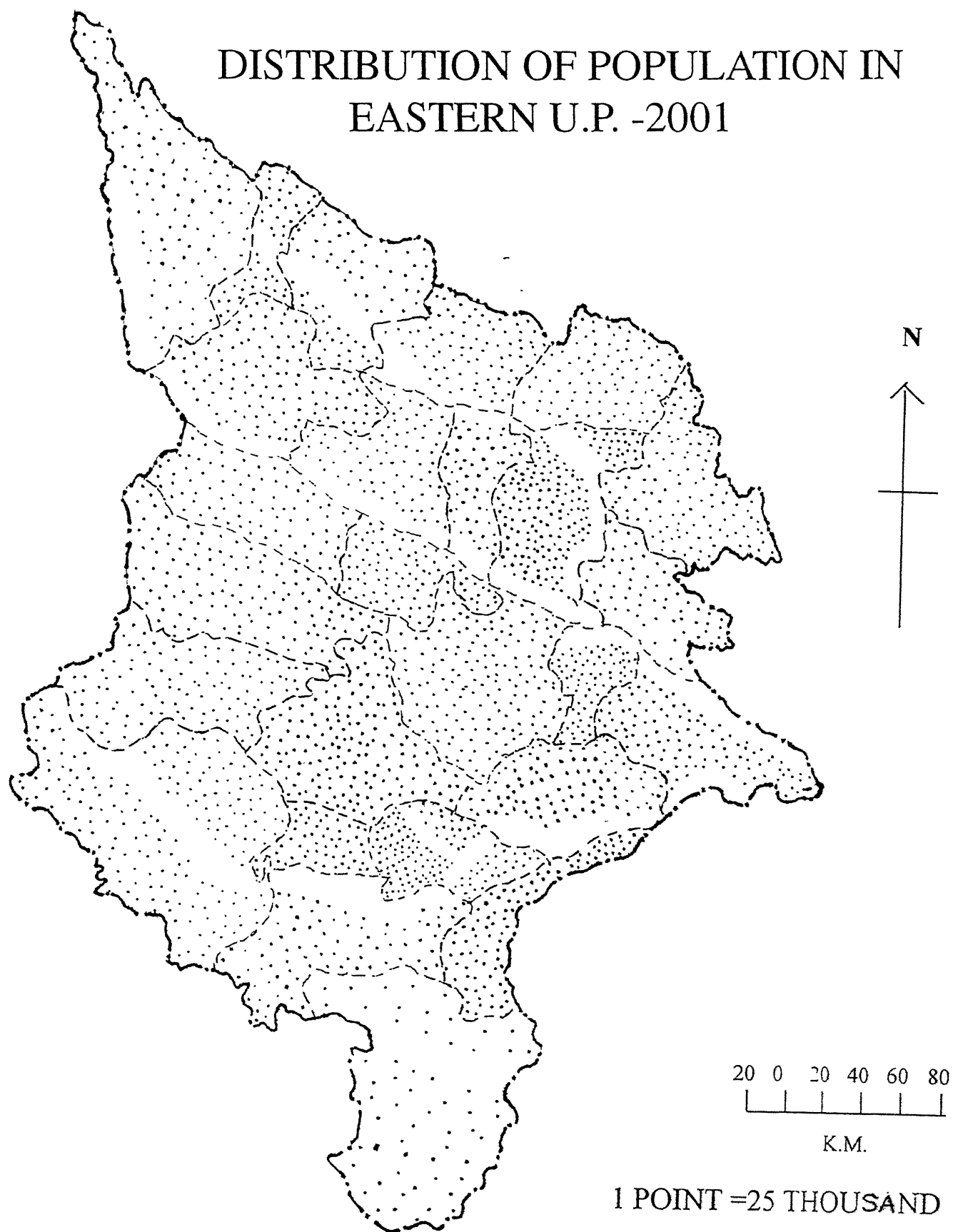
MAP No-3.01

POPULATION DENSITY IN EASTERN U. P. - 2001

MAP No.- 3.02
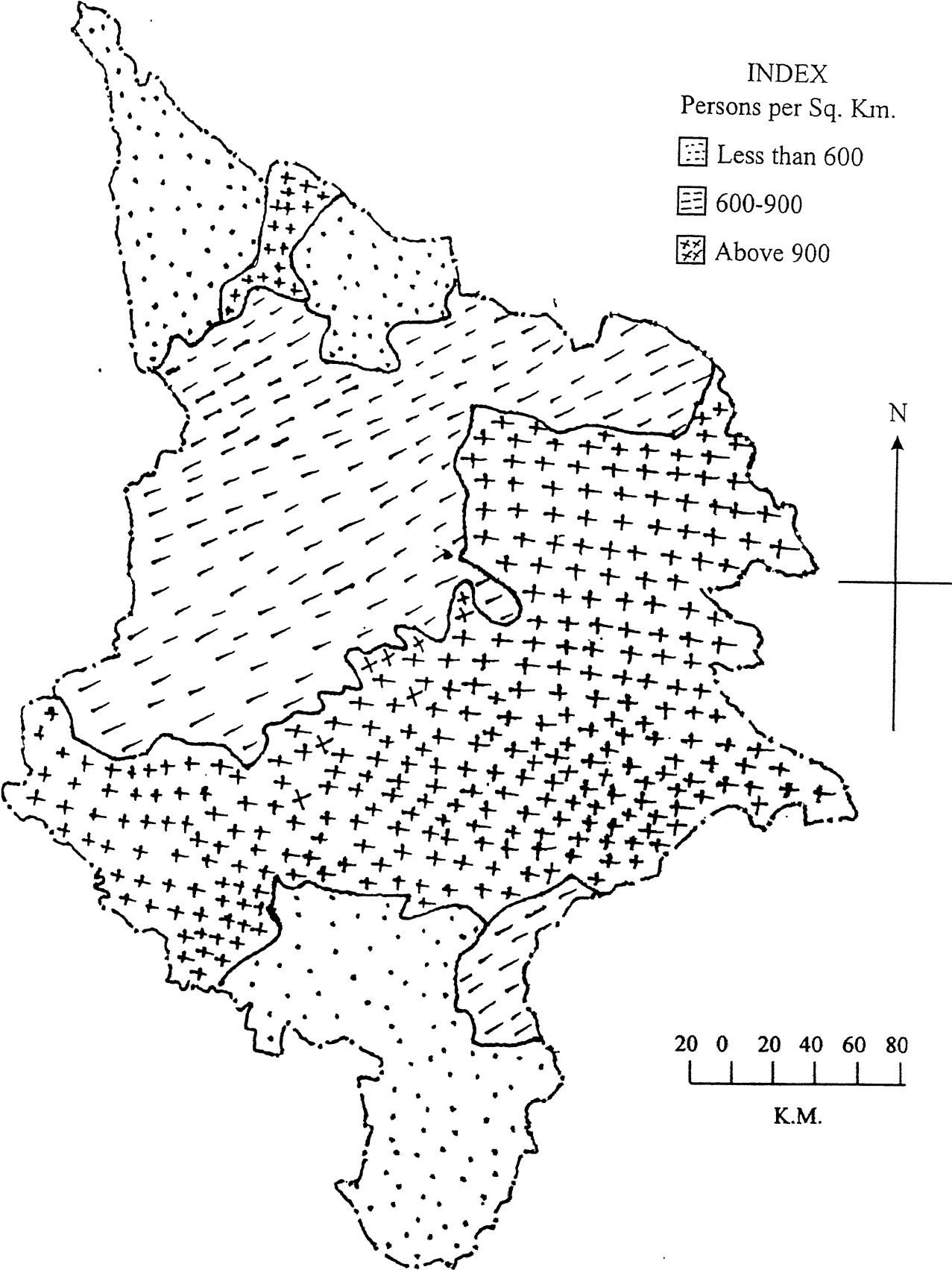
१. न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत उन जनपदों को लिया गया है जिनका जन घनत्व ६०० व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी से कम है। बहराइच ४१५, मिर्जापुर ४६८, बलरामपुर ५७६, तथा सोनभद्र २१६ है।

२. मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत ६०० से ९०० व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी जनसंख्या घनत्व वाले जनपद आते हैं। फैजाबाद ७५५, अम्बेदकरनगर ८५४ प्रतापगढ़ ७३४, सुल्तानपुर ७१६, गोण्डा ६२५, सिद्धार्थनगर ७४१, बस्ती ६८२, महाराजगंज ७३४, चन्दौली ६६२ जनपद इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

३. अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र-

इस वर्ग के अन्तर्गत ९०० व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० से अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। गोरखपुर ११४०, वाराणसी १९९५ तथा सन्त रविदास नगर १४०६, श्रावस्ती १०४४, सन्तकबीर नगर ९८८, कुशीनगर ९९४, देवरिया १०७७, आजमगढ़ ९३८, मऊ १०८०, बलिया ९२३, जौनपुर ९६६, गाजीपुर ९०३। इस वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। रेखाचित्र ३.०२ में जनपदवार जनसंख्या घनत्व स्पष्ट है।

लिंग अनुपात-

जनसंख्या के समस्त गुणों में लिंग संरचना सबसे मूलभूत तथा मानवता को उत्पन्न करने में शक्ति, मृत्यु एवं विवाह से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। (यूनाइटेड नेशन १९७३)। स्त्री एवं पुरुषों की संख्या में सन्तुलन एवं असन्तुलन पर कई सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध आधारित हैं।(ट्रिवार्थ १९६९ पृष्ठ ११४)

जनसंख्या संरचना में असमानता का अध्ययन भूगोलवेत्ताओं हेतु रुचिकर होता है क्योंकि स्त्रियों एवं पुरुषों की भूमिका आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूरक होती है। क्लार्क (१९७६)।

लिंग अनुपात किसी क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक आर्थिक दशाओं का सूचक होता है और प्रादेशिक विश्लेषण के लिये उपयोगी साधन होता है। लिंग अनुपात के अध्ययन से रोजगार व उपयोग का प्रतिशत, सामाजिक आवश्यकतायें और किसी जाति की मनोवैज्ञानिक विशेषतायें समझने में सहायता मिलती है।

"किसी देश एवं प्रदेश में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं।" सुविधा के लिये प्रति १००० पुरुष पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है।

अध्ययन क्षेत्र में लिंग अनुपात को सारणी संख्या ३.०२ में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या ३.०२ को देखने से स्पष्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में लिंग अनुपात (१००७) सर्वाधिक है जबकि श्रावस्ती जनपद का लिंग अनुपात (८३३) सबसे कम है। सारणी संख्या ३.०२ से स्पष्ट है कि सभी जनपदों में लिंग अनुपात एक समान नहीं है। लिंग अनुपात की भिन्नता को निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-

वर्ग	लिंग अनुपात	जनपदों की संख्या
अल्प	८५०-९००	७
सामान्य	९००-९५०	७
उच्च	९५० से अधिक	१२

अल्प लिंग अनुपात वाले नगर-

इस वर्ग के अन्तर्गत ७ जनपद आते हैं जो क्रमशः श्रावस्ती ८५६, बहराइच ८६५, गोण्डा ८६६, इलाहाबाद ८८२, सोनभद्र ८६६, मिर्जापुर

सारणी संख्या -३.०२

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनपदवार लिंग अनुपात -२००१

क्र०स०	जनपद	पुरूष जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	लिंगानुपात
१	फैजाबाद	१०७६०००	१०११९१४	९४०
२	गोण्डा	१४५६४६०	१३०९२९४	८९९
३	सुल्तानपुर	१६११९३६	१५७८९९०	९८०
४	प्रतापगढ़	१३७५६१०	१३५१५४६	९८३
५	इलाहाबाद	२६२५८७२	२३१५६३८	८८२
६	वाराणसी	१६५०१३८	१४९७७८९	९०८
७	महराजगंज	११२०८००	१०४६२४१	९३३
८	सोनभद्र	७७१८१७	६९१६५१	८९६
९	बलिया	१४०९८६६	१३४२५४६	९५२
१०	गाजीपुर	१५४४४९८	१५०४८४१	९७४
११	मऊ	९३३२४२	९१७१५२	९८४
१२	आजमगढ़	१९४९८२७	२०००९८१	१०२६
१३	बहराइच	१२७८२५३	११०५९८६	८६५
१४	मिर्जापुर	१११५११२	९९९७४०	८९७
१५	जौनपुर	१९३५५७६	१९७५७२९	१०२१
१६	बस्ती	१०७९९७१	९८८९५१	९१६
१७	गोरखपुर	१९३१७६२	१८५२९५८	९५९
१८	देवरिया	१३६३२५०	१३६७१२६	१००३
१९	संतरविदास नगर	७०४८००	६४७२५६	९१८
२०	बलरामपुर	८८८५५९	६६६००८	८६६
२१	श्रावस्ती	६३२४५२	५४२९७६	८५९
२२	संतकबीरनगर	७२००२८	७०४४७२	९७८
२३	चन्दौली	८५३०१६	७८६७६१	९२२
२४	कुशीनगर	१४७४८८४	१४१७०४९	९६१
२५	सिद्धार्थनगर	१०४७५७३	९९१०२५	९४६
२६	अम्बेडकरनगर	१०२४७१२	१०००६६१	९७७

स्रोत :- १- जनसंख्या सेन्सस, जनगणना विभाग (उ०प्र०) लखनऊ द्वारा प्रकाशि

EASTERN U.P. (2001)
DISTRICT WISE POPULATION DENSITY
PERSONS PER SQ. K.M.
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
VARANASI
SANT RAVIDAS
GORAKHPUR
MAU
DEORIA
SRAVASTI
KUSINAGAR
SANT KABIR
JAUNPUR
AZAMGARH
BALIA
ALLAHABAD
GHAZIPUR
AMBEDKAR
FAIZABAD
SIDHARTH
PRATAPGARH
MAHARAJ
SULTANPUR
BASTI
CHANDULI
GONDA
BALARAMPUR
MIRZAPUR
BAHRAICH
SONBHADRA
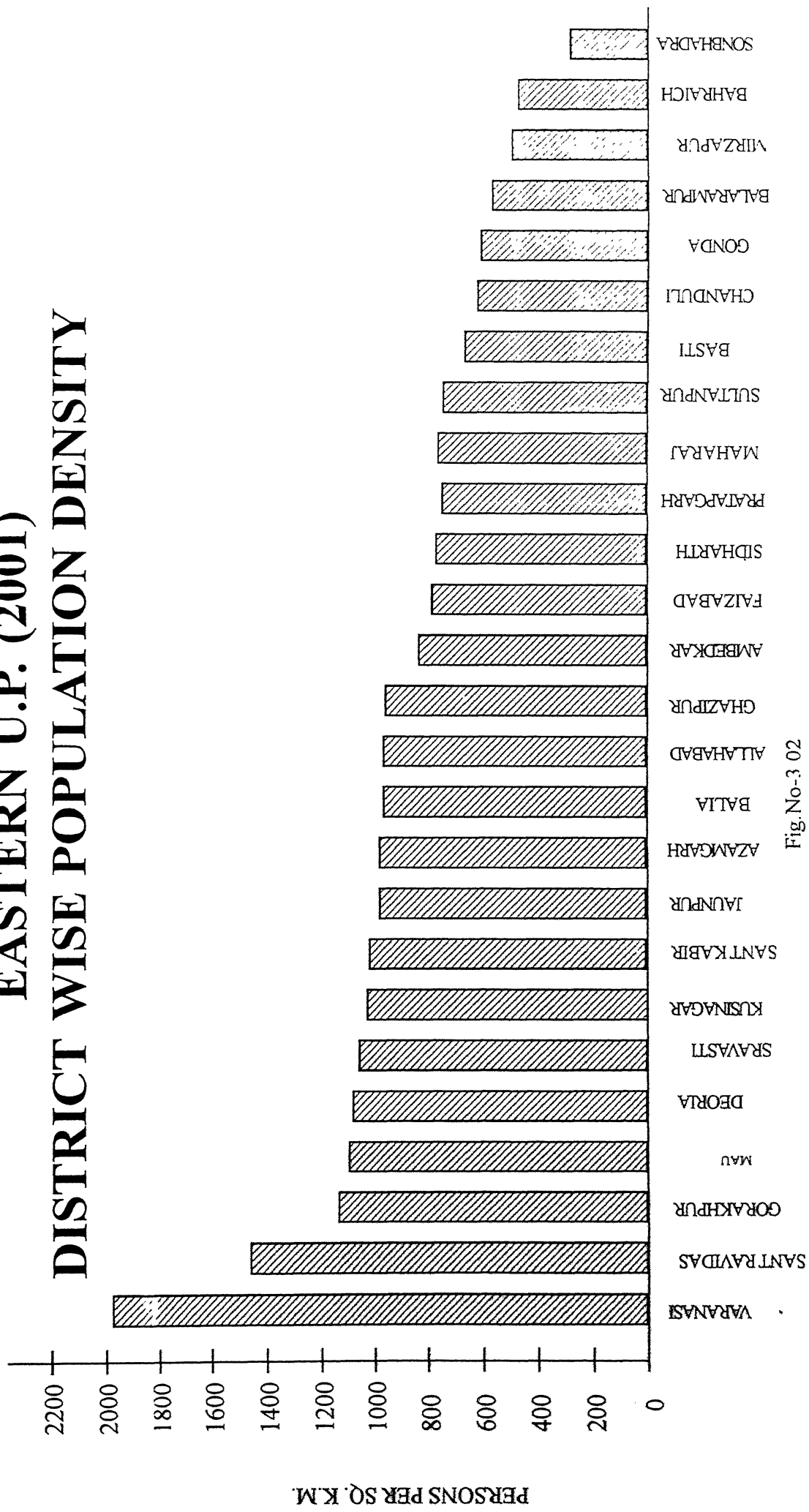
Fig.No-3 02

८६७, बलरामपुर ८६६ हैं। इन जनपदों में प्रति १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कम है जिसका प्रमुख कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। शिक्षा की कमी के कारण बेटी को बोझ माना जाता है। बेटी के विवाह के लिये दहेज की आवश्यकता होती है जो कि गरीब माता-पिता के लिये जुटाना कठिन होता है। इसलिये बेटी को जन्म से ही कष्टकर मानते हैं तथा बेटियों के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है तथा ये उपेक्षित होकर पाली जाती हैं। इसी कारण लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मृत्युदर अधिक है।

सामान्य लिंग अनुपात वाले नगर-

इस वर्ग के अन्तर्गत ७ जनपद आते हैं। फैजाबाद ६४०, वाराणसी ६०८, महाराजगंज ६३३, बस्ती ६१६, सन्तरविदासनगर ६१८, चन्दौली ६२३, सिद्धार्थनगर ६४६ हैं। इन जनपदों में कई शैक्षणिक संस्थायें हैं। जहाँ पुरुषों की प्रधानता स्वाभाविक है। यहाँ नगरीकरण का विकास, परिवहन की सुविधा तथा अन्य लघु एवं कुटीर उद्योगों के कारण लिंग अनुपात में अन्तर पाया जाता है।

उच्च लिंग अनुपात वाले नगर-

इस वर्ग के अन्तर्गत १२ जनपद आते हैं जो क्रमशः गोरखपुर ६५६, सन्तकबीरनगर ६७८, सुलतानपुर ६८०, कुशीनगर ६६१, बलिया ६५२, अम्बेदकरनगर ६७७, गाजीपुर ६७४, मऊ ६८४, जौनपुर १०२१, देवरिया १००३, प्रतापगढ़ ६८३ तथा आजमगढ़ १०२६ है। आजमगढ़ जनपद से लिंग अनुपात सबसे अधिक है जिसका प्रमुख कारण है कि पुरुष अधिकतर नौकरी करने दूसरे जनपदों एवं राज्यों में चले जाते हैं जिस कारण औरतों की संख्या अधिक है। इन भागों में उत्तम चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है तथा स्त्रियाँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तथा इनके साक्षरताा प्रतिशत में वृद्धि हुई है साथ ही उन्हें रोजगार के अनेक सुअवसर भी उपलब्ध हुये हैं। जैसा कि नटराजन ने १६७२ में कहा है कि- यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण निःसन्देह ही लिंग सापेक्ष होता है फिर भी दोनों ही देश जहाँ से प्रवजन हुआ है एवं जहाँ को प्रवजन हुआ है पर कोई तथ्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी तरफ

SEX RATIO IN EASTERN U.P.-2001
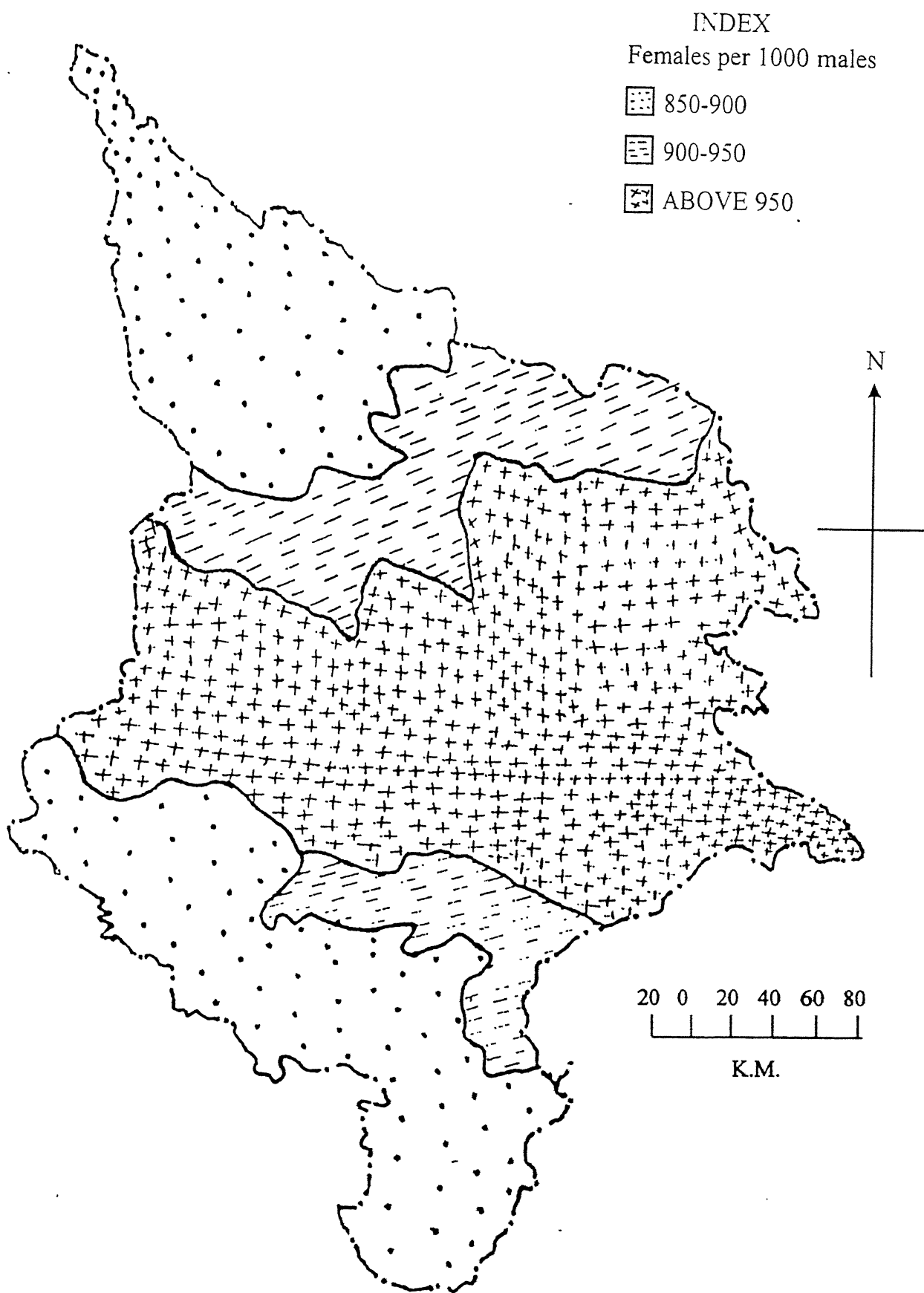
MAP No.- 3.03

आन्तरिक अप्रवास एवं उत्प्रवास लिंग अनुपात के साथ-साथ संरचना एवं वृद्धिदर को प्रभावित करता है।

सारणी संख्या ३.०२ में अध्ययन क्षेत्र का जनपदवार लिंग अनुपात दिखाया गया है। मानचित्र संख्या ३.०३ में अध्ययन क्षेत्र में लिंग अनुपात प्रदर्शित है।

साक्षरता-

भारतीय जनगणना विभाग उस व्यक्ति को साक्षर कहता है जो किसी भाषा में समझ के साथ कुछ पढ़-लिख लेने की क्षमता रखता हो। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता उस व्यक्ति को साक्षर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो लिख सकता है पढ़ नहीं सकता उसे भी साक्षर नहीं कहा जा सकता। जनगणना विभाग ने साक्षरता की गणना करने के लिये आयुसीमा निर्धारित किया है। ४ वर्ष से कम उम्र के बच्चे पढ़ने के लिये शारीरिक रूप से अयोग्य तथा मानसिक रूप से अधकचरे होते हैं।

"विशेष गुणों को प्राप्त करने की लालसा जो व्यवहार में परिपक्वता लाती है जिसकी सहायता से विकासशील समाज विकसित होने के दृष्टिकोंण से प्रयत्नशील रहता है निःसन्देह यही साक्षरता के लाभ हैं।" (मिर्डल १९७७ पृष्ठ ३१३)

अध्ययन क्षेत्र में जनपदवार साक्षरता का विवरण सारणी संख्या ३.०३ में दिया गया है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या की साक्षरता के प्रतिशत को ज्ञात करके हम उस क्षेत्र के विकास कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मात्र ४४.०५ प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर है। अर्थात् अभी भी आधे से अधिक जनसंख्या साक्षर नहीं है। यदि हम अध्ययन क्षेत्र के जनपदों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि श्रावस्ती जनपद में साक्षरता सबसे कम ३४.२५ प्रतिशत है जबकि वाराणसी जनपद में सबसे अधिक साक्षरता ६७.०६ प्रतिशत है। वर्ष १९८१ एवं १९९१ की साक्षरता प्रतिशत की तुलना करने से ज्ञात होता है कि इन १० वर्षों में यहाँ साक्षरता बढ़ी है। इस अवधि में साक्षरता प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि मऊ जनपद में २१.०६% हुई है।

स्पष्ट है कि इस अध्ययन क्षेत्र में ५५.९५ जनसंख्या निरक्षर है अतः इन्हें विकास

LITERACY STATUS IN EASTERN U.P.-2001

MAP No.- 3.04
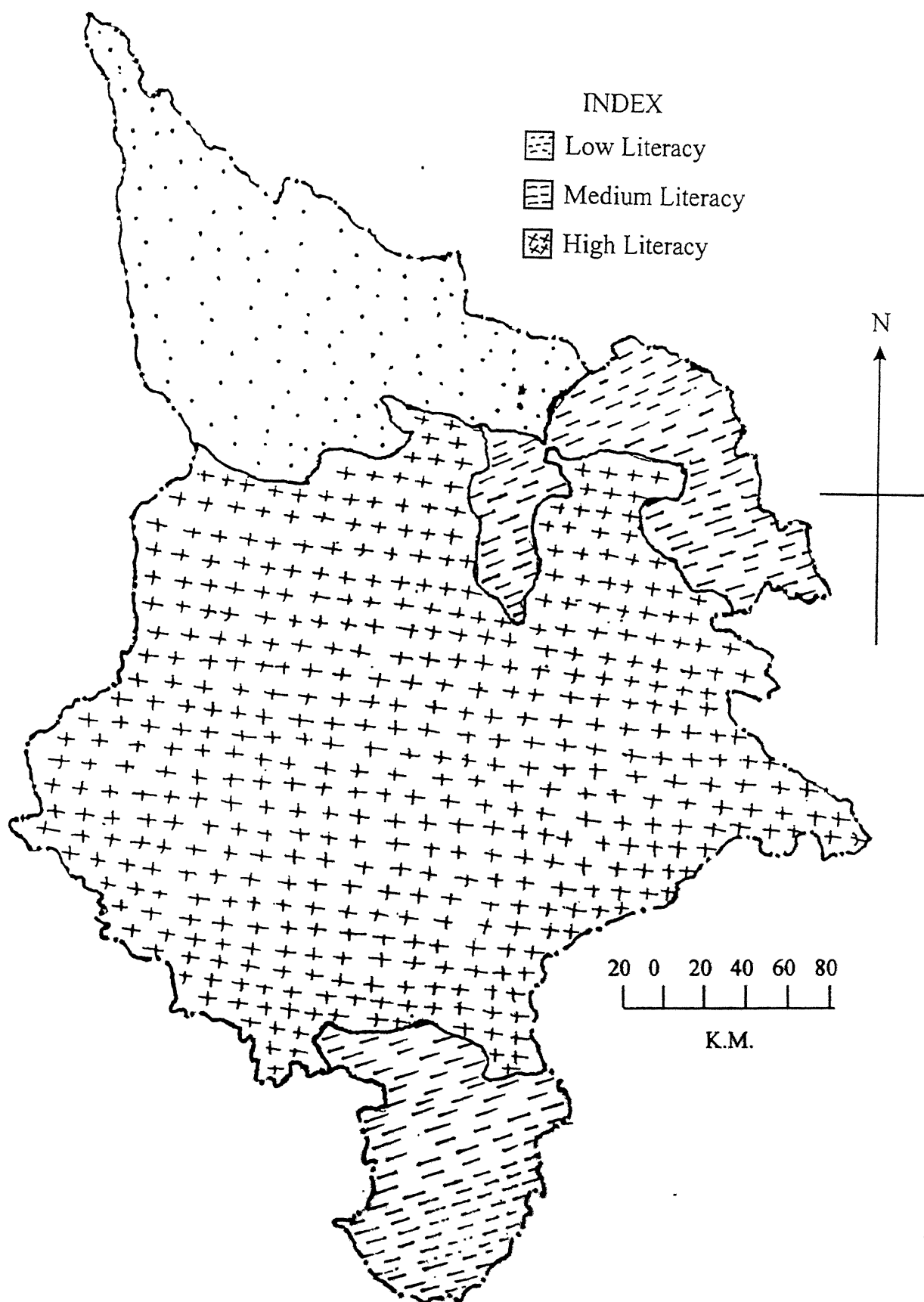
DISTRICT WISE LITERACY STATUS IN EASTERN U.P.2001
Male
Female
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VARANASI
MAU
SANTRAVIDAS NAGAR
JAUNPUR
ALLAHABAD
GORAKHPUR
DEORIA
CHANDUALI
GHAZIPUR
PRATAPGARH
BALLIA
AMBEDKARNAGAR
SULTANPUR
FAIZABAD
MIRZAPUR
AZAMGARH
BASTI
SANTKABARNAGAR
MAHARAGANJ
KUSINAGAR
SONBHADRA
SIDDHARTH NAGAR
GONDA
SRAVASTI
BAHRAICH
BALRAMPUR

DIG. NO.3.03
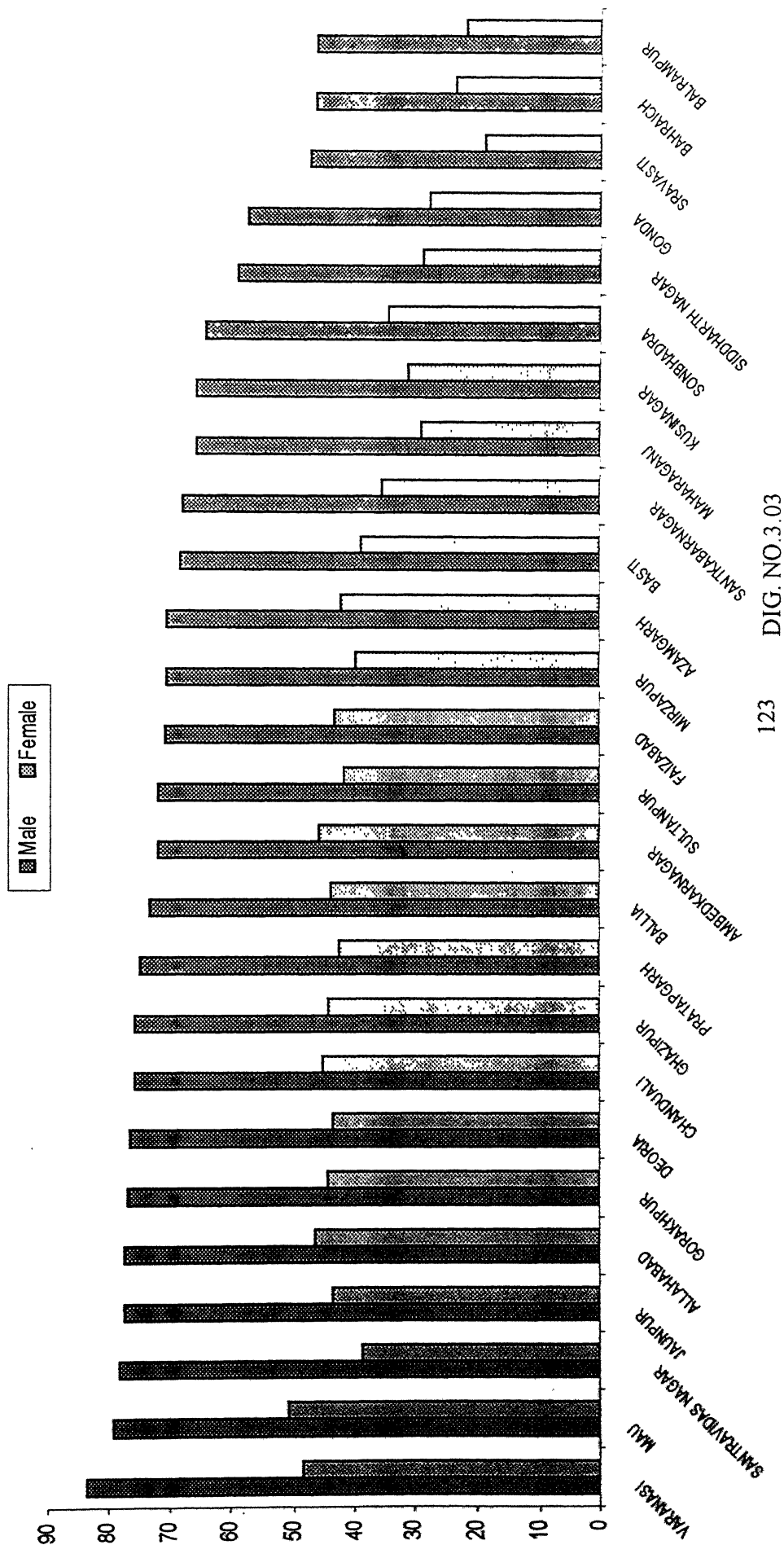
सारणी संख्या -३.०३

पूर्वी उत्तर प्रदेश

जनपदवार साक्षरता प्रतिशत २००१

क्र०स०	जनपद	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता
१	फैजाबाद	७०.७३	४३.३५	५७.४८
२	गोण्डा	५६.६३	२७.२६	४२.६६
३	सुल्तानपुर	७१.८५	४१.८१	५६.४०
४	प्रतापगढ़	७४.६१	४२.६३	५८.६७
५	इलाहाबाद	७७.१३	४६.६	६२.८६
६	वाराणसी	८३.६६	४८.५६	६७.०६
७	महराजगंज	६५.४०	२८.६४	४७.७२
८	सोनभद्र	६३.७६	३४.२६	२६.६६
९	बलिया	७३.१५	४३.६२	५८.८८
१०	गाजीपुर	७५.४५	४४.३६	६०.०६
११	मऊ	७८.६७	५०.८६	६४.८६
१२	आजमगढ़	७०.५०	४२.४४	५६.१५
१३	बहराइच	४६.३२	२३.२७	३५.७६
१४	मिर्जापुर	७०.५१	३०.८६	५६.१०
१५	जौनपुर	७७.१६	४३.५३	५६.६८
१६	बस्ती	६८.१६	३६.००	५४.२८
१७	गोरखपुर	७६.७०	४४.४८	६०.६६
१८	देवरिया	७६.३१	४३.५६	५६.८४
१९	संतरविदास नगर	७७.६६	३८.७२	५६.१४
२०	बलरामपुर	४६.२८	२१.५८	३४.७१
२१	श्रावस्ती	४७.२७	१८.७५	३४.२५
२२	संतकबीरनगर	६७.८५	३५.४५	५१.७१
२३	चन्दौली	७५.५५	४५.४५	६१.११
२४	कुशीनगर	६५.३५	३०.८५	४८.४३
२५	सिद्धार्थनगर	५८.६८	२८.३५	४३.६७
२६	अम्बेडकरनगर	७१.६३	४५.६८	५६.०६

स्रोत :- १-जनगणना सेन्सस , जनगणना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

योजनाओं की कम से कम जानकारी होती है जबकि सरकार इन योजनाओं पर काफी पैसे खर्च कर रही है और ये उन्हीं के विकास के लिये बनायी गयी हैं। निरक्षर व निर्धन जनसंख्या को न तो इन योजनाओं को समझने की क्षमता है और न ही वह इसके लिये इच्छुक प्रतीत होते हैं। वे इसे समझने का प्रयास भी नहीं करते। यहाँ साक्षरता की बहुत कमी है इससे इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अतः अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास के लिये साक्षरता में समुचित वृद्धि आवश्यक है।

सारणी संख्या ३.०३ में जनपदवार साक्षरता को प्रदर्शित किया गया है। रेखाचित्र ३.०३ में जनपदवार साक्षरता दिखायी गयी है। तथा मानचित्र संख्या ३.०४ में अध्ययन क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत प्रदर्शित है।

व्यवसायिक संरचना-

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों का अनुपात (अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के सन्दर्भ में) ३५.१० प्रतिशत है। कुल कार्यरत जनसंख्या का २१.३४ प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है जबकि अन्य व्यवसायों में (जैसे गृह उद्योग, व्यापार परिवहन एवं अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों में मात्र १३.६४ %जनसंख्या ही लगी है। रेखाचित्र ३.०५ में इस बात को दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की व्यवसायगत जनसंख्या को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

१. कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या

२. कृषि कार्यों के अतिरिक्त व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या

यदि हम अध्ययन क्षेत्र में लगी कार्यरत जनसंख्या (विभिन्न जनपदों में) पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि महाराजगंज जनपद से सबसे अधिक (२७.८६ प्रतिशत) कार्यरत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है जबकि सन्तरविदासनगर जनपद में सबसे कम १३.८६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इससे इस क्षेत्र में कृषि की प्रधानता का सहज ही आभास हो जाता है। रेखाचित्र ३.०५ में जनपदवार व्यावसायिक संरचना तथा रेखाचित्र

EASTERN U.P. (2001)
DISTRICT WISE MAIN WORKERS

Fig.No-3 04

125
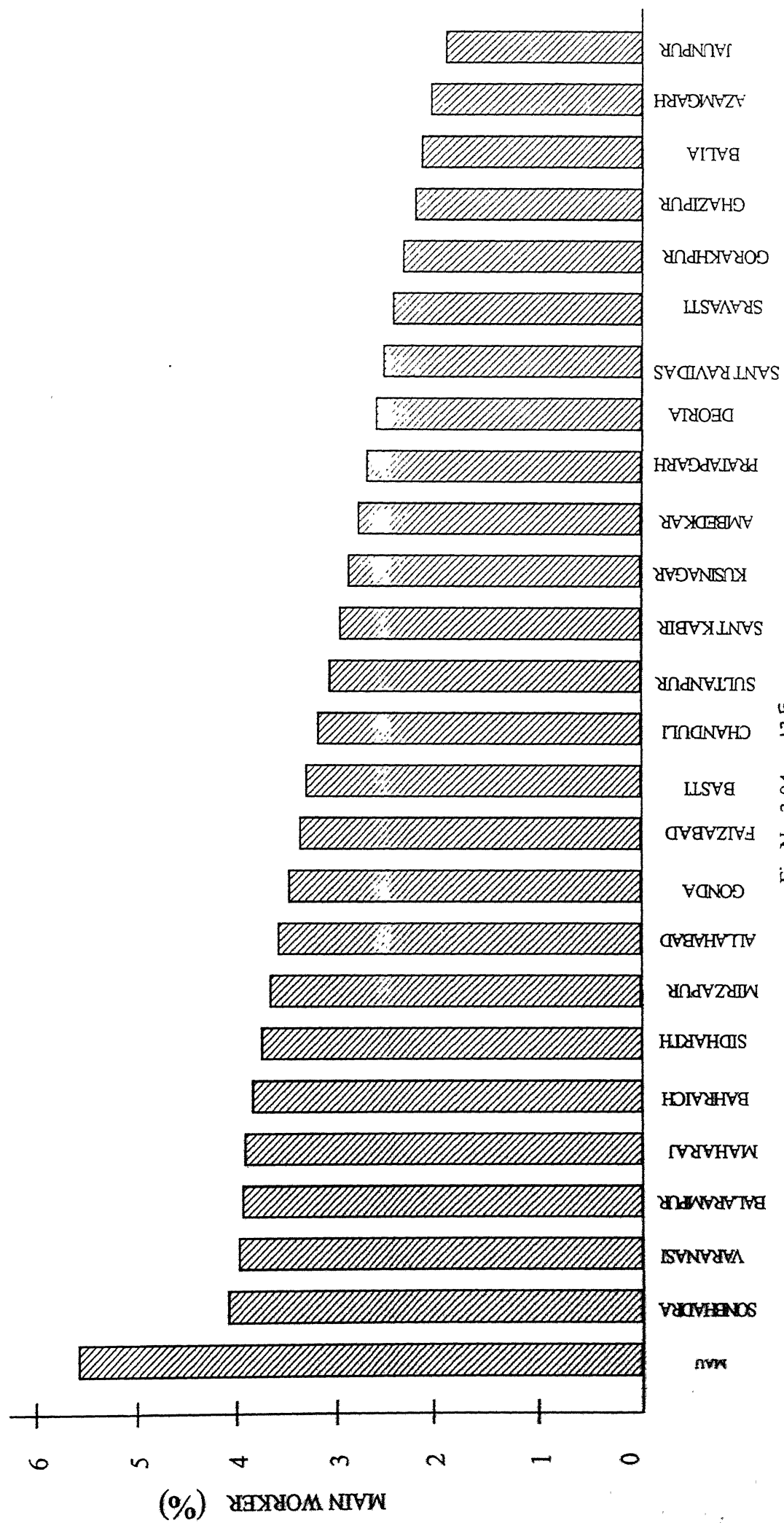
OCCUPATIONAL STRUCTURE OF EASTERN U.P.
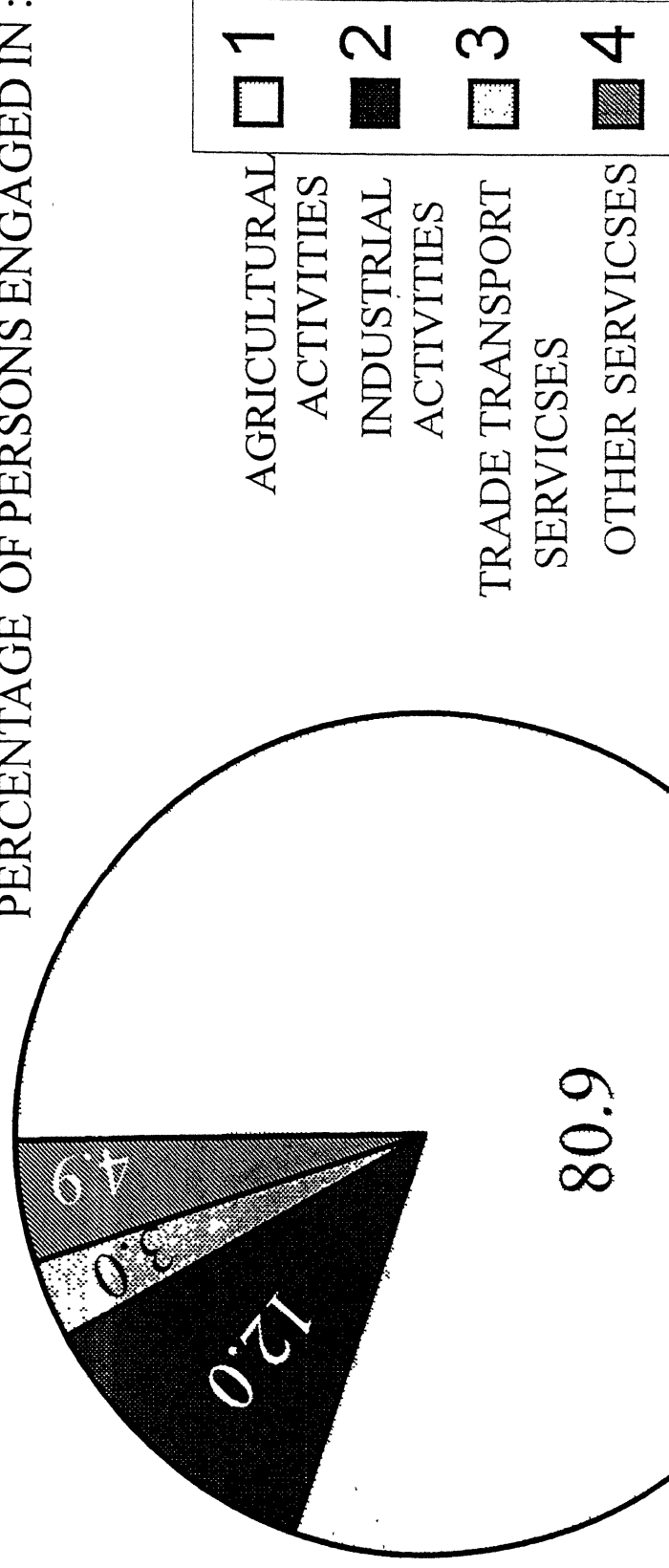
Fig.No -3.05

OCCUPATIONAL STRUCTURE OF POPULATION
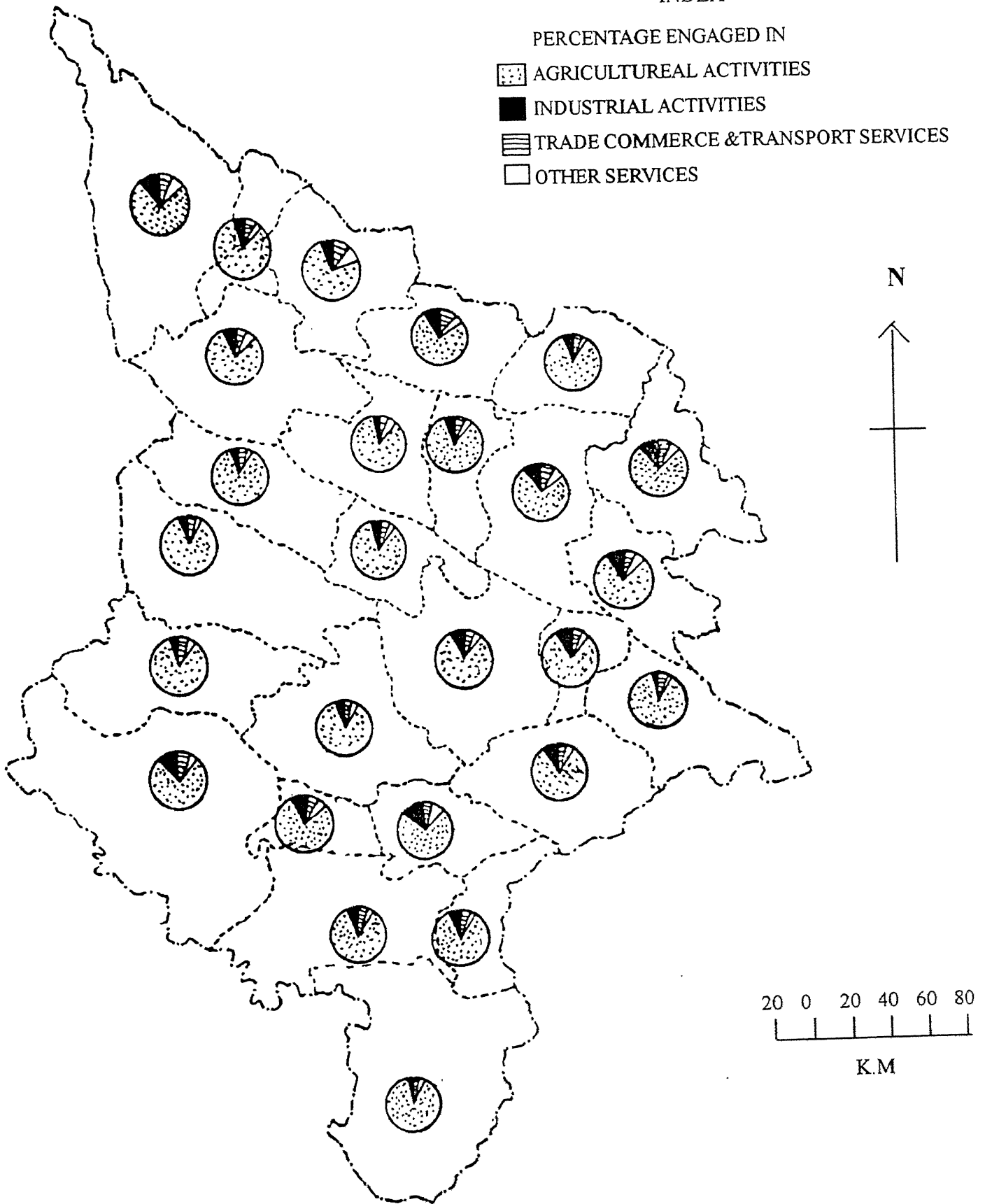
FigNo-3.05

३.०५ में क्रमशः जनपदवार मुख्य कर्मकर तथा ३.०५ में व्यावसायिक संरचना को दिखाया गया है।

■

References

1- Agarwal , S.N. (1967) ; Population. New Delhi.

2- Agarwal , S.N. (1973) ; India's Population Problems.Tata Mc Graw Hill, New Delhi.

3- Bhattacharya , A (1978); Population Geography of India , New Delhi.

4- Clark , J.I. (1976) ; Population Geography . Pergamon Press Oxford .

5- Chakravarti , A.K. (1976);Population growth types in India 1961-71 Journal of Geography .

6- Demko, G.I. ,Rose , H.M. Sehnell G.A. (1970); Population Geography , Reader Mc Graw -Hill Book Company,New York .

7- Davis Kingsley (1951) ; Population growth in India and Pakistan . Princeton University Press , Princeton.

8- Singh , R.L. and K.N. Singh(1971) ; Middle Ganga Plain in R.L.Singh et al. (eds) India : A Regional Geography .

9- Gosal , G.S. and Gopal Krishan (1975) ; Patterns of Internal Migration in India .

10- Gosal ,G.S. (1974) ; Population growth in India : Asian Profile,2.

11- Harvey, D. (1976) ; Explanations in Geography . Edward Arnold London.

12- Kosinski et al. (eds) ; People on the move : Studies on Internal Migration , Anethuen London.

13- Krishan , G. and Madhav Shyam ; Literacy Pattern in India Cities .

14- Myrdal , G. (1977) ; Asian drama , an inquiry in to the Poverty of Nations (abridged) Penguin Books .

15- Naik , J.P.(1975) ; Policy and performance in India education orient Long man New Delhi.

16- Natrajan , D. (1972) ; Inter Census Growth of Population Census Centenary Monography No 3 Census of India .

17- Sengupta , P. (1971) ; Effect of emignation and immigration in (India 1951-61) , National committee for Geography Calcutta .
18- Singh , R.L. and K.N. Singh (1971) ; Middle Ganga Plain in R.L .Singh et al (eds) India .
19- Singh, L.R. (1965) ;The Tarai Region of Uttar Pradesh . Ram Naryan Lal Beni Prasad , Allahabad .
20- Singh, L.R. and D. Nath (1981) ; Spatial Pattern of Scheduled Caste Population in the Saryupar Plain (U.P.) Lucknow .
21- Singh, L.R.et al. (1976) ;Baghelkhand region - A Study in Population /Resource regionalization development model ; National Geography Journal of India .
22- Sinha , B.N. and B.K. Mishra (1976); Tribes of Orissa : A Geographical Analysis . Geographical Review of India .
23- Thompsen , W.S. and S.T. Lewis (1976) ; Population problem . Tata Mc. Graw Hill New Delhi.
24- Tremartha , G.T. (1976) ; A Geography of Population , World Patterns John Willy and Sons New York.
25- Tremartha , G.T. (1953) ; A case for population in Geography : A Reader Mc. Graw - Hill Book Company New York .
26- United Nation (1973) ; The determinats and Consewuences of Population trends . Vol. 1 New York .
27- Warnt Z .M. and D. Neft. (1960) ; Contribution to a Statistical methodology for areal distributions : Journal of Reginal Science 63.
28- Verma, D.N. (1992); Population Patterns: Jaltosh Prakashah Aminabad Lucknow.
29- Zelinsky, W. (1966) A Prologue to population Geography. Prentice hall inc, Engle wlood eliff N.J.

चतुर्थ सोपान

औद्योगिक अवस्थिति सिद्धान्त

औद्योगिक अवस्थिति सिद्धान्त

मानव की आर्थिक क्रियाओं में सर्वप्रथम आवास एवं उसके पश्चात् कृषि का समावेश हुआ था। कृषि कार्यों के लिये उपकरणों की जरूरत थी। प्राचीन काल में हड्डियों,पत्थरों एवं लकड़ियों के माध्यम से उपकरण बनाये जाते थे। ये बहुत टिकाऊ एवं मजबूत होते थे। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि लम्बी अवधि तक चलने वाले यन्त्रों/उपकरणों को विकसित किया जाय इस कार्य हेतु किसी धात्विक वस्तु की जरूरत थी। कालान्तर में मानव को लौह चट्टान की जानकारी हुई। उसे यह भी पता चला कि उसे गलाकर एक ठोस धातु तैयार की जा सकती है। तदुपरान्त उसे लोहे की वस्तुयें तैयार करने की जानकारी हुई इसी के साथ-साथ अन्य धातुओं का भी ज्ञान होता गया।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि किसी न किसी रूप में उद्योगों का प्रारम्भ तभी हो गया था जब पत्थर तथा लकड़ी के उपकरण कृषि कार्यों के लिये निर्मित किये जाने लगे। इसी सन्दर्भ में पी० कुमार ने कहा है कि सम्भवतः उद्योगों का विकास प्रागैतिहासिक काल में हुआ जब मानव ने पत्थरों को तराशा और औजारों का रूप दिया।(कुमार प्रमिला १९९७ पृष्ठ २) शनैः शनैः इस प्रक्रिया में सुधार होता गया और अच्छे यन्त्र बनाये जाने लगे। वर्तमान समय में भी यन्त्रों का निर्माण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास ने इसके तीव्रता से परिवर्तन किया है आज अच्छे-अच्छे उपकरण कृषि कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे हैं।

विद्युत की जानकारी लम्बे अन्तराल के बाद हुई। इससे औद्योगिक कार्य करने में सरलता एवं सुगमता का समावेश हुआ। १८८२ में पर्लस्ट्रीट के विद्युत उत्पादन केन्द्र ने क्रान्ति ला दी। स्मिथ, स्मिथ एवं फिलिप्स ने इस सन्दर्भ में लिखा है- "यद्यपि जेम्सवाट्स के भाप के इंजन में सुधार के फलस्वरूप यान्त्रिक शक्ति का अभ्युदय हुआ परन्तु इसका सर्वोत्तम उपयोग तब हुआ जबकि सितम्बर १८८२ में न्यूयार्क शहर में पर्लस्ट्रीट वैज्ञानिक के द्वारा विद्युत उत्पादन स्टेशन चालू किया गया।(स्मिथ , रसल, थामस एवं फिलिप्स १९५५ पृष्ठ २७२) इसी तारतम्य में सत्रहवीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। इसके उपरान्त अनेक प्रकार की औद्योगिक मशीनें तैयार की जानें लगीं

और नये औद्योगिक युग का सूत्रपात हुआ। इसी समय से उद्योगों का विकास तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। इसके उपरान्त बड़े पैमाने के उद्योग विकसित होने लगे।

भारत भी इस नयी औद्योगिक प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। ग्रामोद्योग एवं हस्तकला पर आधारित उद्योग विद्युत चालित मशीनों से चलने प्रारम्भ हो गये। बड़े उद्योगों के विकास के लिये बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी जो सर्वत्र सुलभ नहीं थे। अतः बड़े उद्योग लाभदायक होने के लिये कहाँ लगाये जॉय यह विश्लेषण का तथ्य बन गया। इस सन्दर्भ में विचारकों ने अपने अपने सैद्धान्तिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। अर्थशास्त्रियों ने इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास किया तदुपरान्त भूगोलवेत्ताओं ने भी इस सन्दर्भ में अपना योगदान दिया है।

उद्योगों के स्थानीकरण का स्वरूप

इस सैद्धान्तिक विचारधारा का सर्वप्रथम प्रारम्भ अल्फ्रेड वेवर ने किया।(सिंह एम० बी० १९८३ पृष्ठ ३६) यद्यपि इनके पूर्ण वान थ्यूनेन ने भी आर्थिक क्रियाकलापों के स्थानीकरण की समस्या पर चर्चा की,लेकिन इन्होंने अपना ध्यान केवल कृषि सम्बन्धी क्रियाकलापों पर ही केन्द्रित रखा । विलहम रोशन ने इस ओर कुछ कार्य प्रारम्भ किया था उनके मतानुसार औद्योगिक अवस्थिति का निर्माण कच्चे माल, श्रमिकों एवं पूजी की सुलभता के आधार पर होता है किन्तु इसमें भी मुख्य निर्धारक कारक वही होता है जिसका उत्पादित वस्तु की मूल्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

उद्योगों के स्थानीकरण की समस्या का अध्ययन अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी किया है। इनमें सोनन फील्ड ,अशिली लोरिया, मेनियर, वर्नर सोमवरी, जीनी मेशिये , श्वर्ज चाइल्ड, लानहार्ड, वेलियों, आस्कर इग्लैण्डर मालकम करे, सारजेण्ट फ्लोरेन्स डेनीसन, अगस्त लाश, मैलविन ग्रीनहट, वाल्टर इर्जाट , जे० एल० वर्नर वेलफ्रेड स्मिथ एवं इ० ए० जी० रोविन्सन आदि विद्वानों के योगदान प्रमुख हैं।(कौशिक,एस० डी०, १९९५ पृष्ठ ३५२)

अशिली लोरिया को औद्योगिक स्थानीकरण का विश्लेषण करने के लिये प्रमुख माना जाता है। इनके विचार में भारी कच्चे मालों पर आधारित उद्योग बाजार क्षेत्र के निकट स्थापित होंगे। परन्तु बाद में इसमे संशोधन किया गया। अनेक लोगों ने जलवायु के प्रभाव

एवं श्रमिकों की उपलब्धि को ध्यान में रखकर इस समस्या पर विचार किया। थोड़े से विचारकों ने औद्योगिक दृष्टिकोण से इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में अल्फ्रेड वेबर की विचारधारा को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है। इन्होंने कुछ मान्यताओं को प्रतिपादित किया है जिसके परीक्षण में उनकी उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है।

अल्फ्रेड वेबर का सिद्धान्त-

अल्फ्रेड वेबर एक प्रमुख जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले जर्मन विद्वानों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने उद्योगों के स्थानीकरण सम्बन्धी सिद्धान्त १६०६ में अपनी पुस्तक,जो कि जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी, Uberden standortder Industrien में प्रतिपादित किया। १६२६ में इसी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद Theory of Location of Industries प्रकाशित हुई और तभी से यह सिद्धान्त अधिकाधिक प्रसिद्ध हुआ।

इन्होंने विश्लेषण एवं संश्लेषण की सहायता से उन कारकों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का स्थानीकरण होता है। इन्होंने अपने सिद्धान्त में कुछ आधारभूत मान्यतायें बतायी हैं जो निम्नलिखित हैं-

१. परिवहन की लागत वस्तु के भार एवं स्थानान्तरण की दूरी पर निर्भर होती है। वेबर ने भाड़ा की दर और परिवहन के साधन के सर्वत्र समान होने की कल्पना की है। इनके सिद्धान्त में केवल भार एवं दूरी का ही विचार किया गया है, वास्तविक लागत का नहीं।

२. उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल किसी निश्चित औद्योगिक क्षेत्र में ही उपलब्ध होते हैं। उनका मूल्य क्षेत्रानुसार पृथक होता है। वेबर ने उनका मूल्य सर्वत्र समान माना है।

३. उद्योगों द्वारा निर्मित माल की बिक्री निश्चित बाजार क्षेत्र में ही होती है तथा इन

बाजारों का आकार भी ज्ञात होता है।

४. उद्योगों में कार्य करने वाला श्रम भी निश्चित क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। श्रम उपलब्धि के अनेक निश्चित स्थान व क्षेत्र हैं। जहाँ से श्रमिक असीमित संख्या में मजदूरी के लिये उपलब्ध हैं।

इन तीन मान्यताओं के आधार पर वेबर ने अपने सिद्धान्त को विकसित किया। वेबर के विचार से कच्चे पदार्थों की तीन श्रेणियाँ होती हैं।

क. स्थानीय पदार्थ- ये निश्चित क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं। इनकी मात्रा सीमित होती हैं। इनका मूल्य स्थानीयता के अनुसार गुणात्मक दृष्टिकोण से कम या अधिक होता है।। इन्हें कारखाने तक ले जाने में परिवहन की दूरी के अनुसार व्यय होता है। ऐसे पदार्थों में खनिज, लकड़ी कृषि उपज आदि आते हैं।

ख. सर्वव्यापी पदार्थ- जो पदार्थ सर्वत्र उपलब्ध होते हैं उन्हें सर्वव्यापी पदार्थ कहा जाता है। इन्हें प्राप्त करने के लिये कम प्रयास करना पड़ता है तथा इनका मूल्य सभी जगह लगभग समान रहता है। इनमें वायु,मिट्टी, जल आदि आते हैं।

ग. परिशुद्ध पदार्थ- जिन पदार्थों का भार उत्पादन प्रक्रिया में कभी क्षय नहीं होता उन्हें परिशुद्ध पदार्थ कहते हैं।

घ. मिश्रित पदार्थ- वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में घटता है उन्हें मिश्रित पदार्थ कहते हैं।

वेबर ने अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये कुछ सूचकांकों का सहारा लिया है जो निम्नलिखित है-

१. पदार्थ सूचकांक- किसी उद्योग में प्रयुक्त कच्ची सामग्री तथा उससे उत्पादित सामग्री के वजनों के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहा जाता है। जिस कच्चे माल में व्यर्थ पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक पायी जाती है, उसका पदार्थ सूचकांक उतना ही अधिक होता है। जब यह सूचकांक एक से अधिक होता है तो उद्योग को कच्चा माल के स्रोत के निकट स्थापित करना लाभदायक होता है। परन्तु जब सूचकांक एक या एक से कम होता

है तो उद्योग को बाजार के निकट स्थापित करना लाभदायक होता है।

पदार्थ सूचकांक (Material Index) = $\frac{\text{कच्चे माल का भार}}{\text{उत्पादित माल का भार}}$

२ श्रम लागत सूचकांक- उत्पादित माल के कुल भार में श्रम लागत के अनुपात को श्रम लागत सूचकांक कहते हैं-

श्रम लागत सूचकांक = $\frac{\text{उत्पादित वस्तु का कुल भार}}{\text{श्रम लागत}}$

३ श्रम गुणांक- श्रम लागत सूचकांक और स्थानीकरण से प्राप्त भार के अनुपात को श्रम गुणांक कहते हैं। इसका सम्बन्ध स्थानीकरण से प्राप्त भार की प्रति इकाई पर तथा श्रम लागत सूचकांक से होता है।

वेबर ने औद्योगीकीकरण स्थानीकरण सिद्धान्त पर मुख्य रूप से दो कारकों का प्रभाव माना है।

१. प्रादेशिक कारक- इसमें यातायात एवं श्रम मूल्य प्रमुख हैं।

२. स्थानीय कारक- इनके आधार पर वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत बिन्दु ज्ञात करने का प्रयत्न किया है।

न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा का विश्लेषण-

वेबर ने अपने सिद्धान्त को कच्चे माल के स्रोत एवं उत्पादित वस्तु के खतप क्षेत्र अर्थात बाजार के सन्दर्भ में विकसित किया है। इसमें इन्होंने कई क्रमों का उल्लेख किया है-

क्रम - १

एक कच्चा माल स्रोत एवं एक बाजार के परिप्रेक्ष्य में

यदि किसी उद्योग के लिये एक ही कच्चे माल की जरूरत हो और उत्पादित वस्तु एक ही जगह बेची जानी हो तो एक प्रकार के उद्योग का स्थानीकरण कच्चे माल के गुण के अनुसार होगा। इनकी तीन स्थितियाँ हैं-

क. स्थिति- यदि उत्पादन में सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग होता तो कारखाने की

स्थापना बाजार में ही होगी। इसमें कच्चे माल का परिवहन नहीं करना होगा। (देखें रेखाचित्र संख्या ४.०१ क)

ख.स्थिति- उत्पादन में यदि कच्चा माल शुद्ध है तो कारखाने की स्थापना कच्चे माल के स्रोत या बाजार या इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकती है-चित्र संख्या ४.०१ (घ)

ग.स्थिति- यदि उत्पादन में मिश्रित पदार्थों का प्रयोग होता है तो कारखाने की स्थापना कच्चेमाल के स्रोत के पास होगी क्योंकि इससे व्यर्थ पदार्थों पर होने वाला अनावश्यक व्यय बच जाता है।(कौशिक, एस० डी०,१९९५.पृष्ठ ३३४-३३५)

दो अथवा दो से अधिक कच्चा मालस्रोत तथा एक ही बाजार के परिप्रेक्ष्य में

ऐसी स्थिति में उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले दो या दो से अधिक कच्चे मालों के गुणों पर उद्योग की स्थिति निर्भर होगी। इसमें निम्न दशायें हो सकती हैं-

क. स्थिति- उत्पादन में दोनों कच्चे माल सर्वव्यापी हैं तो कारखानों की स्थिति बाजार में होगी क्योंकि इससे उत्पादित वस्तु को बाजार तक ले जाने की परिवहन लागत बच जायेगी।

ख. स्थिति- यदि दो कच्चे माल में से एक सर्वत्र सुलभ है तथा दूसरा सकेन्द्रित है जो बाजार के बाहर दूर स्थित है और ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं तो कारखाना बाजार के निकट ही स्थापित होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल दूसरे कच्चे माल के परिवहन पर ही व्यय करना पड़ेगा।

ग. स्थिति- यदि उत्पादन में प्रयुक्त एक कच्चामाल शुद्ध है तथा दूसरा अशुद्ध तो कारखाना अशुद्ध कच्चे माल के स्रोत पर ही स्थापित होगा क्योंकि अशुद्ध कच्चे माल में विद्यमान व्यर्थ पदार्थ पर होने वाला अनावश्यक परिवहन व्यय बच जायेगा।

घ. स्थिति- यदि उत्पादन में प्रयुक्त दोनों कच्चे माल अशुद्ध हैं या मिश्रित हैं तो उद्योग या कारखाने की स्थिति का निर्धारण कठिन होता है। इस समस्या को हल करने के लिये वेबर ने एक समबाहु त्रिभुज का सहारा लिया है, जो कि चित्र संख्या ४.०२ में दर्शाया गया है- इस रेखाचित्र में दर्शाये गये A एवं B कच्चे माल के स्रोत हैं जबकि C स्थान बाजार को दर्शाता है। अब A,B एवं C से प्रत्येक स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वेबर के अनुसार ऐसा उद्योग बाजार के निकट स्थापित नहीं हो

A Raw Material and A Market Site
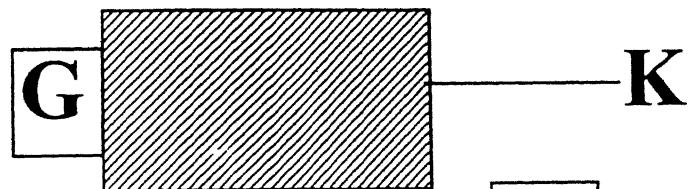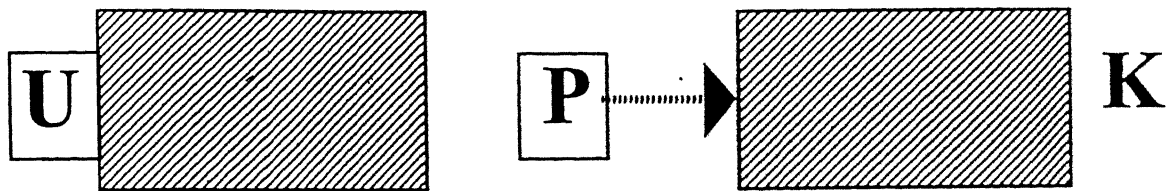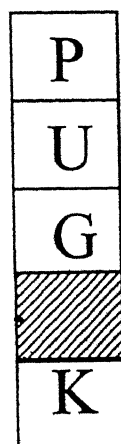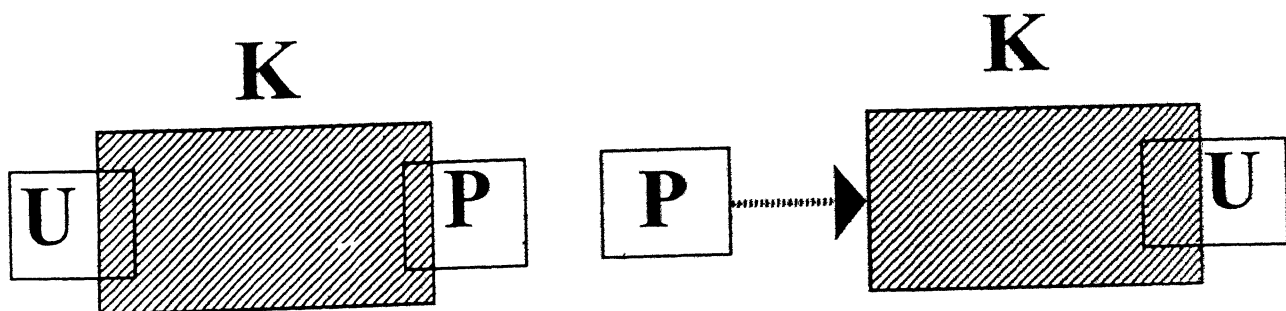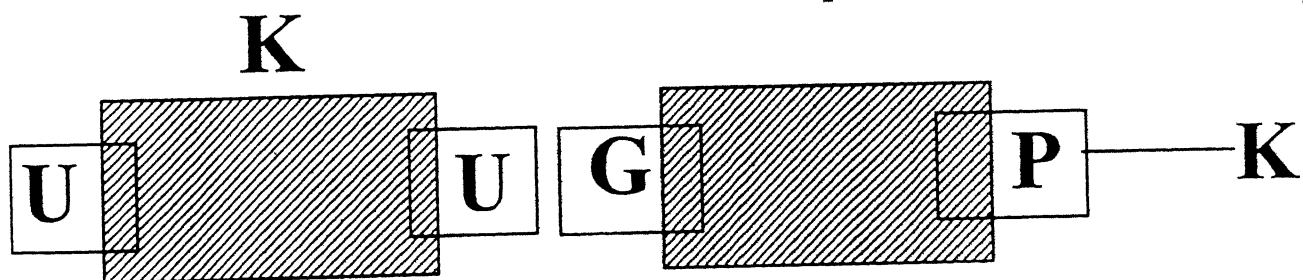
Fig.No-4.01(क)

Fig.No-4.01(ख)

WEBER'S LOCATION TRIANGLE
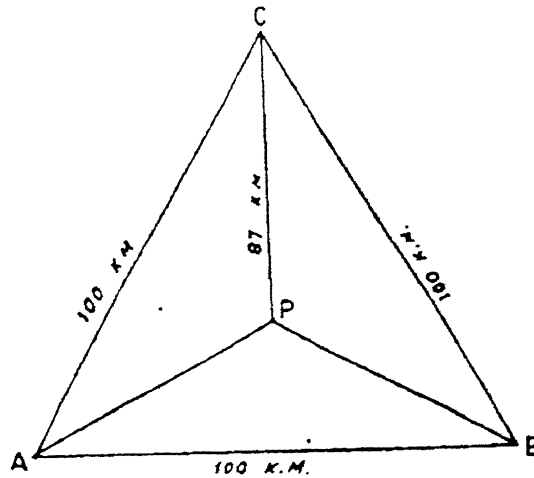
FIG.NO-4.02

ISODAPANE FRAME WORK
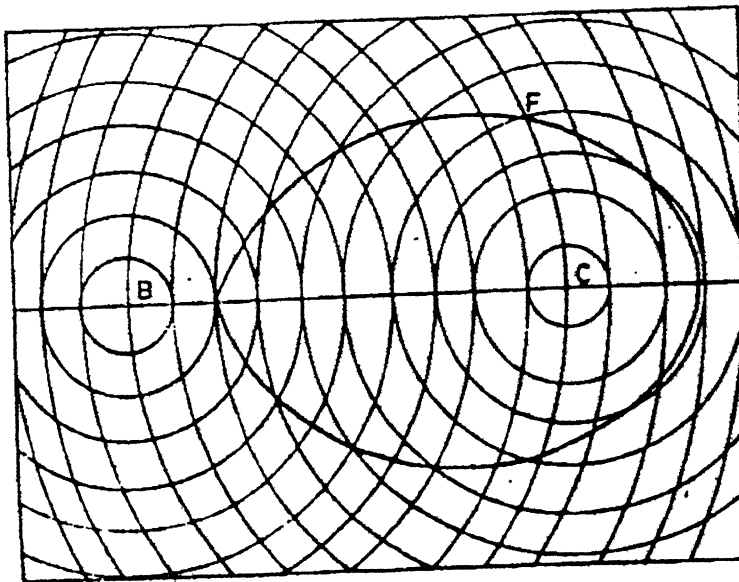
FIG.NO-4.03

सकता क्योंकि वहाँ तक उस वजन पर भी व्यय करना होगा जो निर्माण के वाद नष्ट हो जाता है।

उद्योग या कारखाना A एवं B (मालस्रोत) पर भी स्थापित नहीं होगा क्योंकि इन दशाओं में भी परिवहन लागत अधिक होगी। वेबर के विचार से यदि उद्योग को उक्त त्रिभुज के मध्य बिन्दु अर्थात P बिन्दु पर स्थापित किया जाय तो परिवहन व्यय न्यूनतम होगा और इस स्थान पर उद्योग स्थापित होने से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्रम मूल्य प्रभावित न्यूनतम लागत सिद्धान्त

यह सिद्धान्त वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धान्त का ही पूरक है। श्रम लागत की कमी के कारण भी उद्योगों की स्थिति न्यूनतम परिवहन लागत बिन्दु से विचलित हो जाती है। ऐसा विचलन तभी सम्भव होगा जब नये स्थान पर उद्योगों को श्रम से होने वाली बचत वहाँ तक परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय से पर्याप्त अधिक हो। ऐसी स्थिति की व्याख्या के लिये बेबर ने आइसोडापेन (न्यूनतम परिवहन लागत बिन्दु से हटने पर उसके चारो ओर अतिरिक्त समान व्यय के बिन्दुओं को मिलाने वाली वृत्ताकार रेखा) का उपयोग किया है। इसे रेखाचित्र ४.०३ में प्रदर्शित किया गया है । रेखाचित्र ४.०३ में वेबर ने आइसोडापेन को स्पष्ट करने के लिये कच्चे माल का एक स्रोत 'सी' और खपत का एक स्थान 'बी' कल्पित किया है। इन दोनों बिन्दुओं के चारो ओर समान दूरी पर वृत्ताकार रेखायें खींची गयी हैं जो प्रतिटन परिवहन लागत की एक इकाई को बताती है। माना गया है कि 'सी' बिन्दु पर पाये जाने वाले पदार्थ के भार में निर्माण प्रक्रिया में ५० प्रतिशत की कमी हो जाती है ऐसी दशा में न्यूनतम लागत का विन्दु 'सी' ही हो गया। दशा में न्यूनतम लागत का बिन्दु 'सी' ही होगा। परन्तु यदि उद्योग 'एफ' स्थान पर स्थापित किया जाय तो परिवहन लागत 'सी' की अपेक्षा अधिक होगी। अतः 'एफ' बिन्दु पर उद्योग स्थापित होगा जबकि वहाँ पर उपलब्ध श्रम से लागत में उससे अधिक बचत हो जितनी कि यहाँ कारखाना स्थापित करने में अतिरिक्त परिवहन लागत देनी पड़ेगी।

एकत्रीकरण से प्रभावित न्यूनतम लागत सिद्धान्त

वेबर के विचार से सस्ते श्रम की भाँति एकत्रीकरण भी कारखाने को न्यूनतम परिवहन लागत से विकसित कर सकता है। किसी भी उद्योग की स्थापना एकत्रीकरण वाले क्षेत्रों में उसी स्थिति में सुनिश्चित की जायेगी जबकि उद्योगपतियों को न्यूनतम यातायात लागत या

INDUSTRIAL SITUATION BASED ON ISODAPANES
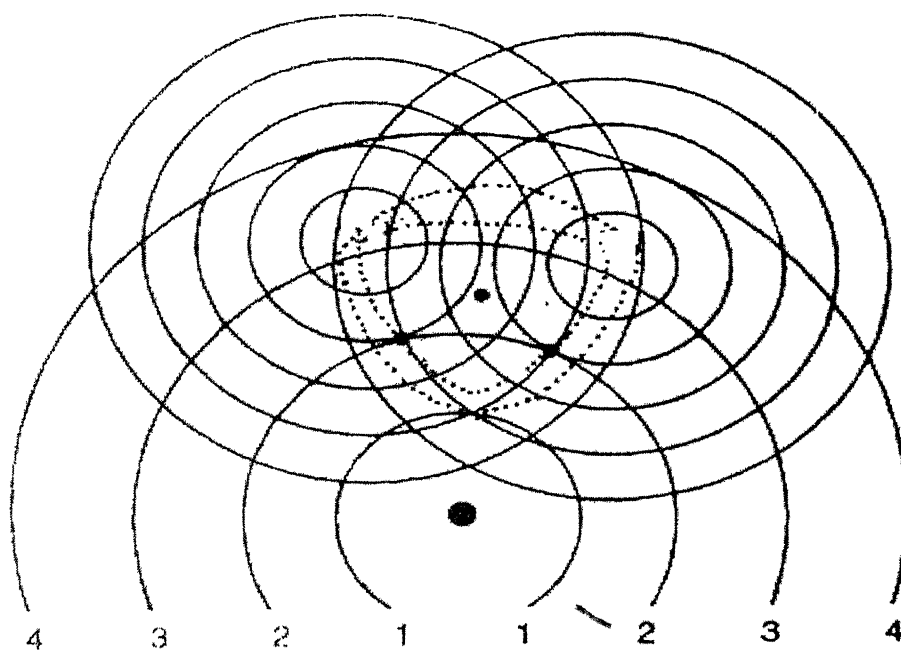
FIG. NO. 4.03 B

न्यूनतम श्रम लागत के स्थान से वहाँ अधिक बचत मिलती हो। रेखाचित्र संख्या ४.०४ में एक ही वस्तु का निर्माण करने वाले पाँच कारखाने A, B, C, D और E किसी क्षेत्र में पृथक-पृथक स्थानीकरण त्रिभुजों के अन्तर्गत दिखाये गये हैं या अवस्थित हैं। प्रत्येक त्रिभुज के चारों ओर निर्मित वृत्त संगत सीमान्त आइसोडापेन(Critical Isodapanes) प्रस्तुत करता है। जिससे दूर जाने पर उद्योगों को वर्तमान से अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसमें से छायांकित भागों में ही एकत्रीकरण की स्थिति सम्भव हो सकती है।

रेखाचित्र संख्या ४.०४ से स्पष्ट है कि तीन कारखानों A, B, C की समलागत वृत्त रेखाओं को मिलाने से उनके कटान बिन्दुओं से बनने वाला त्रिस्थल ही सर्वाधिक उपयुक्त एकत्रीकरण स्थल होगा। इस स्थल पर A, B, C तीनों ही कारखानें स्थापित किये जा सकते हैं। ऐसा करने से इन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। D एवं E कारखानें को इस स्थल पर स्थापित करने पर लाभ नहीं मिल सकेगा बल्कि हानि होगी।(सिद्धार्थ,के,२०००,पृष्ठ १५.-१५७)

सिद्धान्त की आलोचना- वेबर के सिद्धान्त की कई आधारों पर आलोचना की गयी हैं जो निम्नवत है-

१. यह सिद्धान्त स्वमान्यताओं एवं कल्पनाओं पर आधारित है। इन कल्पनाओं ने एक ओर वेबर के विश्लेषण को सरल बना दिया है तो दूसरी ओर उन्हें यथार्थता से दूर भी कर दिया है। उद्योगों के राजनैतिक स्वरूप के सन्दर्भ में डॉ० राजमल लोढ़ा ने लिखा है-वेबर ने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक स्वरूप में उद्योगों के स्थिति की व्यवस्था नहीं की। साम्यवादी, समाजवादी एवं प्रजातन्त्र प्रणाली आदि व्यवस्था में प्रत्येक के अपने विभिन्न उद्देश्य होने के कारण स्थापना स्थिति एक सी नहीं हो सकती। इस स्पष्टीकरण के अभाव में सिद्धान्त कल्पना मात्र है।

२. बेबर ने विभिन्न कारखानों की उत्पादन लागत को समान माना है जबकि ऐसा सम्भव नहीं है।

३. इन्होंने मूल्यों के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया है। मांग बढ़ने के साथ ही वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है।

४. कच्चे मालों के बीच विभेदों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

WEBER'S ANALYSIS OF THE OPERATION OF AGGLOMERATION TENDENCIES :-
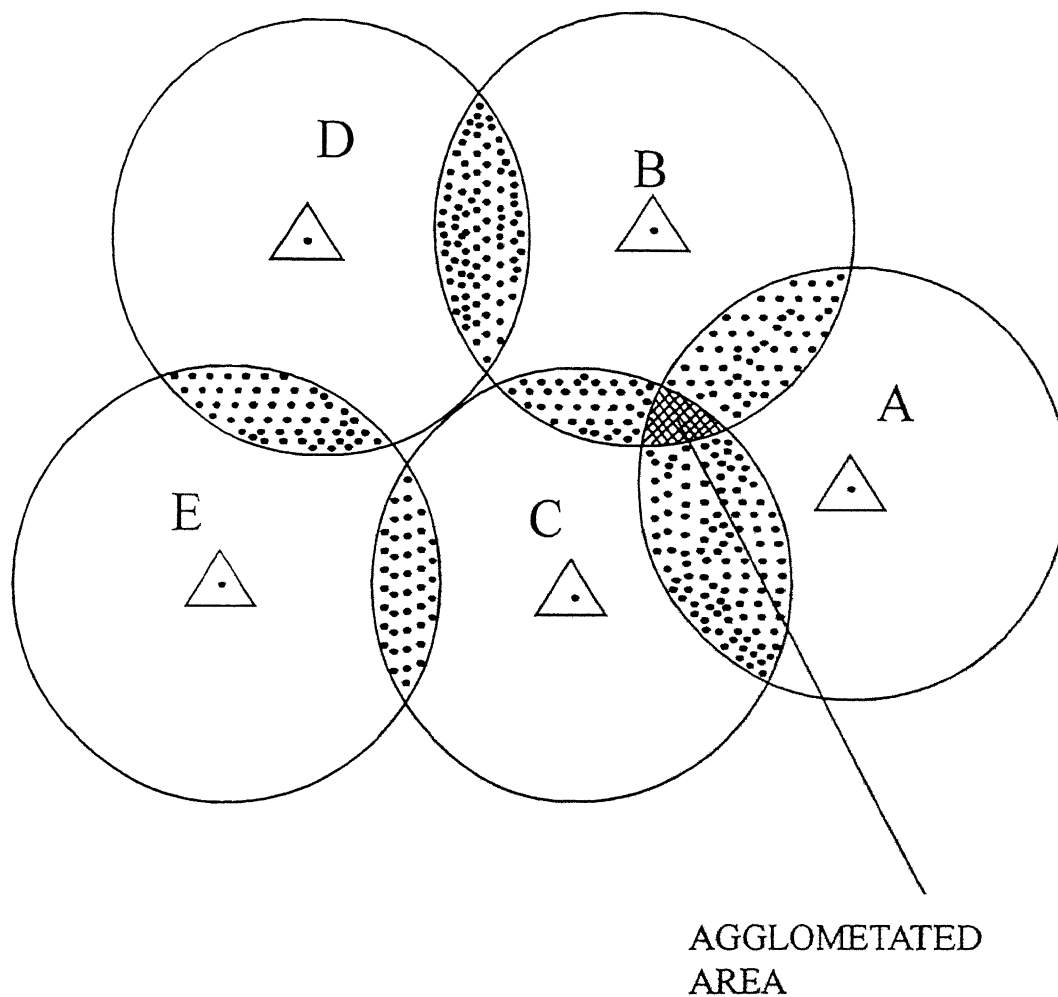
Fig.No-4.04

५. सामान्य स्थिति में न्यूनतम लागत स्थल या तो कच्चे माल के क्षेत्र या बाजार क्षेत्र होते हैं। कच्चे माल के स्रोत एवं बाजारके बीच न्यूनतम लागत का स्थल नहीं हो सकता। ऐसा होने पर माल को लादने एवं उतारने में अधिक व्यय होगा। इन्होंने कुछ स्थिति इन दोनों के बीच बतायी है,जो त्रुटिपूर्ण है।

६. किस क्षेत्र में स्थानीकरण का लाभ लेने के लिये उद्योगों को किस मौके तक विकसित होना चाहिए इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यह सजातीय एवं विजातीय उद्योगों के वितरण का प्रारूप भी स्पष्ट नहीं कर सका है।

७. अनेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं ऐतिहासिक तत्त्वों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

८. वेबर ने उद्योगों में प्रबन्ध के महत्त्व को प्रभावपूर्ण नहीं माना है।

९. रेल एवं सड़क परिवहन विकसित हो जाने से यह सिद्धान्त महत्त्वहीन सा लगता है।

औद्योगिक विकास की तीव्रता के होते हुये वर्तमान समय में भी बेबर का सिद्धान्त उपयोगी प्रतीत होता है। इसमें उद्योगों की स्थिति का उनके महत्त्वपूर्ण कारकों का, उद्योगों की अवस्थिति निर्धारण में पड़ने वाले प्रभावों को विशेष वैज्ञानिक रूप से बताया गया है। अनेक विद्वानों ने बेबर के विचारों, विश्लेषणों एवं विधियों को संशोधित एवं परिवर्द्धित रूप में अपनाया,इससे इसकी व्यावहारिकता बनी हुई है। इस प्रकार यह कुछ सीमाओं में होते हुये भी वास्तविक जगत में लागू होता है। वैसे स्वयं बेबर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सिद्धान्त में कमजोरी हो सकती है। इस सन्दर्भ में बेबर ने कहा कि इस क्षेत्र में यह प्रयास प्रारम्भ है,अन्त नहीं।(स्मिथ,डी० एम०,१९७१,पृष्ठ ११९)

वेबर के सिद्धान्त के अनुप्रयोग को न्यूनतम परिवहन लागत प्रभाव एवं ऐंग्लोमेरेशन प्रभाव को कुछ हद तक पूर्वी उत्तरप्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। चीनी उद्योग कारखाने कच्चे माल स्रोत पर निर्भर हैं लेकिन श्रम का प्रभाव औद्योगिक परिस्थिति पर नहीं दिखायी पड़ता क्योंकि विकासशील देशों जैसे इसी अध्ययन क्षेत्र में श्रमिक सामान्यतः कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर कौशलपूर्ण एवं निपुण श्रमिकों की कमी तो है

लेकिन अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं जिससे विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षायें पूरी की जा रही हैं;

पी० सारजेण्ट फ्लोरेन्स का सिद्धान्त

व्यावहारिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी सिद्धान्त फ्लोरेन्स का है। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धान्त के प्रतिपादन में इन्होंने आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया है। बेबर की भाँति इन्होंने भी अपने विचारों में अनेक कारकों एवं गुणांकों का प्रयोग किया है और निष्कर्ष निकाले हैं। जैसे स्थानीकरण गुणांक, केन्द्रीयकरण गुणांक, संयोजन गुणांक आदि। इनका विवरण निम्नवत है-

स्थानीकरण गुणांक -

इसकी गणना करने के लिये किसी क्षेत्र में किस उद्योग विशेष में कार्य करने वाले कुल श्रमिकों के प्रतिशत को उस क्षेत्र के समस्त उद्योगों में कार्य करने वाले कुल श्रमिकों के प्रतिशत से विभाजित किया जाता है। यदि प्रत्येक क्षेत्र के लिये प्राप्त गुणांक एक के लगभग है तो उस पूरे देश में वह उद्योग समान रूप से वितरित होगा परन्तु यदि वह गुणांक एक क्षेत्र में एक से अधिक और दूसरे क्षेत्रों में शून्य के लगभग है तो जिस क्षेत्र में गुणांक एक से अधिक है वहाँ उद्योगों का अधिक केन्द्रीकरण होगा। किसी भी क्षेत्र में स्थानीकरण गुणांक निम्नवत निकाला जाता है-

माना कि-

एक देश में सम्पूर्ण उद्योग धन्धों में लगे कुल श्रमिकों की संख्या है- ४०,०००

उस देश में कागज उद्योग में लगे कुल श्रमिकों की संख्या है- ७०००

उस देश में एक क्षेत्र के समान उद्योग में लगे कुल श्रमिकों की संख्या है- ८०००

उस क्षेत्र में कागज उद्योग में लगे कुल श्रमिकों की संख्या है- २००० इस तरह

क. उस देश में कुल कागज उद्योगों में लगे श्रमिकों के सन्दर्भ में उस क्षेत्र में कागज उद्योगों में लगे श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत = $2000 \times 100/7000 = 28.6$

ख. उस देश में कुल औद्योगिक श्रमिकों के सन्दर्भ में उस क्षेत्र में लगे कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत = 8000×100/40000=20

अतः स्थानीकरण गुणांक = क/ख = 28.6/20=1.43

इस सूत्र से निकाला गया मान एक से अधिक है अतः कागज उद्योगों का केन्द्रीकरण उस क्षेत्र में विशेष रूप से होगा।

केन्द्रीयकरण गुणांक - एक देश के कुल श्रमिकों के सन्दर्भ में एक क्षेत्र में लगे कुल श्रमिकों के प्रतिशत में से उस देश में किसी उद्योग विशेष में लगे कुल श्रमिकों के सन्दर्भ में उस क्षेत्र विशेष में लगे श्रमिकों के प्रतिशत को घटाकर हर क्षेत्र का पृथक-पृथक विचलन ज्ञात किया जाता है। इसमें से धनात्मक विचलन को १०० से भाग देकर केन्द्रीयकरण गुणांक ज्ञात किया जाता है। यह गुणांक यदि एकसेअधिक होता है तो औद्योगिक इकाईयाँ कच्चे माल के स्रोत के पास केन्द्रीकृत होने लगती है। परन्तु यदि गुणांक शून्य के आस-पास होता है तो यह विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। केन्द्रीयकरण गुणांक ज्ञात करने की बिधि निम्न प्रकार है-

माना कि-

एक देश में कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या ८०,००० है जिनका वितरण उसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः २४०००, १६०००, ३२००० एवं ८००० है।

उस देश में चीनी उद्योगों में कार्य करने वाले कुल श्रमिक १६००० हैं जिनका वितरण पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः ४०००, ८०००, २००० एवं २००० है।

उपर्युक्त आंकड़ों से प्रतिशत एवं विचलन की गणना निम्न प्रकार से की गयी है-

सारणी संख्या- ४.०१

क्षेत्र	एक देश में कुल औद्योगिक श्रमिकों के सन्दर्भ में उस क्षेत्र में कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत	उस देश की कुल चीनी मिलों लगे श्रमिकों के सन्दर्भ में उस क्षेत्र की चीनी मिलों में लगे श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत	विचलन
पूर्वी	३०	२५.०	+५.०
पश्चिमी	२०	५०.०	−३०.०
उत्तरी	४०	१२.५	+२७.५
दक्षिणी	१०	१२.५	−२.५

धनात्मक विचलन का योग = 5.0+27.5=32.5

इस तरह केन्द्रीयकरण गुणांक = 32.5/100 = .325

निष्कर्ष- इस क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल होगी।

संयोजन गुणांक- यह एक सांख्यिकीय प्रविधि है। जिसकी सहायता से किन्हीं दो या दो से अधिक उद्योगों के मध्य औद्योगिक सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि संयोजन गुणांक का मान एक के आसपास है तो इसका अर्थ है कि उन दो अथवा दो से अधिक उद्योगों में आपस में धनात्मक सम्बन्ध है। परन्तु यदि संयोजक गुणांक की गणना करने पर यह मान शून्य के आसपास आता है तो इसका अर्थ यह है कि उन उद्योगों में धनात्मक सम्बन्ध नहीं है।

स्पष्ट है कि संयोजक गुणांक अधिक होने पर एक उद्योग एक क्षेत्र विशेष में केन्द्रीयकृत हो जाता है। जिन उद्योगों का संयोजक गुणांक कम होता है वे एक दूसरे से दूर-दूर स्थापित होते हैं। संयोजक गुणांक की गणना निम्न प्रकार से की जाती है-(देखें सारणी संख्या 4.02 क, ख)

सारणी संख्या -४.०२ क

मान लिया कि एक देश में तीन उद्योग -क, ख एवं ग कार्यरत है जो देश के उत्तरी, दक्षिणी ,पूर्वी , पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित हैं।

उद्योग	देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक उद्योग में कार्य करने वाले श्रामिकों की संख्या					देश के प्रत्येक सम्बन्धित उद्योग में कुल श्रामिको की संदर्भ में प्रत्येक क्षेत्र में सभी उद्योग में सेवारत श्रामिकों का प्रतिशत			
	पूरे देश में श्रामिकों की संख्या	देश के प्रत्येक क्षेत्र में श्रामिकों की सं							
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
१	२		३			४			
क	२००,०००	८०,०००	२०,०००	६०,०००	४०,०००	४०	१०	३०	२०
ख	१६०,०००	३२,०००	६४,०००	४०,०००	२४,०००	२०	४०	२५	१५
ग	१००,०००	२०,०००	३२,०००	८,०००	४०,०००	२०	३२	८	४०

विभिन्न क्षेत्र के प्रतिशत में १०० से भाग देकर प्राप्त मान को एक में से घटा देगें। देखे सारणी संख्या ४.०२ ख

सारणी संख्या -४.०२ख

उद्योग	सारणी सुख्या ४.०२ के स्तम्भ चार के प्रतिशत मानों में १०० से भाग देने पर प्राप्त मान				स्तम्भ ६ के मान को एक में से घटाने पर शेष फल				ख उद्योग को आधार मानकर ख से क एवं ग उद्योगों का विचलन(प्रत्येक क्षेत्र में)स्तम्भ ७ देखे			
	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
५	६				७				८			
क	०.४०	०.१०	०.३०	०.२०	०.६०	०.६०	०.७०	०.८०	१०.२०	-०.३०	१०.०५	१०.०५
ख	०.२०	०.४०	०.२५	०.१५	०.८०	०.६०	०.७५	०.८५	ख आधार उद्योग हैं।			
ग	०.२०	०.३२	०.०८	०.४०	०.८०	०.६८	०.६२	०.६०	१०.००	-०.१७	-०.१७	१०.२५

अतः ख एवं क के मध्य संयोजन गुणांक =०.२० + ०.०५ +०.०५ = ०.३०

ख एवं ग के मध्य संयोजन गुणांक =०.२५

गणना से ख एवं क का संयोजन गुणांक ०.३० तथा ख एवं ग का संयोजन गुणांक ०.२५ प्राप्त होता हैं। ये दोनों ही मान शून्य के अधिक पास हैं । अतः देश के प्रत्येक क्षेत्र में क , ख एवं ग उद्योग एक दूसरे से सम्बन्धित नही हैं

आलोचना- १. इस सिद्धान्त में गुणांकों की गणना के अतिरिक्त कुछ नया नहीं है।

२. गुणांक की गणना करने के लिये क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन आवश्यक है।

३. क्षेत्रीय विभाजन की दशा में गणना में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। अधिक शुद्ध परिणाम ज्ञात करने के लिये लघुत्तम क्षेत्रों का चुनाव करना चाहिए। परन्तु ऐसा करने में अनेक समस्यायें उत्पन्न हो सकती है।

ई० एस० हूवर का सिद्धान्त- उद्योगों के स्थानीकरण के प्रारम्भिक सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त हूबर का है। इन्होंने १६३७ में अमेरिका में चर्म उद्योग एवं १६४८ में आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्यमनएवंविश्लेषण प्रस्तुत किया था। इनका अध्ययन आज भी उपयोगी माना जाता है। इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर औद्योगिक अवस्थिति सम्बन्धी समस्या की सामान्य प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

इनके सिद्धान्त की प्रमुख मान्यतायें निम्न हैं-

१. किसी भी स्थान पर उत्पादकों एवं विक्रेताओं में पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा होती है।

२. उत्पादन के कारकों में गतिशीलता पायी जाती है।

३. उत्पादन की प्रक्रिया पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है।

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर ही हूबर ने सारी सैद्धान्तिक रचना तैयार की। इन्होंने अनेक तकनीकी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो निम्न है-

क. भुगतान मूल्य- इसके अन्तर्गत उत्पादन मूल्य एवं उत्पादन का यातायात मूल्य दोनों को रखा गया है।

ख. यातायात प्रवणता- एक ही दिशा में स्थित विभिन्न बाजारों को जोड़ने वाले यातायात के रेखीय स्वरूप को यातायात प्रवणता कहा जाता है।

ग. सीमान्त रेखायें- यातायात प्रवणता को चिन्हित करने वाली रेखाओं को सीमान्त रेखायें कहते हैं।

हूबर के विचार में उद्योगों की स्थिति निर्धारण नें परिवहन लागत एवं उत्पादन अथवा निष्कर्षण लागत महत्त्वपूर्ण होते हैं। निष्कर्षण उद्योग की व्याख्या हूबर ने स्पष्ट रूप से की है तथा 'ह्रासमान प्रतिफल' नियम के लागू होने का अनुमान किया है। इनके विचार में उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ बाजार क्षेत्र एवं प्रति इकाई उत्पादन व्यय बढ़ता जाता है। इनके सैद्धान्तिक विचारों को रेखाचित्र संख्या ४.०५ में दर्शाया गया है।

हूबर ने निर्माण उद्योगों की व्याख्या में बेबर के विचारों का भी सहारा लिया है। बेवर के समान हूवर ने भी उत्पादन व्यय में अन्तर न होने पर उद्योग की स्थापना न्यूनतम परिवहन लागत स्थल पर ही माना है। यह स्थान कच्चे माल का स्रोत बाजार बिन्दु अथवा अन्य कोई मध्यस्थ बिन्दु हो सकता है।

इस स्थल का चुनाव आइसोडापेन तथा सम विक्रय मूल्य रेखाओं की सहायता से किया जाता है। परिवहन व्यय के समान होने पर भी न्यूनतम परिवर्तन व्यय के बिन्दु के अवस्थिति त्रिभुज के भीतर स्थित होने की सम्भावना अत्यन्त कम होती है। इनके विचार से किसी भी उद्योग की स्थापना करते समय उद्यमीं न्यूनतम लागत वाले क्षेत्र का ही चुनाव करता है। विभिन्न दूरियों पर स्थित स्रोतों से कच्चा माल एकत्रित करने एवं दूरस्थ स्थित उपभोक्ता को उत्पादित वस्तु पहुँचाने में (दोनों पर) होने वाली असुविधा तथा व्यय को न्यूनतम करने के लिये उद्योगपति या तो कच्चामाल स्रोत पर अथवा उत्पादित माल के बाजार स्थल पर अपना उद्योग स्थापित करता है। न्यूनतम लागत के लिये वह स्थानान्तरण व्यय को भी न्यूनतम करना चाहता है। हूवर ने यह भी बताया कि सामान्य दशा में वैकल्पिक मार्ग वाले स्थल तथा अधिक यातायात वाले मार्गो पर किराया दर न्यून होती है। (हूवर,ई० एम० १६४८,पृष्ठ २३)मध्यस्थ स्थानों पर वस्तुओं को उतारने चढ़ाने या उन पर अन्य प्रकार के लागत होने के कारण वहाँ न्यूनतम परिवहन व्यय नहीं हो सकता। परन्तु यदि यह मध्यस्थ स्थल बिन्दु यातायात के साधनों का विच्छेदन बिन्दु है अर्थात् जहाँ पर माल को एक साधन से दूसरे साधन पर उतारना चढ़ाना पड़ता है वहाँ पर भी उद्योग लाभदायक रूप में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इन्होंने बाजार कच्चेमाल के स्रोत तथा विच्छेदन बिन्दु को ही उपर्युक्त न्यूनतम परिवहन लागत का बिन्दु माना है।

BOUNDARY LIMITS BETWEEN TWO PRODUCTION CENTRES (BASED ON HOOVER)
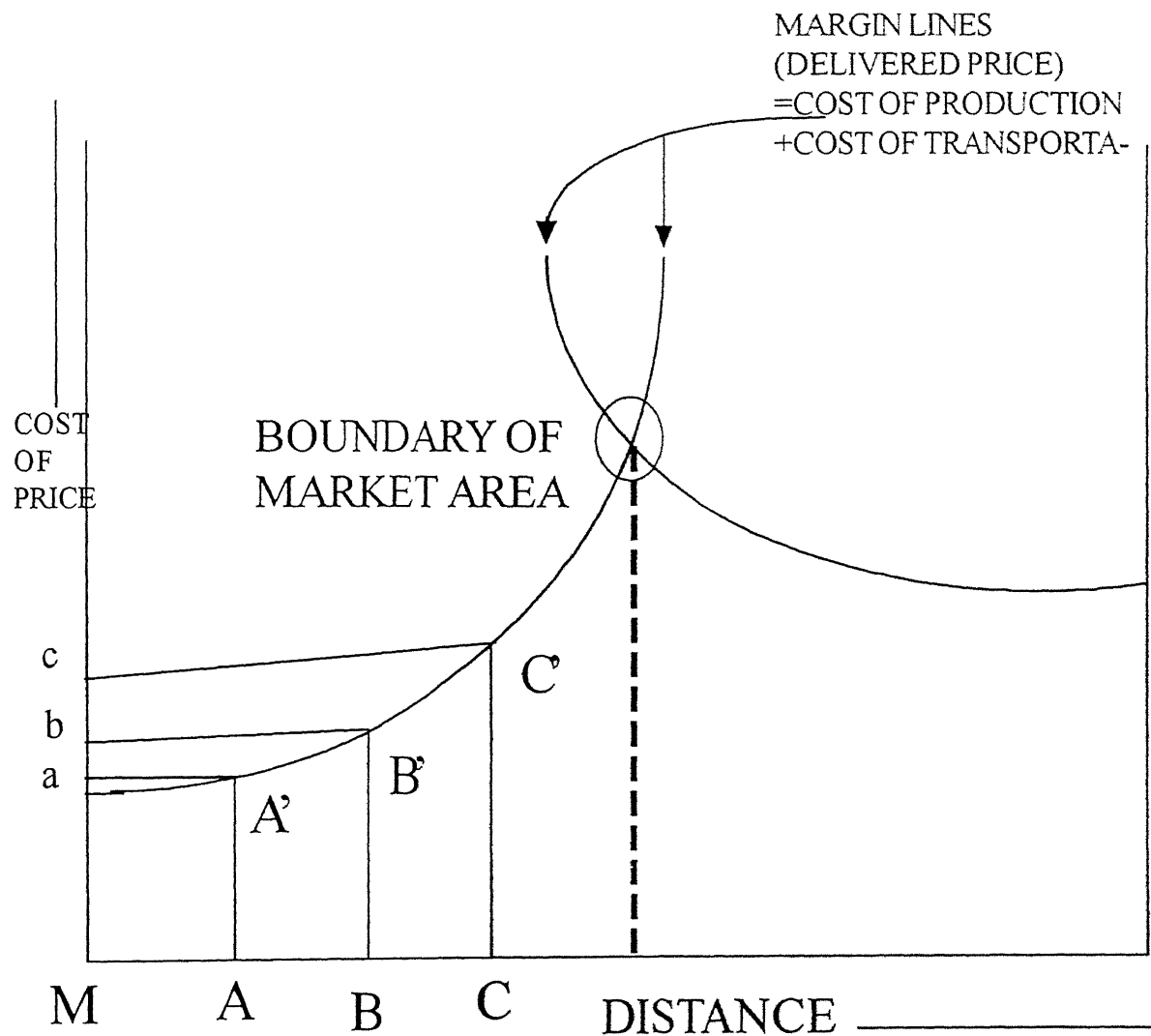
FIG.No.-4.05

आलोचना- इनके सिद्धान्त में कई कमियाँ हैं जिनकी ओर आलोचकों ने ध्यान इंगित किया है-

१. इस सिद्धान्त में परिवहन लागत की व्याख्या में सभी कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

२. इन्होंने उत्पादित वस्तु की मांग की अपेक्षा उसकी लागत को अधिक महत्त्व दिया है इससे इस सिद्धान्त की अवास्तविकता बढ़ी है और उपयोगिता क्षीण हो गई है ।

टार्ड पैलेण्डर का बाजार क्षेत्र सिद्धान्त-

औद्योगिक स्थानीकरण की समस्याओं के सन्दर्भ में यह सिद्धान्त विकसित किया गया है। इसमें उद्योगों के स्थानीकरण पर पड़ने वाले परिवहन व्यय एवं उत्पादन व्यय के प्रभावों स्थानीकरण पर पड़ने वाले परिवहन व्यय एवं उत्पादन व्यय के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में दो मौलिक प्रश्न प्रस्तुत किये गये हैं-

१. कच्चे माल की स्थिति, मूल्य एवं बाजार की स्थिति का समुचित ज्ञान होने पर उद्योग वहाँ स्थापित किया जाय।

२. उत्पादन के स्थान, प्रतिद्वन्द्विता की दशाओं, उत्पादन की लागत एवं परिवहन मूल्य का ज्ञान होने पर बाजार का विस्तार किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य से प्रभावित होता है।

पैलेण्डर ने प्रथमतः बाजार क्षेत्र निर्धारण की समस्या का विश्लेषण किया है। इसके लिये इन्होंने दो औद्योगिक इकाईयों का उदाहरण लिया है जो कि एक ही वस्तु का निर्माण करती है एवं इनका बाजार एक सीधी रेखा के अनुरूप फैला हुआ है। रेखा चित्र संख्या ४.०६ में इसका प्रदर्शन किया गया है। इसमें 'क' और 'ख' दो औद्योगिक इकाईयाँ हैं जिनका बाजार क्षेत्र आरेख के क्षैतिज आधार के अनुरूप फैला हुआ है। इन उद्योगों का कारखाना मूल्य उर्ध्ववर्ती रेखाओं (ए,ए' औद्योगिक इकाई ए के लिये एवं बी. बी' औद्योगिक इकाई बी के लिये) द्वारा दिखाया गया है। कारखानें में दूरी बढ़ने पर उसमें परिवहन व्यय

BOUNDARY DEMARCATION BETWEEN TWO COMPETING FIRMS (A & B
(BASED ON PALANDER)
P (Price)
GRADIENT OF
DELIVERED
PRICE
FREIGHT
COSTS
A′
B′
PRICE
OF
PLANT
A
X
B
d (distance)
MARKET OF A
MARKET OF B
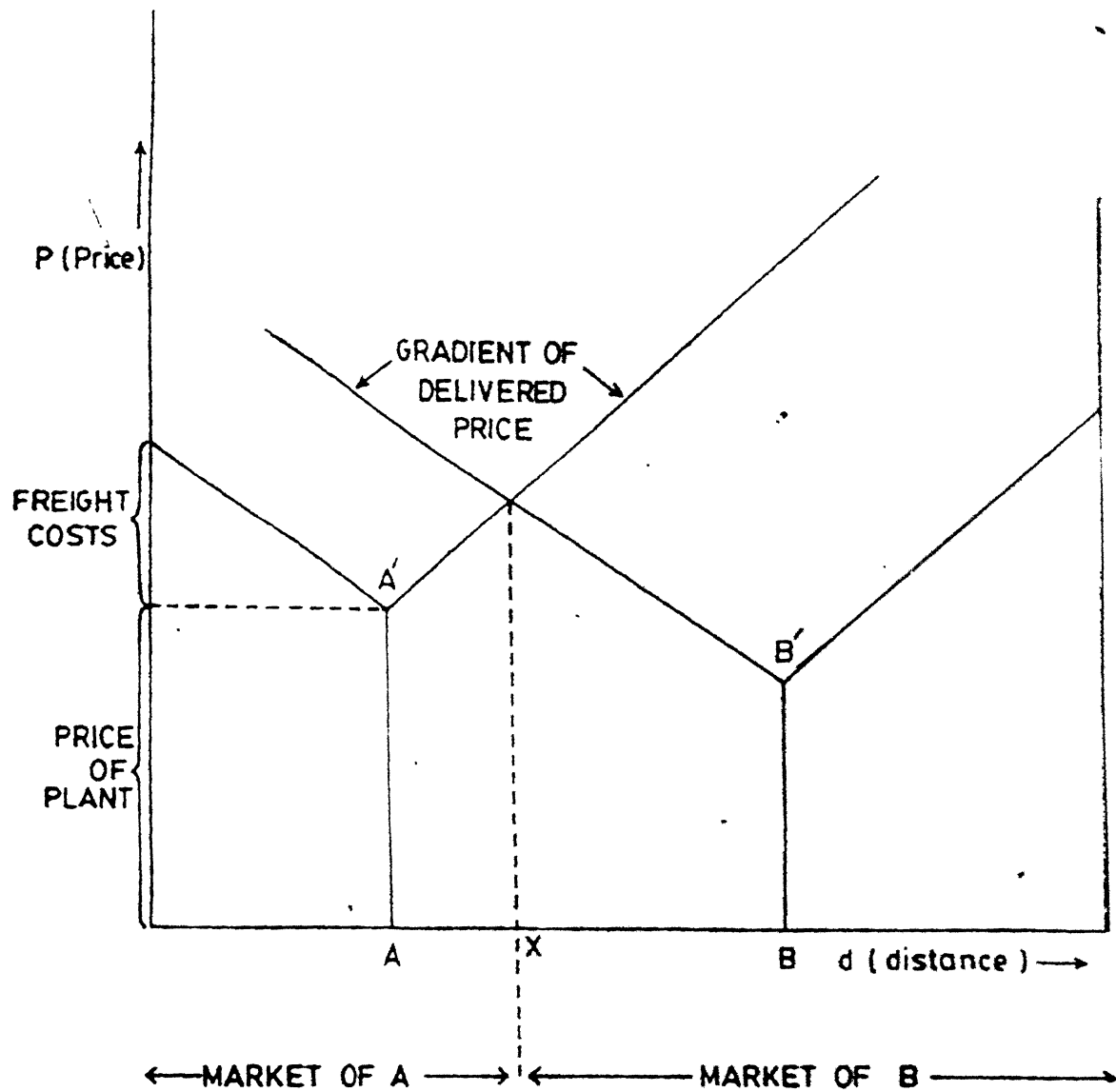
Fig. No-4.06

जुड़ जाता है जिसके कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति को 'ए' एवं 'बी' की बिन्दुओं से दोनों तरफ उठी रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। अतः किसी भी स्थान पर किसी वस्तु के मूल्य में संयत्र मूल्य एवं परिवहन लागत सम्मिलित होते हैं। संयन्त्र मूल्य में दूरी के साथ परिवर्तन नहीं होता जबकि परिवहन व्यय दूरी एवं भार के अनुरूप बदलता जाता है। बिन्दु 'सी' पर दोनों औद्योगिक इकाईयों से पहुँचायी जाने वाली वस्तु का मूल्य बराबर हो जाता है। अतः यही 'सी' बिन्दु दोनों औद्योगिक इकाईयों के बाजार की सीमा होगी।

इन्होंने कारखाना मूल्य एवं परिवहन मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न सम्भावित स्थितियों को भी स्पष्ट किया है। तथा परिवर्तन को महत्त्वपूर्ण माना है। इन्होने वेबर की आइसोडोपेन विधि का प्रयोग करके स्थानीकरण पर पड़ने वाले परिवहन व्यय के प्रभाव को भी स्पष्ट किया है। साथ ही साथ सम परिवहन समय रेखा (आइसोक्रोन्स), सम विक्रय मूल्य रेखा (आइसोरियस), सम परिवहन व्यय रेखा (आइसोवेक्टर्स तथा आइसोडिस्टेन्टर) जैसी प्रणालियों का उपयोग किया है। इनके अनुसार परिवहन व्यय दूरी के अनुसार घटता है। फलस्वरूप त्रिभुज के कोणों पर न्यूनतम परिवहन व्यय के बिन्दुओं की अधिक सम्भावना होती है।

आलोचना- पैलेण्डर के विचारों पर वेबर के विचारों का अधिक प्रभाव था फिर भी इन्होंने वेबर की कई बातों को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने उद्योगों के स्थानीकरण को गत्यात्मक माना है। इनका सिद्धान्त वेबर के सिद्धान्त का मात्र संशोधन ही नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। औद्योगिक इकाईयों के मध्य स्थानिक प्रतिद्वन्द्विता का विश्लेषण इस सन्दर्भ में नया आयाम है।

यद्यपि पैलेण्डर ने उद्योगों के स्थानीकरण के क्षेत्र में नये विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तथापि वेबर के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण की तुलना में इनका प्रयास अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता है। अतः बाद में आने वाले विद्वानों के विचारों को वेबर की अपेक्षा पैलेण्डर के विश्लेषण ने बहुत कम प्रभावित किया है।

आगस्त लॉश का सिद्धान्त -

लॉश भी एक प्रमुख जर्मन अर्थशास्त्री थे। औद्योगिक अवस्थित के सन्दर्भ में लॉश ने अपने सैद्धान्तिक विचारों को अपने १९४० में जर्मन भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। बाद में अंग्रेजी भाषा में भी इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ।

लॉश के अनुसार कोई भी उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहाँ कुल विक्रय मूल्य एवं कुल लागत में अन्तर अधिकतम होगा। लॉश का विचार है कि किसी क्षेत्र में सभी उद्योग अर्न्तसम्बन्धित होते हैं इससे एक उद्योग की स्थापना से दूसरे उद्योग की पुर्नस्थिति निश्चित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अतः उद्योगों की स्थिति को ठीक ढंग से निर्धारित करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसका सरल रूप ही विभिन्न सिद्धान्तों में समाहित किया जा सकता है।

लॉश ने अपने विश्लेषण में अनेक मान्यताओं को शामिल किया है। इन्होंने इसमें ऐसे विस्तृत मैदान की कल्पना की है, जिस पर कच्चामाल समान रूप से सर्वत्र पाया जाता है एवं परिवहन की दरें भी सर्वत्र समान हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपना सिद्धान्त कार्यकलापों पर लागू किया और परीक्षण किया कि आर्थिक सन्तुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, यदि कृषक कुछ वस्तुओं का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और उसे बाजार में प्रस्तुत करते हैं।

लॉश ने सर्वप्रथम आर्थिक सन्तुलन स्थापित करने का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार इसे प्राप्त करने के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उनके गुण विद्यमान होने चाहिए। इस तरह औद्योगिक स्थिति से उत्पादक एवं उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। उत्पादन संस्थानों का वितरण प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। उपभोक्ता उस स्थान पर जहाँ दो उद्योगों के बाजार क्षेत्र मिलते हैं किसी से भी वस्तुयें खरीदने को तैयार हों। आर्थिक सन्तुलन की स्थिति किस प्रकार उत्पन्न होती है इसके बार में इनका कहना है कि किसी क्षेत्र में एक ही उद्योग की स्थिति होने पर बाजार क्षेत्र की आकृति वृत्ताकर होगी लेकिन अनेक औद्योगिक इकाईयों के स्थापित होने पर प्रतिस्पर्द्धा की दशा में बाजार क्षेत्र षटभुज की आकृति का होगा। किसी उद्योग का बाजार तीन अवस्थाओं को

पार करे ही षटभुजीय आधार प्राप्त करता है। इसका प्रदर्शन रेखा चित्र ४.०७ में किया गया है।

प्रथम अवस्था में एक उद्योगपति 'P' स्थान पर उद्योग लगाता है। इसमें उत्पादन का मूल्य दूरी के साथ बढ़ता जाता है तथा उत्पादित वस्तु की मांग मूल्य बढ़ने के साथ-साथ घटती जाती है।

दूसरी अवस्था में वृत्ताकार बाजार वाली कई औद्योगिक इकाईयाँ हैं परन्तु वह पूरे क्षेत्र की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है अतः इन वृत्ताकार बाजार क्षेत्रों के बीच अन्य उद्योगपति भी उद्योग स्थापित करते हैं। फलस्वरूप पूर्व उद्योगपतियों के अतिरिक्त लाभ का क्षेत्र कम हो जाता है और उनके बाजार का क्षेत्र भी छोटा हो जाता है। इस प्रक्रिया में बाजारों का आधार षटभुजीय हो जाता है।

इन षटकोणीय तन्त्रों को घुमाया जाय तो ६ सेक्टर बनेंगे जहाँ कई वस्तुओं का उत्पादन एक ही स्थान पर होगा। इनके बीच बीच में ६ अन्य सेक्टर भी बनेंगे जिनमें ऐसी स्थिति बहुत कम होगी। लाश ने इन्हें क्रमशः ७ नगर सम्पन्न एवं अल्पनगर सम्पन्न सेक्टर कहा है। ऐसी दशा में उद्योगों की इकइायों के बीच की दूरियाँ न्यूनतम होती जायेंगी तथा परिवहन दूरियाँ भी क्रमशः कम होती जायेंगी। इससे परिवहन व्यय भी कम होता जायेगा। इस आदर्श स्थिति में सरकार की विशेष नीतियों के कारण, यातायात की कुछ असुविधाओं में, जनसंख्या वृद्धि से एवं संसाधनों की बढ़ोत्तरी से अथवा उसके ह्रास से स्थिति विरूपण होता रहेगा।

आलोचना- १. इन्होंने लागत में आने वाली स्थानिक भिन्नताओं पर विचार नहीं किया है।

२. इसका प्रयोग विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में करना सम्भव नहीं है।

३. यह अनेक मान्यताओं पर आधारित है इसके कारण इसका महत्त्व कम हो गया है।

४. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आदर्श बाजार तन्त्र का उपयोग नहीं किया जा

HEXAGONAL MARKET AREAS
(ACCORDING TO LOSCH)
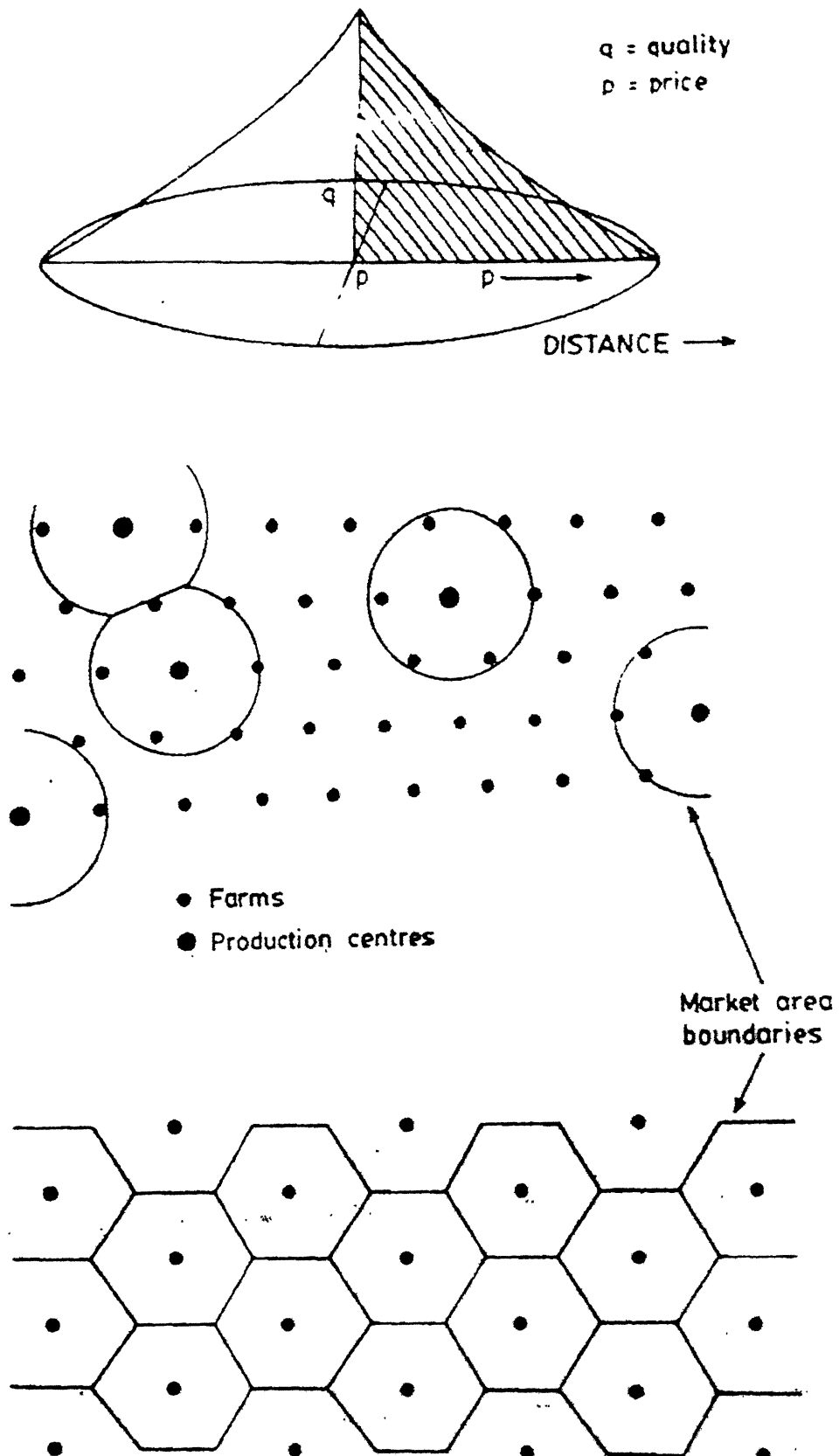
(Source; D.M.Smith, INDUSTRIAL LOCATION, 1970. P. 133.)

Fig. No-4.07

सकता।

मेलवीन ग्रीनहट का सिद्धान्त-

ग्रीनहट ने विर्निमाणी उद्योग के स्थानीकरण के सम्बन्ध में अपना सिद्धान्त विकसित किया है। इनके अनुसार स्थानीकरण के सिद्धान्तों का प्रमुख उद्देश्य यह देखना होता है कि एक कारक कैसे किसी उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण है और दूसरे के लिये नहीं। इन्होंने सबसे पहले न्यूनतम लागत एवं अर्न्तसम्बन्धित स्थानीकरण के सिद्धान्तों को एकही नियम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

ग्रीनहट ने स्थानीकरण के कारकों को ५ वर्गों में विभाजित किया है-

१. परिवहन २. निर्माणलागत ३. मांग ४. लागत घटाने वाले कारक ५. राजस्व बढ़ाने वाले कारक

परिवहन महत्त्वपूर्ण कारक है जिससे स्थानीकरण को बढ़ाया जा सकता है। अतः किसी उत्पादन की कुल लागत पर यातायात के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अलग से अध्ययन करना आवश्यक होता है।

ग्रीनहट की विचारधारा के अनुसार जिस उद्योग की कुल लागत पर परिवहन लागत का अंश अधिक होता है, उस उद्योग का मालिक उद्योग को ऐसे स्थान पर स्थापित करेगा जहाँ परिवहन व्यय न्यूनतम होगा। कभी कभी उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में ही लगाया जाता है। यदि उत्पादित वस्तु जल्दी ही खराब हो जाने वाली है तो ऐसे उद्योगों को बाजार के निकट स्थापित करना ही उचित होता है।

'निर्माण लागत' वर्ग के अन्तर्गत श्रम, पूँजी एवं टैक्स आदि को रखा गया है। इनके अनुसार औद्योगिक स्थानीकरण में 'मांग' प्रमुख कारक है। उत्पादन की मांग की प्रधानतः अधिक होने की दशा में कारखानों का वितरण अधिक फैला होगा। उपभोक्ता तक उत्पादित वस्तु पहुँचाने में परिवहन व्यय अधिक होने की दशा में अथवा कारखानों की संख्या अधिक होने की दशा में भी कारखाने फैले हुये रूप में ही स्थापित होंगे।

ग्रीनहट ने लगात घटाने वाले तथा राजस्व को बढ़ाने वाले कारकों को भी उद्योगों के स्थानीकरण में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। इस कारण कोई भी उद्यमी अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले इन कारकों पर विवेकपूर्ण विचार करता है परन्तु कभी-कभी उद्यमी का निर्णय अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है।

वाल्टर इजार्ड का स्थानापन्न सिद्धान्त

इनके सिद्धान्त को स्थानापन्न उपागम सिद्धान्त भी कहते हैं। इसमें परिवहन को अधिक महत्त्व दिया गया है। इजार्ड ने उत्पादन के ४ उपादानों- श्रम, पूँजी, भूमि एवं प्रबन्ध को भी परिवहन के समान महत्त्वपूर्ण माना है।

इन्होंने परिवहन की व्याख्या में स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया है। इजार्ड के द्वारा वेबर के परिवहन अवस्थिति विश्लेषण का समर्थन किया गया है। व्यावहारिक रूप में सन्तुलित स्थानीकरण की स्थिति वेबर के आइसोडापेन विधि से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इजार्ड ने हूवर एवं लॉश के विचारों को भी स्वीकार किया है। इन्होंने अपने सिद्धान्त में कच्चे माल के अनेक स्रोतों से वस्तुओं के उत्पादन के अनेक केन्द्रों तक तथा इन केन्द्रों से विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक के वितरण पर भी गहन विचार किया है। इन्होंने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिये यातायात एवं श्रम को लिया है तथा बताया है कि सस्ते श्रम स्थल सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं।(इजार्ड,डब्लू,१९५६.पृष्ठ १३१)

इन्होंने स्थानीकरण त्रिभुज के माध्यम से स्थानापन्न के सिद्धान्त को समझाया है। देखे रेखाचित्र संख्या ४.०८ A,B,C। रेखाचित्र संख्या ४.०८ A, B में त्रिभुज के एक कोनें पर बाजार 'K' तथा शेष दोनों कोनों पर GG' पर कच्चे माल के स्रोत हैं। अगर उद्योग में खपत होने वाले कच्चे माल की मात्रा तथा उसके परिवहन की दर मालूम हो तथा किसी कोनें से कारखानों की दूरी तय कर ली गयी हो तो अब प्रश्न इन निर्णयों को ध्यान में रखकर कारखानें की अनुकूलतम स्थिति निर्धारित करना रह जाता है। अगर उद्योग K स्थान से तीन मील दूर की दूरी पर लगाया जाता है तो K से इतनी दूरी पर खींचे गये वृत्तखण्ड I, M पर यह स्थिति कहीं भी हो सकती है। यह निर्धारित करने के लिये कि बिन्दु की स्थिति कहाँ होगी, इस वृत्तखण्ड को रूपान्तरित रेखा के रूप में बनाया जाय,

K
LOCATIONAL TRIANGLE
M
3 MILE
I
8 MILE
5 MILE
G
G′
7 MILE
B-
DISTANCE FROM G (IN MILE)
M
I
C-
ISOSPEND
DISTANCE FROM G (IN MILE)
DISTANCE FROM G
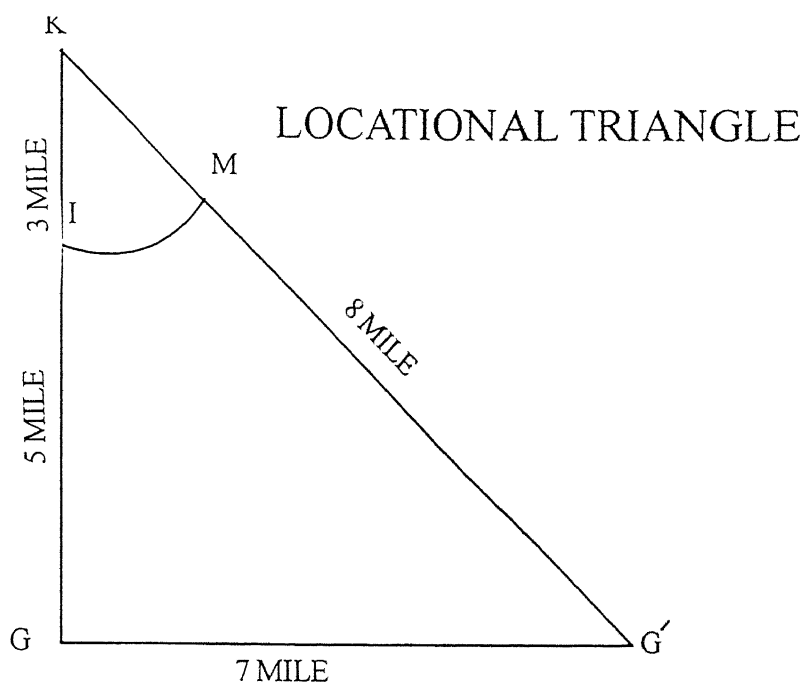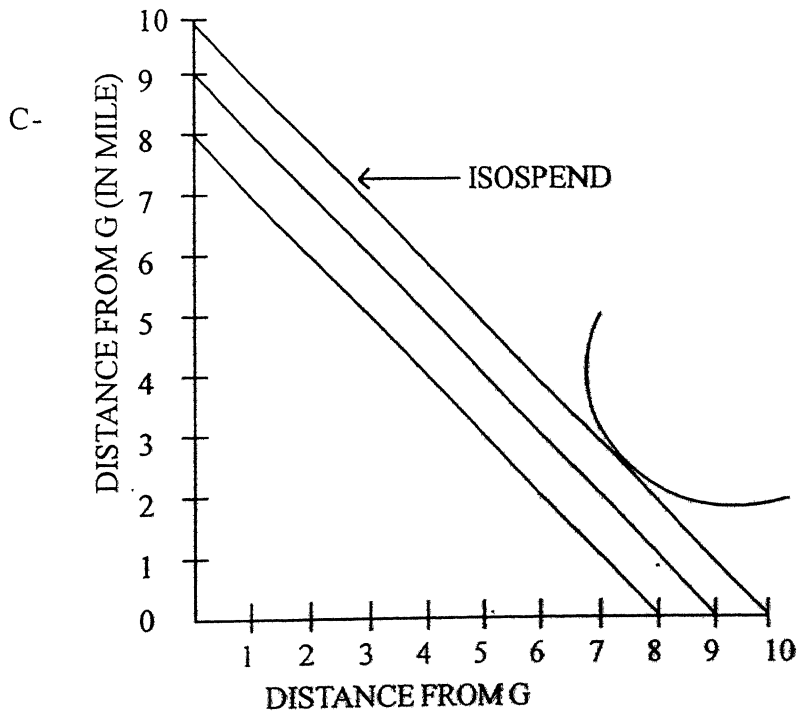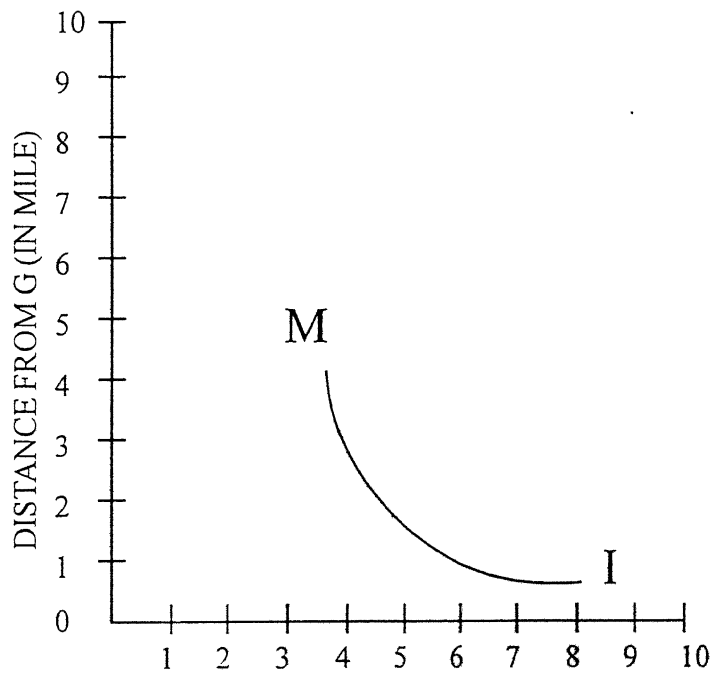
Fig. No-4.08

जिससे दूरियाँ G, G' बिन्दुओं के अनुपात में निश्चित की जाय। इन रूपान्तरित रेखा के M बिन्दु से बिन्दु की ओर बढ़ने पर बिन्दु G से दूरी तो घट जाती है किन्तु G' से यह बढ़ जाती है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बिन्दु के परिवहन निवेश के स्थान की पूर्ति दूसरे स्थान के परिवहन निवेश से हो रही है। ऐसी दशा में न्यूनतम लागत का बिन्दु ढूढ़ने के लिये ग्राफ पर समव्यय रेखायें खीचना आवश्यक होता है। इसके लिये यदि यह कल्पना कर ली जाय कि स्थान G से एक टन तथा स्थान G' से भी एक टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है और परिवहन की दर समान है तो सरलता होगी। ये लाइनें सीधी होती होंगी और उनका नकारात्मक ढाल १.०० होगा । चित्र संख्या ४.०८ C। वक्रखण्ड के जिस बिन्दु पर न्यून सम व्यय रेखाये स्पर्शीय हों वही बिन्दु की आदर्श स्थिति होती है। इस बिन्दु के अलावा व्यय बढ़ता जाता है। यह आदर्श स्थिति K बिन्दु से ली गयी काल्पनिक दूरी पर आधारित है। इसलिये सही आदर्श स्थिति जानने के लिये बिन्दु G तथा G' से भी निश्चित दूरियाँ लेकर इसकी गणना करनी पड़ती है।

आलोचना-

१. इनका सिद्धान्त पूर्व के सिद्धान्तकारों जैसे वेबर पैलेण्डर एवं लॉश से अधिक प्रभावित होता है।

२. विश्व की वर्तमान परिस्थिति में इसका विश्लेषण अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि औद्योगिक कार्यकलापों पर आर्थिक कारकों के अलावा अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है इसमें सामाजिक, क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक कारक महत्त्वपूर्ण हैं।

भूगोलवेत्ताओं का योगदान-

प्रारम्भिक भूगोलवेत्ताओं में हार्टशोर्न का प्रमुख स्थान है। इन्होंने आर्थिक क्रियाओं के स्थानीकरण में उच्चावचन, जलवायु, मिट्टी आदि प्राकृतिक कारकों के प्रभावों को भी सापेक्ष स्थिति के निर्धारण में विशेष स्थान दिया। इन्होंने किसी स्थान पर नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से पूर्व उस विशेष स्थान पर उद्योगों के स्थानीकरण में विभिन्न आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों के सापेक्षिक प्रभावों में मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है। इस प्रकार हार्टशोर्न ने उद्योगों के स्थानीकरण पर विभिन्न कारकों द्वारा डाले जाने

वाले प्रभावों की ओर स्पष्ट संकेत किया है परन्तु विस्तृत स्पर्ष्टीकरण नहीं किया है।

१६४७ में जार्ज रेनर ने भी उद्योगों के स्थानीकरण के विषय में सामान्य सिद्धान्त की विवेचना की है। इन्होंने उद्योगों को ४ श्रेणियों में विभाजित किया है-

१. निष्कर्षण २. जननात्मक ३. निर्माणात्मक ४. सुगमीकरण उद्योग

इनके अनुसार प्रत्येक वर्ग के उद्योग के लिये ६ उपादानों यथा कच्चेमाल, बाजार, श्रम, शक्तिपूंजी एवं परिवहन की जरूरत पड़ती है। अलग-अलग उद्योगों में भिन्न-भिन्न कारक प्रभावशाली होते हैं। कई उद्योगों में एक से अधिक उपादान सम्मिलित रूप से उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन ६ उपादानों की एक साथ एक समान उपस्थिति किसी भी क्षेत्र में सम्भव नहीं है।

इसी कारण किसी उद्योग की स्थापना उस स्थान पर ही लाभकारी होती है। जहाँ एक से अधिक कारक अनुकूल रूप में उपलब्ध होते हैं। जहाँ पर सभी उपादान उपलब्ध नहीं होते वहाँ अन्य स्थानों से कुछ उपादान मंगाये जाते हैं। उद्योग स्थापना के आदर्श नियम के अनुसार उद्योग के स्थानीकरण में वह कारक विशेष निर्णायक होता है जो सर्वाधिक महँगा हो अथवा जिसका परिवहन अधिक व्यय साध्य हो । उद्योग स्थापना की समस्या विभिन्न कारकों को एक चयनित स्थान पर एकत्रित करके सुलझायी जाती है, इस चयनित स्थान पर उनमें एक या अधिक कारक पहले से ही पाये जाते हैं।

शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल का प्रयोग जिस उद्योग में अधिक होता है, उसका कारखाना कच्चे माल के क्षेत्र के निकट ही स्थापित किया जाता है डेरी एवं मत्स्य उद्योग इस वर्ग में आते हैं। परन्तु यदि उत्पादित वस्तु का आकार एवं भार उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु के निर्माण का कारखाना बाजार के समीप ही स्थापित करना लाभदायक होता है।

शीघ्र टूटने, गलने, डिजाइन परिवर्तन तथा तापमान से जुड़ी वस्तुयें आदि के कारखाने बाजार के निकट ही स्थापित किये जाते हैं। जिन उद्योगों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है उनकी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया में उर्जा का विशेष महत्त्व होता है। इस प्रकार

उद्योगों को उर्जा के स्रोतों के समीप ही स्थापित किया जाना आवश्यक है। जिन उद्योगों में अधिक संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और यदि ऐसे कुशल श्रमिक कुछ विशेष क्षेत्रों में रहते हैं तो ऐसे उद्योगों के स्थानीकरण को श्रमिक उपलब्धता के क्षेत्र अधिक प्रभावित करते हैं।

रेनर ने औद्योगिक संकेन्द्रण का भी वर्णन किया है इने इन्होंने औद्योगिक सहजीवन कहा है। इसके दो प्रकार हो सकते हैं-

१. असंयोजक सहजीवन

२. संयोजक सहजीवन

असंयोजक सहजीवन वह है जब औद्योगिक स्थल पर दो से अधिक भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों को एक ही क्षेत्र में स्थापित करना लाभदायक होता है। इनमें कोई जैवकीय समानता नहीं होती है जैसे सिल्क वस्त्र उद्योग में सस्ता महिला श्रम अधिक उपयोगी होता है। अतः यह ऐसे क्षेत्रों में विकसित किया जाता है जहाँ श्रमिकों के परिवार में महिलायें मिल जाती हैं।

इसके अलावा जब किसी क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के उद्योग एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं तो इस स्थिति को संयोजक सहजीवन कहा जाता है । इस प्रकार के उद्योगों में परस्पर जैविकीय सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस दशा में एक उद्योग द्वारा निर्मित माल दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा इस्पात इकाई के निकट लोहे से बनने वाली वस्तुओं के उद्योग लगाये जाते हैं। इस प्रकार उद्योगों का किसी विशेष क्षेत्र में संकेन्द्रण हो जाता है जिसे संयुक्त औद्योगीकरण कहा जाता है। डेविस स्मिथ ने रेनर के सिद्धान्त को महत्त्वपूर्ण माना और रेनर को औद्योगिक सिद्धान्त निर्माताओं में प्रथम विशेषज्ञ माना है।(स्मिथ, डी० एम०, १६७१. पृष्ठ ६८)

आलोचना- यद्यपि रेनर का विश्लेषण व्यापक है किन्तु इसमें आर्थिक पक्ष की कई कमजोरियाँ दिखायी पड़ती है। इन्होंने अनेक कारकों को एकसाथ रखने का प्रयत्न किया है फिर भी आर्थिक कारणों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहे। इनके द्वारा मूल्य में पाये जाने

वाले अन्तर का वर्णन ठीक से नहीं किया गया है। उद्योगों को स्थानीकरण के विषय में ई० एम० रोस्ट्रान का एक शोधपत्र १६५८ ई० में प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने तीन सैद्धान्तिक विचारधाराओं की चर्चा की थी। ये विचारधारायें भौतिक, आर्थिक एवं तकनीक नियन्त्रण से सम्बन्धित थी।

भौतिक नियन्त्रण वहाँ लागू होता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उत्पादन किया जाता है। जैसे प्रकृति ने खनिज के कुछ स्थान निश्चित किये हैं। एक खनिज प्रायः कई क्षेत्रों में पाया जाता है परन्तु हर जगह खनन कार्य आर्थिक रूप से लाभदायक नही होता है। इस सिद्धान्त की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि किसी खनिज का खनन किस क्षेत्र में लाभदायक होगा।

आर्थिक नियन्त्रण लाभ की स्थानिक परिधि के नियम पर आधारित है। कोई भी उद्योग उस परिधि से बाहर स्थापित नहीं किया जा सकता, जहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से लागत अधिक हो इसका पता लागने के लिये कच्चे माल, श्रम, भूमि व्यापार एवं इसमें पूंजी के व्यय को सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने परिवहन व्यय को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। इनके अनुसार अन्य कारकों की लागत के स्थानिक अन्तर द्वारा ही परिवहन व्यय स्वतः व्यक्त हो जाता है। स्थिति चुनाव के कारण आने वाली लागत को स्थानिक लागत कहा जाता है। न्यूनतम स्थानिक लागत वाले स्थान पर ही उद्योग स्थापित करना लाभदायक होता है।

तकनीक नियन्त्रण में औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले नवीन यान्त्रिक एवं तकनीकी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। जिन उद्योगों को तकनीकी परिवर्तन की जरूरत पड़ती है वे इस क्षेत्र के सम्पर्क में आते हैं। इनके विश्लेषण में प्रमुख आधार न्यूनतम लागत ही है। रोस्ट्रान के विचार से किसी भी परिस्थिति में उद्योग की स्थापना न्यूनतम लागत वाले स्थान पर ही की जानी चाहिए।

इस तरह इनकी विचारधारायें भौगोलिक जगत के लिये महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हैं तथा यह लागत पर आधारित होने के कारण व्यावहारिक भी प्रतीत होती हैं।

बेरी एवं प्रेड़ ने भी इस दिशा में प्रयत्न किये हैं इनका कहना है कि क्रिस्टालर द्वारा

प्रतिपादित केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त औद्योगिक क्षेत्र मे भी लागू किया जा सकता है। ऐसे उद्योग जिनके स्थानीकरण में कच्चे माल की तुलना में बाजार तथा परिवहन का अधिक महत्त्व है। उन उद्योगों की स्थिति निर्धारण में क्रिस्टालर के पदानुक्रम एवं परिवहन नियम का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ वस्तुओं की सीमा, आन्तरिक सीमा एवं बाजार के षटभुजीय होने की परिकल्पना का भी उपयोग किया जा सकता है। इनके विचारों का बाद में औद्योगिक स्थानीकरण करने वाले विद्वानों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

सारांश-

वास्तव में अनेक लोगों के द्वारा प्रस्तुत स्थानीकरण के सिद्धान्त वेबर के सिद्धान्त से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित हैं। वास्तविकता तो यह है कि ये विचारधारायें वेबर के विचारों के ही परिवर्तित पुर्नक्रमित एवं विस्तारित रूपहैं प्रायः अधिकांश विचारकों ने बेबर के विचारों का किसी न किसी रूप में अनुसरण किया है। कुछ लोगों ने सैद्धान्तिक तो कुछ ने कार्यवाहक पक्ष को महत्त्व दिया हैं। सरजेण्ट फ्लोरेन्स ने आर्थिक पक्ष को महत्त्व दिया है। इजार्ट ने बेबर एवं लॉश के विचारों का समाकलन किया है। वेबर के विश्लेषण में स्थानीकरण के सम्पूर्ण प्रमुख कारकों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार बेबर का सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों से अधिक व्यावहारिक है। इसी कारण बेबर के सिद्धान्त का समर्थन लगभग सभी लोगों ने किया है।

अवस्थापना के आधार-

किसी भी उद्योग की अवस्थापना करने के लिये ऐसी स्थिति का चुनाव आवश्यक है जिससे प्रदेश विशेष की अधिकांश सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकतायें पूरी हो सकें। उचित स्थान पर अवस्थापना न होने के कारण तथा कई अन्य कारणों से उद्योग वहाँ विकसित नहीं हो पाने और कभी-कभी कारकों के महत्त्व में अधिक परिवर्तन हो जाने के कारण उद्योग विशेष को नये क्षेत्रों में स्थापित करना पड़ता है। क्षेत्र विशेष में उपयुक्त भूमि उपयोग योजना की सहायता से उद्योगों की स्थापना की स्थिति का चयन अपेक्षाकृत सरलता से किया जा सकता है।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री परिवहन कच्चे माल एवं शक्ति पर होने वाले व्यय की अपेक्षा सामाजिक एवं क्षेत्रीय लागत पर अधिक बल देते हैं। वास्तविक अर्थ में सबसे अच्छा अवस्थापना का स्थान वह होगा जहाँ अधिक मानव कल्याण प्राप्त हो सके।

भौगोलिक दृष्टिकोण से किसी भी उद्योग की अवस्थापना के लिये विस्तृत समतल मैदान एवं सस्ती भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। यह भूमि यातायात के साधनों से भी जुड़ी होनी चाहिए भूमि का ढाल ३.१ से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि की मिट्टी में अधिक भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उद्योगों की स्थिति निर्धारण करते समय जलवायु सम्बन्धी दशाओं एवं सामाजिक कारकों का भी ध्यान रखना चाहिए। उद्योगों के विकास हेतु जल एवं शक्ति (उर्जा) की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता आवश्यक है। कोयला शक्ति का साधन है। यह एक भारी पदार्थ है । इसके नाते वे उद्योग जिन्हें शक्ति की ज्यादा जरूरत पड़ती थी कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किये जाते थे। वर्तमान समय में पेट्रोलियम एवं विद्युत का अधिक उपयोग होने लगा है। इनके द्वारा संचालित परिवहन अपेक्षाकृत सरल होता है।

किसी भी क्षेत्र का महत्त्व रेललाइनों एवं अच्छी एवं सुविधाजनक सड़कों के कारण बढ़ जाता है। इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्र में उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं में लागत कम होती है। उद्योगों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में होनी चाहिए जो कच्चेमाल के क्षेत्र में एवं व्यापार के क्षेत्र, से परिवहन मार्गों द्वारा भली-भाँति सम्बद्ध हों। औद्योगिक स्थिति का निर्धारण करते समय सस्ते श्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों की प्राप्ति न होने की दशा में उद्योगपति को श्रमिकों की मजदूरी पर अधिक व्यय करना पड़ता है इससे लागत बढ़ जाती है। इन कारकों के साथ-साथ उद्योगों के क्षेत्र एवं राज्य सरकार के बीच तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच अधिकाधिक समन्वय होना चाहिए जिससे तीव्र औद्योगिक एवं सहयोगी विकास हो सके। अतः वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक कारक भी उद्योगों की स्थापना एवं स्थान-चयन में कम महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करते हैं।

References

1- Arnott: R.(1986); Location Theory .Harwood Academic Chur .

2- Beaver : S.H. (1935) ; The Location of Industry Geogaphy .

3- Beekmann : M.(1968); Location Theory . Random House New York .

4- Christraller : W. (1966) ; Central Places in Southern Ger many Prentie Hall New Jessey.

5- DreZner : Z. (2002) ; Klamroth K.; Schobel , Wesolowsky . G.O. The Weber Problem . Drezner and Harmacher (eds.).

6- Everebt :E.H. (1959) ; Handbook for Industry Studies 'Asia Publication House , Bombey.

7- Fujita :M and I.E. Tisse (2002) ; Economics of Agglomera tion Cites Industrial Location of Human Activites . A nu merical Geography approach Cheltenham, Edward Elgar Publishing .

8- Hoover, E.M.(1948);The Location of Economic Activity . Megraw Hill New York .

9- Hartshrone , R.(1929):The Economic Geography of Plant Location , Annals of Real Eatate Practice No.7 1927 and Location as a factor of Geography Annals AAG 17.

10- Hamilton , F.E. (1971); Models of Industrial location in Chorley , R.J. and P. Haggeilt models in Geography Nethuen London.

11- Kaushik , S.D. (1995) ; Geography of Resouces Rastogi and Campaney Meert.

12- Kumar , P and Shrma (1997) ; Udyogik Bhogol Bopal .

13- Lodha , R.M. (2000); Udyogik Bhogol Jaipur .

14- Losch , A(1954);The Economic of Location Translated by woglum, W.H. from his book Dic reumliche ordnung der wists Choft (1940) Vale University Press New Haven Coun.

15- Lutlrel , W.P. (1962);Factory Location and Industrial move ment , London.

16- Mehta , M.M. (1952) ;Location of Indian Industries Allahabad

17- Renner , G.T. and others (1960) ; World Economic Geography An Introduction to Geonomies Thomas Y. Crowell Co. New York .

18- Renner, G.T. and others (1917) ; Geography of Industrial Lo calization Economic Geography.
19- Rawstron, E.N. (1958); Three Principles of Industrial Loca tion, Transaction and Papers I.B.G.
20- Smith ,D.M. (1971) ; Industrial Location John Willey New York .
21- Smith , J. Russell Smith , Thomas ,B and Phillips ,M. Ogden (1955) ;Industrial and Commercial Geography Hencry Holt.
22- Singh , M.B. (1983) ; Industrial Development Patterns and Potentials in Eastern U.P. Varanasi.
23- Siddartha ,K; Economics Geography ; Kislay Publication Patna
24- Tiwari , R.N. (1965) ; Location and Development of Large Scale Industries in Uttar Pradesh Unpublished D.Lit. Thesis . Agra University Agra Vol. I

खण्ड अ

कृषि आधारित उद्योगों का कालिक एवं स्थानिक विश्लेषण

खण्ड ब

पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का स्थानिक प्रतिरूप

खण्ड अ

कृषि आधारित उद्योगों का कालिक एवं स्थानिक विश्लेषण

कृषि के बाद उद्योग ही महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्य है। विश्व के विभिन्न देशों में यह कृषि से अधिक विकसित एवंउन्नतशील अवस्था में पाया जाता है। संसार की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग २०.४ प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या उद्योग से जीवकोपार्जन करती है। किसी भी देश में उद्योगों का विकास उस देश के आर्थिक विकास का मापदण्ड भी होता है। औद्योगीकरण, परिवहन एवं संचार का विकास एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। जिन प्रदेशों में उद्योगों का विकास हुआ है वहाँ अन्य आर्थिक कार्य जैसे- व्यापार एवं परिवहन का विकास होना स्वाभाविक है।(कुमार प्रमीला, १६६७.पृष्ठ १) जब उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तु निर्यात होने लगती है तो उससे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगता है तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन के कई आवश्यक मशीनें,जो कि विकासशील देशों में नहीं बनायी जाती,आयात की जाती हैं। इससे औद्योगिक विकास की गति और तीव्र होती है। उद्योगों के विकास से मानव का जीवनस्तर ऊँचा उठता है तथा प्रतिव्यक्ति अधिक आय के कारण बाजार का विस्तार भी होता है इससे उस क्षेत्र में अन्य उपभोक्ता साम्रगियों के उद्योग भी विकसित हो जाते हैं।(कुमार प्रमीला, १६६७.पृष्ठ १) उद्योगों के विकास के कारण उस क्षेत्र में जीविका प्राप्ति के आकर्षण से बहुत से लोग आकर बस जाते हैं जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या में औसत से अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र नगर पुंजों को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसी सम्बन्ध में ब्राइस ने कहा कि- "विकास के किसी भी सुदृढ़ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अन्ततः एक व्यापक भूमिका का निर्वहन करना होता है।(ब्राइस; इण्स्डटियल डेवलपमेन्ट, पृष्ठ ५)

विकासशील देशों में औद्योगीकरण आर्थिक विकास में बहुत हद तक सहायक होता है, किन्तु विकासशील देशों का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जब औद्योगिक उत्पादन के साथ ही साथ अनार्थिक कार्यों का भी समुचित विकास हो। मानव जीवन की अनेंक सुख-सुविधायें औद्योगिक उत्पादन के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अनार्थिक कार्यों के बारे में उल्लेख करते हुये रेगनर नर्क्से ने कहा है कि - "मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों

राजनैतिक दशाओं एवं ऐतिहासिक घटनाओं का आर्थिक विकास से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध होता है।(कुलश्रेष्ठ, आर० एस०, पृष्ठ १७) गिल ने कहा है-अर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रकिया नही है और न यह चयनित साधनों को जोड़नें की सरल क्रिया है। अन्ततोगत्वा यह एक मानवीय प्रयास है तथा समस्त मानवीय प्रयासों की भांति इसका परिणाम अन्ततः उन व्यक्तियों की दक्षता, योग्यता एवं मनोवृत्ति पर निर्भर होगा। जिन पर इसे सम्पन्न करने का भार है।(शिल , रिचार्ड टी०, पृष्ट १२)

वर्तमान उद्योगों के विकास में विज्ञान एवं तकनीकी विकास के उद्योगों के विकास से पूर्व कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, कागज उद्योग आदि प्रमुख थे। किन्तु वर्तमान समय के उद्योगों से ये बिलकुल भिन्न थे। इसी छोटी-छोटी इकाइयाँ होती थी जो आवासीय क्षेत्रों में गृह उद्योग के रूप में विकसित थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण इन इकाईयों का आकार भी बढ़ता गया और अब एक इकाई कई सौ एकड़ क्षेत्र में फैली होती है। इनमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता और उनमें हजारों मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है। परन्तु जिन क्षेत्रों में साधन सीमित है वहाँ इन्हीं उद्योगों की मध्यम अथवा लघु आकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो जाती है।

इस प्रकार आकार के आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

१. वृहत्त स्तरीय उद्योग

२. मध्यम स्तरीय उद्योग

३. लघुस्तरीय उद्योग

वृहत्तस्तरीय उद्योग- वृहत्त स्तरीय उद्योगों की श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनमें पाँच करोड़ रुपये रु० से अधिक की पूँजी का विनियोजन होता है। इन उद्योगों को अधिक मात्रा में कच्चे माल की एवं अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा इनसे उत्पादित वस्तुओं का अधिक मात्रा में सुदूरवर्ती क्षेत्रों को अथवा विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र पूर्वी प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के अन्तर्गत वर्तमान समय तक केवल चीनी मिल उद्योग ही वृहत्त

स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत आते हैं।

२. **मध्यम स्तरीय उद्योग** - साठ लाख से पाँच करोड़ रुपये तक की लागत की मशीन एवं सयन्त्र वाले उद्योगों को मध्यम स्तरीय उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। ये उद्योग महानिदेशक तकनीकी विकास या भारत सरकार से पंजीकृत होते हैं।

३. **लघुस्तरीय उद्योग**- ऐसे उपक्रम जिनमें मशीनों एवं अन्य सयन्त्रों भी कीमत साठ लाख रुपये या इससे कम होती है इन्हें लघुस्तरीय उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। लघुस्तरीय उद्योगों के लिये समय-समय पर भिन्न-भिन्न मानक निर्धारित किये जाते रहे हैं। पारम्परिक विचारधारा के अनुसार लघुस्तरीय उद्योग को कुटीर एवं गृह उद्योग के सदृश ही माना जाता रहा था। १६४६-५० में फिसकल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार "लघु उद्योग मजदूरों के द्वारा क्रियान्वित होते हैं जिनकी संख्या १० से ५० हो सकती है।" कुटीर उद्योग वे हैं जिनमें मूलतः एक परिवार के ही लोग काम करते हैं चाहे वे दिन में कुछ समय तक ही काम करें अथवा पूर्णतः उसी उद्योग में लगे हों। (कुमार प्रमीला,१६६७,पृष्ठ ३४७)ये इकाईयाँ आकार में छोटी होती हैं इनका बाजार स्थानीय होता है तथा तकनीकी दृष्टिकोण से परम्परागत होती हैं। वर्तमान समय में लघु उद्योगों के लिये साठ लाख रुपये की पूंजी निर्धारित की गयी है जबकि सहायक उद्योगों के लिये ७५ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गयी है।(कुलश्रेष्ठ, आर० एस०,१६६५.पृष्ठ ५८२) भारत में लघुस्तरीय औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। भारत सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु १२८ वस्तुओं के उत्पादन को इस श्रेणी में आरक्षित किया है।

इस दृष्टिकोण से लघु उद्योगों को कई वर्गों में वगीकृत किया जा सकता है-

१. **परम्परागत कुटीर उद्योग**- इसमें परम्परागत विधि से वस्तुओं का उत्पादन होता है और ये उद्योग कारीगरों द्वारा घर में ही चलाये जाते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य या कुछ सदस्य बारी बारी से समय मिलने पर अपना योगदान देकर आवश्यकता की वस्तुयें बनाते हैं जिनकी खपत स्थानीय बाजारों या निकटवर्ती क्षेत्रों में ही होती है। जैसे-गुड़ बनाना, चावल कूटना।

२. **हस्त शिल्प उद्योग**- यह भी परम्परागत कुटीर उद्योग है परन्तु विशिष्ट स्थानों पर ही स्थापित है। इसकी औद्योगिक प्रक्रिया भी परम्परागत है तथा इन्हें मनुष्य की कलात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति माना जाता है।(कुमार प्रमीला, १९९७, पृष्ठ ३४७) बनारस का जरी के कपड़े का उद्योग इस प्रकार का उद्योग है। इसमें मुख्यतः परिवार के ही लोग कार्यरत होते हैं तथा अपने स्वयं के औजारों और निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं।

आधुनिक लघु उद्योग, आधुनिक तकनीक, कुशल कारीगरों तथा शक्ति के उपयेाग से आधुनिक वस्तुयें निर्मित करते हैं। इन उद्योगों के लिये आवश्यक नहीं है कि कच्चामाल स्थानीय ही रूप में मिले। इनका बाजार भी विस्तृत होता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ३० अप्रैल, १९९० में एक औद्योगिक नीति घोषित की गयी थी। इस नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं वांछित गति से औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्यमियों तथा औद्योगिक इकाइयों को विशेष सुविधायें एवं प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण करने हेतु एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये तथा प्रदेश के लघु उद्योगों से विभिन्न आर्थिक एवं विवेकपूर्ण योजना बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों को आधुनिकीकरण करने हेतु, उत्पादकता बढ़ाने हेतु, एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उपयुक्त अनुदान दिया जाता है तथा प्लाण्ट एवं मशीनों को चलाने के लिये बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

उद्योगों के विकास की प्रक्रिया, उनकी अवनति के कारण एवं नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के कार्य निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं। आधुनिक समय के उद्योगों के विकास से पूर्व भारत में वस्त्र उद्योग, धातु से सम्बन्धित उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग आदि छोटी-छोटी इकाइयों के रूप में आवासीय क्षेत्रों में बिखरे हुये थे। इन इकाइयों में स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता था। वर्ष १७५० से १८५० के बीच यूरोप में हुई औद्योगिक क्रान्ति के कारण उद्योगों के स्वरूप में समग्ररूप से एवं विश्वव्यापी रूप से विकास हुआ। औद्योगिक प्रक्रियायें अधिक परिष्कृत होती गयी

तथा उद्योग पहले की अपेक्षा अधिक कुशलता से चलाये जाने लगे। औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में एवं उनकी इकाइयों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई। बीसवीं शताब्दी में विज्ञान एंव तकनीकी ज्ञान में बहुमुखी विकास हुआ। फलस्वरूप नये नये उद्योग विकसित हुये एवं औद्योगिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती गयी।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों (दाल, चीनी, चावल. आटा, एवं खुदरा तेल उद्योग) के लिये पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो जाता है जिससे कृषि पर आधारित अनेक औद्योगिक इकाइयाँ विकसित हो गयी हैं। यहाँ इन उद्योगों की कुल २३८६ इकाइयाँ पंजीकृत हैं। जिनके विकास काल (१९८० से २००० तक) को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-

१. औद्योगिक विकास का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप

२. पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप

किसी भी उद्योग की स्थापना अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसमें भौगोलिक आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कारक अपना अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। इन कारकों का प्रभाव समान रूप नहीं होता है। इसी कारण से स्थानिक दृष्टिकोण से उद्योगों का स्थानीकरण एवं विकास कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही होता है। समय के साथ-साथ इन कारकों के स्वरूप एवं प्रभाव में परिवर्तन होता रहता है और नये-नये कारकों का भी जन्म होता रहता है इसलिये कुछ उद्योग समाप्त प्राय हो जाते हैं, कुछ नये विकसित हो जाते है तथा कुछ उद्योगों का स्थानान्तरण हो जाता है। स्पष्ट है कि किसी भी उद्योग की अनुकूलतम परिस्थितियाँ सदैव एक समान नहीं रहती हैं।

वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रविधिकीय ज्ञान के विकास के साथ अनुकूलतम परिस्थितियाँ परिवर्तित होती जाती हैं। इसी कारण समय पर उद्योगों के स्थानीकरण के प्रतिरूप भी बदलते जाते हैं।

किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की

उपलब्धि का विशेष महत्त्व है। उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल को प्राप्त करने एवं उससे उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिये बाजार की आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त उद्योगों के स्थानीकरण को अनेंक अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे- सस्ता श्रम, पूंजी, शक्ति के साधन, यातायात की सुविधा आदि। ये पृथक-पृथक रूप मे अवस्थिति को प्रभावित करते हैं।

भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में लघु औद्योगिक इकाईयों का विशेष महत्त्व है इसी कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के विकास को अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। इन इकाईयों के विकास में कच्चे माल की प्राप्ति का विशेष योगदान रहा है। जहाँ कहीं कच्चे माल की सुलभता प्राप्त हो जाती है वहाँ लघुस्तर की विभिन्न औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो जाती हैं।

अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित कच्चे पदार्थ जैसे- गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन एवं गन्ना प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। परन्तु कुछ स्थानों पर ये वृहत एवं लघु उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन कच्चे माल पर आधारित विभिन्न प्रकार की वृहत एवं मध्यम तथा लघु इकाईयाँ अध्ययन क्षेत्र में स्थापित हो गयी है। जिनके विकास का विवरण निम्न प्रकार है-

इन उद्योगों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

१. चावल उद्योग

२. आटा उद्योग

३. खाद्य तेल उद्योग

४. दाल प्रशोधन उद्योग

५. शीतगृह उद्योग

६. चीनी मिल उद्योग

इन उद्योगों के अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र के कुछ सीमित स्थानों पर सिल्क उद्योग, इत्र बनाने का उद्योग, तम्बाकू उद्योग, कारपेट उद्योग आदि विकसित हुये हैं।

यह सर्वविदित है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख कृषि उपजों में गेहूँ, धान, तिलहन, दाल एवं गन्ना उल्लेखनीय है। इन कृषि उपजों पर आधारित कई वृहत एवं मध्यम तथा लघु औद्योगिक इकाईयाँ अध्ययन क्षेत्र में स्थापित हो गयी हैं जिनमें चावल उद्योग, आटा उद्योग, दाल मिल उद्योग, एवं चीनी मिल उद्योग प्रमुख है। अध्ययन क्षेत्र में सन् १९८० से २००० के बीच इन औद्योगिक इकाईयों के विकास की प्रवृत्ति का विवरण निम्नवत है-

चावल उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों में चावल उद्योग एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में धान से चावल निकालने का काम किया जाता है उद्योगों के लिये कच्चे माल (धान) की प्राप्ति निकटवर्ती क्षेत्रों से कर ली जाती है।

सारणी संख्या ५.०१ को देखने से स्पष्ट होता है कि सन १९८० में चावल उद्योग की पंजीकृत इकाइयों में सुलतानपुर(५) , इलाहाबाद (५), आजमगढ़ (४), जौनपुर (४), गोरखपुर (४) अग्रणी जनपद रहें हैं। इन उद्योगों में पंजीकृत उद्योगों की सर्वाधिक इकाईयाँ पाँच-पाँच एवं चार-चार थीं जिसमें ६७ श्रमिक कार्यरत थे। सबसे कम औद्योगिक इकाईयाँ बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, श्रावस्ती, चन्दौली एवं बलरामपुर जनपदों में थी। इन जनपदों में चावल उद्योग की दो-दो पंजीकृत इकाईयाँ थी जिसमें ५८ व्यक्ति सेवारत थे। अन्य जनपदों में तीन-तीन औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित थी जिनमें ८६ श्रमिक कार्यरत थे। इस प्रकार १९८० में अध्ययन क्षेत्र में कुल ८० चावल मिलों की पंजीकृत इकाईयाँ थीं जिनमें कुल २५३ व्यक्ति सेवारत थे। सन् १९८० में सुलतानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर जनपदों में ७५४९६ कुन्तल चावल का उत्पादन किया गया जबकि जिन जनपदों में सबसे कम औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित थीं अर्थात बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, श्रावस्ती, चन्दौली जनपदों में १२२५७० कुन्तल चावल का उत्पादन किया गया और अन्य जनपदों में १६१४४४ कुन्तल चावल का उत्पादन किया गया।

सारणी संख्या -५.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश

चावल मिल उद्योग का विकास

क्र०स०	जनपद	१९८०		१९८५		१९९०		१९९५		२०००	
		U	W	U	W	U	W	U	W	U	W
१	फैजाबाद	३	१२	५	१६	९	३२	१२	४०	१२	४८
२	गोण्डा	३	१०	४	१५	१०	३५	१४	४२	१०	४०
३	सुल्तानपुर	५	१५	६	२४	७	२८	१०	३५	१२	३९
४	प्रतापगढ़	३	१०	५	२०	६	२४	८	२७	११	४४
५	इलाहाबाद	५	१५	४	२०	७	३२	१२	४५	१०	३५
६	वाराणसी	३	९	५	१८	१०	३६	८	३०	१०	४०
७	महराजगंज	३	१०	४	१४	६	२४	५	३०	८	३२
८	सोनभद्र	२	६	२	६	५	२२	७	२८	६	२४
९	बलिया	२	८	४	१६	८	३५	११	३५	१२	४५
१०	गाजीपुर	२	६	४	१५	७	२८	९	३६	१०	४०
११	मऊ	२	५	३	६	६	२४	५	२५	७	२८
१२	आजमगढ़	४	१२	४	२०	६	२३	८	३२	११	४५
१३	बहराइच	३	१०	५	२२	८	३२	१०	३५	१२	४८
१४	मिर्जापुर	२	७	२	९	४	२५	६	१८	८	४०
१५	जौनपुर	४	१२	५	२५	६	२४	१०	३२	१२	४५
१६	बस्ती	२	९	६	२०	६	२२	९	२४	९	३८
१७	गोरखपुर	४	१२	४	२५	७	३०	१०	३५	१२	४८
१८	देवरिया	२	५	६	१६	८	२४	६	१८	९	३६
१९	संतरविदास नगर	४	१३	२	५	५	२५	६	२२	६	२०
२०	बलरामपुर	२	९	२	८	३	१६	२	५	२	१२
२१	श्रावस्ती	२	७	४	१५	६	१८	५	३५	३	१२
२२	संतकबीरनगर	३	१०	५	१४	७	२७	९	२५	२	८
२३	चन्दौली	२	५	२	५	४	१५	३	८	४	१२
२४	कुशीनगर	४	१२	२	४	५	१०	८	२४	३	१०
२५	सिद्धार्थनगर	६	१८	७	२१	६	२४	४	२५	५	२०
२६	अम्बेडकरनगर	३	६	२	४	५	१०	२	४	३	१२
	योग	८०	२५३	१०४	३८३	१६७	६४५	१९९	७१५	२०९	८२१

स्रोत :- १- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त आकड़े ।

सारणी संख्या -५.०२
पूर्वी उत्तर प्रदेश
चावल उद्योग का उत्पादन(कुन्टल में)

क्र०स०	जनपद	१९८० उत्पादन	१९८५ उत्पादन	१९९० उत्पादन	१९९५ उत्पादन	२००० उत्पादन
१	फैजाबाद	१३१४०	३५०४०	५२५६०	८७६००	९२५००
२	गोण्डा	१४२१५	३७१४०	५३२५०	८६३००	९४२५०
३	सुल्तानपुर	१३२१६	३६२४८	५६६६०	७२६८०	९०६६०
४	प्रतापगढ़	१२४१८	३४६४०	५०३६३	७४३४०	८९३८०
५	इलाहाबाद	१६६१०	३८४८०	७४६४० .	८९३६०	९५६४०
६	वाराणसी	१७७१५	३७८४०	५८९६०	९०६४०	९१६१०
७	महराजगंज	१०९२१	२२२४२	५५३१०	८५२३०	९०६४५
८	सोनभद्र	१३२१६	२५६३५	४८२५०	७१६९०	८७२४०
९	बलिया	३१९१०	३६४८०	५५४९०	८३९३०	९३६१८
१०	गाजीपुर	१४६१०	३७३७०	५६१६०	८५९३०	९२६४०
११	मऊ	१२२११	२४२६१	५६८४०	८६४३२	९४३६३
१२	आजमगढ़	१३९३९	३८३१०	५५४८०	८०९४०	९३९४०
१३	बहराइच	१५६१००	३७९३०	५६६६०	९०१०७	९८९४०
१४	मिर्जापुर	११३६०	३०४३०	५०४९०	८२२३०	९०६४०
१५	जौनपुर	१३४१९	३५९१०	५३३११	८०३१२	९३४१२
१६	बस्ती	१६३१२	३८६३४	५८४१०	४५६१४	९५६१०
१७	गोरखपुर	१८३१२	२९९३०	५८६४० ·	८७६४०	९५२१२
१८	देवरिया	१६६४०	३८७१८	५६९३०	८८२११	९६६१२
१९	संतरविदास नगर	१५१६२	२१२६३	५४२२०	६०२३०	७०२४०
२०	बलरामपुर	१८२१६	२०१२४	५२२०२०	६८२४४	८७२२०
२१	श्रावस्ती	१४१२९	१६१८२	५३५४५५	७०२०२	८०२४०
२२	संतकबीरनगर	११२४१	१४१६२	४६५७२०	६५३०४	५५६४०
२३	चन्दौली	१०१८२	१८१९१	५४५४२०	६०४०३	७२२६०
२४	कुशीनगर	१२१२४	१५१४२	५०५१५२	६२१५५	६०२३०
२५	सिद्धार्थनगर	१३२६२	१७२१५	५२५१५०	६४१८९	६२२४०
२६	अम्बेडकरनगर	१२२४४	१८२९४	५०५२५४	५६१५५	८०२३०

इसी प्रकार सारणी संख्या ५.०१ से यदि १९८५ में विभिन्न जनपदों में चावल उद्योग की पंजीकृत इकाईयों की संख्या को देखें,तो सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर,बस्ती एवं देवरिया जनपदों में सर्वाधिक पंजीकृत इकाईयाँ थी। इन जनपदों में चावल उद्योग की ७.६-६ इकाईयाँ पंजीकृत थीं, जिनमें ८१ श्रमिक सेवारत थे। इसके बाद प्रतापगढ़, वाराणसी, बहराइच एवं जौनपुर जनपद तथा संतकबीरनगर जनपद द्वितीय स्थान पर आते हैं,जहाँ चावल उद्योग की पंजीकृत इकाईयों की संख्या पाँच-पाँच थी जिनमें ६६ श्रमिक सेवारत थे जबकि फैजाबाद, गोण्डा, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज एवं श्रावस्ती जनपदेां में चार-चार इकाइयाँ पंजीकृत थी जिनमें १५७ श्रमिक सेवारत थे सबसे कम पंजीकृत इकाईयाँ मिर्जापुर एवं सोनभद्र सन्त रविदासनगर, बलरामपुर, चन्दौली कुशीनगर एवं अम्बेदकरनगर जनपदों में थीं इन जनपदों में दो-दो इकाइयाँ पंजीकृत थीं जिनमें ४१ श्रमिक सेवारत थे। इस प्रकार १९८५ में चावल उद्योग की कुल १०४ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें कुल ३८३ व्यक्ति सेवारत थे। सारणी संख्या ५.०२ से यदि इन विभिन्न जनपदों के उत्पादन को देखें तो सिद्धार्थनगर सुलतानपुर एवं देवरिया जनपदों में ६२१८१ कुन्तल चावल का उत्पादन हुआ था जबकि प्रतापगढ़, वाराणसी, बहराइच, बस्ती, जौनपुर तथा सन्तकबीरनगर जनपदों में १६६११६ कुन्तल चावल का उत्पादन हुआ एवं सबसे कम पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों वाले जनपदों में ४७१५१४ कुन्तल चावल उत्पादित किया गया।

इस तरह यदि हम सारणी संख्या ५.०१ का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि १९८० से १९८५ के मध्य पंजीकृत चावल उद्योग की कुल इकाईयाँ में वृद्धि हुई है तथा चावल के उत्पादन एवं श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उद्योगों की संख्या में जनपदवार वृद्धि १९८० से १९८५ के मध्य केवल इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलरामपुर एवं अम्बेदकरनगर जनपद को छोड़कर सभी जनपदों में हुई है। इन जनपदों में उद्योगों की संख्या के बजाय चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

१९९० में गोण्डा, वाराणसी, जनपदों में चावल उद्योग की सर्वाधिक पंजीकृत इकाईयाँ थीं। इन जनपदों में १०-१० इकाईयाँ पंजीकृत थी जिसमें ७१ व्यक्ति रोजगार प्राप्त थे।

DEVELOPMENT TRAND OF RICE MILLING INDUSTRY IN EASTERN U.P.
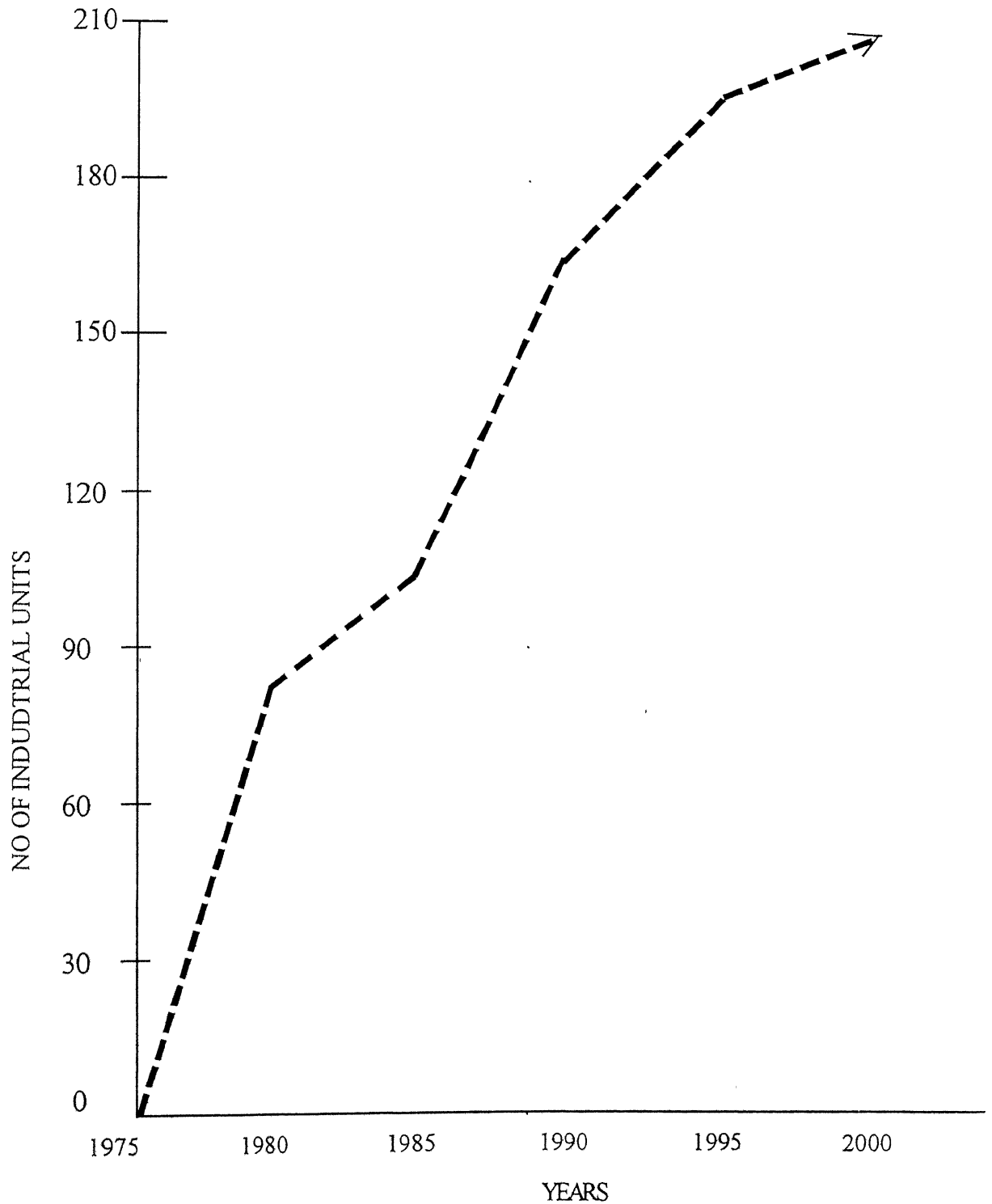
Fig.No-5.01

सारणी संख्या -५.०३

पूर्वी उत्तर प्रदेश

आटा उद्योग का विकास

क्र०सं०	जनपद	१९८०		१९८५		१९९०		१९९५		२०००	
		U	W	U	W	U	W	U	W	U	W
१	फैजाबाद	२	६	४	१२	७	२४	९	३०	१०	४०
२	गोण्डा	२	७	२	८	८	३०	६	२४	८	३२
३	सुल्तानपुर	३	९	४	१६	६	२५	८	३२	९	३६
४	प्रतापगढ़	४	१०	६	२४	७	२८	७	२८	६	२४
५	इलाहाबाद	३	९	५	२०	६	२५	५	२१	९	३६
६	वाराणसी	२	८	४	२०	८	३३	९	२७	११	४०
७	महराजगज	२	६	३	९	४	१६	५	२०	८	३०
८	सोनभद्र	२	६	३	९	४	२४	७	२५	६	२६
९	बलिया	३	९	५	२०	६	२३	१०	२८	११	४२
१०	गाजीपुर	४	१६	४	२०	८	२४	१२	३६	१४	५०
११	मऊ	३	९	४	१२	४	१४	९	३२	१०	४०
१२	आजमगढ़	२	८	३	१६	६	२४	१०	३९	१२	४५
१३	बहराइच	३	१२	४	१५	७	२०	९	३८	६	२७
१४	मिर्जापुर	३	१२	२	८	३	१४	६	२५	७	२८
१५	जौनपुर	४	१६	६	२४	५	२५	१०	२४	१४	४०
१६	बस्ती	२	५	५	२०	७	२७	८	३२	१०	३५
१७	गोरखपुर	२	८	५	२४	६	२२	१०	३०	९	६
१८	देवरिया	२	८	३	१२	६	२४	६	३६	८	३२
१९	संतरविदास नगर	२	६	५	१५	२	८	६	३५	८	३०
२०	बलरामपुर	२	६	२	९	४	२०	३	९	३	२४
२१	श्रावस्ती	३	९	२	६	५	९	४	१२	६	३०
२२	संतकबीरनगर	४	१२	५	२०	२	६	४	१६	३	१०
२३	चन्दौली	३	९	२	६	५	२०	४	२०	४	१२
२४	कुशीनगर	५	१५	२	६	४	१६	३	९	२	८
२५	सिद्धार्थनगर	३	९	३	९	२	६	५	१५	४	१२
२६	अम्बेडकरनगर	२	६	४	१६	५	२०	३	९	३	९
	योग	७४	२३६	९८	३७६	१४३	५२७	१७८	६५२	२०१	७७४

स्रोत :- १- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त आकड़े ।

इससे कम औद्योगिक इकाईयाँ फैजाबाद, इलाहाबाद, बलिया, बहराइच, देवरिया जनपदों में थीं यहाँ चावल उद्योग की ६ एवं ८-८ इकाईयों पंजीकृत थीं तथा १५५ श्रमिक सेवारत थे जबकि सुलतानपुर, गाजीपुर, गोरखपुर तथा सन्तकबीरनगर जनपदों में सात-सात औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें ११३ व्यक्ति सेवारत थे। अन्य जनपदों में ६-६ एवं ५-५ तथा ४-४ औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें ३६८ व्यक्ति सेवारत थे। १९९० में कुल पंजीकृत चावल उद्योग की संख्या १६७ थी और इनमें ६४५ व्यक्ति सेवारत थे। यदि सारणी संख्या ५.०२ में उत्पादन को देखें तो स्पष्ट होता है कि गोण्डा एवं वाराणसी जनपदो मे ११२२१० कुन्तल चावल का उत्पादन किया गया जबकि फैजाबाद, इलाहाबाद, बलिया, बहराइच तथा देवरिया जनपदों में २७६२८० कुन्तल चावल का उत्पादन किया गया तथा सुलतानपुर, गाजीपुर, गोरखपुर तथा सन्तकबीरनगर जनपदों में कुल ६३७१८० कुन्तल चावल उत्पादित किया गया।

१९९० में सबसे कम पंजीकृत इकाईयाँ मिर्जापुर एवं चन्दौली जनपदों में भी जहाँ चावल का कुल उत्पादन ५७५९१० कुन्तल था।

सन् १९९५ में गोण्डा जनपद में चावल उद्योग की सर्वाधिक १४ इकाईयाँ पंजीकृत थी जिनमें ४२ श्रमिक सेवारत थे। इलाहाबाद एवं फैजाबाद जनपद का द्वितीय स्थान रहा जहाँ चावल उद्योग की १२ -१२ इकाईयाँ पंजीकृत थी। इनमें ८५ श्रमिक सेवारत थे। जबकि सुलतानपुर में १०, बहराइच में १० तथा गोरखपुर में १० इकाईयाँ पंजीकृत थी जिनमें कुल १७७ व्यक्ति सेवारत थे। बलिया जनपद में ११ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें ३५ श्रमिक सेवारत थे। अन्य जनपदों में ६ इकाईयों से लेकर २ इकाईयाँ पंजीकृतथी जिसमें कुल ४२८ श्रमिक सेवारत थे। सबसे कम औद्योगिक इकाईयाँ अम्बेदकरनगर जनपद में पंजीकृत थीं। इस प्रकार १९९५ में कुल १९९ इकाईयाँ पंजीकृत थी जिसमें ७१५ श्रामिक सेवारत थे।

सारणी संख्या ५.०२ से स्पष्ट हैं कि १९९५ में गोण्डा जनपद में ८९३०० कुन्तल चावल का उत्पादन प्राप्त हुआ था और इलाहाबाद जनंपद में ८९३६० कुन्तल चावल का उत्पादन हुआ अन्य जनपदों में २०१९९९८ कुन्तल चावल उत्पादित किया गया।

सन् २००० में अध्ययन क्षेत्र में चावल उद्योग की इकाईयों में सर्वाधिक इकाईयाँ फैजाबाद , बलिया, बहराइच, जौनपुर, गोरखपुर में १२-१२ इकाईयाँ पंजीकृत थीं तथा २३४ श्रमिक सेवारत थे जबकि गोण्डा, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर में १०-१० इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें १५५ श्रमिक सेवारत थे। प्रतापगढ़ में ११ इकाईयॉ पंजीकृत हैं। सबसे कम इकाईयां संतकबीरनगर एवं बलरामपुर में पंजीकृत है जिसमें २० श्रमिक सेवारत हैं। इन जनपदों में यदि उत्पादन को देखा जाय तो सुलतानपुर जनपद में ६०६६० कुन्तल चावल उत्पादित किया गया जबकि फैजाबाद, बलिया, बहराइच, जौनपुर एवं गोरखपुर जनपद में ४७३६८२ कुन्तल चावल उत्पादित किया गया। सन्त कबीरनगर में ५५६४० कुन्तल चावल का उत्पादन हुआ। चावल उद्योग में सन् १६८० से २००० तक वृद्धि को रेखाचित्र ५.०१ में द्वारा दर्शाया गया है।

यदि जनपदवार १६८० से २००० के बीच जनपदवार उद्योग की प्रगति देखा जाय तो अध्ययन क्षेत्र में गोण्डा जनपद में चावल उद्योग की सर्वाधिक ४१ इकाईयाँ पंजीकृत थीं और इसमें १४२ व्यक्ति सेवारत थे।

आटा उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में आटा उद्योग भी कृषि आधारित उद्योगों के अन्तर्गत एक प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग में गेहूँ को पीसकर आटा तैयार करने का कार्य किया जाता है। वर्तमान समय में आटा पीसने के लिये बिजली से चलने वाली चक्कियों का प्रयोग किया जाता है। आटा पीसने की चक्कियाँ तेल पेरने की मशीनों के साथ ही कम पैसों में लगायी जा सकती हैं। अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में आटा उद्योग की कई पंजीकृत इकाईयाँ कार्यरत हैं जिनके विकास का वर्णन निम्नवत है-(सरणी संख्या ५.०२)

अध्ययन क्षेत्र के प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सन्तकबीरनगर तथा कुशीनगर जनपदों में १६८० में आटा उद्योग की पंजीकृत इकाईयों की संख्या सर्वाधिक थी। सबसे अधिक ५ पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ कुशीनगर जनपद में थीं तथा ४-४ पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ अन्य उपर्युक्त जनपदों में थी जिसमें ५७ श्रमिक कार्यरत थे जबकि इलाहाबाद, बलिया, बहराइच, मिर्जापुर, सुलतानपुर, मऊ, श्रावस्ती, चन्दौली एवं सिद्धार्थनगर जनपदों में ३-३ इकाईयाँ पंजीकृत थी जिनमें ७७ श्रमिक सेवारत थे। अन्य जनपदों में आटा उद्योग

सारणी संख्या -५.०४
पूर्वी उत्तर प्रदेश
जनपदवार आटा उद्योग का उत्पादन -(कि०ग्रा०)

क्र०स०	जनपद	१९८० उत्पादन	१९८५ उत्पादन	१९९० उत्पादन	१९९५ उत्पादन	२००० उत्पादन
१	फैजाबाद	३६५००	१०९५	४३८०	७३००	१०९५०
२	गोण्डा	३२३००	१२४०	४२१८	७०००	१२३४०
३	सुल्तानपुर	३४१८०	१४३०	४५२०	७०३०	१४६२५
४	प्रतापगढ़	२६२१०	१२१९	४२२५	७२२५	१३३२२
५	इलाहाबाद	३८४	१६२०	४५४५	८०४०	१६९४०
६	वाराणसी	४०३६०	१८६०	४६४८	९०३०	१८९३२
७	महराजगंज	२५३२१	१२१४	४८३८	१६९०	१८२४८
८	सोनभद्र	२६४२६	१०५०	३२३४	१८६८	१४६४०
९	बलिया	३७२४०	१६२५	४४२०	७६३४	१९८१६
१०	गाजीपुर	३५१३०	१५४०	४३३०	७८९०	१८२८०
११	मऊ	२२२१२	१३१८	४६३४	१८१६	१६४२०
१२	आजमगढ़	३४४१०	१३६०	४२४०	७५६०	२०२१०
१३	बहराइच	३३३१६	१२८०	४०६८	७२३८	१८२१५
१४	मिर्जापुर	२८९२०	१२३६	४०२५	६९३२	१६४००
१५	जौनपुर	३४६१२	१४४७	४३१२	७४३८	१८२६०
१६	बस्ती	३०३१८	१२३६	४२३४	७३३४	१७२१४
१७	गोरखपुर	३७३४८	१८६०	५०३४	७८९०	२१८४०
१८	देवरिया	३२६१८	१६४२	४६१८	७६३७	२२९५०
१९	संतरविदासनगर	३०१४६	१०१९	३८८०	१४३०	१४६६८
२०	बलरामपुर	२६१२६	१५१८	३५०१	१८२०	१२९३०
२१	श्रावस्ती	२५४१६	१३२४	३७६७	१६४०	११२४०
२२	संतकबीरनगर	२३३२१	१२१०	२९०४	१९५९	१०९३०
२३	चन्दौली	२२३२४	११९१	३८०१	२०२१	१४२४०
२४	कुशीनगर	२१२२३	१३१२	३०६४	१५१६	१६६३०
२५	सिद्धार्थनगर	३४२१४	१२२०	३२३५	१८१४	१६३८०
२६	अम्बेडकरनगर	३५६७८	११२१	३२३५	१८१४	१६३८०

DEVELOPMENT OF FLOUR MILLING INDUSTRY IN EASTERN U.P.
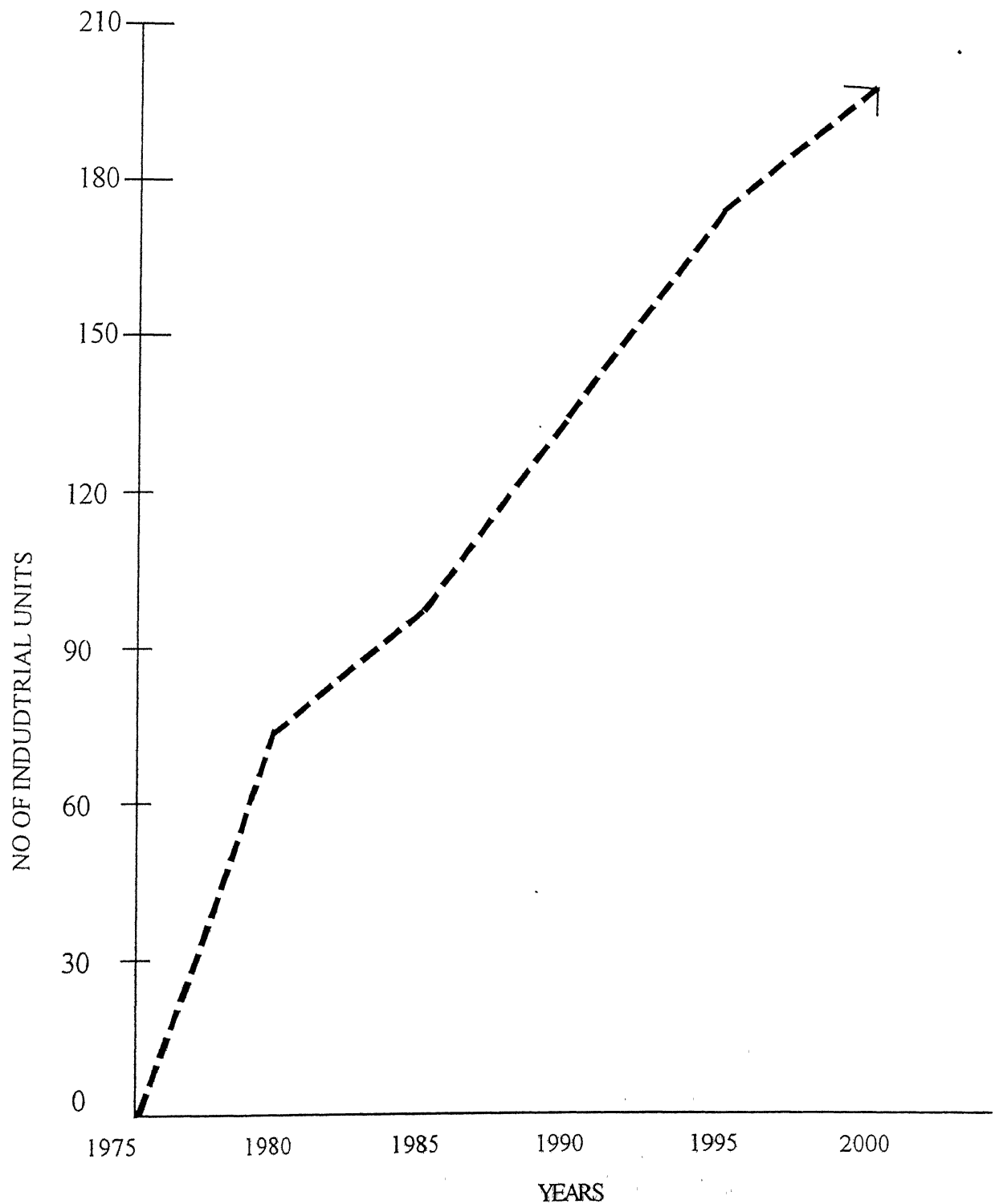
Fig.No-5.02

तेल मिल

तेल मिल
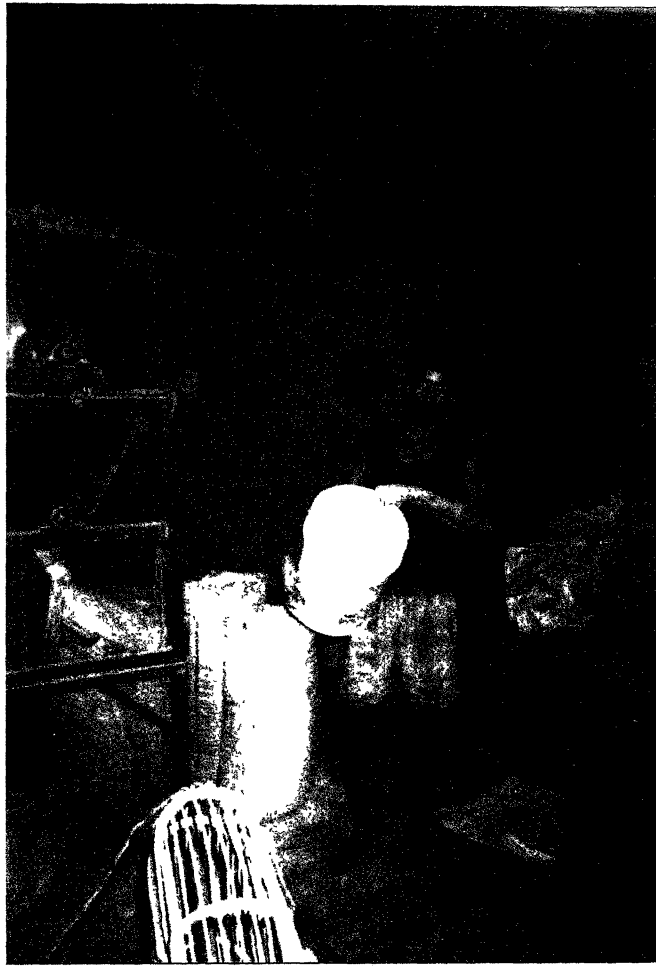
आटा मिल

तेल मिल

की २-२ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें कुल ८० श्रमिक कार्यरत थे।

इस प्रकार सन् १६८० में कुल ७४ इकाईयाँ आँटा उद्योग की पंजीकृत थीं जिनमें कुल २३६ श्रमिक सेवारत थे। यदि उत्पादन को देखा जाय तो प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सन्तकबीरनगर तथाकुशीनगर जनपदों में कुल १४०४६६ कुन्तल ऑटे का उत्पादन किया गया, जबकि इलाहाबाद, बलिया, बहराइच, मिर्जापुर, सुलतानपुर, मऊ, श्रावस्ती, चन्दौली एवं सिद्धार्थनगर जनपदों में २७६२४२ कुन्तल आँटा उत्पादित किया गया एवं अन्य जनपदों में १४३७०० कुन्तल आँटा पीसा गया।

१६८५ में सर्वाधिक पंजीकृत इकाईयाँ प्रतापगढ़ एवं जौनपुर जनपदों में थीं। इन जनपदों में सर्वाधिक ६-६ इकाईयाँ पंजीकृत थीं एवं ४८ श्रमिक कार्यरत थे जबकि इलाहाबाद, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, सन्तरविदासनगर एवं संत कबीरनगर में ५-५ औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनें कुल ६४ श्रमिक सेवारत थे। अन्य जनपदों में ४-४, ३-३ तथा २-२ औद्योगिक इकाई या पंजीकृत थीं एवं इनमें १६८ श्रमिक सेवारत थे।

इस प्रकार १६८५ में अध्ययन क्षेत्र में कुल ६८ आँटा मिल की इकाईयाँ पंजीकृत थीं। प्रतापगढ़, जौनपुर जनपद में २६६६ कुन्तल आँटे का उत्पादन किया गया जबकि इलाहाबाद, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, सन्तरविदासनगर एवं सन्तकबीरनगर में ८५७० कुन्तल आँटा पीसा गया।

सन् १६६० में सर्वाधिक आँटा मिलें गोण्डा, बनारस, गाजीपुर जनपदों में थीं। इन जनपदों में ८-८ आँटा मिलें पंजीकृत थीं जिसमें ८७ श्रमिक सेवारत थे। प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद ,बहराइच जनपद दूसरे स्थान पर थे जहाँ ७-७ मिलें पंजीकृत थीं तथा ६६ श्रमिक सेवारत थे। इसके अलावा अन्य जनपद तीसरे स्थान पर थे जहाँ ६ से लेकर २-२ मिले पंजीकृत थीं और ३४१ श्रमिक सेवारत थे।

सन् १६६५ में पंजीकृत आटा इकाईयों में गाजीपुर जनपद अग्रणी रहा है। यहाँ १२ पंजीकृत इकाईयाँ थीं जिनमें कुल कार्यरत थे। बलिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गोरखपुर जनपदों में १०-१० इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें १२१ श्रमिक कार्यरत थे। फैजाबाद,

सुलतानपुर, बहराइच, बस्ती,वाराणसी तथा मऊ जनपदों में ६-६ एवं ८-८ इकाईयाँ पंजीकृत थीं तथा १६१ श्रमिक सेवारत थे। अन्य जनपदों में ७ पंजीकृत इकाईयों से लेकर ३ पंजीकृत इकाईयाँ कार्यरत थीं जिनमें ३०४ श्रमिक सेवारत थे।

इस प्रकार १९९५ में कुल आँटा मिलों की १७८ पंजीकृत इकाईयाँ थीं जिनमें ६५२ श्रमिक कार्यरत थे।

उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाय तो गाजीपुर जनपद में ७८९० कुन्टल आँटे का उत्पादन हुआ।

सन् २००० में जौनपुर एवं गाजीपुर जनपद में १४-१४ इकाईयाँ पंजीकृत थीं और ९० श्रमिक कार्यरत थे। आजमगढ़ जनपद में १२ इकाईयाँ पंजीकृत थीं एवं ४५ श्रमिक सेवारत थे/ वाराणसी एवं बलिया जनपदों में ११-११ इकाईयाँ स्थापित थी तथा ८२ श्रमिक कार्यरत थे। फैजाबाद, बस्ती एवं मऊ जनपदों में १०-१० इकाईयाँ थीं जिनमें कुल ११५ श्रमिक कार्य कर रहे थे। अन्य जनपदों में आँटा उद्योग का कम विकास हुआ है। इन जनपदों में २ से लेकर ६ इकाईयाँ तक पंजीकृत हैं जिनमें ४७४ श्रमिक कार्यरत हैं।

सबसे कम औद्योगिक इकाईयाँ कुशीनगर जनपद में पंजीकृत थीं। यहाँ केवल २ इकाइयाँ हैं जिनमें कुल ८ श्रमिक सेवारत हैं।

सन् २००० में आँटा उद्योग की कुल पंजीकृत इकाईयौं की संख्या २०१ थीं जिनमें ७७४ व्यक्ति सेवारत थे।

जौनपुर तथा गाजीपुर जनपद में ३६५४० कुन्तल आँटा का उत्पादन हुआ जबकि आजमगढ़ जनपद में २०२१० कुन्तल आँटा उत्पादित किया गया। फैजाबाद, बस्ती, मऊ जनपदों में कुल ४४५८४ कुन्तल आँटा का उत्पादन हुआ जबकि कुशीनगर जनपद जहाँ कि सबसे कम औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकृत थीं १६६३० कुन्तल आँटा का उत्पादन हुआ।

रेखाचित्र संख्या ५.०२ में आँटा उद्योग के विकास के उत्पादन को दिखाया गया है।

खाद्य तेल उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में खाद्य तेल उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। इन

सारणी संख्या -५.०५
पूर्वी उत्तर प्रदेश
खाद्य तेल उद्योग की प्रगति

क्र०स०	जनपद	१९८०		१९८५		१९९०		१९९५		२०००	
		U	W	U	W	U	W	U	W	U	W
१	फैजाबाद	५	२०	७	२८	१०	३६	१०	३०	१०	३६
२	गोण्डा	६	२४	६	२४	८	३२	१२	२८	१३	३९
३	सुल्तानपुर	७	२१	५	२०	७	२८	९	३६	१०	४०
४	प्रतापगढ़	६	२४	४	१६	६	२४	१०	३५	११	३३
५	इलाहाबाद	५	२०	६	२४	८	२४	६	३०	१०	४०
६	वाराणसी	४	१२	७	२८	१०	४०	१३	३७	१२	४५
७	महराजगंज	३	९	४	१६	६	२४	८	३२	१०	३०
८	सोनभद्र	३	९	२	६	३	९	५	२०	९	३६
९	बलिया	३	१०	४	२५	८	२४	९	३२	१०	४२
१०	गाजीपुर	४	१२	६	३०	८	३२	८	३२	१०	३५
११	मऊ	२	६	३	१२	७	२८	१०	३९	९	३५
१२	आजमगढ़	५	२५	४	२५	६	३०	९	३२	१२	४०
१३	बहराइच	५	२४	६	२४	९	३२	११	४५	१२	३६
१४	मिर्जापुर	२	८	३	१२	५	२०	६	३०	८	३६
१५	जौनपुर	३	१२	५	२०	७	२८	९	३३	११	४४
१६	बस्ती	३	९	४	१६	७	३०	१०	४५	१२	४५
१७	गोरखपुर	४	१६	६	२४	९	३६	१०	२५	१०	४२
१८	देवरिया	३	१०	५	२०	८	४०	१०	३५	९	३८
१९	संतरविदास नगर	४	१२	५	९	७	३०	९	३९	१०	३०
२०	बलरामपुर	५	१५	४	१६	३	९	२	६	६	२४
२१	श्रावस्ती	२	६	५	१५	३	९	४	१६	४	२४
२२	संतकबीरनगर	५	१५	४	१६	२	६	३	९	४	१६
२३	चन्दौली	३	९	२	६	४	१२	५	१५	६	२४
२४	कुशीनगर	५	१५	६	१८	३	९	१	३	७	२८
२५	सिद्धार्थनगर	३	९	२	६	६	१८	५	१५	६	३०
२६	अम्बेडकरनगर	२	६	४	१२	३	९	४	१२	५	२०
	योग	१०२	३५८	१२०	४६८	१६३	६१९	१९८	७११	२३६	८८८

स्रोत :- १- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त आकड़े ।

मिलो में मुख्यतः सरसों का तेल ही निकाला जाता है।

सारणी संख्या ५.०५ को देखने से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सन् १९८० में सर्वाधिक तेल मिलों की संख्या सुलतानपुर जनपद में थीं। इस जनपद में सात मिलें थीं जिनमें २१ श्रमिक सेवारत थे। गोण्डा एवं प्रतापगढ़ जनपद में तेल उद्योग की ६-६ इकाईयाँ पंजीकृत थीं तथा इसमें ४८ श्रमिक कार्यरत थे। फैजाबाद, सन्तकबीरनगर, बलरामपुर तथा कुशीनगर जनपदों में ५-५ इकाईयाँ पंजीकृत थीं और इसमें श्रमिक सेवा कार्य में लगे थे। अन्य जनपदों में २ से लेकर ४ मिलें तक पंजीकृत थीं तथा इनमें कुल १५५ व्यक्ति कार्यरत थे।

इस प्रकार खाद्य तेल उद्योग की कुल १०२ पंजीकृत थीं जिनमें ३५८ व्यक्ति सेवारत थे।

उत्पादन की दृष्टि से सुलतानपुर जनपद में १७२४ कुन्तल तेल का उत्पादन हुआ तथा गोण्डा एवं प्रतापगढ़ जनपद में ३५५४ कुन्तल तेल का उत्पादन हुआ जबकि फैजाबाद, आजमगढ़, बहराइच तथा इलाहाबाद जनपदों में ७३०६ कुन्तल खाद्य तेल उत्पादित किया गया।

सन् १९८५ में सर्वाधिक खाद्य तेल मिलें फैजाबाद तथा वाराणसी जनपदों में स्थित थीं यहाँ ७-७ मिलें पंजीकृत थीं जिनमें ५६ श्रमिक कार्यरत थे। गोण्डा, कुशीनगर, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, बहराइच जनपदों में खाद्य तेल मिलों की ६-६ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें कुल १४४ श्रमिक सेवारत थे। इसी प्रकार सुलतानपुर, बलिया, जौनपुर, देवरिया तथा श्रावस्ती जनपदों में ५-५ इकाईयाँ पंजीकृत थीं और १०० श्रमिक सेवारत थे। अन्य जनपदों में ४-४ एवं २-२ तथा ३-३ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिसमें १६८ श्रमिक सेवारत थे।

उत्पादन की दृष्टि से फैजाबाद तथा वाराणसी जनपद में ८१४८ कुन्तल तेल उत्पादित किया गया तथा गोण्डा, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर जनपदों में २०७२० कुन्तल तेल उत्पादित हुआ।

सारणी संख्या -५.०६

पूर्वी उत्तर प्रदेश

खाद्य तेल उद्योग का उत्पादन (कुन्टल में)

क्र०स०	जनपद	१९८० उत्पादन	१९८५ उत्पादन	१९९० उत्पादन	१९९५ उत्पादन	२००० उत्पादन
१	फैजाबाद	१८२५	३८३२	६४०८	७३००	८२१२.५
२	गोण्डा	१९३८	४०४२	६६६७	७४७०	८४७८
३	सुल्तानपुर	१७२४	२९३२	६५३४	७२१६	८२१४
४	प्रतापगढ़	१६१६	३४१२	६२१३	७०९६	८०१४
५	इलाहाबाद	२२२६	४२१८	६९२२	८०१४	८८१८
६	वाराणसी	२१२२	४३१६	७०११	८१२१	८७१६
७	महराजगंज	२०२४	४३२१	६०११	७४२७	७९३८
८	सोनभद्र	२२४४	३०१६	५९१८	७०११	७९१६
९	बलिया	१५१४	४०३१	७५१६	८०११	८६३२
१०	गाजीपुर	१६२७	३८१६	६४११	७६१२	८४१६
११	मऊ	२१२५	६३१४	६८८१	७६१९	८२७४
१२	आजमगढ़	१८३७	२९३८	६५२५	७४१६	८३१२
१३	बहराइच	१४२१	३७३८	६९२२	७५३०	८५२५
१४	मिर्जापुर	१७२३	३२२१	६०६१	७०२१	८०११
१५	जौनपुर	१९१८	३२२२	६४१८	७६४८	८६१८
१६	बस्ती	२०३३	३६४४	६८१६	७६२१	८७१८
१७	गोरखपुर	२०२४	४०३२	६९३२	७८९६	८९३२
१८	देवरिया	२२१४	४४१७	७०७८	८०९६	९०१२
१९	संतरविदास नगर	२२१६	५४१६	७०२८	७८८२	८६७६
२०	बलरामपुर	२१२८	३०४१	६९२४	६२४१	७०११
२१	श्रावस्ती	२३१४	६०१४	५४२६	८२१४	७११६
२२	संतकबीरनगर	२२०४	३९१४	८७६१	६४२१	६९१२
२३	चन्दौली	२३१४	२६८४	७०३४	७३३१	६८७२
२४	कुशीनगर	२२४१	४६१२	६७८१	६३२१	७२८१
२५	सिद्धार्थनगर	२०१४	३२४१	६८८१	९२३४	७६७८
२६	अम्बेडकरनगर	१८१४	३८७१	७१२४	५३२१	७८६९

EASTERN U.P. DEVELOPMENT
OF
EDIBLE OIL INDUSTRY
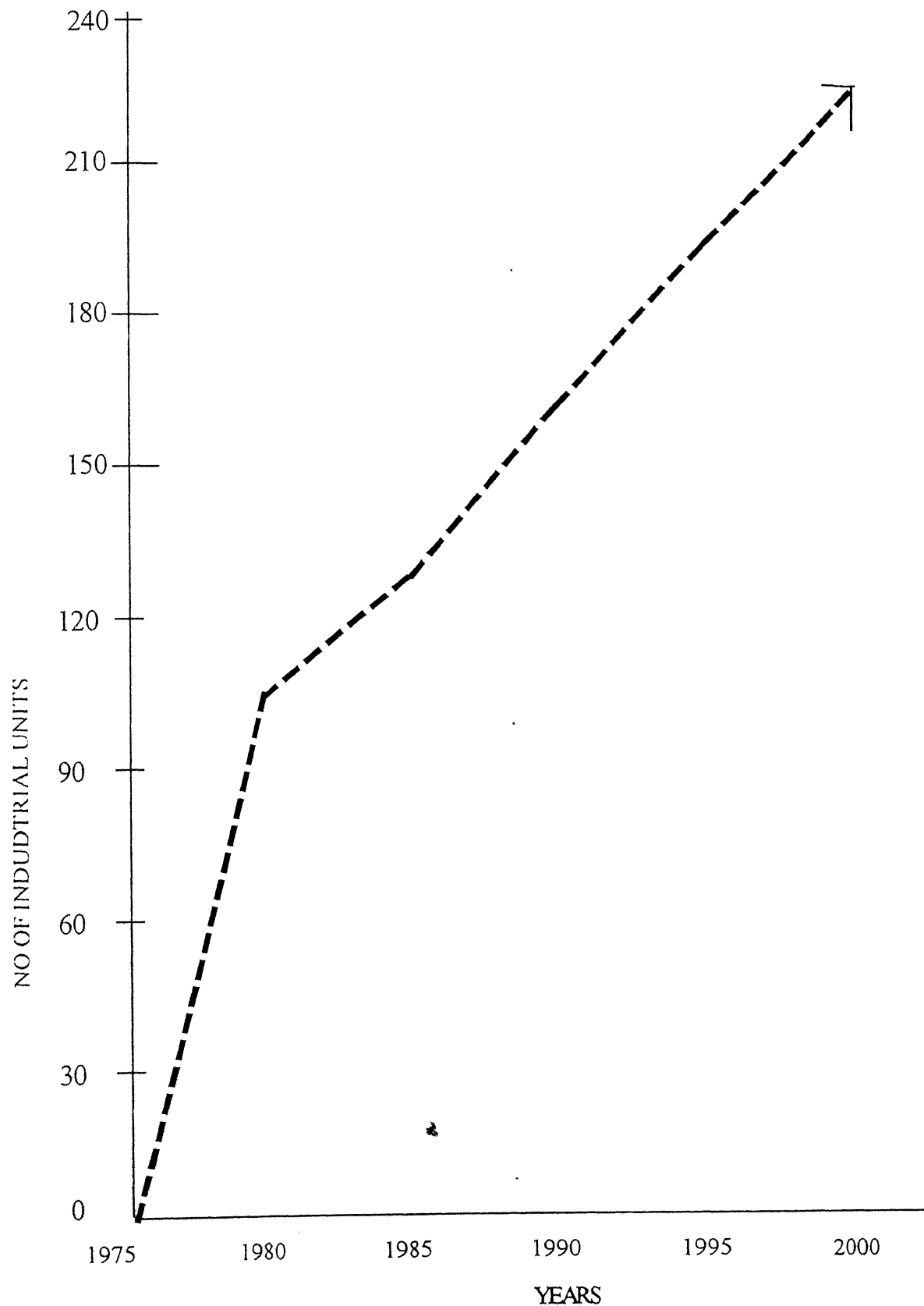
Fig No-6.03

सन् १६६० में वाराणसी एवं फैजाबाद जनपद तेल मिलों की संख्या में सर्वप्रमुख रहा है। यहाँ १०-१० तेल मिलें थीं जिनमें ७६ श्रमिक कार्यरत थे। गोरखपुर जनपद में ६ तेल मिलें थीं जिनमें कुल ३६ श्रमिक कार्यरत थे। उत्पादन की दृष्टि से वाराणसी जनपद में ७०११ कुन्तल तेल का उत्पादन किया गया।

१६६५ में वाराणसी जनपद में सर्वाधिक १३ तेल मिले पंजीकृत थीं जिसमें ३७ श्रमिक कार्यरत थे तथा २००० में सर्वाधिक तेल मिलों की १३ इकाईयाँ गोण्डा जनपद में पंजीकृत थी जिनमें कुल ३६ श्रमिक सेवारत थे।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में १६८० में १०२ तेल मिलें पंजीकृत थीं जिनमें ३५८ व्यक्ति कार्यरत थे। १६८५ में १२० तेल मिले थीं जिनमें कुल ४६८ व्यक्ति सेवारत थे। १६६० में १६३ मिलें पंजीकृत थीं जिनमें कुल ६१६ व्यक्ति कार्यरत थे। १६६५ में पंजीकृत तेल मिलों की संख्या बढ़कर १६८ हो गयी जिनमें ७११ व्यक्ति कार्यरत थे। सन् २००० में २३६ पंजीकृत तेल मिलें थीं जिनमें ८८८ श्रमिक सेवारत थे।

रेखाचित्र संख्या ५.०३ में खाद्य तेल मिलों की वृद्धि की उपनति को दिखाया गया है।

दाल प्रशोधन उद्योग

अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य दलहन फसलें अरहर, मसूर, उरद, चना एवं मटर हैं। इन अनाजों को दर कर इनका छिलका निकालकर दाल तैयार की जाती है। दाल निकालने का काम पहले घरों की महिलायें ही जाँतों की सहायता से करती थीं। परन्तु आधुनिक युग में **इस** कार्य में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया है।(सरणी संख्या ५.०७)

१६८० में सर्वाधिक दाल मिलें सुलतानपुर जनपद में थीं यहाँ दाल प्रशोधन की ७ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिसमें ५६ श्रमिक कार्यरत थे। दूसरे स्थान पर गोण्डा एवं प्रतापगढ़ तथा फैजाबाद जनपद हैं जहाँ ६-६ इकाईयाँ तथा १३५ श्रमिक सेवारत थे। फैजाबाद इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच जनपदों में ५-५ इकाईयाँ तथा १२० श्रमिक सेवारत थे जबकि अन्य जनपदों में २ से लेकर ४ इकाईयाँ तक कार्यरत थीं जिसमें २१६ श्रमिक सेवारत थे। सुलतानपुर जनपद में १६८० में १६३१२ कुन्तल दाल का प्रशोधन किया गया

सारणी संख्या -५.०७
पूर्वी उत्तर प्रदेश
दाल उद्योग की प्रगति

क्र०स०	जनपद	१९८०		१९८५		१९९०		१९९५		२०००	
		U	W	U	W	U	W	U	W	U	W
१	फैजाबाद	६	३५	२	१४	-	-	-	-	-	-
२	गोण्डा	६	४८	२	१६	-	-	-	-	-	-
३	सुल्तानपुर	७	५६	२	१५	-	-	-	-	-	-
४	प्रतापगढ़	६	५२	१	८	-	-	-	-	-	-
५	इलाहाबाद	५	४०	३	२४	-	-	-	-	-	-
६	वाराणसी	४	३२	२	१४	-	-	-	-	-	-
७	महराजगंज	-	-	-	-	२	१६	-	-	-	-
८	सोनभद्र	-	-	१	८	-	-	-	-	-	-
९	बलिया	३	२५	२	१४	-	-	-	-	-	-
१०	गाजीपुर	४	२८	२	१६	-	-	-	-	-	-
११	मऊ	-	-	-	-	२	१६	-	-	-	-
१२	आजमगढ़	५	४०	३	२४	-	-	-	-	-	-
१३	बहराइच	६	४०	३	२६	-	-	-	-	-	-
१४	मिर्जापुर	२	१६	१	७	-	-	-	-	-	-
१५	जौनपुर	३	२६	१	८	-	-	-	-	-	-
१६	बस्ती	३	२४	२	२५	-	-	-	-	-	-
१७	गोरखपुर	४	३२	३	२१	-	-	-	-	-	-
१८	देवरिया	३	२५	२	१४	-	-	-	-	-	-
१९	संतरविदास नगर	-	-	-	-	१	८	-	-	-	-
२०	बलरामपुर	-	-	-	-	२	१४	-	-	-	-
२१	श्रावस्ती	-	-	-	-	१	७	-	-	-	-
२२	संतकबीरनगर	-	-	-	-	१	७	-	-	-	-
२३	चन्दौली	-	-	-	-	२	१६	-	-	-	-
२४	कुशीनगर	-	-	-	-	१	८	-	-	-	-
२५	सिद्धार्थनगर	-	-	-	-	३	२४	-	-	-	-
२६	अम्बेडकरनगर	-	-	-	-	२	१४	-	-	-	-
	योग	६७	५१६	३२	२५४	१७	१३०	-	-	-	-

स्रोत :- १- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त आकड़े ।

सारणी संख्या -५.०८
पूर्वी उत्तर प्रदेश
दाल उत्पादन -(कुन्टल मे)

क्र०स०	जनपद	१९८० उत्पादन	१९८५ उत्पादन	१९९० उत्पादन	१९९५ उत्पादन	२००० उत्पादन
१	फैजाबाद	१५२५०	१३१४०	१४६००	१८२५५	३६५००
२	गोण्डा	२२३१०	१७२३०	१७३२०	२०६४०	३८३२०
३	सुल्तानपुर	१९३१२	१५३४०	१९२४०	२१२५२	४०३६०
४	प्रतापगढ़	१६११७	१४२१८	१८२९८	२०१९५	३६६२५
५	इलाहाबाद	२४२९६	१८१६७	२०२१६	२२४९६	४२२५८
६	वाराणसी	२३४१८	२०९१२	२१६९३	२३२९४	४३३१७
७	महराजगंज	-	-	२५१४२३	-	४०६५४३७
८	सोनभद्र	-	-	-	-	३८६५१०२
९	बलिया	१७१२५	१९२२०	२२६४०	२३९१४	४०२२०५
१०	गाजीपुर	१८९२२	२१६५०	२३२६०	२४२२५	४१२३६५
११	मऊ	-	-	२३२१४३	-	४२६२३८२
१२	आजमगढ़	२०२१४	२३३६६	२५२६५	२६२३५	४२२६५४
१३	बहराइच	२२६४५	२५६३५	२७८९४	२९८९५	४५६३२५
१४	मिर्जापुर	१७२१४	२२३१४	२४६२५	२३२१४	४२२६१७२
१५	जौनपुर	१९६३५	२१३२५	२४६२५	२८९३५	४०२५०१
१६	बस्ती	१८९५०	२०४०६	२४९६५	२७२६५	४२६१२३
१७	गोरखपुर	१९२६५	२३२१५	२५२१४	२६२१४	४३१६५१
१८	देवरिया	१७२२५	२४२३५	२६३१५	२७८९५	४२१६५१२
१९	संतरविदास नगर	-	-	२५६७८९	-	४१२२६५४
२०	बलरामपुर	-	-	२६७८९०	-	३८९६२५१
२१	श्रावस्ती	-	-	२४६३२१	-	३६२६४२५
२२	संतकबीरनगर	-	-	२२१६७२	-	२९२१६४१
२३	चन्दौली	-	-	२४२३२५	-	२६२१९४
२४	कुशीनगर	-	-	२१६४५४	-	४०२२६४१
२५	सिद्धार्थनगर	-	-	२३२५१	-	४५३६१४३
२६	अम्बेडकरनगर	-	-	२६३२६४	-	४७२५१४९

EASTERN U.P. DEVELOPMENT OF DAL MILLING INDUSTRY
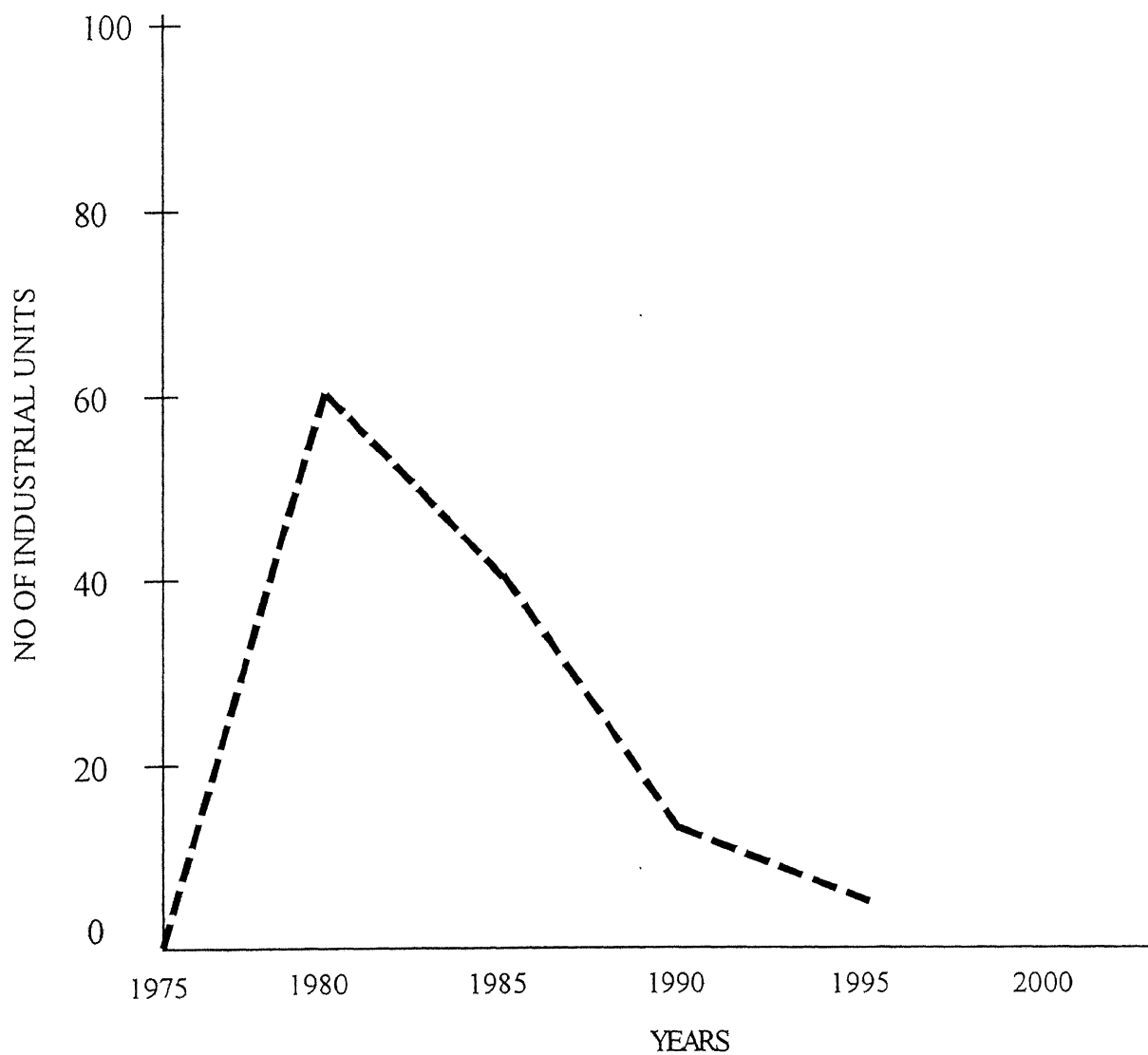
Fig.No-6.04

जबकि गोण्डा तथा प्रतापगढ़ जनपदों में ३८४२७ कुन्तल दाल प्रशोधित की गयी। दाल प्रशोधन की सबसे कम इकाईयाँ मिर्जापुर जनपद में भी थीं। यहाँ दाल प्रशोधन की २ इकाईयाँ कार्यरत थीं जिसमें १६ श्रमिक कार्यरत थे। इनमें कुल १७२१४ कुन्तल दाल का प्रशोधन हुआ।

इसी प्रकार १९८५ में सर्वाधिक दाल प्रशोधन मिलें इलाहाबाद जनपद में थीं यहाँ पर ३ मिलें थीं तथा २४ श्रमिक कार्यरत थे। आजमगढ़ गोरखपुर, बहराइच में भी ३-३ मिलें थीं एवं ७१ श्रमिक सेवारत थे। अन्य जनपदों में एक से लेकर २ मिलें तक स्थापित थीं जिनमें १५९ श्रमिक कार्यरत थे। सन् २००० में सन्त रविदास नगर श्रावस्ती कुशीनगर में एक-एक मिलें तथा ३० श्रमिक कार्यरत थे जबकि बलरामपुर, चन्दौली, सिद्धार्थनगर एवं अम्बेदकरनगर में २ से ३ इकाईयाँ कार्यरत थीं जिनमें कुल ६८ श्रमिक कार्यरत थे। १९८५ में इलाहाबाद जनपद में १८१६७ कुन्तल दाल का उत्पादन हुआ एवं आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच में ७२२१६ कुन्तल दाल का उत्पादन हुआ। सन् २००० में सन्त रविदास नगर, कुशीनगर, श्रावस्ती, सन्तकबीरनगर में १४६९३३६१ कुन्तल दाल का प्रशोधन किया गया जबकि बलरामपुर, चन्दौली, सिद्धार्थनगर एवं अम्बेदकरनगर में १३४१९७३७ कुन्तल दाल का प्रशोधन हुआ।

सुलतानपुर जनपद में अन्य जनपदों की अपेक्षा दाल मिलों की संख्या सर्वाधिक है यहाँ ६ दाल मिलें हैं। जिसमें ७१ व्यक्ति सेवारत हैं। (रेखाचित्र ५.०४)

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों में चावल उद्योग, आटा उद्योग, दाल प्रशोधन तथा खाद्य तेल उद्योग एवं शीतगृह उद्योग प्रमुख हैं। इन वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ-साथ इन औद्योगिक इकाईयों की संख्या में भी धीरे-धीरे वृद्धि होती गयी। अध्ययन क्षेत्र में स्थापित इन कृषि आधारित उद्योगों में से लगभग ७० प्रतिशत औद्योगिक इकाईयाँ नगरीय क्षेत्रों के आसपास ही स्थित हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुत कम इकाईयाँ स्थित हैं क्योंकि इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मांग बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न है जिसको इन वस्तुओं के क्रय की आवश्यकता बहुत

EASTERN U.P. GROWTH OF
COLD STORAGES
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
NO OF UNITS
1975
1980
1985
1990
1995
2000
YEARS
Fig.No-5.05
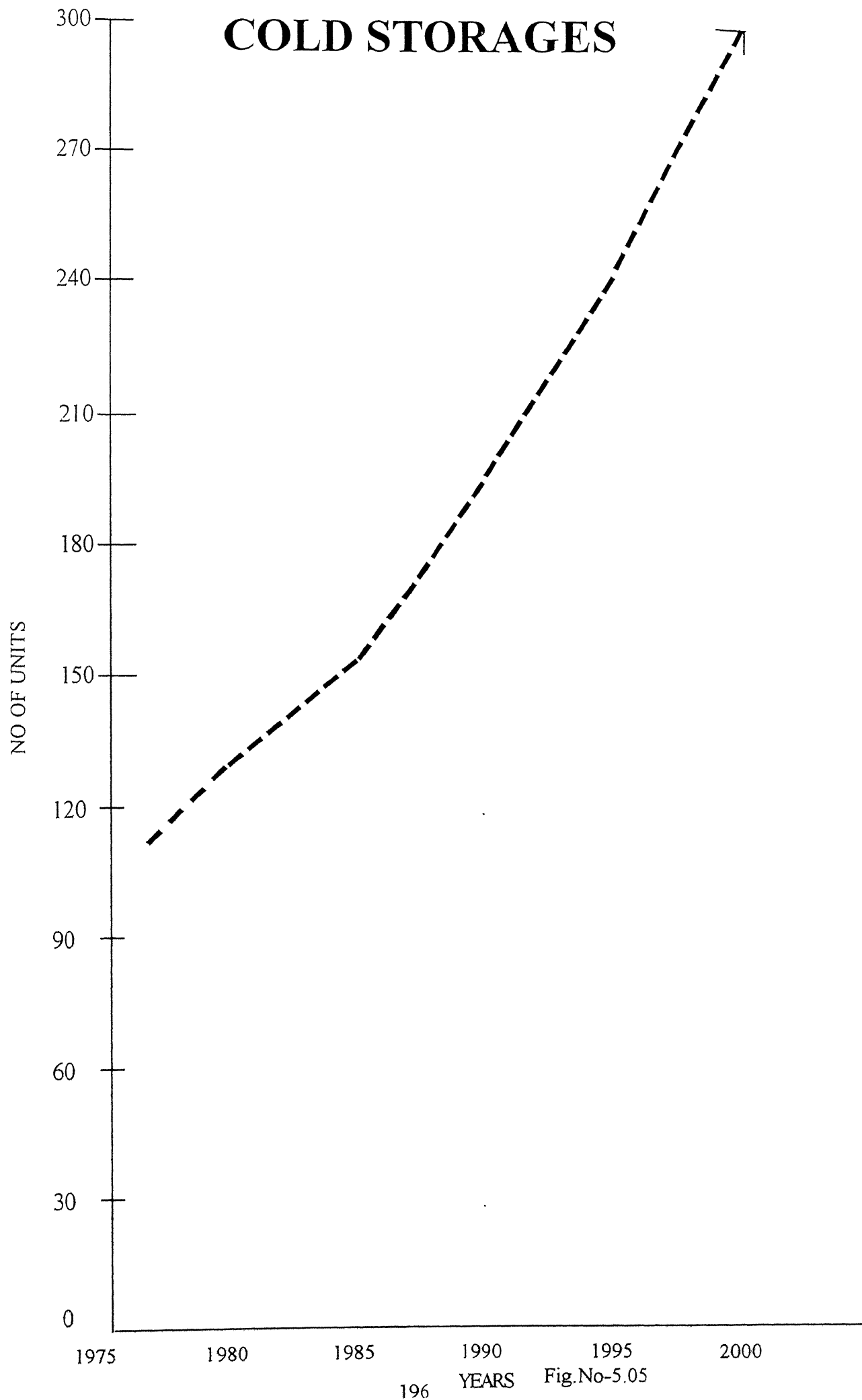
ही कम होती है। अध्ययन क्षेत्र में इन उद्योगों के लिये कच्चा माल स्थानीय रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है क्योंकि इन उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल कृषि फसलों से मुद्रित होता है जो निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उगायी जाती हैं।

शीतगृह उद्योग- यह उद्योग आलू अथवा बाहरी सब्जियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। यहाँ उपयुक्त शीतलता होने से ये पदार्थ अधिक समय तक खराब नहीं होते। अध्ययन क्षेत्र में १९८० में १३१ शीतगृह उद्योग पंजीकृत थे जिसमें वाराणसी जनपद में सर्वाधिक ९ इकाईयाँ पंजीकृत थी जिनमें कुल १०८ श्रमिक सेवारत थे। सबसे कम पंजीकृत इकाईयाँ २ इकाइयाँ सन्तकबीरनगर में थी जिनमें २४ श्रमिक सेवारत थे। १९८० में कुल १७०० श्रमिक शीतगृह उद्योग में सेवारत थे।

१९८५ में अध्ययन क्षेत्र में पंजीकृत शीतगृह इकाईयों की संख्या बढ़कर १५८ हो गयी तथा इसमें २०४४ श्रमिक सेवारत थे। सबसे अधिक पंजीकृत इकाईयाँ १९८५ में वाराणसी जनपद में थी यहाँ १० इकाइयाँ पंजीकृत थीं तथा जिनमें कुल १२० श्रमिक सेवारत थे। सबसे कम पंजीकृत इकाईयाँ गाजीपुर जनपद में ३ थी तथा ३६ श्रमिक सेवारत थे।

१९९० में अध्ययन क्षेत्र में शीतगृह उद्योग की पंजीकृत इकाईयों की संख्या बढ़कर २१३ हो गयी जिनमें कुल २६२१ श्रमिक सेवारत थे। वाराणसी जनपद में ये सर्वाधिक १३ इकाईयाँ थी जिनमें १५६ श्रमिक सेवारत थे। १९९५ में शीतगृह उद्योगों की संख्या बढ़कर २४५ हो गयी तथा इनमें ३१९० व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। सन् २००० में सर्वाधिक इकाईयाँ बस्ती जनपद में कार्यरत थीं जिनमें सर्वाधिक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे थे। इस जनपद में १६ इकाईयाँ पंजीकृत थीं जिनमें कुल २०८ व्यक्ति सेवारत थे। अध्ययन क्षेत्र में सन् २००० में २००२ शीतगृह पंजीकृत थे और जिनमें ३७५१ व्यक्ति सेवारत थे। (रेखाचित्र ५.०५)

अध्ययन क्षेत्र में चीनी मिलों की सं० सबसे अधिक देवरिया जनपद में है। यहाँ पर ५ चीनीं मिलें हैं जिसमें ३९९३ श्रमिक कार्यरत हैं। बस्ती जनपद में २ चीनीं मिलें स्थापित हैं। बलिया, आजमगढ़, सुलतानपुर, मऊ में एक-एक बहराइच जनपद में दो तथा गोण्डा जनपद में एक तथा गोरखपुर एवं जौनपुर जनपद में एक-एक चीनी मिलें स्थापित हैं। सभी

तेल मिल

तेल मिल

शीत गृह उद्योग

आलू गोदाम
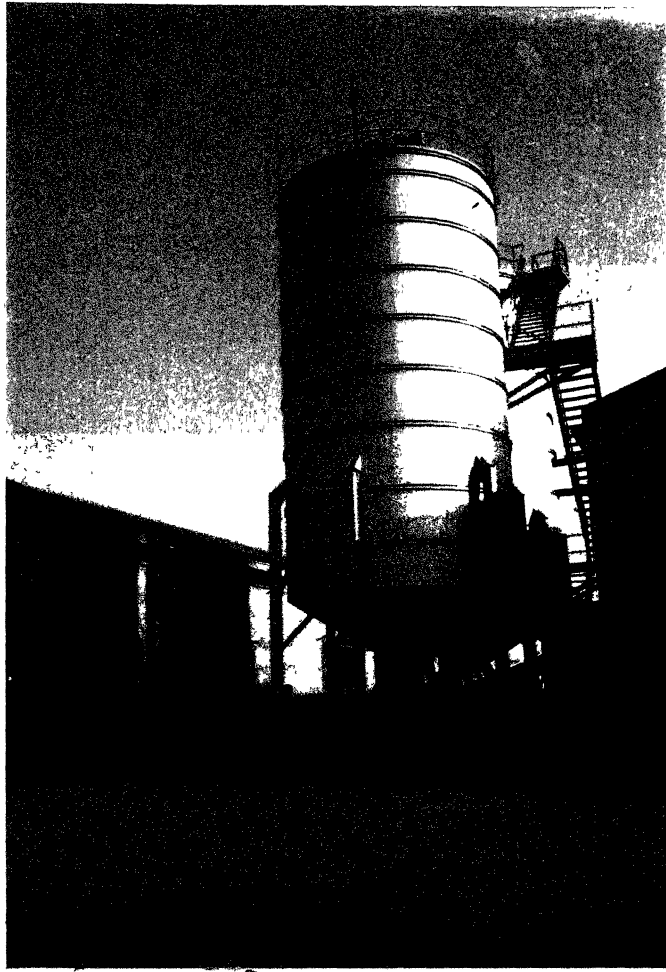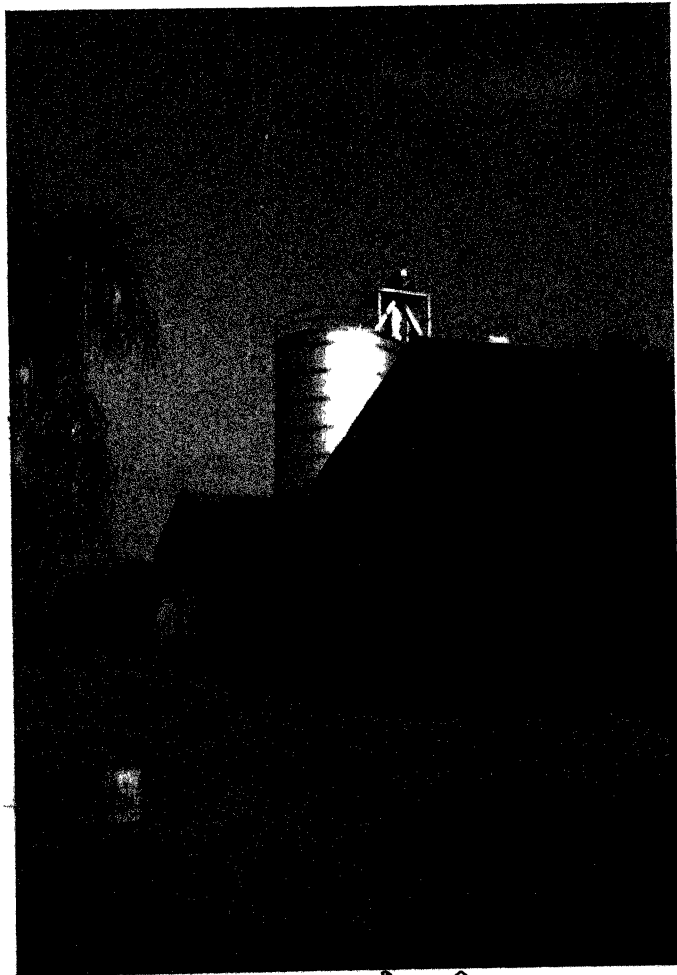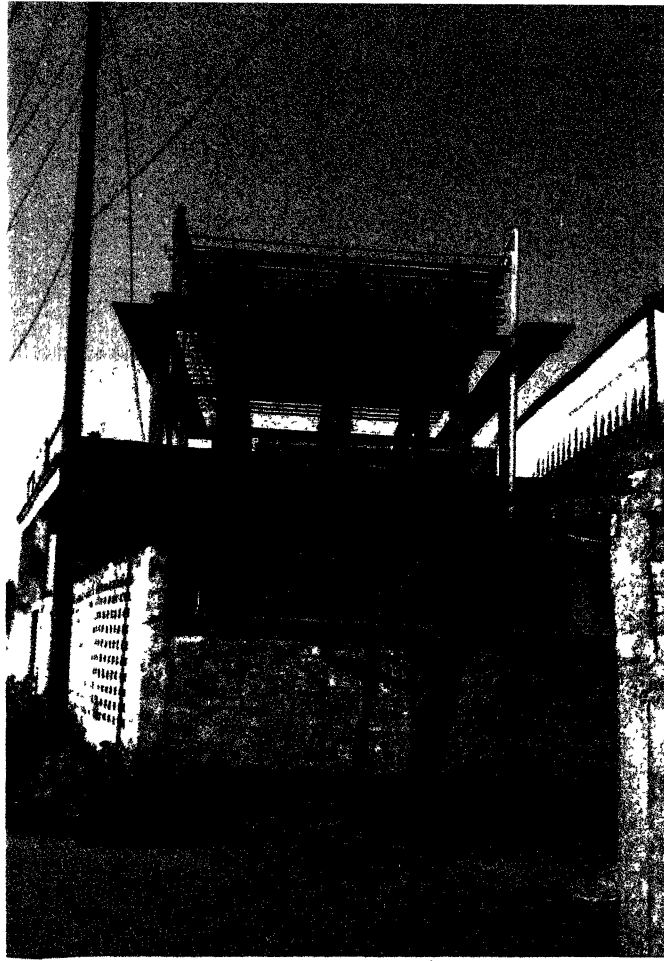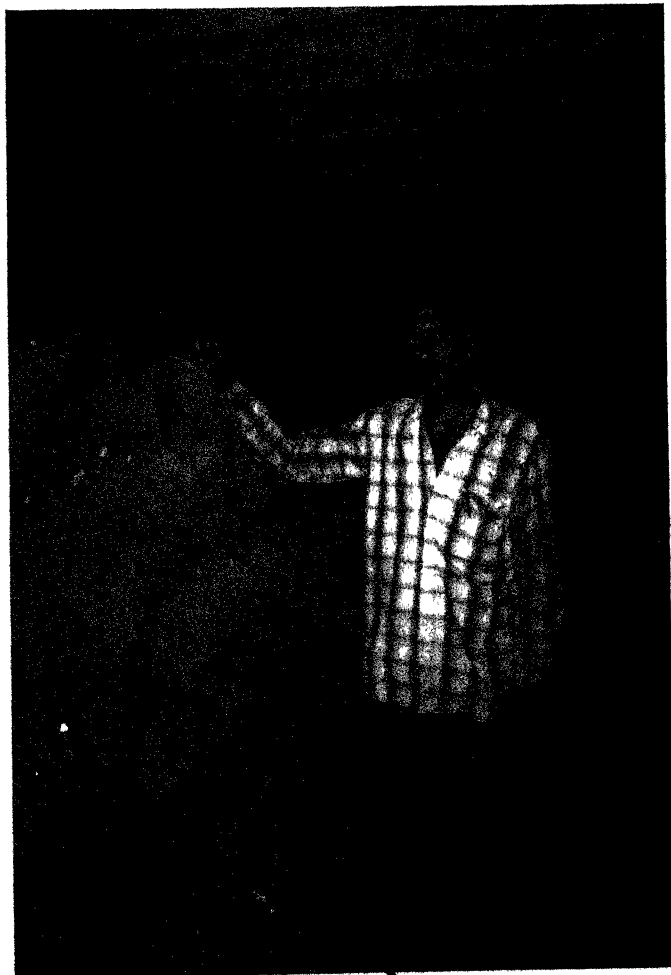
चीनी मिलें कच्चे माल के स्रोत पर ही स्थापित हैं इनके लिये गन्ना आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इनसे उत्पादित चीनी देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों को भी निर्यात की जाती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कुल २१ चीनी मिलें स्थापित हैं। जिनमें कुल १४७३८ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

अध्ययन क्षेत्र में उपर्युक्त वृहतस्तरीय मध्यम स्तरीय एवं लघुस्तरीय कृषि आधारित उद्योगों के अतिरिक्त कुछ कृषि आधारित कुटीर उद्योगों का भी सीमित स्थानों पर विकास हुआ है जिसमें परिवार के ही सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। इन कृषि आधारित कुटीर उद्योगों में मुख्य रूप से तम्बाकू उद्योग, कारपेट उद्योग, इत्र उद्योग एवं सिल्क से सम्बन्धित उद्योग प्रमुख हैं।

तम्बाकू उद्योग का विकास गोण्डा जनपद में नवाबगंज, कर्नेलगंज, तरबगंज, आदि क्षेत्रों में हुआ है। इसमें परिवार के सदस्यों द्वारा अपने खेतों में तम्बाकू बोयी जाती है तथा सूख जाने पर उसको गांठ बनाकर स्थानीय बाजारों में बेच दिया जाता है। इसमें परिवार मिलजुलकर कार्य करते हैं।

इसी प्रकार कारपेट उद्योग का विकास मिर्जापुर जनपद में हुआ है। इस जनपद में इस उद्योग के विकास हेतु सुविधायें उपलब्ध हैं। जूट कुछ मात्रा में इस जनपद तथा पड़ोस के जनपदों में उत्पन्न किया जाता है । शेष पश्चिमी बंगाल से आयात किय जाताहै। जूट को धुलने तथ रंगने की भी आवश्यकता पड़ती है जिसके लिये जल की पूर्ति गंगा नदी से कर लिया जाता है। यह कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है तथा बाद में उससे दरी एवं चटाइयाँ एवं कालीन आदि बनाकर बाजारों में बेंच दिया जाता है। अन्य राज्यों में भी इसकी मांग है। भदोहीं के समीप ऊनी कालीन बनाने का उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हैं यहाँ से बने कालीन विदेशों को भी निर्यात किये जा रहें हैं।

इसी क्रम में अम्बेदकरनगर जनपद के टाण्डा तहसील में सरयू नदी के किनारे कुटीर उद्योग के रूप में कपड़ा बुनायी का काम होता है। यह सूत सन्त कबीरनगर जनपद से मंगाया जाता है तथा यहाँ के कुछ परिवारों द्वारा हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बनाया जाता है एवं इसका उपयाग अम्बेदकरनगर जनपद में स्थित खादी ग्रामोद्योग में किया जाता

EASTERN U.P. - INDUSTRIAL UNITS
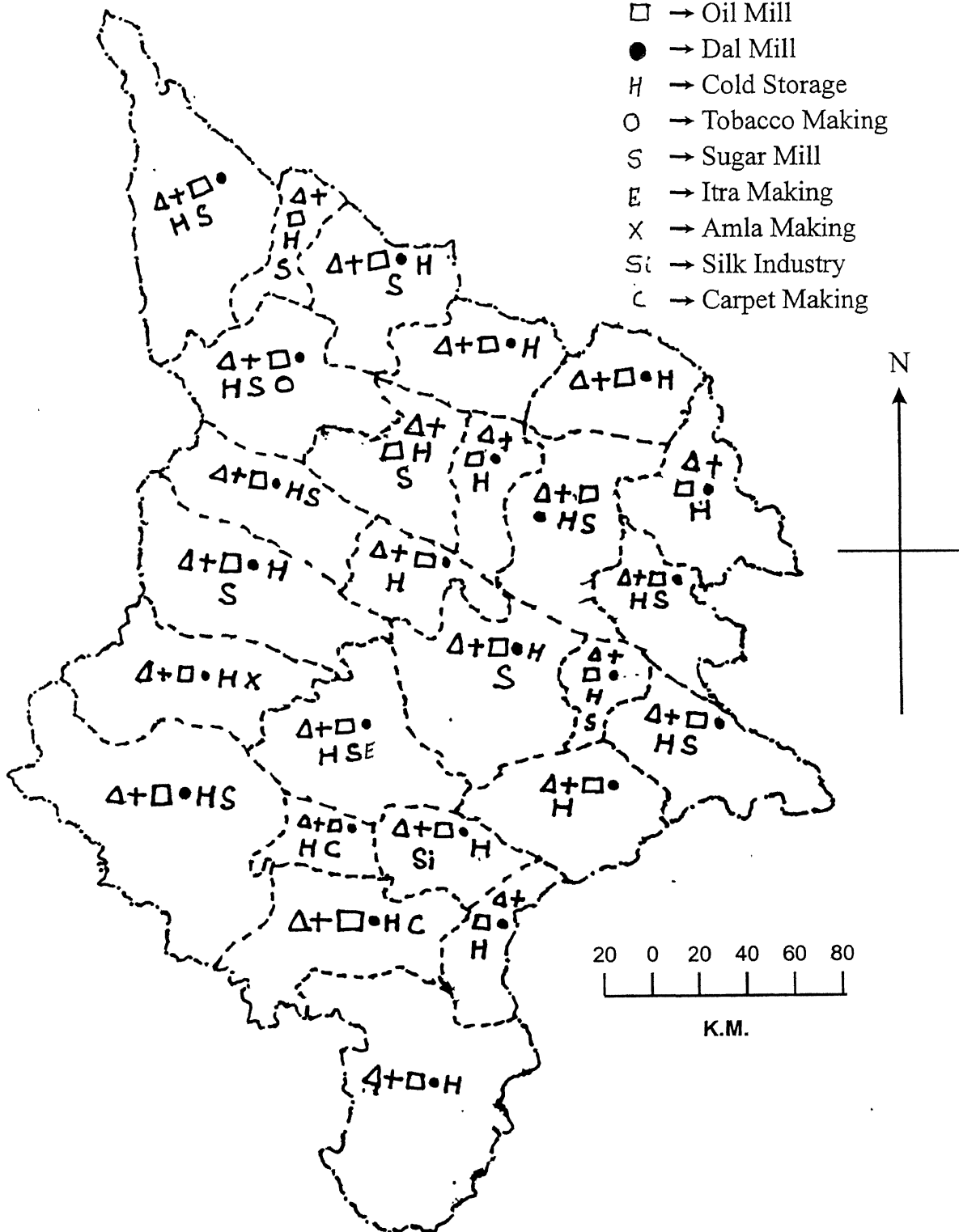
MAP No.- 5.06
2004

है। मऊनाथभंजन के क्षेत्र में भी हथकरघा द्वारा वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसी प्रकार वाराणसी जनपद में सिल्क से सम्बन्धित उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ की सिल्क की बनी बनारसी साड़ियों विश्व प्रसिद्ध हैं।

अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास की समीक्षा–

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर ध्यान देने से विदित होता है कि यहाँ अधिकांश कृषि आधारित उद्योग मांग पर आधारित हैं। दालमिल, चीनी मिल को छोड़कर शेष सभी उद्योग लघुस्तरीय उद्योग हैं जो छोटे पैमाने पर कच्चे माल का उपयोग करते हैं और छोटे पैमाने पर उत्पादन कार्य भी करते हैं। अतः वेवर एवं अन्य सिद्धात प्रर्वतकों द्वारा प्रस्तुत कच्चे पदार्थ एवं परिवहन के प्रभावों का महत्त्व दृष्टिगत होता है। इससे भी अधिक प्रभाव मांग केन्द्र या बाजार का है।

अध्ययन क्षेत्र में विकसित कृषि आधारित उद्योगों की अवस्थिति का यदि उक्त सिद्धान्तों के आलोक में अध्ययन करें, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र के उद्योगों के स्थानीकरण पर अवस्थिति के सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है। वृहतस्तरीय उद्योग के अन्तर्गत चीनी मिल उद्योग प्रमुख है। जिस पर वेवर के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रभाव दिखायी पड़ता है। मध्यमस्तरीय उद्योग में दाल मिलें सम्मिलित हैं जो कि मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हैं यह मुख्यतः मांग पर आधारित उद्योग है इसकी मांग स्थानीय भी है और दूर दराज के इलाकों में भी इसका निर्यात किया जाता है इस उद्योग के लिये कच्चामाल स्थानीय रूप से प्राप्त हो जाता है। शेष अन्य उद्योग लघुस्तरीय हैं इनको अल्पमात्रा में कच्चेमाल की आवश्यकता होती है तथा उत्पादित वस्तु की खपत भी अल्प मात्रा में स्थानीय बाजारो में हो जाती है।

वृहतस्तरीय उद्योगों के लिये विनिर्माण कार्य हेतु अधिक मात्रा में कच्चेमाल एवं उत्पादित मूल्य की खपत हेतु वृहत बाजार की आवश्यकता होती है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयों के विकास के सम्बन्ध में अवस्थिति के सिद्धान्तों की जो सार्थकता सम्भव प्रतीत होती है उसका विवेचन निम्न रूप से किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों पर अवस्थिति सिद्धान्तों का प्रभाव-

जैसा कि पूर्व विवरणों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में मुख्य रूप से चावल, ऑटा, तेल, दाल एवं चीनी मिल उद्योग ही कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग हैं जिनमें चीनी मिल उद्योग वृहतस्तरीय उद्योग के अन्तर्गत आता है तथा दाल मिल मध्यम स्तरीय एवं शेष लघु स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। दाल प्रशोधन, चावल, मिल उद्योग तथा चीनी मिल उद्योग भारक्षयी कच्चे पदार्थ (अनाज एवं गन्ना) पर आधारित है अतः इन उद्योगों का कच्चे पदार्थ के प्राप्ति स्थल पर ही स्थानीकरण होना चाहिए और ऐसा हुआ भी हैं खाद्य तेल उद्योग भी उत्पादन प्रक्रिया में भारक्षयी पदार्थ पर आधारित है इसलिये इस उद्योग का सरसों उत्पादक क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। गांवों में कोल्हू तेल उद्योग का इसी आधार पर विकास हुआ है। परित्यक्त पदार्थ खली के रूप में गांवों में ही प्रयुक्त हो जाता है। नगरीय क्षेत्र में खाद्य तेल की अधिकांश मांग होने के कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर के बीच परिवहन की उचित सुविधा न होने के कारण नगरीय क्षेत्र में इस उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। खाद्य तेल तरल पदार्थ है अतः इसे नगरीय क्षेत्रों तक ले जाना सरसों ले जाने की अपेक्षा कठिन होता है। इस कारण भी नगरीय क्षेत्रों में यह उद्योग अधिक विकसित हुआ है। आटा उद्योग मुख्यतः बाजार क्षेत्र से अधिक प्रभावित होता है अतः इस उद्योग का नगरीय क्षेत्रों में जहाँ बाजार की सुविधा उपलब्ध है में अधिक स्थानीकरण हुआ है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में विकसित होने वाले कृषि आधारित उद्योग मुख्यतः लघुस्तरीय (चीनी एवं दाल प्रशोधन मिल उद्योग को छोड़कर) उद्योग ही है वृहत स्तरीय चीनी उद्योग तथा मध्यमस्तरीय दाल प्रशोधन मिल उद्योग तो औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धान्तों के प्रभावों से प्रभावित हैं लेकिन शेष लघुस्तरीय उद्योगों पर इसका प्रभाव कम है क्योंकि इन उद्योगों के विकास पर मुख्य रूप से उपभोक्ता केन्द्रों का अधिक प्रभाव पड़ा है। भविष्य में भी लघु उद्योगों का विकास उपभोक्ता केन्द्रों के प्रभावों के आधार पर निश्चित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों का ही विकास सम्भव हो सकेगा।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी औद्योगिक विकास हेतु समुचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। सड़कों का विकास कम हुआ है। विद्युतीकरण भी भली-भाँति नहीं हो सका है ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण कार्य भी नहीं किया गया है अतः कुछ ब्लाक समूहों के लिये पृथक-पृथक सेवा केन्द्रों का विकास आवश्यक है जो कालान्तर में बाजारों के रूप में होकर लघुउद्योग के केन्द्र बन सकते हैं। ऐसी दशा में ही गांवों का विकास सम्भव हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य आधार कृषि है अतः कृषिगत कच्चे पदार्थों का विकास आवश्यक है। जिनसे उन पर आधारित कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सके। ग्रामीण अँचलों की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित होने से ही सुधर सकती है। अतः इस ओर सक्रिय प्रयास किया जाना आवश्यक है।

खण्ड ब

पूर्वी उत्तरप्रदेश में औद्योगिक विकास का स्थानिक प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तरप्रदेश में सम्मिलित समस्त जनपदों के कृषि आधारित उद्योगों के विकास को ज्ञात करने के लिये Z Score विधि का प्रयोग किया गया है जिसका सूत्र निम्नवत है-

$$Z\ Score = \frac{X - X^{-}}{Sd}$$

इस सूत्र की सहायता से अध्ययन क्षेत्र के समस्त जनपदों के प्रत्येक कृषि आधारित उद्योगों के विभिन्न मूल्यों (उद्योगों की संख्या, उत्पादन, कर्मकरों का प्रतिशत एवं कर्मकरों की संख्या) को लेकर उनका Z Score ज्ञात किया गया है तथा मूल्यों के Z Score को जोड़कर सूचकांक बनाया गया है। इन्हीं सूचकांकों के आधार पर समस्त जनपदों को चार वर्गों में बांट कर उद्योगों के स्थानिक प्रतिरूप का विश्लेषण किया गया है जो निम्नवत है। (सारणी ६.०६ एवं ६.१०)

१. अति पिछड़े क्षेत्र- इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के उन जनपदों को सम्मिलित किया गया है जिनका सूचकांक ० से कम है। इसमें १६ जनपद सम्मिलितत हैं जिसमें फैजाबाद, गोण्डा, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, मऊ, सन्तरविदासनगर, श्रावस्ती, सन्तकबीरनगर जनपद हैं। इनका सूचकांक क्रमशः (—-4.18), (–4.46), (–6.35), (–9.38), (–4.05), (–0.06), (–2.97), (–2.25), (–2.90), (–7.13), (–2.49), (–3.18), (–2.16), (–2.76), (–10.35), (–3.42) हैं। इन जनपदों के अत्यन्त पिछड़े होने के पीछे मुख्य कारण इनके मूल्यों का कम होना है। ये जनपद अन्य वर्गों में आने वाले जनपदों के मूल्यों से अत्यन्त कम हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत सबसे पिछड़ा जनपद बलिया है जिसका सूचकांक (–0.06) है। इसी जनपद का उद्योगों की संख्या का सूचकांक (–0.05) है जबकि उत्पादन का सूचकांक (–1.44) तथा कर्मकरों के प्रतिशत का सूचकांक (0.77)

सारणी संख्या -६.०६

पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का स्थानिक प्रतिरुप

क्र०स०	वर्ग	सूचकांक	जनपदो की संख्या	जनपदो के नाम
१	अति पिछड़े क्षेत्र	० से कम	१६	फैजाबाद ,गोण्डा , सुल्तानपुर , प्रतापगढ़,इलाहाबाद,बलिया, गाजीपुर ,अजमगढ़,जौनपुर , मिर्जापुर, सोनभद्र, महराजगंज,मऊ,सुतरविदासनगर , श्रावस्ती ,सुतकबीरनगर।
२	पिछड़े क्षेत्र	० -- ५	५	बहराइच, बस्ती , देवरिया ,गोरखपुर, चन्दौली ।
३	विकासशील क्षेत्र	५ -- १०	३	बलरामपुर , सिद्धार्थ नगर , कुशी नगर ।
४	विकसित क्षेत्र	१० -- १५	२	वाराणसी , अम्बेडकर नगर ।

सारणी संख्या -६.१०

विभिन्न मूल्यों का Z Score एवं सूचकांक

क्र०स०	जनपद	Z Score	Z Score	Z Score	Z Score	सूचकांक
१	फैजाबाद	०.८४	-४.५७	-०.००	-०.४५	-४.१८
२	गोण्डा	१५.श्रंद	-४.३७	०.८१	-२.०१	-४.४२
३	सुल्तानपुर	०.६३	-४.८८	०.१२१	-२.२३	-६.३५
४	प्रतापगढ़	१.०८	-५.३१	-०.६०	-४.६५	-६.७८
५	इलाहाबाद	०.२६	-२.८८	-०.६१२	-०.८५	-४.०५
६	वाराणसी	-०.६५	-६.०६	-०.१५	-०.८३	१०.६६
७	महराजगंज	-०.४३	-२.३०	-०.८६	०.४१	-३.१८
८	सोनभद्र	-१.०२	-०.७५	-०.८८	०.१६	-२.४६
९	बलिया	०.५०	-१.४४	०.११	०.७७	-०.०६
१०	गाजीपुर	०.८८	-३.६६	-०.६३	०.४७	-२.९७
११	मऊ	१.७१	-४.८३	०.२२	०.७४	-२.१६
१२	आजमगढ़	०.५३	-३.७४	०.३०	०.६६	-२.२५
१३	बहराइच	०.७७	-३.४६	१.०६	२.६८	१.०५
१४	मिर्जापुर	-१.०५	-६.६३	०.१९	०.३९	-७.१
१५	जौनपुर	०.८८	-४.१०	-०.०१५	०.३३	-२.९०
१६	बस्ती	०.३६	३.७७	०.१५	०.२७	४.५५
१७	गोरखपुर	०.७७	२.४२	०.२०	०.०६	३.४५
१८	देवरिया	०.०५	-४.७०	३.७२	१.८२	०.८९
१९	संतरविदास नगर	-०.५७	-३.०१	०.१८	०.६४	-२.७६
२०	बलरामपुर	-१.९५	१०.९३	०.५२	०.२६	९.७६
२१	श्रावस्ती	-१.३३	-८.३४	-०.९९	०.३१	-१०.३५
२२	संतकबीरनगर	-१.३६	-१.१९	-०.९१	०.०४	-३.४२
२३	चन्दौली	-१.५७	७.०९	-०.९८	०.०४	४.५८
२४	कुशीनगर	-१.२२	१०.२५	-०.९८	०.४२	८.४७
२५	सिद्धार्थनगर	-०.९८	११.४९	-०.९१ .	०.२३	९.८३
२६	अम्बेडकरनगर	०.०५	११.२३	०.७९	०.४१	१२.४८

है तथा कर्मकरों की संख्या का सूचकांक (0.11) है। सबसे कम पिछड़ा जनपद श्रावस्ती है जिसका सूचकांक (-1035) है। बलिया जनपद में उद्योगों की संख्या का सूचकांक (-1.33), उत्पादन का सूचकांक (-8.34) कर्मकरों के प्रतिशत का सूचकांक 0.31 तथा कर्मकरों के संख्या का सूचकांक (-0.99) है।

अतः इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले जनपद प्रत्येक मूल्यों के दृष्टिकोण से अन्य वर्गों में आने वाले जनपदों से काफी पीछे है स्पष्ट है कि इन जनपदों में कृषि आधारित का उतना विकास नहीं हुआ है जितना कि अन्य वर्ग में आने वाले जनपदों का।

२. पिछड़े क्षेत्र- इस वर्ग के अन्तर्गत वे जनपद सम्मिलित हैं जिनका सूचकांक ० से ५ है। इस वर्ग के अन्तर्गत ५ जनपद सम्मिलित हैं। ये जनपद बहराइच, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तथा चन्दौली है इनका सूचकांक क्रमशः (1.05) (0.89) (4.55) (3.45) तथा (4.58) है।

इन जनपदों में कृषि आधारित उद्योगों का विकास प्रथम वर्ग के अन्तर्गत अन्य जनपदों की अपेक्षा अधिक हुआ है। सर्वाधिक विकास चन्दौली , जनपद में है जिसका सूचकांक 4.58 है। इस जनपद में उद्योगों की संख्या का सूचकांक -1.57 है तथा उत्पादन का सूचकांक 7.09 है कर्मकरों के प्रतिशत का सूचकांक 0.04 है तथा कर्मकरों की संख्या का सूचकांक -0.98 है। इस प्रकार इस जनपद में कृषि आधारित उद्योगों में उत्पादन का सूचकांक सर्वाधिक है जो कि इस जनपद को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सबसे विकसित जनपद में ला देते हैं। इस वर्ग में सबसे कम औद्योगिक विकास देवरिया जनपद में है जिसका सूचकांक 0.89 है। इस जनपद में उद्योगों की संख्या का सूचकांक चन्दौली जनपद की अपेक्षा अधिक है जबकि कृषि आधारित उद्योगों में लगे कर्मकारों की संख्या के सूचकांक में भी यह चन्दौली , जनपद के कृषि आधारित उद्योगों में लगे कर्मकारों के सूचकांक में काफी आगे जबकि उत्पादन सूचकांक में चन्दौली जनपद अग्रणी है जो इस जनपद को देवरिया जनपद की अपेक्षा विकास में अग्रणी बना देता है।

३. अल्पविकसित क्षेत्र- इस वर्ग के अन्तर्गत वे जनपद आते हैं जिनका सूचकांक ५

SPATIAL PATTERN OF AGRO-BASED INDUSTRIES IN EASTERN U.P.

MAP No.- 6.06
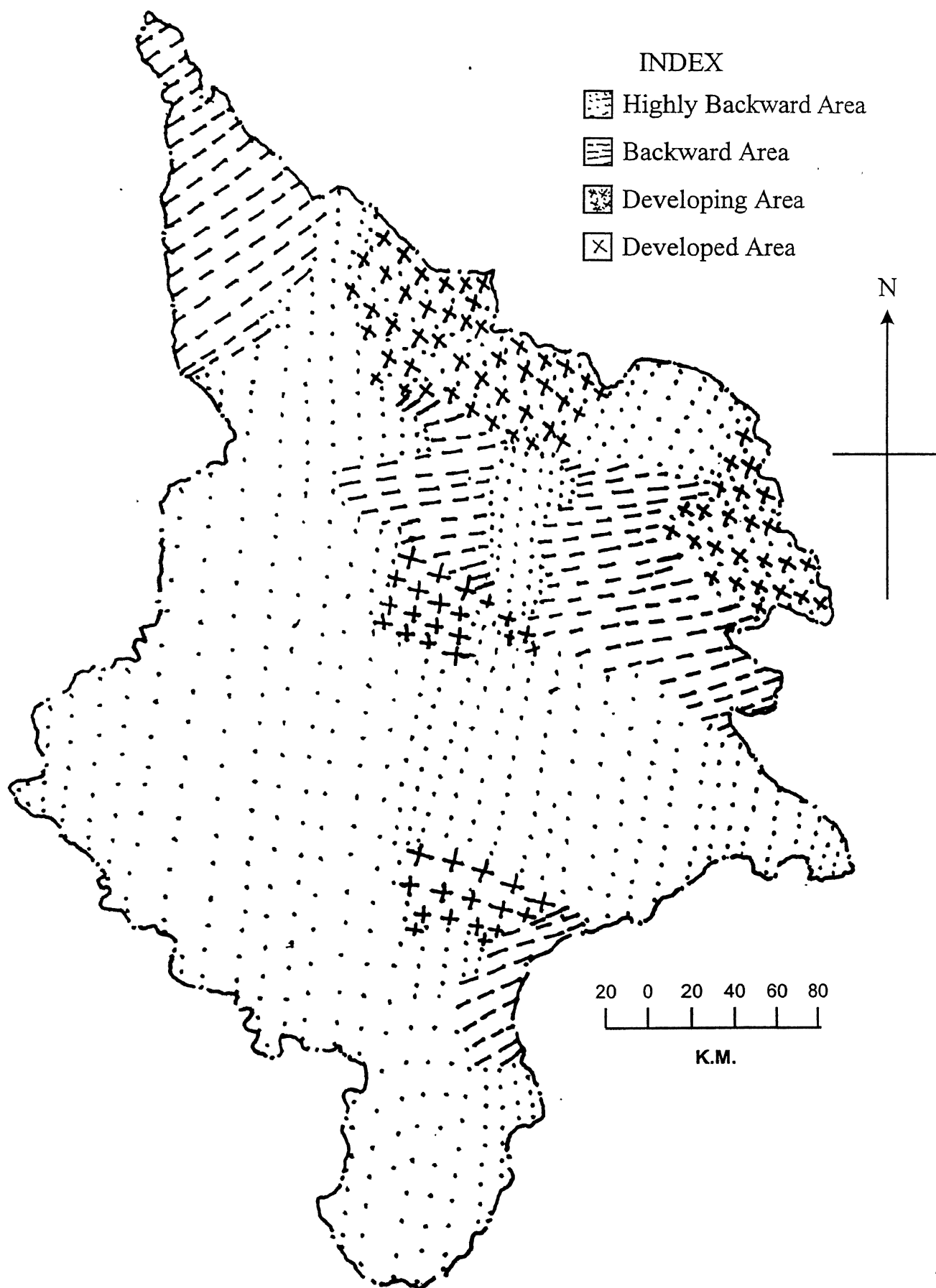
से १० के बीच पाया जाता हैं इसमें बलरामपुर तथा सिद्धार्थनगर एवं कशीनगर जनपद सम्मिलित है। इनका सूचकांक क्रमशः ६.७६ तथा ६.८३ एवं ८.४७ है। इन जनपदों में अन्य मूल्यों के सूचकांकों की अपेक्षा श्रमिकों के प्रतिशत तथा उत्पादन का सूचकांक सर्वाधिक है जैसा कि सारणी संख्या ७.०२ से स्पष्ट हैं। बलरामपुर जनपद में चीनी मिलों की संख्या अधिक है तथा चावल का उत्पादन भी अच्छा होता है जबकि सिद्धार्थनगर जनपद में उत्तम श्रेणी का चावल उत्पन्न किया जाता है। अतः चावल का उत्पादन एवं बलरामपुर जनपद में चीनी मिलों में लगे तथा अन्य कृषि उद्योगों में लगे श्रमिकों के प्रतिशत का सूचकांक इन जनपदों को अल्पविकसित श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है।

४. **विकसित क्षेत्र-** इस वर्ग के अन्तर्गत वे जनपद सम्मिलित हैं जिनका औद्योगिक सूचकांक १० से १५ है। इसमें वाराणसी अम्बेदकरनगर तथा जनपद सम्मिलित हैं। जिनका सूचकांक क्रमशः (10.69), (12.40) है। इन जनपदों में उत्पादन का सूचकांक सर्वाधिक होने के नाते ये जनपद विकसित क्षेत्र की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वाराणसी जनपद में सिल्क उद्योग का अच्छा विकास हुआ है तथा सबसे अधिक श्रमिक भी इसी उद्योग में लगे हुये हैं जिससे श्रमिकों की संख्या का सूचकांक तथा उत्पादन का सूचकांक मिलकर वाराणसी जनपद को विकसित क्षेत्र बना देते हैं। अम्बेदकरनगर जनपदों में उत्पादन का सूचकांक सर्वाधिक है जिसका कारण ये जनपद विकसित क्षेत्र की श्रेणी मे आ गये हैं। जबकि अन्य मूल्य उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं।(चित्र६.०६)

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तरप्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की दृष्टि से अधिकांश जनपद अत्यधिक पिछड़े हैं तथा बहुत कम जनपद इनके विकास में अग्रणी हैं। अत्यधिक पिछड़े जनपदों की संख्या काफी अधिक है। अतः अत्यधिक पिछड़े जनपदों में नये उद्योगों का सृजन किया जाना आवश्यक है जिससे श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तथा अन्या मूल्यों, जिसमें ये पिछड़े हैं, ये भी वृद्धि होगी।

■

References

1- Brown ,C.M. - (1962) ; Successful features in the planning of new Town Inustrial Estates - Journal of Town planning Institute .

2- Chaudhary ,M.R.(1970) ; Indian Industries Develop -ment location.

3- Dutt, R. (1906) ; The Economic History of India ; Tara Publication New Delhi.

4- Dunn, E.S.; The location of Agricultureal production Gainesville : uni.of Fiorida Press.

5- Dayal ,P. (1958); The location of Development of Aluminium Industry in India .Published in N.G.J.I.

6- Development of Industries in Uttar Pradesh (1964) Directorate of Induatries U.P. Kanpur Planning and Research Devision.

7- Estall, R.C. and Buchanan R.O.(1961). Industiral Ac -tivity and Economic Geography,London .

8- Florence, P. Sargant (1958). Investment Location and Size of Plants . University Press. Cambridge .

9- Hoffman, L.A. (1965). Economic Geography.New York.

10- Jarrett, H.R.(1977) ; A Geography of manufacturing. Oxford University Press.London.

11- Kumar Pramila (1997); Udyogik Bhogoal,Geography : M.P. Hindi granth Academy .

12- Kulsratha , R.S.(1986); Industrial Economical.Sahitya Bhavan Prakashan.Agra .

13- Mahdal , B. (1971); Manufacturing Regions of North Bihar.National Geographical Journal of India .

14- Pred Allan , Industrialization Initial Advantage and American Metropolitian Growth.Geographical Review.

15- Predohl Andreas (1958), 'Theory of Locationand General Economics', Journal of Politi cal Economy. Vol.96.

16- Riley, R.C. (1973); Industrial Geography , New Delhi.
17- Rao, R.V. (1967); Cottage and small Indutries and Plan -ning Economy ,'sterling Publishers.New Delhi.
18- Smith, M.D. (1971); Industrial Location an Economic Geography Analysis.John Wiley and Sons.INS.New Delhi.
19- Sinha , B.N.(1972) Industrial Geography of India. Calcutta .
20- Singh , B.B. ; Agro -Industrial Intergration ; A Model .
21- Srivastava , P.K. and C.B. (1973); Industrial Economics. Sahitya Bhawan , Agra .
22- Sastry , N.S.R. (1948); A Statistical study of India's Industrial /development : Thackeral Co. Ltd. Bombay.
23- Thompson , J.H. (1955); A New Methods for Measuring Manufacturing ; A.A.A.G.
24- Thaper , S.D. (1962); Small Industries:study Methodology and concepts ; Asian Economic Review 4,2 Feb.
25- Uttar Pradesh mein Udyogon Ka Vikas Pragati smiksha 1998-99 Udyog Nideshalaya,Kanpur .
26- Yaseen , Leonard C. (1956); Plant location,American Research council,New Delhi..
27- औद्योगिक निदेशिका(१९९९) - जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित
28- औद्योगिक प्रेरणा(१९९९) - जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित
29- उ० प्र० में औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा (१९९८-२०००) - उद्योग निदेशालय उ० प्र०
30- उ० प्र० 99 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उ० प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित

चीनी मिल उद्योग

चीनी मिल उद्योग
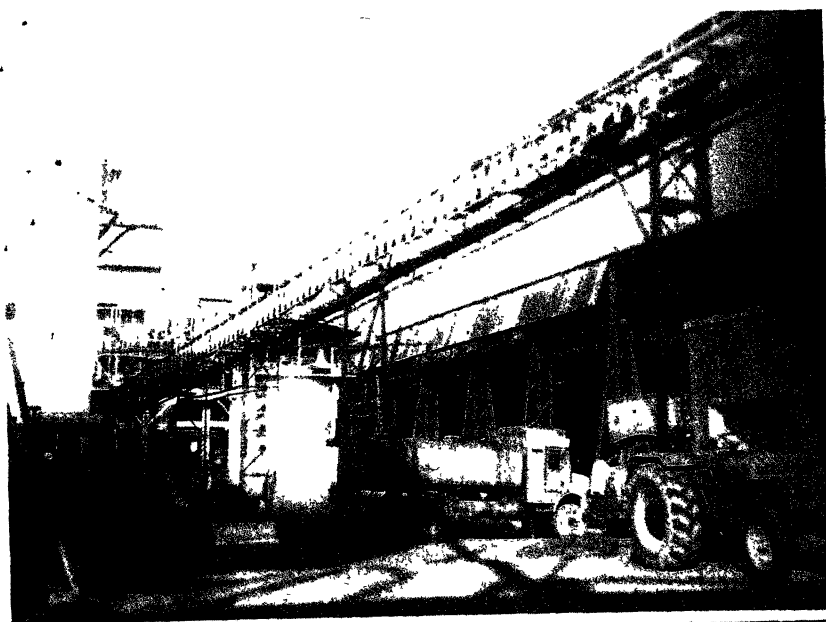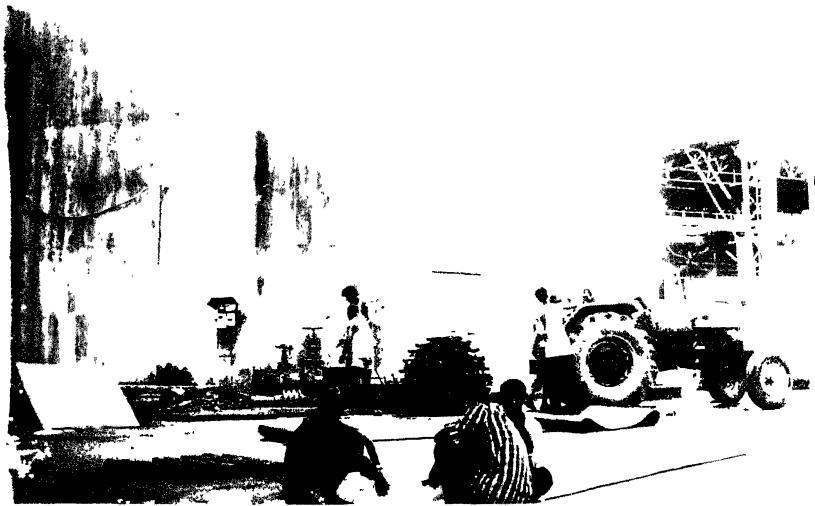
चीनी मिल उद्योग
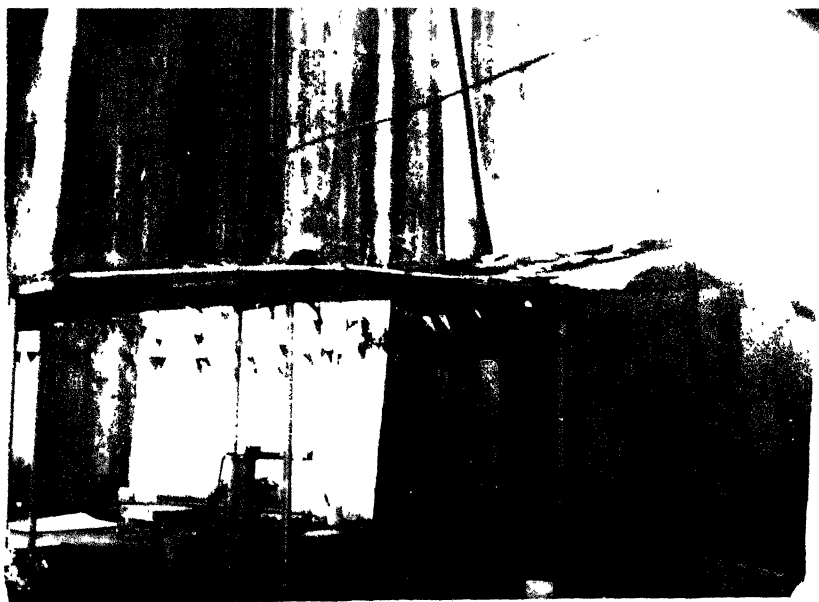
–चीनी मिल उद्योग

–चीनी मिल उद्योग

–चीनी मिल उद्योग

षष्टम् सोपान

कृषि आधारित उद्योग प्रतिदर्श अध्ययन

कृषि आधारित उद्योग : प्रतिदर्श अध्ययन

उद्योगों के विकास पर क्षेत्रीय कारकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों के विकास को समझने के लिये यह आवश्यक है कि कुछ प्रतिदर्श इकाईयों का सर्वेक्षण किया जाय जिससे प्राथमिक आधार पर यह ज्ञात हो सके कि उन इकाइयों की क्या विशेषतायें हैं और इनकी क्या समस्यायें हैं। ये दोनों तथ्य सामान्य अध्ययनों से कुछ पृथक भी हो सकते हैं क्योंकि ये स्थानीय कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिये जो भी अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किये जाते हैं, उनकी वास्तविकता को समझने के लिये प्राथमिक आधार के आंकड़ों का अध्ययन आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य में कुछ प्रतिदर्श औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन किया गया है। इस विवेचन से पूर्वी उत्तरप्रदेश में कृषि पर आधारित औद्योगिक संरचना का समुचित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि पर आधारित जिन प्रतिदर्श औद्योगिक इकाईयों का सर्वेक्षण किया किया है वे निम्न हैं-

क. चीनी उद्योग

ख. चावल उद्योग

ग. आटा उद्योग

घ. तेल उद्योग

ङ. दाल उद्योग

उपरोक्त प्रकारों से सम्बन्धित जिन प्रतिदर्श इकाईयों का सर्वेक्षण किया गया है उनका उल्लेख सारणी संख्या ७.०१ में किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सम्मिलित किया गयाहै। सर्वेक्षण कार्य में केवल कुछ औद्योगिक इकाईयों को ही सम्मिलित किया गया है।

सारणी संख्या -७.०१

पूर्वी उत्तर प्रदेश

प्रतिदर्शे सर्वेक्षित औद्योगिक इकाइयाँ

कृषि आधरित उद्योगों के प्रकार	औद्योगिक केन्द्र	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम एवं स्थापना वर्ष
चीनी उद्योग	बभनान (गोण्डा)	१	बलरामपूर सुगर मिल इकाई बभनान -१६३५
	बलरामपुर नगर	२	बलरामपूर सुगर मिल इकाई बभनान -१६३२
	फैजाबाद (मसोधा)	३	मसोधा सुगर मिल फैजाबाद -१६४०
चावल उद्योग	अम्बेडकर नगर	४	राजपूत चावल मिल-१६६४
	फैजाबाद (रसूलापुर)	५	पूर्वांचल चावल मिल -१६६३
	अम्बेडकर नगर	६	अशोक मिनी राइस मिल -१६६३
	मिर्जापुर साकतगढ़	७	बाबू चावल मिल -१६६५
आठा उद्योग	फैजाबाद (रानीबाजार)	८	रमेश आटा चक्की -१६८७
	फैजाबाद (सहादतगंज)	६	कृष्णा आठा मिल -१६६३
	फैजाबाद नगर	१०	छोटे लाल आटा मिल -१६६६
	गोरखपुर (जगत बेला)	११	जगत आटा मिल -१६६५
तेल उद्योग	गोण्डा (इडिया थोक)	१२	रामऔतार आयल मिल -१६६६
	अम्बेडकर नगर	१३	बी०आर० आयल मिल अम्बेडकर नगर
	फैजाबाद नगर	१४	गुप्ता आयल मिल.-१६६३
	मिर्जापुर(बरौधा)	१५	रामधनी तेल मिल -१६६८
	बलिया (रसडा)	१६	छेदी आयल मिल -१६६५
	गोरखपुर (शहजनवा)	१७	बहोरे तेल मिल -१६६५
	प्रतापगढ़ (हरनामगंज)	१८	खालीद तूल मिल -१६६६
दाल उद्योग	बहराइच (पयागपुर)	१६	पयागपुर दाल मिल -१६८०
	बहराइच नगर	२०	राम आसरे दाल मिल -१६८८
	बलिया (बेलथरा)	२१	रामेश धनी तेल मिल
	फैजाबाद (पूरा बाजार)	२२	शिवम् दाल मिल -१६६०
	प्रतापगढ़ (अन्नू)	२३	निहोर दाल मिल -१६६५
	आजमगढ़ (सरायरानी)	२४	कुमकुम दाल मिल -१६६०
खाण्डसारी उद्योग	गोण्डा (मनकापुर)	२५	राम लाल खाण्डसारी -१६८७
	गोण्डा (मोतीगंज)	२५	पाण्डेय खाण्डसारी उद्योग -१६६०

अधिकतर उद्योग लघु उद्योग (चीनी उद्योग एवं दाल उद्योग को छोड़कर) वर्ग के हैं। केवल चीनी उद्योग ही वृहत उद्योगों के अन्तर्गत आता है। अध्ययन क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की १०४ लघुस्तरीय औद्योगिक इकाईयाँ विकसित हैं जिनमें कुल ४५६ श्रमिक कार्यरत हैं। शेष औद्योगिक इकाईयाँ नगरीय क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है।

जनपद की दृष्टि में सबसे अधिक औद्योगिक इकाईयाँ वाराणसी जनपद में स्थित है। इसके बाद गोण्डा तथा सुलतानपुर जनपदों का स्थान है। इन जनपदों में क्रमशः खाद्य तेल एवं सिल्क, खाद्य तेल, चावल उद्योग का विकास अधिक हुआ है।

आटा उद्योग में गाजीपुर जनपद का प्रथम स्थान है जबकि जौनपुर बलिया का स्थान क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। इसी प्रकार चीनी उद्योग में देवरिया जनपद का प्रथम स्थान है तथा दाल मिलों में सुलतानपुर जनपद प्रथम स्थान रखते हैं।

सारणी संख्या ७.०१ से विदित है कि शोध के सम्बन्ध में कुल २६ औद्योगिक इकाईयों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनका विश्लेषण सारणी संख्या ७.०१ में दिया गया है। जिसमें से प्रत्येक उद्योग से तीन-तीन इकाईयाँ हैं। इनका विवरण निम्नवत है-

अध्ययन क्षेत्र में कृषि आधारित २६ औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षित इकाइयों में ८ नगरीय क्षेत्रों की तथा १८ इकाईयाँ नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की है। इनका विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है-

चावल उद्योग-

१. उद्योगकर्ता रामधनी सिंह, अम्बेदकरनगर-

१९९४ में ५०,००० रुपये की लागत से चावल मिल लगायी थी। अपना घर होने के कारण वहीं कारखाना भी लगाया। यहाँ धान की दराई का काम फुटकर रूप में किया जाता है। धान यहाँ के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों से खरीद लिया जाता है तथा उससे निकाले गये चावल को बोरों में भरकर निकटवर्ती बाजार में भेज दिया जा रहा है यहाँ ४ कारीगर काम करते हैं। वर्ष में लगभग २५००० रुपये प्राप्त होते हैं इसमें २४०० रुपये भाड़ा (माल पहुँचाने में) में खर्च हो जाता

है तथा लगभग ५००० रुपये कारखाने में खर्च हो जाता है कुछ अन्य व्यय में चला जाता है १२००० रुपये की वार्षिक बचत होती है। मैकिनिकल स्टॉफ नहीं है। विद्युत एवं इंजन दोनेां सुविध ायें उपलब्ध है।

२. उद्योगकर्त्ता रामबस गुप्ता, रसूलपुर-

१९९३ में ४८००० रुपये की लागत से चावल मिल लगायी गयी थी। घर से लगभग आधा किमी० दूरी पर यह मिल स्थित है। यहाँ पर भी धान की दराई का काम फुटकर रूप में होता है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों से धान खरीद लिया जाता है तथा उससे उत्पादित चावल को बोरों में भरकर समीप के बाजारों में बेच दिया जाता है। वर्ष में कुल ४०,००० रुपये की आय प्राप्त होती है जिसमें से लगभग ५००० रुपये कारखाने में खर्च हो जाते हैं। लगभग प्रतिशत उद्योग में २०,००० रुपये की बचत होती है। विद्युत सुविधा उपलब्ध है। मैकनिकल स्टॉफ नहीं है। मशीनों में गड़बड़ी आने पर बाजार से मिस्त्री को बुलाया जाता है।

३. उद्योगकर्त्ता अशोक, अम्बेदकरनगर-

१९९३ में लगभग एक लाख रुपये की लागत से चावल मिल लगायी गयी। मिल के समीप में ही घर भी स्थित है। यहाँ पर धान की दरायी का काम थोक रूप में किया जाता है। नगर के निकट स्थिता ग्रामीण क्षेत्रों से धान मंगा लिया जाता है तथा उसको दर कर यहाँ बाजार में भेज दिया जाता है धान को मंगाने में ३००० रुपये वार्षिक खर्चा आता है। वर्ष में लगभग ५५००० रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होती है। ४ श्रमिक कार्य करते हैं। मशीन में गड़बड़ी आने पर बाजार से मिस्त्री उपलब्ध हो जाते हैं। विद्युत व्यवस्था तथा इंजन व्यवस्था दोनों उपलब्ध है।

४. उद्योगकर्ता रमेश रानीबाजार, फैजाबाद

१९८७ में लगभग २५००० रुपये की लागत से आटा चक्की लगायी गयी थी।यहाँ गेहूँ की पिसाई का काम फुटकर तथा थोक में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूँ खरीद लिया जाता है तथा उसको पीसकर बोरों में भरकर तथा छोटे-छोटे पैकेट में भरकर नगर के बाजारों को भेज दिया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग ४५००० रुपये की आय प्राप्त होती है। ३००० रुपये प्रतिवर्ष परिवहन पर व्यय होता है स्वयं की एक टेम्पों है जिस पर माला को बाजार में भेजा जाता है कारखाने में २ श्रमिक कार्यरत

है मैकेनिकल स्टॉफ नहीं है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। प्राप्त आय में से ३०००० रुपये की वार्षिक बचत होती है।

उद्योगकर्ता कृष्णकुमार सहादतगंज, फैजाबाद

१९९३ में लगभग ४० हजार रुपये की लागत से आटा मिल लगायी गयी थी यहाँ पर थोक एवं फुटकर रूप में पिसाई का काम किया जाता है। पास के गांवों से गेहूँ खरीदा जाता है तथा आटा पीसकर बोरों में भरकर स्वयं की टैम्पों से उसे फैजाबाद नगर में दुकानों पर भेज दिया जाता है। प्रतिवर्ष ५२ हजार रुपये की आय प्राप्त होती है। परिवहन पर प्रतिवर्ष ४००० रुपये व्यय होते हैं। लगभग प्रतिवर्ष १०,००० रुपये कारखाने पर व्यय करना पड़ता है। ३५००० हजार रुपये की प्रतिवर्ष बचत होती है। ३ श्रमिक कार्य करते हैं। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मिस्त्री बाजार में मिल जाते हैं। विद्युत का प्रयोग किया जाता है।

६. उद्योगकर्ता छोटेलाल, फैजाबाद

१९९४ में ५०,००० की लागत से आटा मिल की स्थापना की गयी थी। यहाँ पर गेहूँ की पिसाई का काम थोक तथा फुटकर दोनों रूपों में किया जाता है। नगर से ही गेहूँ खरीदकर उसे पीस कर पैकिंग में भरकर मार्केट में बेच दिया जाता है। परिवहन लागत वार्षिक ५००० रुपये है। वर्ष में लगभग ५५ हजार रुपये की आय प्राप्त होती है जिसमें से ३०,००० रुपये की बचत होती है। तीन श्रमिक कार्य करते हैं। विद्युत व्यवस्था तथा इंजन दोनों सुविधायें उपलब्ध हैं। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है। बाजार में मिस्त्री सुलभ हो जाते हैं।

७. उद्योगकर्ता रामऔतार इटियाथोक, गोण्डा–

१९९६ में २०,००० रुपये की लागत से तेल मिल खोली गयी थी यहाँ दोनों में पेराई का काम फुटकर तथा थोक रूप दोनों में होता है। तेल को ड्रमों में भरकर बाजार में भेज दिया जाता है। सरसों बाजार से ही और निकटवर्ती गांवों से प्राप्त हो जाती है। प्रतिवर्ष ३५००० रुपये की आय प्राप्त होती है। तीन श्रमिक कार्य करते हैं। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। प्रतिवर्ष ३००० रुपये परिवहन लागत पड़ती है। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है। एक कुन्तल सरसों से लगभग ३५ किलो तेल प्राप्त होता है।

८. उद्योगकर्ता वीरेन्द्रराव अम्बेदकरनगर

१९९४ में ३५००० की पूँजी से तेल मिल की स्थापना की गयी। सरसों की पेराई का काम थोक एवं फुटकर दोनों रूपों में किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों से सरसों प्राप्त हो जाती है उसको यहाँ मशीन में पेरकर कनस्टरों में भरकर बाजार में बेच दिया जाता है। लगभग ४००० रुपया प्रतिवर्ष परिवहन व्यय पड़ता हैं ४५००० रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है जिसमें से लगभग ३८००० रुपया की बचत होती है। तीन श्रमिक कार्य करते हैं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है।

९. उद्योगकर्ता रामनरेश गुप्ता, फैजाबाद

१९९३ में ३०,००० रुपये की लागत से तेल मिल स्थापित की गयी । सरसों पेराई का काम थोक रूप में किया जाता है। सरसों बाजार से खरीद ली जाती है तथा मशीन से तेल निकालकर कनस्तर में भरकर बाजार में भेज दिया जाता है। परिवहन लागत लगभग ३००० रुपये की प्रतिवर्ष पड़ती है। ४५००० रुपये की प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है। जिसमें से ३२००० रुपये की बचत होती है। दो श्रमिक कार्य करते हैं। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है। कुन्तल सरसों में लगभग ३५ किलोग्राम तेल प्राप्त होता है।

१०. उद्योगकर्ता रामधनी पयागपुर बहराइच-

१९८० में लगभग २ लाख रुपये की लागत से दालमिल की स्थापना की गयी थी। अरहर को निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदा जाता है तथा उसे मशीनों में साफकर एवं पालिश करके बाजार को भेज दिया जाता है। निकटवर्ती-गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जिलों को दाल भेजी जाती है। प्रतिवर्ष ५०००० रुपये परिवहन लागत आती है ८०००० रुपये की आय होती है जिसमें से ५०००० रुपये प्रतिवर्ष बचत होती है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। दो टेक्निकल स्टॉफ है ७ श्रमिक कार्य करते हैं। एक कुन्तल दाल में ८० किलोग्राम शुद्धदाल प्राप्त होता है।

११. उद्योगकर्ता रामआसरे, बहराइच

१९८८ में लगभग ढाई लाख रुपये की लागत से दाल मिल खोली गयीं। इसमें ७ श्रमिक कार्य करते हैं २ टेक्निकल स्टॉफ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से दाल प्राप्त की जाती है फिर उसे मशीन में डालकर उसे छिलके साफ किये जाते हैं तथा पालिस कर बोरों में भरकर बाजार को भेजा जाता है। बलरामपुर,

गोण्डा, उतरौला आदि को दाल भेजी जाती है। लगभग ४५००० रुपये प्रतिवर्ष परिवहन लागत आती है। ७०००० रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है। जिसमें से ४५००० रुपये की बचत होती है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है।

१२. उद्योगकर्ता शिवम जायसवाल पूरा बाजार, फैजाबाद

१९९० में ढाईलाख रुपये की लागत लगी थी। इसमें ८ श्रमिक काम करते हैं दो टेक्निकल स्टॉफ है। निकट के ग्रामीण क्षेत्रों से अरहर की दाल मंगाई जाती है फिर उसे शुद्धकर बोरों में भरकर फैजाबाद, अकबरपुर, टाण्डा आदि केन्द्रों पर भेजा जाता है। परिवहन लागत ५०००० रुपये प्रतिवर्ष आती है। लगभग ९०००० रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है जिसमें से ५०,००० रुपये प्रतिवर्ष बचत होती है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है।

१३. प्रबन्धक बलरामपुर, शुगर मिल इकाई, बभनान

बलरामपुर शुगर मिल की स्थापना १९३५ में की गयी थी। वर्तमान समय में इसमें में ८१० श्रमिक कार्य करते हैं। कच्चा माल गन्ना पास के ग्रामीण इलाकों में बहुतायत से उगाया जाता है और चीनी को उत्तरप्रदेश के विभिन्न जिलों एवं भारत के अनेक राज्यों में भेजा जाता है। एक कुन्तल गन्ने का लगभग १२ किलो चीनी प्राप्त होता है प्रतिवर्ष १२ लाख टन चीनी प्राप्त होती है। प्राप्त चीनी का पूरा भाग बेच दिया जाता है।

१४. प्रबन्धक बलरामपुर शुगर मिल, बलरामपुर

बलरामपुर शुगर मिल की स्थापना १९३२ में की गयी थी। वर्तमान समय में इसमें १०१० श्रमिक कार्य करते हैं। कच्चा माल गन्ना आस-पास के क्षेत्रों में बहुतायत से उगाया जाता है।

चीनी को देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है रेलवे परिवहन सुविधा उपलब्ध है। प्रतिवर्ष लगभग १५ लाख टन चीनी का उत्पादन प्राप्त होता है। प्राप्त चीनी का पूरा भाग बेच दिया जाता है।

१५. प्रबन्धक, मसौधा शुगर मिल, फैजाबाद

इस शुगर मिल की स्थापना १९४० में की गयी। वर्तमान समय में इसमें १२४० श्रमिक कार्य

करते हैं। कच्चामाल फैजाबाद नगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से उगाया जाता है जो इस मिल के ३० किमी० के क्षेत्र में फैले हैं। चीनी को उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि राज्यों को भेजा जाता है। प्रतिवर्ष लगभग १२ लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है।

१६. रामराख खाण्डसारी उद्योग, मनकापुर, गोण्डा

खाण्डसारी उत्पादन करने वाली इस औद्योगिक इकाई की स्थापना वर्ष १९८७ में हुई थी। यह खादी ग्रामोद्योग इकाइयों के अन्तर्गत पंजीकरण हुई थी। इस इकाई में एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा लगभग नौ हजार रुपये पूँजी के रूप में विनियोजन किया गया है। मनकापुर में खाण्डसारी बनाने का उद्योग विकसित करने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ आसपास के गांवों में गन्ना पैदा किया जाता है। इस उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष १६ हजार रुपये की आय होती है।

१७. पाण्डेय खाण्डसारी उद्योग, मोतीगंज, गोण्डा

इस औद्योगिक इकाई की स्थापना, १९९० में की गयी जो खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत है। एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है तथा लगभग १० हजार रुपये की पूँजी का विनियोजन किया गया है। आसपास के क्षेत्रों से तथा स्थानीय रूप से गन्ना सुलभ हो जाता है। प्रतिवर्ष लगभग २० हजार की आय प्राप्त होती है।

१८. उद्योगकर्ता रामबाबू गुप्ता, साकतगढ़, मिर्जापुर

वर्ष १९९५ में ५०००० रुपये की लागत से चावल मिल की स्थापना की गयी। घर से लगभग ४०० मीटर की दूरी पर यह मिल स्थापित है। यहाँ पर धान की दराई का काम फुटकर तथा थोक दोनों रूपों में किया जाता है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से व्यापारियों द्वारा धान खरीद लिया जाता है तथ उनसे निकाले गये चावल को बोरे में भरकर यहाँ के बाजारों में बेंच दिया जाता है। वर्ष में कुल ४५००० रुपये की आय प्राप्त होती है। जिसमें से लगभग ५००० रुपये कारखाने में खर्चा होते हैं। २०००० रुपये की बचत होती है। विद्युत सुविधा उपलब्ध है। मैकेनिकल स्टॉफ नहीं है।

२०. उद्योगकर्ता रामधनी, बरौंधा, मिर्जापुर

१९९८ में ५५००० रुपये की लागत से तेल मिल की स्थापना की गयी। सरसों की पेराई काकाम

थोक एवं फुटकर दोनों रूपों में किया जाता है। ग्रार्माण क्षेत्रों के व्यापारियों से सरसों का क्रय कर लिया जाता है। और पेरकर उसे बाजार में बेंच दिया जाता है। लगभग ५००० रुपये प्रतिवर्ष परिवहन व्यय पड़ता है। ४५००० रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है। जिसमें से लगभग ३८००० रुपये की बचत होती है। तीन श्रमिक कार्य करते हैं। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। टेक्निकल स्टॉफ एक है।

२१. उद्योगकर्ता रमेशलाल, बेलथरा, बलिया

१९८२ में लगभग २.५० लाख रुपये की लागत से दाल मिल की स्थापना की गयी थी। अरहर को निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदा जाताहै तथा उसे मशीनों से साफ कर एवं पालिश करके बाजार में बेंच दिया जाता है। निकटवर्ती इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, सुलतानपुर जनपदों को दाल भेजी जाती है। प्रतिवर्ष लगभग ४५००० रुपये परिवहन लागत आती है। ८०००० रुपये की आय प्राप्त होती है। ३५००० रुपये की बचत होती है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। दो टेक्निकल स्टॉफ है। ८ श्रमिक कार्य करते हैं। १ कुन्तल अरहर से लगभग ७५ से ८० किलो दाल प्राप्त होती है।

२२. उद्योगकर्ता छेदीलाल, रसड़ा, बलिया

सन् २००० में ५७ हजार रुपये की लागत से तेल मिल खोली गयी। आसपास के ग्रामीण बाजारों में सरसों प्राप्त कर उससके तेल निकाल कर बाजार में भेज दिया जाता है। तीन श्रमिक कार्य करते हैं। ४६ हजार रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है ४००० रुपये परिवहन व्यय प्रतिवर्ष आता है। टेक्निकल स्टॉफ एक है।

२३ . उद्योगकर्ता रामनिहोर, जगतबेला, गोरखपुर

लगभग ३५००० रुपये की लागत से १९९५ में आटा मिल की स्थापना की गयी। यहाँ गेहूँ की पिसाई का काम फुटकर एवं थोक दोनों रूपों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूँ का क्रय कर लिया जाता है तथा उसको पीसकर बोरों में भरकर बाजार तक पहुँचा दिया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग ५५००० रुपये की आय प्राप्त होती है। ४००० रुपये प्रतिवर्ष परिवहन व्यय आता है। कारखाने में तीन श्रमिक कार्यरत हैं। मैकेनिकल स्टॉफ एक है। विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। प्राप्त आय में से ३५००० रुपये प्रतिवर्ष बचत होती है।

२४. उद्योगकर्ता बहोरे, शहजनवां, गोरखपुर

१६६७ में ४५००० रुपये की लागत से तेल मिल खोली गयी। सरसों की पेराई का काम थोक एवं फुटकर रूप में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से सरसों प्राप्त हो जाती है। जिससे तेल निकालकर बाजार में बेच दिया जाता है। तीन श्रमिक काम करते हैं। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है। २५००० रुपये की प्रतिवर्ष बचत होती है।

२५ . उद्योगकर्ता रामवृक्ष अन्तू प्रतापगढ़

१६६५ में ३ लाख रुपये की लागत से दाल मिल की स्थापना हुई थी। अरहर को बाजार से तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदा जाता है तथा उसे मशीनों में साफ कर उस पर पालिश कर बाजारों में भेज दिया जाता है। बस्ती, देवरिया, संतकबीरनगर, महाराजगंज जनपदों को दाल भेजी जाती है। ४५००० रुपये परिवहन व्यय पड़ता है। ६०००० रुपये प्रतिवर्ष आय होती है। ७ श्रमिक कार्य करते हैं। दो टेक्निकल स्टॉफ हैं।

२६. उद्योगकर्ता खालिद, कुण्डा हरनामगंज, प्रतापगढ़

१६६६ में ५०००० रुपये की लागत से तेल मिल की स्थापना की गयी यहाँ सरसों की पेराई का काम थोक रूप में किया जाता है। बाजार से तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से सरसों प्राप्त की जाती है। उसे मशीनों में पेर कर तथा तेल निकालकर बाजारों में भेज दिया जाता है। प्रतिवर्ष ४०००० रुपये की आय प्राप्त होती है। ५००० रुपये प्रतिवर्ष परिवहन व्यय पड़ता है। दो श्रमिक कार्य करते हैं। टेक्निकल स्टॉफ नहीं है।

उद्योगकर्ता छेदीलाल, सरायरासी, आजमगढ़

सन् १६६० में २.५० लाख रुपये की लागत से दाल मिल स्थापित हुई। बाजार से तथा ग्रामीण क्षेत्रों से दाल प्राप्त की जाती है बाद में उसे मशीनों में साफ कर तथा पालिश कर दिया जाता है और फिर बाजारों में भेज दिया जाता है। प्रतिवर्ष ७५००० रुपये की आय प्राप्त होती है ८ श्रमिक कार्य करते हैं। दो टेक्निकल स्टाफ हैं। दाल को गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, बलिया आदि जनपदों में भेजा जाता है।

प्रासिसिंग प्रक्रिया

दाल तैयार करने की प्रक्रिया

सर्वप्रथम अरहर को मशीन में डालकर साफ किया जाता है। पुनः साफ अरहर में पानी मिलाकर उसका छिलका उतारा जाता है। तत्पश्चात इसे पानी में भिगोकर २-३ दिन धूप में फैला दिया जाता है और उसके बाद मशीन में डाल दिया जाता है। और दो प्रकार की दाल प्राप्त होती है-

१. फूल दाल

२. स्पेशल दाल

फूल दाल उच्च क्वालिटी का होती है। पुनः इसे मशीन में डालकर पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के लिये दाल को मशीन में डाला जाता है मशीन में पानी एवं दाल एवं एक विशेष प्रकार का तेल गिरा करता है और दाल पॉलिश होकर निकलती रहती है और पॉलिस डिस्को पॉलिश होता है जिसमें चमड़े की परत होती है उसमें पावडर एवं पानी मिला रहता है और दाल को डाल दिया जाता है पॉलिश की हुई तैयार दाल प्राप्त हो जाती है।

गन्ने से चीनी $C_{12}O_{22}H_{11}$ तैयार करना

सर्वप्रथम गन्ने को ढोंगे में गिराया जाता है। डोगा आगे ले जाकर गन्ने को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटता है फिर और आगे जाने पर लोहे के मोटे-मोटे बेलनों के बीच से होकर गुजरता है यहाँ बगास (खुईया) अलग हो जाता है तथा गन्ने का रस अलग होकर लोहे से निर्मित बड़ी-बड़ी टंकियों में चला जाता है इन टंकियों की संख्या ६ है। इन टंकियों को स्टीम द्वारा खूब गर्म किया जाता है फिर इसमें जो मैल निकलता है उसे मशीन द्वारा छान लिया जाता है। उसके बाद इसमें एक निश्चित मात्रा में चूना गंधक व अन्य पदार्थ मिलाया जाता है। फिर यह हीट होकर टंकियों में से मोटे-मोटे पाइपों के द्वारा और आगे जाता है। लगातार खौलने के बाद एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि यह रवेदार गाढ़े घोल का रूप धारण कर लेता है और आगे जाने पर इसे फिर गर्म करके सुखाया जाता है। चीनी को जितने बड़े आकार का बनाना होता है उसे आवश्यकतानुसार यन्त्र को सेट करके रखा जाता है और जब वह गाढ़ा घोल इस यन्त्र (मशीन) के अन्दर आता है तो जिस प्रकार दाना बनाना हो उसी प्रकार का चीनी का दाना बनता जाता है और आगे जाने पर आटोमेटिक सिस्टम द्वारा निश्चित

EASTERN U.P. - SURVEYED INDUSTRIAL UNIT
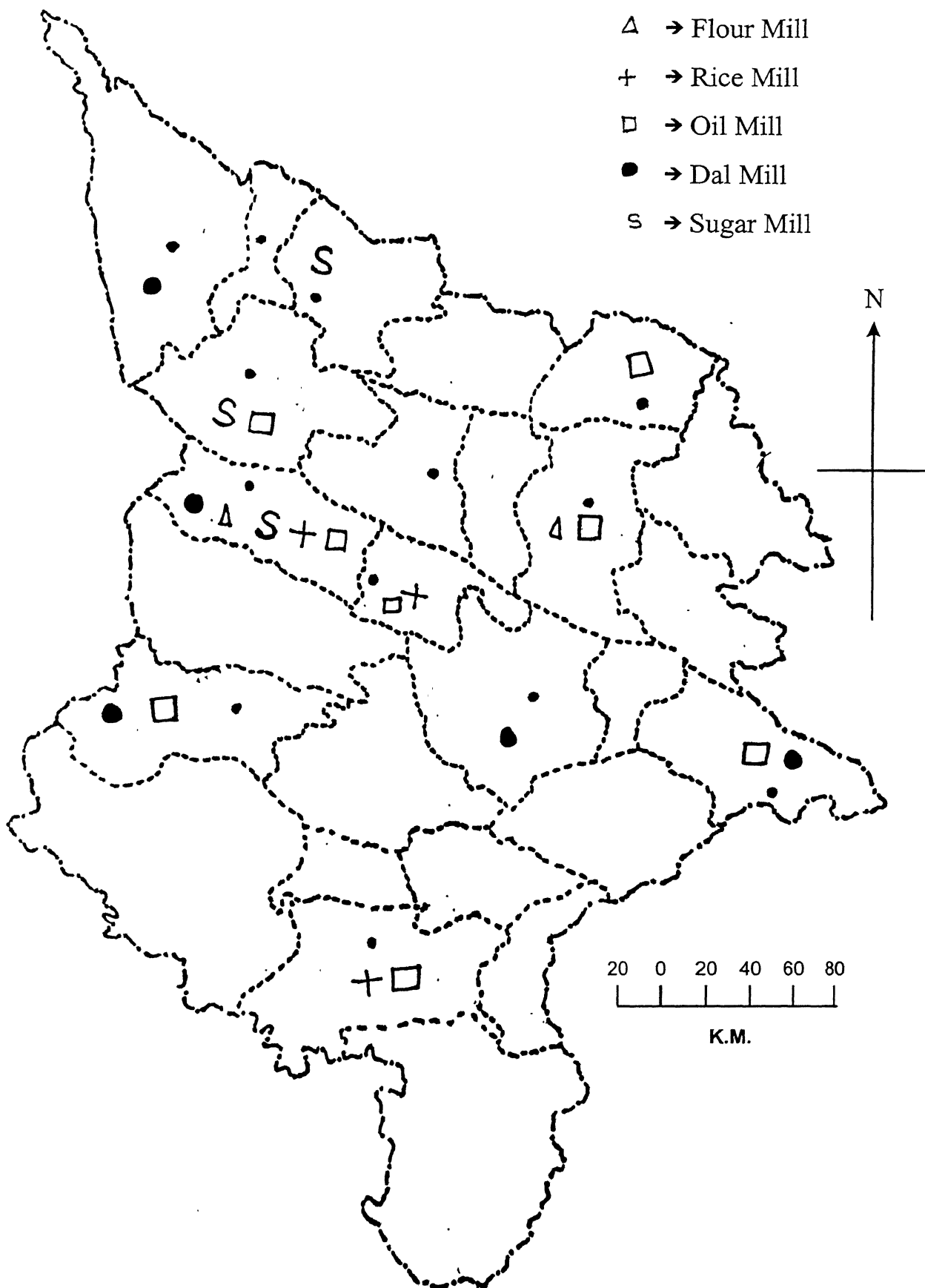
MAP No.- 6.09

मात्रा (वजन) के बोरी में अपने आप भर जाता है। इस पर बोरा सिलने वाली मशीन से सिलाई कर दी जाती है इस प्रकार यही प्रक्रिया बार-बार होती रहती है और चीनी बनती रहती है।

समीक्षात्मक निष्कर्ष-

ऊपर दिये गये सर्वेक्षित इकाईयों के विवेचनों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूर्वी उत्तरप्रदेश में कृषि पर आधारित कई लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाईयाँ सक्रिय हैं। इनमें छोटी पूँजी लगी हुई है। प्रत्येक इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। सम्यक व्यवस्था से ये सभी इकाईयाँ लाभ प्रदान कर रहीं हैं एवं सुनियोजन से क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

■
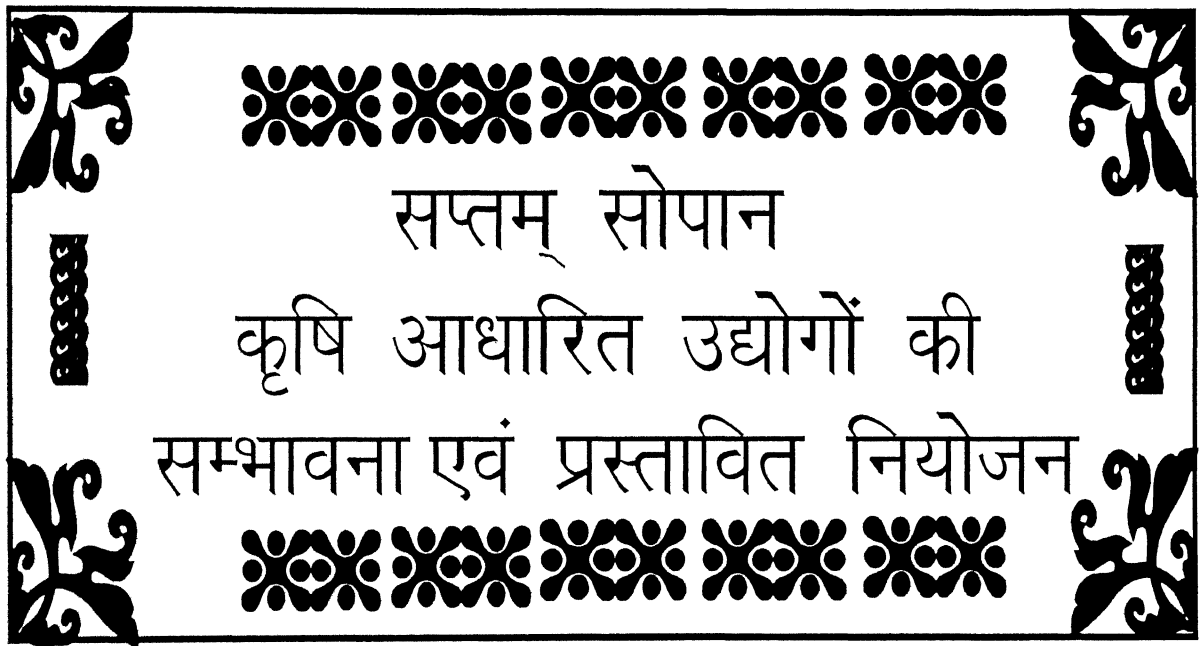
सप्तम् सोपान

कृषि आधारित उद्योगों की सम्भावना एवं प्रस्तावित नियोजन

कृषि आधारित उद्योगों की सम्भावना एवं प्रस्तावित नियोजन

अध्ययन क्षेत्र पूर्वी उत्तरप्रदेश ग्रामीण आंचलों से भरपूर है तथा यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ है जैसा कि पिछले अध्यायों से स्पष्ट है। क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिये इस क्षेत्र को उद्योन्मुख बनाना आवश्यक है।

किसी भी प्रकार के विकास के लिये नियोजन की आवश्यकता होती है। औद्योगिक विकास के लिये तो यह और भी आवश्यक है। किन्तु औद्योगिक विकास भी कई प्रकार के अवसंरचनात्मक विकासों पर निर्भर करता है जो उसके लिये सक्रिय भूमिका प्रदान करते हैं। इसमें परिवहन, विद्युतीकरण, श्रम प्रशिक्षण, बैंकिंग सुविधा आदि का विशेष योगदान हेता है। उद्योगों के सम्भावित विकास में कार्यशील इकाईयों के विस्तार तथा उनमें नये उद्योगों के सृजन से लेकर नये केन्द्रों पर उद्योगों के विकास तक का नियोजन सम्मिलित किया जाता है। उपर्युक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखकर औद्योगिक नियोजन एवं सम्भावित विकास के लिए निम्न कारकों का विवेचन एवं उनके सभाव्यता का आंकलन आवश्यक है-

अवसंरचनात्मक कारक-

अ. परिवहन विकास

ब. विद्युतीकरण विकास

स. मानव संसाधन विकास

द. वित्तीय सुविधा विकास

य. संसाधन विकास

र. अन्य प्रकार के विकास

औद्योगिक प्रगति के कारक-

१. अध्ययन क्षेत्र में पुरानी ईकाइयों का विस्तार

२. अध्ययन क्षेत्र में नये उद्योगों का सृजन

३. अध्ययन क्षेत्र के नये केन्द्रों में उद्योगों की स्थापना।

उक्त कारकों का संक्षिप्त विवेचन निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है-

अ. परिवहन विकास-

शोध क्षेत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ परिवहन के साधनों का समुचित विकास हुआ है। शोध क्षेत्र में सड़को एवं रेलमार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ से ६ राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं जो क्रमशः फैजाबाद-बस्ती, गोरखपुर देवरिया एवं इलाहाबाद, वाराणसी , चन्दौली, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों से होकर गुजरते हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों से कई अन्य छोटी-छोटी सड़के निकलती हैं जो कि एक जनपद को दूसरे जनपद से जोड़ती हैं। क्षेत्र के कस्बों, बाजारों एवं कई बड़े-बड़े गांवों को भी ये सड़के जोड़ती हैं/औद्योगिक इकाईयों के विस्तार तथा सृजन के लिये यह आवश्यक है,लेकिन अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आज भी पक्की सड़को का अभाव है अधिकांश सड़के कच्ची ही हैं जो कि बरसात के मौसम में बहुत ही खराब हो जाती हैं तथा आवागमन के लिये योग्य नहीं रह जाती है। अतः औद्योगिक विकास के लिये इन कच्ची सड़कों को पक्की करना आवश्यक है ताकि आवागमन सुचारू रूप से सम्भव हो सके।

रेल मार्गों का भी अच्छा विकास अध्ययन क्षेत्र में हुआ है लेकिन विभिन्न जनपदों के कुछ भाग अभी भी ऐसे हैं जो रेल मार्गों से काफी दूर स्थित हैं। अतः इन क्षेत्रों में रेल सुविधाओं का विकास आवश्यक है जिससे औद्योगिक विकास की गति बढ़ाई जा सके।

ब. विद्युतीकरण का विकास-

आधुनिक उद्योगों के संचालन में विद्युत उपयोग का महत्त्व सर्वविदित है। छोटे-छोटे उद्योगों में भी अब विद्युत का उपयोग किया जाने लगा है। इस यान्त्रिक युग में विद्युत के बिना किसी प्रकार का विकास सम्भव नहीं है। शोध क्षेत्र में विद्युतीकरण का अच्छा विकास हुआ है केवल कुछ ही स्थानों पर विद्युत का विकास नही

हुआ है। जन-पदवार विद्युतीकरण का विकास सारणी सं० ७.०१ में दिखाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ ही स्थानों पर विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति अनियमित, लघुभारयुक्त एवं अल्पकालिक होती है। इससे उद्योगों का विकास कठिन हो जाता है अतः विद्युत की सुविधा हेतु निम्न प्रयास आवश्यक है-

क. सभी बड़े गांवों तक जहाँ विद्युत लाइन पहुँचायी गयी है वहाँ विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति की जाय। इससे अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण भागों में लघु एवं लघुत्तर उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी।

ख. अनियमित विद्युत प्रवाह को सुधारने के लिये आपूर्ति का प्रभार बढ़ाया जाय। ऐसे केन्द्रों को आपूर्ति के बड़े-बड़े केन्द्रों से जोड़ दिया जाय जहाँ मांग को देखते हुये विद्युत उपयोग कम है। जहाँ उद्योगों के विकास के अवसर हैं अथवा जहाँ पहले से ही कुछ-न-कुछ औद्योगिकीकरण हो चुका है वहाँ पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाय।

सारणी संख्या-७.०१

पूर्वी उत्तरप्रदेश में जनपदवार विद्युतीकरण का विवरण

जनपद	विद्युतीकरण गांवो का प्रतिशत	अविद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत
फैजाबाद	७६	२४
गोण्डा	६८	३२
सुलतानपुर	७७	२३
प्रतापगढ़	७०	३०
इलाहाबाद	८०	२०
वाराणसी	८२	१८
महाराजगंज	६०	४०

सोनभद्र	६२	७८
बलिया	७२	२८
गाजीपुर	७५	२५
मऊ	७२	२८
आजमगढ़	७०	३०
बहराइच	६६	३१
मिर्जापुर	६५	३५
जौनपुर	७४	२६
बस्ती	७३	२७
गोरखपुर	७६	२७
देवरिया	७८	२२
सन्तरविदासनगर	६८	३२
बलरामपुर	६५	३५
श्रावस्ती	६५	३५
सन्तकबीरनगर	६०	४०
चन्दौली	६४	४०
कुशीनगर	६८	३२
सिद्धार्थनगर	७३	२७
अम्बेदकरनगर	७२	२८

ग. विद्युत आपूर्ति में अवरोध को हटाया जाय जिससे प्रवहन जनित ह्रास कम हो सके। विद्युत की चोरी को रोककर आपूर्ति की क्षमता बढ़ाई जाय।

स. मानव संसाधन विकास-

सभी आर्थिक क्रियायें मानवीय प्रयासों द्वारा ही सम्पन्न होती हैं। उद्योगों में तो मनुष्य का विशेष योगदान होता है। कृषि पर आधारित उद्योगों में भी श्रम महत्त्वपूर्ण है। प्रशिक्षित एवं कुशल उद्यमी या श्रमिक अधिक उत्पादन प्राप्त करने में अधिक सक्षम होता है। मानव

DISTRICT WISE DISTRIBUTION OF
ELECTRICFICATION IN EASTERN U.P.
PERSCENT OF VILLAG'S
NON ELECTRIFIED VILLAG
ELECTRIFIED VILLAG
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
FAIZABAD
GONDA
SULTANPUR
PRATAPGARH
ALLAHABAD
VARANASI
MAHARAGANJ
SONBHADRA
BALLIA
GHAZIPUR
MAU
AZAMGARH
BAHRAICH
MIRZAPUR
JAUNPUR
BASTI
GORAKHPUR
DEORIA
SANTRAVIDAS NAGAR
BALRAMPUR
SRAVASTI
SANTKABARNAGAR
CHANDUALI
KUSINAGAR
SIDDHARTH NAGAR
AMBEDKARNAGAR
FIG. NO.7.03

की सक्रियता को विकसित करने के लिये कई प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहें हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रतीत हो रहे हैं-

१. **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण-** औद्योगिक विकास की गति को तेजी देने तथा शिक्षित एवं तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना अध्ययन क्षेत्र में चलायी जा रही है। इण्टरमीडिएट पास व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उन्हें उद्योग चलाने के लिये ऋण भी प्रदान किये जा रहे हैं।(उ० प्र० ६६ पृष्ठ ५८६) कुछ प्रमुख प्रशिक्षण परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं-

क. ट्राइमेस योजना- १८ से ३५ वर्ष के आयु के लोगों को इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के पैटर्न पर बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है।(उ० प्र० ६६ पृष्ठ ५८६)

ख. महिला उद्यमी प्रकोष्ठ परियोजना- इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को उनके अनुरूप या हस्तशिल्प कार्य चलाने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।(उ० प्र० ६६ पृष्ठ ५६१)

ग. मास्टर क्राफ्टमैन प्रशिक्षण योजना- इस योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें योग्य प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। इसमें लोहारी, बढ़ईगिरी आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें शिल्पकला चलाने योग्य बनाया जाता है। (उ० प्र० ६६ पृष्ठ ५६५)

घ. वित्तीय सुविधा विकास- उद्योगों के विकास तथा उन्हें चलाने के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है। लघु, लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों का लाभ निर्बल व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिये उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा ऐसी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। कुछ योजनाओं का विवरण निम्नवत है-

१. अंश पूंजी भागीदरी योजना-

उत्तर प्रदेश के राज्य औद्योगिक विकास निगम नये उद्योग खोलने के लिये निर्धारित शर्तों पर योजना का कुछ भाग अंश पूजीं के रूप में प्रदान किया जाता है।(उ० प्र० ६६ पृष्ठ ५६८)

२. अल्पसंख्यक समुदाय ऋण योजना-

इस योजना के अन्तर्गत भी कुछ शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है।(औद्योगिक प्रेरणा १६६६ पृष्ठ १२)

३. जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी योजना

प्रदेश सरकार द्वारा अध्ययन क्षेत्र में लघु इकाईयों की स्थापना हेतु कुछ शर्तों के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है। (औद्योगिक प्रेरणा १६६६ पृष्ठ ५)

४. प्रवासी भारतीय उद्योग बन्धु योजना- इस योजना के अन्तर्गत प्रवासी भारतीयों को उद्योग लगाने हेतु १५ लाख रुपये तक का सीड कैपिटल विक्रय ऋण यू० पी० एफ० सी० द्वारा प्राथमिकता पर दिया जाता है।

५. एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना- इसमें प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योमियों को कुछ शर्तों के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।(औद्योगिक प्रेरणा १६६६ पृष्ठ ५)

शोध क्षेत्र के उद्यमियों को भी इन योजनाओं से लाभ हो रहा है परन्तु पर्याप्त लोग इनसे लाभान्वित नहीं हुये हैं। शोध क्षेत्र के छोटे कस्बे व बड़े-बड़े गावों में भी उद्योग को लगाये जाने की रुचि बढ़ायी जानी चाहिए।

य. औद्योगिक अस्थानों का विकास- इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को विकसित सेड तथा विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थापना सुविधाओं जैसे- सड़क, जलव्यवस्थ्रा, जलनिकासी प्रबन्ध तथा औद्योगिक फीडर लाइन की सुविधा आदि उपलब्ध करायी जाती है। उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिये रोड़

तथा भूखण्ड का मूल्य का १० प्रतिशत अर्जेण्ट मनी जमा करने के पश्चात शेष धनराशि को १५ वर्षों में ६ प्रतिशत के ब्याज के साथ आसान किश्तों पर दिया जाता है।(औद्योगिक प्रेरणा १९९९ पृष्ठ १०)

क. संसाधन विकास- उद्योगों की स्थापना हेतु कच्चामाल बड़ा बड़ा संसाधन है। इसलिये उद्योग कच्चे माल पर विशेष रूप से निर्भर होते हैं। शोध क्षेत्र में मुख्य कच्चे पदार्थ कृषि प्रदत्त तथा पशु प्रदत्त हैं। वनों से प्राप्त तथा खनिज संसाधन नगण्य हैं। अतः इस क्षेत्र का विकास कृषि तथा पशुधन के नियोजित विकास पर ही निर्भर है। यहाँ गन्ना, जूट, कपास, फलोत्पादन, रेशम आदि के उत्पादन को बढ़ाकर नये उद्योगों का विकास किया जा सकता है। दूध उत्पादन को बढ़ाकर डेरी उद्योग का और अधिक विकास हो सकता है। आटा, चावल, दाल मिलों को नये केन्द्रों पर स्थापित किया जा सकता है पुराने केन्द्रो में भी इनकी नयी इकाइयाँ लगायी जा सकती हैं।

ख. अन्य विकास- अन्य प्रकार के विकास में उत्पादित वस्तु के लिये विपणन व्यवस्था उचित ढंग की होनी चाहिए जिससे उद्यमियों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिये बाजारों एवं हाटों का समुचित अन्तराल पर होना आवश्यक है।

२. औद्योगिक प्रगति के कारक- किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति के लिये उद्योगोंका नियोजित विकास करना आवश्यक है। शोध क्षेत्र में भी उद्योगों के विकास को द्रुतगति प्रदान करने के लिये उनका नियोजित विकास आवश्यक है। इसके लिये निम्न तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए-

क. पुरानी इकाईयों का विस्तार- शोध क्षेत्र में कार्यरत अनेक इकाईयाँ पूर्ण क्षमता से कार्यशील नहीं हैं। मशीनों की गड़बड़ी, विद्युत की अनियमितता उद्यमियों का अल्पज्ञान, अकुशल श्रमिक तथा वस्तु का उचित मूल्य न मिलने से औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गयी है। अतः इन व्यवधानों को दूर करना आवश्यक है।

पुराने केन्द्रों पर पुराने उद्योगों की और अधिक इकाईयाँ तभी लगायी जा सकती हैं जब उस उद्योग की मांग को पूरा करने से पहले से स्थापित इकाइयाँ पर्याप्त न हों।

ख. नये उद्योगों को सृजन

पुराने केन्द्रों पर नये उद्योग भी लगाये जा सकते हैं यदि उनके लिये उचित सुविधायें सुलभ हों।

ग. नये केन्द्रों में उद्योगों का सृजन-

शोध क्षेत्र में नये केन्द्रों पर कच्चे माल एवं वस्तुओं की मांग के अनुसार उद्योगों का सृजन किया जाना चाहिए। शोध क्षेत्र मे भी नये केन्द्रों में प्राप्त होने वाले कच्चे माल के आधार पर तथा वस्तुओं के मॉग के अनुरूप उद्योगों का विकास आवश्यक है।

औद्योगिक विकास में सन्तुलन-

अध्ययन क्षेत्र में उद्योगों के विकास को कृषि विकास से सन्तुलित करना आवश्यक है। बिना दोनों के समन्वय के अपेक्षित आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। नगर एवंग्राम्य औद्योगिक केन्द्रों में कुछ हद तक संतुलन आवश्यक है कुछ प्रकार के लघु एवं लघुत्तर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आरक्षित करना चाहिए अन्यथा नगरीयइकाईयों की होड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की इकाइयाँ विकसित नहीं हो सकती हैं।

औद्योगिक विकास का अन्य पेशों से सन्तुलन

विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में स्वयं का सन्तुलन होता है। इसलिये लोग अधिक लाभप्रद पेशे की ओर स्वतः आकृष्ट होते रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से विभिन्न पेशों का कुछ हद तक सन्तुलन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सरकारी प्रयत्न द्वारा इस ओर प्रयास करना चाहिए। उद्योगों का विकास भी इस प्रयास की एक कड़ी होगी।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुये अब शोध क्षेत्र में उद्योगों के सम्भावित विकास पर विचार किया जायेगा। वर्तमान गतिविधि को ध्यान में रखते हुये भविष्य में औद्योगिक विकास मात्रा तथा विविधता में किस प्रकार का होना चाहिए यह उद्योगों के सम्भावित विकास का उद्देश्य होगा।

सारणी संख्या ८.०२ में शोध क्षेत्र में सम्भावित उद्योगों की सूची दी गयी हैं इससे

सारणी संख्या -७.०२

पूर्वी उत्तर प्रदेश

सम्भावित उद्योगों के विवरण

क्र०स०	उद्योग का वर्ग	इकाई	श्रमिक	पूंजी
१	कृषि पर आधारितउद्योग	४३०	३०५१	६१८.०
२	वनों पर आधारित उद्योग	३६०	१८७५	३१८.०
३	पशुधन पा आधारित उद्योंग	१६८	६४०	४८०.०
४	केमिकल्स पर आधारित उद्योग	२४०	२०८०	५८७.०
५	इंजीनियरिंग पर आधारित उद्योग	२१०	१६८७	७७८.०
६	विविध उद्योग	६८	१०१२	२२८.०
	योग	१५६६	६१४५	३३६०.०

स्रोत :- लीड़ बैक रिपार्ट : बैक आफ बडौदा द्वारा प्रकाशित

स्पष्ट विदित होता है कि इस शोध क्षेत्र में भावी उद्यमियों द्वारा वनों पर तथा कृषि पर आधारित औद्योगिक इकाईयाँ अधिक संख्या में स्थापित की जायेगी। सबसे अधिक पूंजी का विनियोग कृषि पर आधारित उद्योगों में किया जायेगा साथ ही साथ आवश्यकता के अन्य सामानों (जैसे साबुन, चर्म उद्योग, प्रिटिंग प्रेस आदि) पर आधारित उद्योगों के विकास के भी सुअवसर है।

सम्भावित उद्योगों का वितरणीय विश्लेषण

कृषि पर आधारित उद्योग

चीनी उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में चीनी उद्योग की स्थापना की प्रबल सम्भावनायें है। इन क्षेत्रों में गन्ने का कुल उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर चीनी मिलों की स्थापना की सम्भावना विद्यमान है। फैजाबाद जनपद का मिल्कीपुर क्षेत्र, सुलतानपुर जनपद का कादीपुर क्षेत्र, अम्बेदकरनगर जनपद का जलालपुर क्षेत्र तथा आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना की जा सकती है। इन क्षेत्रों में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन ५६ कुन्तल प्रति हेक्टेयर है इसे बढ़ाकर ६५ कुन्तल प्रति हेक्टेयर किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के २७०० एकड़ भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। गन्ना उत्पादक भूमि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कुल १५६३०० टन गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अतः इन क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना की जा सकती है।

रेशम उद्योग- अध्ययन क्षेत्र के तराई वाले भागों में रेशम उद्योग विकसित किया जा सकता है। बस्ती, गोण्डा, बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर तथा श्रावस्ती जनपदों के तराई क्षेत्रों में रेशम उद्योग के विकास की काफी सम्भावनायें विद्यमान हैं। इन तराई क्षेत्रों की जलवायु, भूमि किस्म, सिंचन सुविधायें, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर रेशम उत्पादन के सर्वथा अनुकूल हैं। इन जनपदों के लगभग १८०० एकड़ क्षेत्रफल में शहतूत वृक्षारोपण द्वारा शहतूती रेशम के उत्पादन की प्रबल सम्भावनायें विद्यमान हैं। बहादुरपुर, बनकटी, हलधरमऊ, महासी, सरदारनगर, सिसवां, परिवारा, खडडा, पयागपुर प्रमुख केन्द्र

हैं।

रस्सी तथा बोरे बनाने का उद्योग- अध्ययन क्षेत्र के गोण्डा बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बस्ती जनपदों में जूट की अच्छी कृषि की जाती है। इन जनपदों में कुल १२ कुन्टल प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किया जाता है। कुल १२६३ हेक्टेयर भूमि पर जूट की कृषि की जाती है तथा १४६३० टन रेशे का उत्पादन किया जाता है। इन रेशों से रस्सी तथा बोरे बनाने काकार्य इन जनपदों में किया जा सकता है । कटका, चितौर, केसरगंज, लक्ष्मीपुर, कप्तानगंज प्रमुख केन्द्र हैं।

तम्बाकू बनाने का उद्योग- गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती तथा बस्ती जनपदों में तम्बाकू की अच्छी कृषि की जाती है। प्रति हेक्टेयर २४० टन तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है। जबकि इन जनपदों में तम्बाकू का कुल उत्पादन २७०२४० कुण्टल है। इस उत्पादन को थोड़ा और अधिक बढ़ाकर तथा उत्पादकों को प्रोत्साहित कर तम्बाकू उद्योग का विकास सम्भव है। मनकापुर, वजीरगंज, इन्का, छावनी प्रमुख केन्द्र हैं।

महिला गृह उद्योग- इस उद्योग के अन्तर्गत उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अन्तर्गत महिलायें कच्चे माल द्वारा घर पर ही वस्तुओं का निर्माण करती हैं। निर्मित माल को निकटवर्ती बाजार केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश जनपदों में इस उद्योग के विकास की प्रबल सम्भावना विद्यमान है। इन उद्योगों में आलू से चिप्स बनाना, चावल से पापड़ तैयार करना आदि सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र के सभी जनपदों में आलू तथा चावल की अच्छी पैदावार होती है तथा बाजार केन्द्रों पर इन सभी वस्तुओं की अच्छी मांग भी है।

बेकरी उद्योग- जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण तथा जनसंख्या की क्रयशक्ति में वृद्धि के कारण इस अध्ययन क्षेत्र में बिस्कुट आदि पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है। अतः अध्ययन क्षेत्र मे इस उद्योग की भी इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है।

वनों पर आधारित उद्योग

दियासलाई उद्योग - अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कुटीर उद्योग के रूप में

दियासलाई उद्योग के विकास की प्रबल सम्भावनायें विद्यमान हैं। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, देवरिया जनपदों के क्रमशः नौगढ़, डुमरियागंज, इटवा, पयागपुर, नौतनवा, सलेमपुर तथा मरयाररानी केन्द्रों पर कुटीर उद्योग के रूप में दियासलाई उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं। इन क्षेत्रों में पपीता आदि की अच्छी कृषि की जाती है तथा वनों से सेमल आदि की लकड़ी की बहुतायत से मिल जाती है जो कि मुलायम होती है। इसके निर्माण में प्रयुक्त रसायन यथा पोटैशियम, क्लोरेट, पोटाश, पैराफिन, फास्फेट आदि को अन्य जनपदों से आयात किया जा सकता है। अतः इन जनपदों के विभिन्न केन्द्रों पर दियासलाई उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। डुमरियागंज, इटवा, पयागपुर, नौतनवाँ, सलेमपुर, मटियारदानी प्रमुख केन्द्र हैं।

खेल के सामान बनाने का उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, श्रावस्ती जनपदों में खेल के सामान बनाने की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। केसरगंज, मटरसी, बांसी, इटवा, निचलौल हाटा, रूद्रपुर ऐसे केन्द्र हैं जहाँ इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों से बेंत तथा शहतूत की लकड़ी तथा पशुओं की आतें, खाल तथा पंख आदि आसानी से आवश्यकतानुसार उपलब्ध है। साथ ही अध्ययन क्षेत्र तथा उसके बाहर इन सामानों की पर्याप्त मांग भी है। केसरगंज, महसी, बांसी, इटवा, निचलौल, हाटा, रूद्रपुर प्रमुख केन्द्र हैं।

फर्नीचर उद्योग- महाराजगंज, बस्ती तथा बहराइच जनपदो में फर्नीचरों की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। इन जनपदों में वनों से इस उद्योग के लिये पर्याप्त लकड़ी प्राप्त हो जाती है तथा फर्नीचर आदि की नगरीय क्षेत्रों में काफी अधिक माँग भी है। इसके अलावा नक्कासीदार लकड़ी तख्तों आदि का भी निर्माण किया जा सकता है। अतः इन जनपदों में स्थानीय रूप से लकड़ी की पूर्ति न होने के कारण फर्नीचर उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है। निचलौल, नानपारा, केसरगंज तथा भानपुर एवं मेंहदावल केन्द्रों पर ये इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है।

पैकिंग बाक्सेज उद्योग- अध्ययन क्षेत्र को दफ्ती तथा लकड़ी से बने पैकिंग बाक्सेज की मांग नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। अतः बैंक ऑफ बड़ौदा की लीड़ रिपोर्ट के अनुसार

श्रावस्ती, महाराजगंज, देवरिया, बहराइच तथा फैजाबाद जनपदों में पैकिंग बाक्सेज बनाने की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में पैकिंग एवं बाक्सेज बनाने की कई इकाइयाँ स्थापित हैं। फिर भी इनसे मांग की पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती है। अतः उपर्युक्त जनपदों में जहाँ कि लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तथा फैजाबाद जनपद में कागज से तश्तरी, झोले, कागज के डिब्बे बनाने की भी इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। इन जनपद में कागज की मिल होने के नाते ये छोटे सह उद्योग आसानी से विकसित किये जा सकते हैं। इस प्रकार जौनपुर जनपद में दोनों उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

बीड़ी उद्योग- अध्ययन क्षेत्र के बहराइच, महाराजगंज, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, जनपदों में बीड़ी बनाने वाले कुशल श्रमिक अधिक संख्या में पाये जाते हैं। अतः इन जनपदों में बीड़ी बनाने की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है।

पशुधन पर आधारित उद्योग

चर्मशोधन एवं जूता चप्पल उद्योग-

अध्ययन क्षेत्र के बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर तथा महाराजगंज जनपदों में चर्मशोधन एवं जूता चप्पल उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। इन जनपदों में लगभग ४० हजार टन वार्षिक पशुओं की खालें प्राप्त होती हैं जिसका अधिकांश भाग अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अतः अध्ययन क्षेत्र में चर्मशोधन इकाइयाँ लगाने के इच्छुक उद्यमियों को प्रशिक्षित करके उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जूता एवं चप्पलों की भी मांग बढ़ रही है। साथ ही बैग, अटैची की भी पर्याप्त मांग होने के कारण इन कारखानों की भी इकाइयाँ इन जनपदों में स्थापित की जानी चाहिए। जनपदों के प्रमुख केन्द्रों में नानपारा, इंटियाथोक, उतरौला तथा नौतनवाँ हैं।

डेरी उद्योग - अध्ययन क्षेत्र में प्राचीन समय से ही मनुष्य गाय, भैसों को पालता चला आ रहा है। यदि इन गाय भैसों का पोषण देखरेख वैज्ञानिक ढंग से की जाय तो अध्ययन क्षेत्र में दूध के उत्पादन को वर्तमान उत्पादन की अपेक्षा कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

अतः अध्ययन क्षेत्र डेरी उद्योग के विकास की सम्भावनायें अधिक है। दूध, मक्खन, पनीर, खोया आदि जल्दी नष्ट हो जाते हैं अतः अध्ययन क्षेत्र डेरी उद्योग को खपत क्षेत्रों के निकट ही लगाया जाना चाहिए। डेरी उद्योग मिर्जापुर, सन्तकबीरनगर, गोरखुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जनपदों में खोले जा सकते हैं। प्रमुख केन्द्र, लालगंज, शहजनवां सोरांव, पिण्डरा है। जहाँ डेरी उद्योग की इकाई स्थापित की जा सकती है। एतदर्थ महिलाओं का सहयोग प्राप्त कर महिला डेयरी योजना को लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

केमिकल्स पर आधारित उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में साबुन डिटर्जेण्ट बनाने की इकाइयाँ इस क्षेत्र की मांग को पूरा नहीं कर पाती हैं अतः अध्ययन क्षेत्र में साबुन तथा डिटर्जेण्ट बनाने की नयी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता है ये इकाइयाँ क्रमशः मऊ, चन्दौली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर जनपदों में तथा चकिया, पट्टी, फुलपुर, हंडिया, शाहगंज, केराकत, पिण्डरा, मड़िहान, सैदपुर, केन्द्रों पर स्थापित की जा सकती है।

अगरबत्ती बनाने का उद्योग - अगरबत्ती बनाने की इकाइयाँ लगाने के लिये अधिक पूँजी तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगरबत्ती स्थानीय बाजार में तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त मांग भी होती हैं। फैजाबाद, सुलतानपुर, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद जनपदो में अगरबत्ती बनाने की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। ये प्रायः पिछड़े केन्द्रों पर यथा मया, शाहबगंज, अमेठी, मोहम्मदाबाद, रसडा, घेरावल तथा लालगंज एवं हांडिया केन्द्रों पर खोली जा सकती है।

इनके अलावा, फिनायल, पेण्टस, स्याही, इत्र, सुगन्धित तेल बनाने के कारखाने जौनपुर, सन्त रविदास नगर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, प्रतापगढ़ जनपदों में इनकी इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। ये इकाइयाँ क्रमशः मडियाहूँ, शहजनवाँ बांसडीह, फूलपुर तथा लालगंज आरा केन्द्रों पर स्थापित की जा सकती है।

इन्जीनियरिंग पर आधारित उद्योग-,

स्टील बाक्स व आलमारी बनाने का उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में स्टील के बाक्स बनाने का उद्योग प्राचीन समय से ही विकसित है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में पहले से ही अनेक स्टील व बाक्स बनाने की इकाइयाँ हैं। फिर भी इलाहाबाद, अम्बेदकरनगर, चन्दौली, मिर्जापुर बलिया आदि जनपदों में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित केन्द्र सोरांव, वारा आलापुर, रावलडीह, चुनार, सिकन्दरपुर है।

पीतल व अल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का उद्योग-

अध्ययन क्षेत्र के इलाहाबाद, मऊ, संतरविदासनगर, वाराणसी में बर्तन बनाने के कुशल कारीगर अधिक संख्या में मिलते हैं। अतः इन क्षेत्रों में पीतल तथा अल्युमिनियम के बर्तन बनाने की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है जिसकी स्थानीय तथ सुदूरवर्ती बाजार में काफी मांग है। इलाहाबाद के मेजा, करछवा, फुलपुर में इसकी इकाइयाँ तथा मऊ के घोसी तथा मधुबन वाराणसी के पिण्डरा केन्द्रों पर इनकी इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

ग्रिल बनाने का उद्योग-

लकड़ी से बने दरवाजों की अपेक्षा लोहे के बने ग्रिल दरवाजे तथा चैनल आदि अधिक सुरक्षित माने जाते हैं अध्ययन क्षेत्र के फैजाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जनपदों के कप्तानगंज देहलीबाजार, कुण्डा तथा मिर्जापुर के लालगंज केन्द्रो पर इनकी इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

विविध उद्योग

सेवा सम्बन्धी उद्योग-

आधुनिक युग में मानव जीवन में विभिन्न यन्त्र चालित मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। टी० वी०, स्कूटर, आटोरिक्शा, ट्रांजिस्टर आदि मानव जीवन के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। इन यन्त्र चलित वस्तुओं को समय-समय पर मरम्मत (सेवा) की आवश्यकता होती है अध्ययन क्षेत्र के फैजाबाद, सुलतानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोण्डा

आदि जनपदों में मरम्मत सम्बन्धी उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावनायें हैं।

इसके अलावा, अध्ययन क्षेत्र में कपड़े के झोले व बस्ते बनाने, निवाड व डेरी बनाने, मत्सय पालन, मुर्गीपालन, कुटीर कुम्हारी उद्योग के विकास की प्रबल सम्भावनायें विद्यमान हैं। प्रिटिंग प्रेस उद्योग की इकाइयाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है। मानचित्र संख्या ८.०१ से प्रस्तावित उद्योग को दिखाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान समय तक कृषि आधारित औद्योगिक विकास कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। पंचम अध्याय में मानचित्र संख्या ६.०६ के अवलोकन से स्पष्ट विदित है कि अध्ययन क्षेत्र में उद्योग कुछ विशेष केन्द्रों पर ही सीमित है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास के लिये उद्योगों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। अतः भविष्य में उद्योगों को उन स्थानों में विकेन्द्रित करने पर बल दिया जाना चाहिए जहाँ पर की जनसंख्या अधिक है। इन स्थानों में सम्भावित औद्योगिक इकाइयाँ, आवश्यकता एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये स्थापित की जा सकती है। इस ओर सरकारी तथा निजी प्रयत्न किया जाना चाहिए। इससे पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। इसी प्रकार नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु समाज के कमजोर वर्गों की सरकारी ऋण आदि की सुविधायें प्रदान कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

■

DISTRICT WISE PROPOSED INDUSTRIAL UNIT IN EASTERN U.P.

MAP No.- 7.01

Reference

1-Boudewille,J.(1966) Problems of Regional Economic Planning,Edinburgh.

2- Bhagwati, J. N. (1970) India : Planning for Industrialization·Bhopal

3- Brown. C. M.(1962); Successful Features in the Planning of New Town Industrial Estates, IJournal of Town planning Institute .

4- Chand, M. and Puri V. K. (1983) Regional Planning in India·Allied Publishers Pvt. New Delhi.

5- Friedmann, J and Lanso, W. (1964). Regional Development and Planning· Reader·University Press, Cambridge.

6- Mathur, J. S. (1977) Area Planning Critical Review and Regional Develop ment with Course in IRD Sept. October NICD Hyderabad.

7- Mishra, R. P. (1978) Regional Planning and National Development·New Delhi.

8- Minshul, R. (1967) Regional Geography, London.

9- Mishra, R. P. (1974) Reginal Planning in India·New Delhi.

10- Mukherjee , A(1992)Methodologies in Decen tralised Planning·New Delhi.

11- Ojha R. N. (1991) Regional Planning.

12- Reiner, T. A. (1971) A multiple Goals Framework for regional Planning Oxford University Press, London.

13- Singh R. P. (1972) Eastern U. P. : A Geographical Analysis in Regional Planning·Varanasi.

14- Singh M. B. (1997) Regional development Planning·Varanasi.

15- Uapdhyay R. D. (1970) Resource and Planning For industrial development in the Gangapar Region of Eastern U. P. Unpublished Ph.D. thesis, Gorakhapur University, Gorakhpur.

16- एक्शन प्लान (१६६८-२०००) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित।

17- औद्योगिक प्रेरणा, १६६६, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित।

18- औद्योगिक निदेशिका १६६८-२००० जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित।

19- लीड बैंक रिपोर्ट १६६६, बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित।
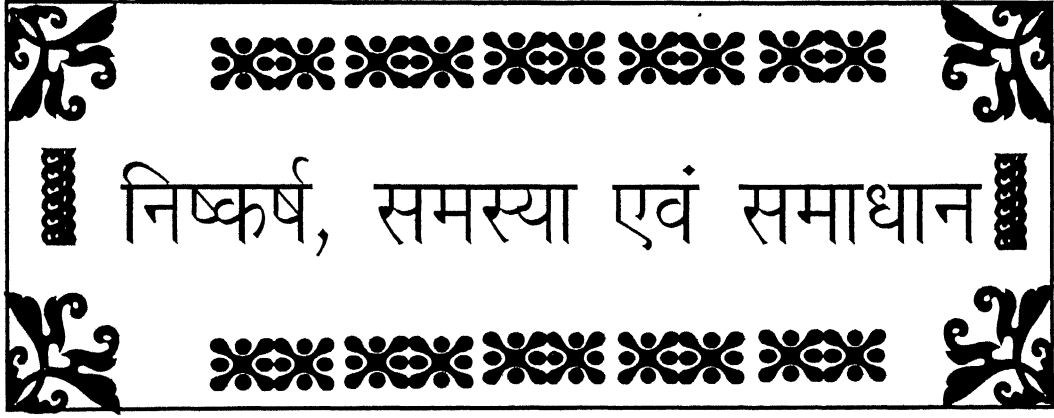
निष्कर्ष, समस्या एवं समाधान

प्रत्येक शोध प्रबन्ध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं । शोध समस्या के विवेचन के उपरान्त कतिपय निष्कर्ष उभरकर सामने आते हैं । जिसके आधार पर शोध की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर भावी शोधों के लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं एवं समस्याओं के समाधान हेतु भावी रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है।

शोध प्रबन्ध के शुरुआत में कुछ परिकल्पनायें बनायी जाती हैं जो शोध क्षेत्र की प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं और शोध विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती हैं। इन परिकल्पनाओं को बनाने के कुछ प्रमुख आधार होते हैं, जो क्षेत्र की सामान्य परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। शोध-प्रबन्ध में इन परिकल्पनाओं की जाँच की जाती है और उसकी सत्यता या असत्यता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस शोध प्रबन्ध में भी ऐसा ही प्रयास किया गया है।

क. निष्कर्ष– कृषि आधारित उद्योग- विशेष रूप से कृषि उत्पादों से सम्बन्धित होते हैं। ये कृषि उत्पाद वृहत स्तरीय लघुत्तर उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के लिये कच्चा माल प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास इन्हीं उत्पादों पर आधारित है। शोधक्षेत्र में उद्योन्मुख फसलों का विकास कम हुआ है। अतः यहाँ उद्योगों का विकास भी कम हुआ है। जाँच के उपरान्त इस परिकल्पना को सही पाया गया है।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः लघु, लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों के विकास की अधिक सम्भावनायें होती हैं। मध्यम स्तरीय या बृहत स्तरीय उद्योगों के विकास की सम्भावनायें प्रायः नहीं होती है। इस शोध क्षेत्र में भी ऐसा ही पाया गया है।

३. परिवहन एवं विद्युतीकरण का पर्याप्त विकास उद्योगों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी इनका पर्याप्त विकास हुआ है उन स्थानों पर उद्योगों का विकास आसान हो जाता है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र में सड़कों का विकास पर्याप्त हुआ है किन्तु रेलों का विकास सीमित क्षेत्रों तक ही हुआ है। विद्युत का भी विकास हुआ है लेकिन अभी भी कुछ गाँवों में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेलमार्गों एवं विद्युतीकरण की अपर्याप्तता के कारण शोध क्षेत्र में उद्योगों का विकास कम हुआ है। मुख्यतः कुछ लघुत्तर एवं कुटीर उद्योग ही

विकसित हो सके हैं जो कृषिगत आधारों पर विकसित हुये हैं।

जाँच के उपरान्त इस परिकल्पना को भी सही पाया गया है। यद्यपि विद्युतीकरण का विस्तार गांवों तक कर दिया गया है परन्तु लघुभार एवं लघुअवधि तथा अनिश्चितता के कारण विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। इसका उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

४. प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का भी उद्योगों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शोध क्षेत्र के ग्रामीण आंचलों में ऐसी सुविधायें प्रायः न के बराबर हैं। केवल नगरीय क्षेत्रों में ही ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं। यही कारण है कि उद्योगों के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

५. आर्थिक साधन भी उद्योगों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे सभी उद्योग प्रभावित होते हैं फिर भी लघु,लघुत्तर एवं कुटीर उद्योग इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। आर्थिक साधनों की ब हुलता का उद्योगों के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है जहाँ इनकी उपलब्धता कम है या नहीं है वहाँ उद्योगों के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शोधक्षेत्र के ग्रामीण भागों में आर्थिक साधनों की कमी है अतः यहाँ उद्योगों के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शोध कार्य में जाँच के उपरान्त इस परिकल्पना को सही पाया गया है।

६. कृषि आधारित उद्योगों पर पशुपालन, मुर्गीपालन एवं फलोत्पादन जैसे कार्यों का भी प्रभाव होता है। वास्तव में लघु,लघुत्तर एवं कुटीर स्तर के इस प्रकार के उद्योग एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े होते हैं। शोध क्षेत्र के ग्रामीण अँचलों में पशुपालन, मुर्गीपालन एवं फलोत्पादन पर आधारित उद्योगों का बहुत कम विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी माँग भी कम है। जाँच के उपरान्त यह परिकल्पना सत्य पायी गयी है।

७. अभियान्त्रिक सेवा कार्य भी उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय-समय पर परिवहन एवं मशीनों की मरम्मत में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शोध क्षेत्र में अभियान्त्रिकी सेवाकार्य का अच्छा विकास हुआ है। जाँच के उपरान्त यह परिकल्पना सत्य पायी गयी।

८. शोधक्षेत्र के ग्रामीण भागों में यदि उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय तो मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन तथा अँचार आदि बनाने के छोटे छोटे उद्योग विकसित हो सकते हैं। प्रस्तुत शोध क्षेत्र के ग्रार्माण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की विशेष कमीं है। जिससे उद्योगों का विकास सम्भव नहीं हो सका है। केवल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका विकास हुआ है। जाँच के उपरान्त यह परिकल्पना काफी हद तक सही पायी गयी है।

समस्यायें- उद्योगों के विकास के लिये मुख्य रूप से ५ कारक आधारभूत माने जाते हैं। यदि इनकी उपलब्धता सीमित है या नहीं है तो अनेक समस्यायें आ जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र के विषय में इन कारकों की स्थिति से उत्पन्न कई प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैं-

१. उद्योगों के विकास में कच्चां माल प्रमुख भूमिका निभाता है, अध्ययन क्षेत्र में नगरीय भागों के अलावा ग्रामीण एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से उत्पन्न पदार्थ कच्चे माल के रूप में उत्पन्न होते हैं। फलों का उत्पादन, मसालों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हर जगह नहीं हो पा रहा है जिससे इन पर आधारित उद्योगों का विकास विस्तृत रूप से किया जा सके, अध्ययन क्षेत्र में चीनी मिलों, दाल मिलों, आँटा मिलों एवं तेल मिलों तथा चावल मिलों का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में पापड़, मैदा, सूजी, बेकरी एवं मसाला उद्योग भी पर्याप्त मात्रा में विकसित किये गये हैं। यहाँ का कृषक वर्ग आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक सम्पन नहीं है उनमें उद्योगों के विकास सीमित ही है। निर्धन कृषकों की इन उद्योगों के उत्पादित पदार्थों के भाग भी कम हैं। इसीलिये ऐसे उद्योगों के विकास की भी एक प्रमुख समस्या है।

२. यातायात के साधनों के विकास के कारण तेल मिल, दाल मिल का विकास शहरी क्षेत्रों में ही हुआ। उनमें उत्पादित वस्तुयें ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से सुलभ होने लगी हैं। ऐसी दशाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक समस्या बन जाती हैं।

३. उद्योगों के विकास में श्रम एक आवश्यक कारक है। कुशल श्रम और विशेष प्रकार से प्रशिक्षित श्रम उत्पादन में सक्रिय योगदान प्रस्तुत करता है। इस शोध क्षेत्र के नगरीय

भाग में तो प्रशिक्षित श्रम सरलता से सुलभ हो जाते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसका समाधान भी औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक है।

४. आधुनिक उद्योग शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। कुछ लघुत्तर एवं कुटीर उद्योग को छोड़कर शेष सभी में किसी-न-किसी रूप में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। शोध क्षेत्र में विद्युत का बहुत हद तक विस्तार हुआ है परन्तु विद्युत भार कम रहता है और विद्युत की उपलब्धता भी लघुकालिक रहती है। उद्योगों के विकास में यह एक जटिल समस्या है। इसका समाधान तो अति आवश्यक है।

५. उद्योगों के विकास में पूँजी की आवश्यकता होती है कोई भी उद्योग बिना पूँजी के नहीं विकसित हो सकता है। शोध क्षेत्र के ग्रामीण अन्चलों में वित्तीय साधनों की विशेष कमी है। गांव के निर्धन कृषक तो बिना बाहरी वित्तीय सहायता के कोई भी उद्योग नहीं लगा सकते हैं। अतः वित्तीय साधनों की उपलब्धता भी एक प्रमुख समस्या है। नगरीय क्षेत्रों में इस समस्या का बहुत कुछ समाधान सरलता से हो जाता है।

६. उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं का विक्रय भी आवश्यक है बिना विक्रय के उद्योगों में लगी पूंजी का आवर्तन नहीं हो सकता है जो उद्योगों के विकास के लिये अति आवश्यक है विक्रय के लिये मांग केन्द्रों या बाजारों का होना आवश्यक है उपयुक्त बाजारों के बिना उत्पादित वस्तु का विक्रय नहीं हो सकता। अतः इन बाजारों के समुचित विकास की भी समस्या है जो शोध क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है।

७. इन प्रमुख समस्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्यायें भी हैं जैसे मुद्रादायनी फसलों का अल्पविकास। यदि कृषक मुद्रादायनी फसलों के विकास पर ध्यान दें तो इस धन को वे उद्योगों के विकास में लगाकर अपने मन चाहे उद्योगों का विकास कर सकते हैं।

८. इन समस्याओं के अतिरिक्त एकीकृत ग्रामीण विकास की अलग समस्या है जो कुछ हद तक औद्योगिक विकास से भी जुड़ी है। ग्राम्यांचलों के उचित विकास के लिये इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

समाधान- समस्याओं का उल्लेख करने के बाद उनके समाधान की ओर संकेत करना भी आवश्यक हो जाता है। किसी समस्या का पूर्ण समाधान तो सम्भव नहीं है। परन्तु आंशिक समाधान अवश्य हो सकता है। ऊपर दी गयी समस्याओं का समाधान निम्न रूप में किया जा सकता है-

१. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कृषि उपजों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, जिनसे उद्योगों के लिये पर्याप्त कच्चामाल मिल सके। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती को बढ़ाना चाहिए जिससे खाण्डसारी उद्योग का विकास किया जा सकता है। मूँगफली की खेती भी प्रचारित करनी चाहिए जिससे इस पर आधारित उद्योग भी लगाये जा सके। चावल मिल, तेलमिल, दालमिल तथा आटा मिल के विकास के लिये उनसे सम्बन्धित कृषि उपजों के उत्पाद में वृद्धि आवश्यक है। मसालों की उपज बढ़ाकर उन पर आधारित उद्योगों का विकास भी किया जा सकता है। सूर्यमुखी की कृषि को लोकप्रिय बनाकर इससे तेल उद्योग को बढ़ाया जा सकता है।

२. इस शोध क्षेत्र में परिवहन का विकास सड़कों के विकास द्वारा ही सम्भव है। कस्बों को तथा बड़े-बड़े गांवों को जहाँ तक सम्भव हो सके पक्की सड़कों से जोड़ देना आवश्यक है। ग्रामीण अंचलों की कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने की आवश्यकता है।

३. उद्योगों के विकास में श्रम को प्रशिक्षित करना तथा उसे समुचित रूप से लगाना आवश्यक है। नगर से प्रशिक्षित श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है। सरकारी सहायता द्वारा ऐसे प्रशिक्षितों को प्रोत्साहन देकर उद्योग लगानें के लिये उत्साहित करना चाहिए।

४. इस शोध क्षेत्र में ग्रामीण अँचलों में भी विद्युत का पर्याप्त विस्तार हुआ है। परन्तु मुख्य समस्या विद्युत के कम भार की तथा उसके अल्प अवधि तक उपलब्ध होने की है। इस समस्या के समाधान के लिये विकास खण्डों में स्थित पावरहाऊस शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है सम्भव हो सके तो विकास खण्ड मुख्यालयों पर उष्मा विद्युत केन्द्र स्थापित कर विद्युत शक्ति क्षमता भी बढ़ाई जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस, सौरऊर्जा एवं वायु उर्जा

कर विद्युत शक्ति क्षमता भी बढ़ाई जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस, सौरऊर्जा एवं वायु उर्जा के समुचित विकास से इस कमी को दूर किया जा सकता है।

५. ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी की कमी को देखते हुये ग्रामीण बैंकों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा भी ऐसी सुविधायें प्रदान की जाने लगी हैं। इस प्रकार पूँजी की समस्या का आंशिक रूप से समाधान हो सकता है। पूंजी देने कीशर्त को आकर्षक बनाकर एवं ब्याज की दर को कम कर नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

६. उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय होना आवश्यक है। अन्यथा उद्योगों का आकर्षण ही समाप्त हो जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर विपणन केन्द्रों या बाजारों का विकास आवश्यक है।*परिशिष्ट विपणन केन्द्रों या बाजारों का विकास आवश्यक है।* परिशिष्ट सारणी संख्या १ में नये बाजारों के विकास का प्रस्ताव किया गया है तथा उन्हें मानचित्र संख्या ८.०१ में दर्शाया गया है। यदि इनमें से कुछ भी बाजारों का विकास सम्भव हो सकेगा तो उससे उद्योगों के विकास में सहायता अवश्य मिलेगी। बाजार तो क्रय केन्द्र का कार्य भी करते हैं जहाँ उद्योगों के विकास के लिये कच्चा पदार्थ मिल सकेगा। इन बाजारों में विक्रय, भण्डारण आदि की पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है।

७. गांवों का एकीकृत विकास होना आवश्यक है। उद्योगों का विकास भी इसके अन्तर्गत एक कारक होगा। एकीकृत विकास में मानव संसाधन से लेकर अवसंरचनात्मक कारकों का विकास किया जाता है। ऐसे विकासों का उद्योगों के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

८. कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मुद्रादायक फसलों का प्रचार आवश्यक है। इन्हें लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार उद्योग हेतु पूँजी की आवश्यकता का आंशिक समाधान सम्भव हो सकता है।

आशा है ऊपर प्रस्तुत किये गये सुझावों से क्षेत्र की औद्योगिक समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नयी दिशा मिल सकेगी।

■

APPENDIX I

QUESTIONNAIRE

WORKING INDUSTIRES / UNITS IN THE DOAB REGION OF ALLAHABAD

1- Name of the Unit

2- Year of Establishment

3- Which of the following features were considered favourable for installing the industry/Unit in this particular areas:

(a) Climatic conditions

i) Temperature

ii) Humidity

(b) Topography

(c) Environment

(d) Handy availability of raw materials required for the Industry .

(e) Easy avilability of power/fuel/energy/water

(f) Availability of land / accommodation .

(g) Availability of labour-skilled / unskilled

(h) Transport facilities.

(i) Market for selling finished goods produced.

(j) Easy disposal of bye products/wastes

(k) Suitable Drainage system

(l) Any other feature

4- Year in which Prodcution started

Type of the Unit

A. Large Scale

B. Medium Scale

C. Small Scale

D. Village & Cottage Industry

Products-

(i) Major Products

(ii) Minor Products

(iii) By- Products

Capital Investment -

(i) Fixed Captial (in Rs.)

(ii) Working Captial (in Rs.)

Production -

(i) Installed Capacity (Annual)

(ii) Actual Production (Annual)

(a) Weight or Number

(b) Value (in Rs.)

Raw Materials-

(i) Types (Indigenous / Scarce /Controlled)

(ii) Nature (Gross/Pure)

(iii) Volume of consumption (annually)

(iv) Sources

10- Consumption of Finished Products

(i) Local

(ii) Export (Outside the region/Foreign . if any)

(iii) Centres to which exported

(iv) Year and volume of export

11- Labour -

(i) Total employment

(ii) Skilled

(iii) Semi-skilled

(iv) Non-skilled

(v) Daily wages

12- Nature of Ownership-

(i) State undertaking

(ii) Private Ltd. - Partnership

(iii) Private Enterprise

(iv) Sole Proprietorship

(v) Co-operative Societies

13- Problems

(i) Labour

(ii) Power

(iii) Land and Accommodation

(iv) Water

(v) Transportation

(vi) Raw materials

(vii) Inter departmental Cooperation

(viii) Finance

(ix) Machinery

(x) Environmental

(xi) Marketing

(xii) Disposal of bye-products /waste

Fuels and Power-

(i) Thermal

(ii) Hydel

(iii) Sources of Supply

(iv) Total requirement

(v) Availability

Character of Enterpreneurs-

(i) Technical Education

(ii) Experience in running any industry

(iii) Whether it is first initiative

(iv) Family Occupation

(v) Subsidiary Occupation

(vi) Whether local or from distant place

Working Associations , if any .

Future expansion and modernisation programme , if any.

Additional Bibliography

1. Alexander, J. W. (1950) 'Geography of Manufacturing': What is it ? Journal of Geography- 49.
2. Abler, R. J. S. and P. Gould (1971) Spatial organisation. The Geographer's view of the world.Englewood clifts, N.J
3. Alexander .J.W. and Gibson , L.I. (1979), Economic Geography .N.I. U.S.A.
4. Arnott, R.(1986) Location Theory .Harword Academic press .
5. Agrawal, S.N. (1967) Population. New Delhi.
6. Agrawal, S.N. (1973) India's Population problems.Tata Mc Graw Hill, New Delhi.
7. Brown ,C.M. (1962) Successful features in the planning of new Town Industrial Estates. Journal of Town planning Institute .
8. Basak. J. K.(1964), Industrial Estate in India- The journal of Industries and Trade, Feb..
9. Bondeville, J. (1966) Problems of Regional Economic Planning Edinburgh.
10. Bhagwati, J. N. (1970) India : Planning for Industrialization Bhopal.

11. Brown, C.M.(1962) Successful Features in the Planning of New Town Industrial Estates, Journal of Town planning Institute .

12. Beaver ; S.H. (1935) 'The Location of Industry' Geography 20.

13. Beekmann ; M.(1968) 'Location Theory' , Random House New York .

14. Bhattacharya , A (1978) 'Population Geography of India' New Delhi.

15. Boudewille, J. R. (1966) Problems of Regonal Economic Planning Vol I University Press, Eidnburgh..

16. Chaudhary ,M.R.(1970), 'Indian Industries Development and location',An Economic Geographical appraisal, IBH pub. Crop. Calcutta .

17. Choose, B.C. (1945) 'Industrial Location' ,Oxford, Panchcel on India Affairs No. 32. London.

18. Chand, M. and Puri, V. K. (1983) Regional Planning in India. Allied Publisher Pvt. New Delhi.

19. Christraller , W. (1966), 'Central Places in Southern Germany. Prentie Hall. New Jersey.

20. Clark, J.I. (1976), 'Population Geography . Pergamon Press. Oxford .

21. Chakravarti , A.K. (1976),Population growth types in India, 1961-71. Journal of Geography .

22. Chauhan, V. S. and Gautam (1995), An Advanced Geog raphy of India (15ed) Rastogi Publications,Meerut.

23. Dutt, R. (1906), The Economic History of India. Tara Publication, New Delhi.

24. Dunn, E.S.,The location of Agricultureal production. Gainesville : uni of Fiorida Press.

25. Dayal ,P. (1958),The location of Development of Aluminium Industry in India. Published in N.G.J.I.

26. Development of Industries in Uttar Pradesh (1964) Directorate of Induatries U.P. Kanpur Planning and Research Devision.

27. DreZner , Z. (2002), Klamroth K.; Schobel ,Wesolowsky G.O. The Weber Problem . Drezner and Harmacher eds.

28. Demko, G.I. ,Rose , H.M. Sehnell, G.A. (1970), Population Geography, Reader, Mc Graw Hill Book Company. New York .

29. Davis Kingsley (1951) ; Population growth in India and Pakistan . Princeton University Press , Princeton.

30. Estall, R.C. and Buchanan, R.O.(1961). Industrial Activity and Economic Geography. London .

31. Everctt, E.H. (1959) 'Handbook for Industry Studies', 'Asia Publising House, Bombay.

32. Florence, P. Sargent (1958), 'Investment Location and Size of Plants'. University Press. Combridge.

33. Friendman ,J. and Lanso, W. (1964) Regional Development and Planning .Reader. Unt. Press, Cambridge.

34. Fujita ,M and I.E. Tisse (2002), Economics of Agglomeration Cites Industrial Location of Human Activites. A numerical Geography approach. Cheltenham, Edward Elgar Publishing co.

35. Gosal , G.S. and Gopal, Krishan (1975) Patterns of Internal Migration in India.

36. Gosal ,G.S. (1974) Population growth in India : Asian Profile.2.

37. Hoover, E.M.(1948);The Location of Economic Activity. Megraw Hill New York.

38. Hartshrone, R.(1929) The Economic Geography of Plant Location, Annals of Real Estate Practice. No.7 1927 and Location as a factor of Geography. Annals. AAG 17.

39. Hamilton , F.E. (1971) Models of Industrial location in Chorley , R.J. and P. Haggeilt models in Geography Nethuen London.

40. Hoffman, L.A. (1965). 'Economic Geography'. New York.

41. Hunker, H. L. (1964), Zimmerman's Introduction to world Resources. Harper and Row. U. N. Publication.

42. Harvey, D. (1976) 'Explanations in Geography' .Edward Arnold. London.

43. Jarrett, H.R.(1977) 'A Geography of manufacturing'. Oxford University Press. London.

44. Kumar Pramila (1997); Udyogik Bhogol,M.P. Hindi granth Academy , Bhopal .

45. Kulsrastha , R.S.(1986) Industrial Economical, Sahitya Bhavan Prakashan ,Agra U.P.

46. Kaushik, S.D. (1995) Principles of Economic Geography (9th ed.) Rastogi and Co. Meerut.

47. Kaushik .S.D. (1995) ; Geography of Resources (IInd ed.) Rastogi pub. Co. Meerut.

48. Kolb, A(1971); East Asia – Geography of Cultural Region Methuen pub. Co. London .

49. Krishan , G. and Madhav Shyam ; Literacy Pattern in India Cities .

50. Kosinski et al. (eds) ; People on the move : Studies on Internal Migration . Anethuen London.

51. Lodha , R.M. (2000); Udyogik Bhogol. Jaipur .

52. Losch , A(1954) 'The Economics of Location', Translated by woglum, W.H. Vale University Press New Haven .

53. Lutlrel , W.P. (1962) Factory Location and Industrial movement , London.

54. Mahdal , B. (1971) Manufacturing Regions of North Bihar. National Geographical Journal of India .

55. Mamoria, C. and Gautam (1998) 'Geographyof India' . Sahitya Bhavan Prakation. Agra.U.P.

56. Mathur. J. S. (1977) Area Planning, Critical Review and Regional Development with Course in IRD Sept. October NICD Hyderabad.

57. Mishra, R. P. (1978) Regional Planning and National Development. New Delhi.

58. Minshul, R. (1967) 'Regional Geography.', London.

59. Mishra, R. P. (1974) Regional Planning in India New Delhi.

60. Mukherijee , A(1992)Methodologies in Decen tralised Planning. New Delhi.

61. Mehata , M.M. (1952) 'Location of Indian Industries'. Allahabad.

62. Mamoria, C.(1995) 'India' (15 ed) Sahitya Bhawan Publication. Agra.U.P.

63. Myrdal , G. (1977) Asian drama , an inquiary in to the Poverty of Nations (abridged). Penguin Books .

64. Naik , J.P.(1975) Poliey and performance in India. Long man, New Delhi.

65. Natrajan , D. (1972) Inter Census Growth of Population Census Centenary Monography No 3 Census of India .

66. Ojha, R. N. (1991) Regional Planning.

67. Pred Allan , Industrialization Initial Advantage and American Metropolitian Growth. Geographical Review.

68. Andreas, P. (1958), 'Theory of Locationand General Economics' Journal of Political Economy Vol.96.

69. Reiner, T. A. (1971) A multiple Goals Framework for regional Planning Oxford University Press. London.

70. Riley, R.C. (1973) Industrial Geography . New Delhi.

71. Rao, R.V. (1967) 'Cottage and small Indutries and Planning Economy ,'sterling Publishers New Delhi.

72. Royan , Von. W. and Bengston, N.A. (1971) Fundamental of Economic Geography . Prentice Hall.

73. Renner , G.T. and others (1960) World Economic Geography An Introduction to Geonomies Thomas Y. Crowell Co. New York .

74. Renner , G.T. and others (1970) Geography of Industrial Localization, Economic Geography.

75. Rawstron , E.N. (1958) Three Principles of Industrial Location , Transaction and Papers I.B.G.

76. Raja, M., A trend Report in Geography 1972 to 1998. ICSSR popular Prakshan Bombay.

77. Smith, M.D. (1971) Industrial Location: an Economic Geography Analysis, John Wiley and Sons, INS, New Delhi.

78. Sinha , B.N.(1972) Industrial Geography of India Calcutta .

79. Singh , B.B. , Agro -Industrial Integration : A Model .

80. Srivastava , P.K. (1973), 'Industrial Economics', Sahitya Bhawan , Agra .(U.P.)

81. Sastry , N.S.R. (1948), 'A Statistical study of India's Industrial /development', Thaekera and Co. Ltd., Bombay.

82. Singh, M. B.(1983) Industrial development patterns and patentials in eastern U.P. lotus publications. Varanasi.

83. Singh, R.L.(1971) 'India A Regional Geography' N.G.S.T. Varanasi.

84. Singh ,K. N. Singh J.(1996) 'Economic Geography' Gyanodaya Publications Gorakhapur.

85. Singh , R. P. (1972) Eastern U. P. : A Geographical Analysis in Regional Planning Varanasi.

86. Singh M. B. (1997) Regional development Planning. Varansi.

87. Smith , J. Russell Smith , Thomas ,B and Phillips ,M. Ogden (1955) ;Industrial and Commercial Geography Hencry Holt.

88. Siddartha ,K; Economics Geography ; Kislay Publication Patna.

89. Singh , R.L. and Singh, K.N. (1971) Middle Ganga Plain inR.L.Singh et al. (eds) 'India : A Regional Geography' .

90. Spengler , J.I. (1961) , Natural Resources and Economic Growth . U.S.A.

91. Stringer, F. and Davis, J.S. (1966) Geography of Resources, World Survey and British Isles London .

92. Symons ,L. (1967) Agricultural Geography, London 12. Singh, R.B.(1963); Road Traffic Flow in U.P. , N.G.N.I Vasanasi .

93. Singh, K.N.(1990) Transport Network in Rural Development , Daudpur Gorakhpur .

94. Singh, K.N.and Singh .J. (1999) 'Economic Geography' , Gyanodaya Prakason, Gorakhpur .

95. Sengupta , P. (1971) ; Effect of emignation and immigration in India 1951-61 , National committee for Geography, Calcutta .

96. Singh, L.R. (1965) The Tarai Region of Uttar Pradesh . Ram Naryan Lal Beni Prasad , Allahabad .

97. Singh, L.R. and D. Nath (1981) Spatial Pattern of Scheduled Caste Population in the Saryupar Plain (U.P.) Lucknow.

98. Singh, L.R.et al. (1976) ;Bundel khand region - A Study in Population /Resource regionalization development model , National Geography Journal of India .

99. Sinha , B.N. and B.K. Mishra (1976); Tribes of Orissa : A Geographical Analysis . Geographical Review of India

100. Thoman, R.S. , Conkling, E.C. and Yeates ,M.H. (1968) ; Geography of Economic Activity.Mc. Graw Hill.New York.

101. Tiwari, R. N. (1965) Location and development of Large Scale Industries in Uttar Pradesh.Unpublished D. Lit., Agra University, Agra, Vol.-I.

102. Thompson , J.H. (1955); A New Methods for Measuring Manufacturing , A.A.A.G.

103. Thompson , W.S. and Lewis, S.T. (1976) Population problems . Tata Mc. Graw Hill. New Delhi.

104. Tremartha , G.T. (1976) ; A Geography of Population: World Patterns John Willy and Sons. New York.

105. Tremartha , G.T. (1953) ; A case for population in Geography : A Reader Mc. Graw - Hill New York .

106. Thaper , S.D. (1962) Small Industries study Methodology and concepts ; Asian Economic Review 4,2 Feb.

107. Uttar Pradesh mein Udyogon Ka Vikas Pragati smiksha 1998-99 Udyog Nideshalaya Kanpur .

108. "UTTAR PRADESH 99" सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

109. Upadhaya, R. D. (1970) Resource and Planning For industrial development in the Gangapar Region of Eastern U. P. Unpublished Ph.D. thesis,Gorakhapur University, Gorakhpur.

110. United Nation ; The determinats and Consequences of Population trends . Vol.(1973) 1. New York .

111. Warnt Z .M. and D. Neft. (1960) Contribution to a Statistical methodology for areal distributions : Journal of Regional Science 63.

112. Wills , K.G.(1969) Transport in Rural Areas Methuen and Co. London .

113. Wilson , A.G. (1967) A Statistical Theory of Spatial Dis tribution Models Transportation Research .

114. Verma, D.N. (1992); Population Patterns: Jaltosh Prakashan Aminabad Lucknow.

115. Yaseen , Leonard C. (1956) Plant location ,American Research council, New Delhi.

116. Zelinsky, W. (1966) A Prologue to population Geography. Prentice hall , Engle wlood, eliff N.J.

117. Zimmermann,W. E. (1951) World Resorces and Industries, Harper and Row, U. N. Publication.

118. औद्योगिक निदेशिका(१९९९) - जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित

119. औद्योगिक प्रेरणा(१९९९) - जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित

120. उं० प्र० में औद्योगिक विकास प्रगति समीक्षा (१९९८-२०००) - उद्योग निदेशालय उ० प्र०

तेल मिल

शीत गृह उद्योग

शीत गृह उद्योग